राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 2] चौदहवीं विधान सभा के दूसरे सत्र का सातवां दिवस [संख्या : 5

गुरुवार,

17 जुलाई, 2014

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: नमस्कार, किरोड़ी लालजी। आज किरोड़ी लालजी पहला सवाल है, इसलिए इनको पहले नमस्कार। प्रश्नकाल। डा. किरोड़ी लाल।

जनजाति समुदाय की मांगों की समीक्षा हेतु गठित समिति

47. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2011 में विभागीय आज्ञा क्रमांक प.6 (14)प्र.सु./अनु-3/2011 के द्वारा जनजाति समुदाय की 42 सूत्रीय मांगों की समीक्षा, क्रियान्वयन एवं पालना सुनिश्चित करने की दृष्टि से सरकार ने एक समिति का गठन किया है? यदि हां, तो समिति के गठन की प्रति एवं 42 सूत्री मांगें कौन-कौनसी थीं तथा उन पर सरकार द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन के पटल पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त 42 सूत्रीय मांगों में से एक मांग कोटड़ा में भूख से मरे 33 लोगों को एक-एक लाख रुपये के मुफ्त आवास का निर्माण, मुफ्त अनाज, आदि की घोषणा सरकार ने की थी? यदि हां, तो उक्त परिवारों को क्या-क्या सहायता दी गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 6(14)प्र.सु/अनु-3/2011 दिनांक 7 मई, 2014 के आदेश द्वारा जनजाति समुदाय के हितों के लिये गठित उक्त समिति को समाप्त किये जाने के क्या कारण हैं?

जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री (श्री नन्दलाल मीणा) : (1) जी हां। सरकार ने संदर्भित आज्ञा से एक समिति का गठन किया है। समिति गठन आदेश परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। 42 सूत्री मांगों की प्रति परिशिष्ट-ब पर

(श्री नन्दलाल मीणा)

संलग्न है। विभाग द्वारा इन मांगों पर की गयी कार्यवाही की अनुपालना रिपोर्ट परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(2) ऐसी कोई घोषणा राज्य सरकार द्वारा नहीं की गयी है। 'भूख से हुई मौत' नामक शीर्षक से कोटड़ा के झेर गांव में हुई आदिवासी की मृत्यु के सम्बन्ध में दिनांक 12.6.2010 को 'दैनिक भास्कर' समाचार पत्र में प्रकाशित समाचार के क्रम में जिला कलक्टर, उदयपुर द्वारा की गई जांच रिपोर्ट की प्रति उत्तर के साथ परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(3) वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अधिकांशत: बिन्दुओं की क्रियान्विति हो जाने के उपरान्त समिति की उपादेयता नगण्य रहने से सक्षम स्तर पर गठित समिति को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय मंत्री मेरे बड़े भाई हैं। आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा और इनकी भी कृपा चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: बड़े भाई के प्रति सहानुभूति रखिये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बड़े भाई की सहानुभूति मेरे प्रति चाहिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कोई किसी का भाई नहीं है इस मंच पर तो।

श्री अध्यक्ष: कोई बात नहीं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप हमारे दुश्मन नहीं हैं, आप हमारे मित्र हैं।

अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के खण्ड 3 में मंत्रीजी ने जवाब दिया है कि वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए अधिकांश बिन्दुओं की क्रियान्विति हो जाने के उपरान्त समिति की उपादेयता नगण्य रह गयी है, इसलिए समिति की आवश्यकता नहीं है। मंत्रीजी उस ट्राइबल एरिया से आते हैं, उनको मेरे से बहुत ज्यादा जानकारी है। मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, जो 42 सूत्री मांगें थीं, उनमें कुछ मांग गिनाऊंगा; ज्यादा तो बहुत लम्बी हो जायेगी,

(डा. किरोड़ी लाल)

अध्यक्षजी भी अलाउ नहीं करेंगे; जनजाति उपयोजना क्षेत्र का दायरा बढ़ाया जाये, यह मांग में है, जिसमें आबू, पिण्डवाड़ा, आपके प्रतापगढ़ जिले का भी कुछ एरिया है, क्या यह बढ़ा दिया गया?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): सब आपने घूमा हुआ है, देखा हुआ है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): क्या यह बढ़ा दिया गया? मैं मंत्रीजी से पूछ रहा हूं। क्योंकि उपादेयता नहीं करे, उपादेयता नहीं है इसकी।

दूसरा, मैंने इसमें मांग की है, एस.सी., एस.टी. का एक विशेष भर्ती अभियान चलाकर बैकलाग को भरा जाये। यह भी इस मांग पत्र में है। माही, सोम, कमला, अम्बा, कडाना बैक वाटर एवं अन्य बड़े बांधों में मत्स्य पालन एवं आखेट का ठेका जयसमंद की भांति स्थानीय आदिवासियों को दिया जाये और माइनर मिनरल्स का शत-प्रतिशत अधिकार उस क्षेत्र में जनजातियों को दिया जाय। आदिवासियों की खानों पर गैर-आदिवासियों का कब्जा है, वह आदिवासियों को मिले। वन भूमि पर आदिवासियों के कब्जे हैं, उनको खातेदारी राइट्स मिलें और वन पट्टे मिलें और फोरेस्ट प्रोड्यूस जो वहां होता है, उसका संग्रहण और निर्गमन स्थान तक ले जाने की परमिशन भी उसी आदिवासी को मिले। राशन की जो दुकानें हैं, शत-प्रतिशत नहीं, तो आबादी के हिसाब से उस इलाके के आदिवासियों को मिलनी चाहिये।

इस मांग पत्र में शहर क्षेत्र, जो उदयपुर है, अध्यक्षजी, आप तो जानते हैं, आते-जाते रहे हैं, वहां पर जितनी भी आदिवासियों की जमीनें हैं, चारों तरफ शहर के, बेशकीमती, उन जमीन के फर्जी दस्तख्त कराकर, 90-बी कराकर, आदिवासियों की जमीनों पर लोगों ने कब्जे कर रखे हैं। फिर वहां एन जी ओ इतने आ गये, अध्यक्षजी, देश-विदेश का जितना भी पैसा आदिवासियों के उत्थान के लिये आया है, वह सब एन जी ओ उस पैसे को डकार गये।

तो मैंने कहा, एक तो सी.बी.आई. जांच; मैंने इसमें कहा है, इसमें श्वेत पत्र जारी करो; मैंने इसमें कहा है कि कथोड़िया परिवार की तरह पूरे आदिवासी इलाके, जो भुखमरी के कगार पर हैं, उनको ए.ए.वाई. में चयनित किया जाये।

मैं मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा, ये सभी मांगें पूरी हो गयी हों, तब तो ठीक किया आपने कि वह समिति आपने भंग कर दी, वरना उस समिति को बहाल करके, हर दो-माह में मीटिंग होती थी और उसमें इन मामलों को लेकर प्रोग्रेस रिपोर्ट पूछते थे, उसको क्या आप रिवोक करोगे?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय भूतपूर्व सांसद महोदय, इन्होंने ट्राइबल सब-प्लान एरिये का दौरा किया और समस्याओं के बारे में ज्ञापन दिया था। ज्ञापन में तत्कालीन राज्य सरकार ने एक कमेटी का गठन किया, जिनके नाम मैं आपके सम्मुख रखना चाहूंता हूं, जितेन्द्र सिंह, ऊर्जा मंत्री; श्रीमती बीना काक, पर्यटन मंत्री; जनजाति परामर्शदात्री समिति के सदस्य में से नामित सदस्य; प्रमुख शासन सचिव, आयोजना विभाग; प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति; सम्भागीय आयुक्त; एवं आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग थे। इस समिति की नियमित बैठकें दो माह में होना निर्धारित किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि न तो इस कमेटी का गठन करने वाले यहां के नेता मुख्य मंत्री हैं; जितेन्द्र सिंहजी, बीना काक, श्री अर्जुन लाल बामणिया, ये सब इस सदन के सदस्य नहीं हैं और माननीय सदस्य, जो शिकायतकर्ता हैं, तत्कालीन समय में लोक सभा के सदस्य थे, जो आज लोक सभा के सदस्य नहीं हैं। ऐसी स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यह केवल मात्र इसीलिए कि कोई सदस्य जीतकर नहीं आया, या मैं सदस्य नहीं हूं, यह कोई जवाब है क्या? मैंने जो समस्या गिनाई है, उनके बारे में कमेटी ने क्या किया? यह कह रहे हैं, इसका क्रियान्वयन हो गया; क्रियान्वयन क्या हुआ, यह तो बतायें।

श्री अध्यक्ष: जवाब तो वही होगा जो माननीय मंत्रीजी देंगे। आप अपने सुझाव दे सकते हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): इसी तरह से जो 42-सूत्री प्रतिवेदन के बारे में लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रश्न किया है, उस पर मेरा यह निवेदन है कि जब समिति ही एग्जिस्टिंग नहीं है, ऐसी स्थिति में समिति का...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): यही तो पूछ रहा हूं, आपने भंग क्यों की? जब इन समस्याओं का क्रियान्वयन ही नहीं हुआ, तो आपने भंग क्यों की?

श्री अध्यक्ष: जवाब आ रहा है। जवाब आ रहा है, आप बाधा मत डालिये। आप बाधा मत डालिये, जवाब आ रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं जवाब दे रहा

(श्री नन्दलाल मीणा)

हूं। अध्यक्ष महोदय, समिति के सम्मुख जो मामले विचाराधीन थे, उसके हिसाब से समिति की तीन बैठकें हुई और बैठकों के बाद 37 बिन्दुओं पर की गयी कार्यवाही पर संतोष व्यक्त किया। 42 में से 37 बिन्दु ऐसे थे, जो इस समिति ने संतोष व्यक्त किया कि यह कोई खास नहीं हैं, इसका समाधान किया गया। शेष 7 बिन्दुओं पर समिति ने आवश्यक निर्देश दिये हैं।

राजस्थान विधान सभा के नये चुनावों के बाद, जैसा कि हर नई सरकार जो-जो भी समितियां गठित करती है अपने कार्यकाल में, समय समाप्त हो जाने के बाद उनको भंग कर दिया जाता है। तो गठित नई सरकार की समिति का गठन का निर्णय लिया गया है।

समिति के समक्ष रखे गये समस्त 42 बिन्दुओं पर व्यापक विचार-विमर्श कर सम्बन्धित विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की समीक्षा के उपरान्त बिन्दुओं के निस्तारण हेतु निर्देश दिये गये। इस प्रकार, समिति ने अपना कार्य लगभग पूर्ण किया है। समिति का कोई निश्चित समय निर्धारित नहीं किया गया था।

साथ ही, समिति के संयोजक एवं जन-प्रतिनिधि के रूप में सम्मिलित सदस्यों के पदभार समाप्त हो जाने के कारण समिति प्रासंगिक नहीं रह गयी है। अत: दिनांक 7-5-2014 ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं तो, बड़े भाई, यह पूछ रहा हूं कि मैंने जो गिनाई हैं, साहब, मैंने 42 नहीं गिनाई हैं...

श्री अध्यक्ष: पूरा जवाब आने दीजिए।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): और, अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो ज्ञापन दिया है और जो अख़बार में कोटड़ा के झेई गांव के बारे में छपा है, इसमें मुख्य मंत्रीजी ने जो शब्द कहे हैं वे आपके सामने निवेदन करना चाहता हूं, 'भूख से कोई नहीं मरा।'

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कौन से मुख्य मंत्री ने कहा, यह भी बता दो।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): बता रहा हूं। तत्कालीन मुख्य मंत्री ने।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप भी उसमें ठप्पा ठोक रहे हो।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): हां, तत्कालीन

(श्री नन्दलाल मीणा)

मुख्य मंत्री। ठप्पा नहीं ठोक रहा हूं, मैं यह कह रहा हूं कि किस तरह से आपने और मुख्य मंत्री ने मैनिपुलेशन कर के, यह शब्द यूज कर रहा हूं, मैनिपुलेशन कर के कुछ गरीब आदिवासी समाज को, आज सवाई माधोपुर का आदिवासी भूख से नहीं मर रहा, अलवर का नहीं मर रहा, भरतपुर का नहीं मर रहा, दौसा का नहीं मर रहा।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप करौली में कह कर आये हो। इतना जल्दी मत मुकरो आप।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): जनता ने वोट दिया है, इसलिए आये हैं।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने कहा, हम को चाहे अनुसूचित जनजाति, यह हो, आदिवासी इलाके का हो।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): ऐतिहासिक तथ्य बतायें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): शोषण करने वाले सवर्ण...(व्यवधान) नहीं, नहीं, यह गलत तथ्य...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैंने ऐतिहासिक तथ्य बताये थे।

अध्यक्ष महोदय, वह कथन जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इनके एतराज पर उठाये थे, उन्होंने कहा है, दौसा में कहा, इनके वहां, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश में भूख से कोई मौत नहीं हुई है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप इसको मानते हैं?

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): नहीं, मैं नहीं मानता हूं। यह घटना भी मेरे टाइम की नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप डिस्टर्ब मत कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप यह अखबार की कटिंग... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया बार-बार डिस्टर्ब मत कीजिए हर सवाल पर। आप विराजिये। पूरा जवाब आने दीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप फिर अखबार की इनकी कटिंग को आथैंटिकेट क्यों मान रहे हों?

श्री अध्यक्ष: पूरा जवाब आने दीजिए, उसके बाद आपका प्रश्न ... (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अखबार की कटिंग है। अध्यक्षजी, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने जांच की है। मैं मांग करूंगा, रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन की कटिंग सदन में रखो न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह अखबार की बात नहीं है, उनका स्टेटमेंट है।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): नहीं, अखबार से दे रहे हैं, अखबार से बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप स्थान ग्रहण कीजिए। जवाब आ रहा है।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): मैं वे शब्द कोट कर रहा हूं, जो तत्कालीन मुख्य मंत्री ने आपके एतराज के बाद खण्डन किया था। ''कोटड़ा में भूख से 26 मौतों के मामले में भास्कर द्वारा छपे हुए सवाल पर गहलोत ने कहा कि अब भूख से कोई नहीं मरता। उन्होंने कहा कि सब को गांव में काम मिल रहा है, महानरेगा योजना चल रही है। डाक्टर किरोड़ी लालजी उदयपुर सम्भाग में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए यह कृत्य कर रहे हैं।''

श्री अध्यक्ष: जवाब आ गया अब।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्षजी, आप मेरी बात सुनो।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपकी भी सुनेंगे। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: हो गया। हो गया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ठहरो, हो गया, 'हो गया' क्या होता है?

श्री अध्यक्ष: अब तो जवाब आ गया।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आप बेशक हंसें और ये बेशक ताली बजाएं ...(व्यवधान) क्या पिट गया? यह जवाब है? इसको जवाब कहते हैं? बहुत बढ़िया। आपको भी मंत्री बना देंगे।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं सवाल करूंगा। स्थान क्यों ग्रहण करूं?

श्री अध्यक्ष: हां, तो एक दूसरा सवाल, पूरक प्रश्न और कर लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): या आप संतुष्ट हों इससे?

श्री अध्यक्ष: मुझे तो जो आप सब बोलते हैं, उससे संतुष्ट होना पड़ता है। मैं चेयर पर बैठा हूं। मैं किस को गलत कहूं, किस को सही कहूं?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, सरकार का एक पत्र है 15.04.2011 का। (व्यवधान) तो क्या करें? मेरे को संतुष्ट तो होना पड़ेगा न, भाई। "कोटड़ा तहसील क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कराया जाएगा ताकि ज्ञात हो सके कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे आदिवासी परिवारों में कहां आकस्मिक, असामयिक मृत्यु हुई हैं तथा ऐसे परिवारों के समग्र उत्थान के लिए राज्य सरकार एक पैकेज घोषित करेगी जिसमें पक्का घर, इन्दिरा आवास के पैटर्न पर, नि:शुल्क चिकित्सा, शिक्षा नि:शुल्क, नि:शुल्क अनाज, बस यात्रा, बी.पी.एल. के समकक्ष लाभ, इत्यादि सम्मिलित होंगे। इसी पैकेज में राज्य सरकार इन परिवारों का सर्वेक्षण दो माह में सम्पादित कर यथोचित आर्थिक सहायता और सम्बल प्रदान करेगी। 33 आदिवासियों को चिह्नित करेगी जिनकी कुपोषण के कारण या भूख के कारण मौत हुई है।"

यह सरकार का पत्र है और इसकी जांच दी है चीफ सेक्रेटरी ने राजस्व मण्डल के अध्यक्ष को। आप बताएं कि राजस्व मण्डल के अध्यक्ष की क्या रिपोर्ट है?

श्री अध्यक्ष: अब स्थान ग्रहण कीजिए, वे बता रहे हैं।

श्री नन्दलाल मीणा (जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, समिति द्वारा जो तीन बार मीटिंग कर के जो निर्णय लिये, उसके हिसाब से तो इनको साफ कह दिया कि यह सब कोई प्रभावशाली नहीं है। फिर भी मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करता हूं, चूंकि आपको अब थोड़ा दर्द कम हुआ है आदिवासियों के बारे में, अब और ज्यादा होना चाहिए, मैं आपके साथ चल कर, वापस इस कोटड़ा तहसील में उन गांवों में चलना चाहता हूं जहां के बारे में आपने यह कहा कि 30 मौतें हो गयीं, भूख से यह हो गया। यह हुआ, न वह हुआ।

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट। श्री निर्मल कुमावत।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): और फिर अगर मौत पायी गयी तो आर्थिक पैकेज दोगे न?

श्री अध्यक्ष: 15 मिनट ले लिये एक सवाल ने। श्री निर्मल कुमावत।

फुलेरा के गांवों को बीसलपुर परियोजना से जोड़े जाने की योजना

48. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के समस्त ग्रामों में बीसलपुर परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु जुलाई, 2013 से कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु कितनी राशि का प्रावधान किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था और वर्तमान में कितना कार्य पूर्ण हो चुका है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त परियोजना से किन-किन गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो रूलिंग दी है **...** (व्यवधान) हमने महामहिम को ज्ञापन दे रखा है, हमने ज्ञापन दे रखा है और मंत्री संविधान के तहत नहीं रह सकते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): यह अब रोज-रोज क्या खड़े हो जाते हैं? यह कोई बात हुई?

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, विपक्ष के लोग मंत्री नहीं मानते, इससे मंत्री...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आसन नियमों से चलता है। यह आपने हमें एक किताब दी है, यह आसन इससे चलता है। आसन सर्वोपरि है। आसन की व्यवस्था को ये चुनौती नहीं दे सकते। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): उस संविधान के प्रति मंत्री **...** (व्यवधान) इसमें हमें न्याय की उम्मीद है। हमें आप न्याय दो। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सांवर लालजी मंत्री हैं और मंत्री रहेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): राज्य सरकार के मंत्री हैं, जवाब यही देंगे। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, सांवर लालजी जाट मंत्री हैं और अब ये आगे भी रहेंगे। (व्यवधान) प्रतिपक्ष के मानने और नहीं मानने से कोई भी व्यक्ति हटता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री (श्री सांवर लाल): (1) जी हां। बीसलपुर-दूदू बृहद् पेयजल परियोजना के स्वीकृत प्रथम चरण में विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 151 ग्रामों में से 45 गांवों को मुख्य पाइपलाइन (टी.एम.-प्रथम) के नरैना आफटेक से लाभान्वित करने के कार्यों हेतु राशि रुपये 52.46 करोड़ तथा शेष 106 गांवों को सांभर पम्पिंग स्टेशन से लाभान्वित करने के कार्यों हेतु राशि रुपये 226.95 करोड़ रुपये, कुल 279.41 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। आप भी स्थान ग्रहण करें।

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय सदस्य पहली बार जीत कर आये हैं विधान सभा के अन्दर, इनको पता नहीं कानून-कायदे का। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष ने जो व्यवस्था दी है, उस व्यवस्था को आपने माना। आपके मानने के बाद में मुख्य मंत्री महोदया का भाषण हुआ यहां पर। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): हर बार यह फालतू की बातें लेकर सदन को गुमराह करने की आवश्यकता नहीं है...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेताजी ने प्रश्न उठाया है कि वे इनको मंत्री नहीं मानते...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री अध्यक्ष: ...और आसन से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार यह व्यवस्था दी जा चुकी है। ये प्रामाणिकता से मंत्री हैं और इनको आपको सुनना पड़ेगा।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): (2) उक्त परियोजना के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 45 ग्रामों हेतु 45 प्रतिशत तथा 106 ग्रामों हेतु 13 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है। 45 ग्रामों को दिनांक 12.11.2014 तक तथा 106 गांवों को दिनांक 24.01.2016 तक लाभान्वित किया जाना है।

आपके मानने से नहीं होगा ...(व्यवधान) आप कह दोगे कल, सरकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): (3) उक्त परियोजना से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के 151 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है। ग्रामों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। (व्यवधान)

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस रूलिंग का आदर करेंगे, प्रतिपक्ष के नेता होने के नाते। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): 17.11.14 तक शेष रहे गांवों को ...(व्यवधान) थर्ड फेज के ...(व्यवधान) 152 गांवों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है ...(व्यवधान) गांवों की सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है। (व्यवधान)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 11.22 बजे 11.32 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

(11.32 बजे)

पुन: समवेत् होने पर

(श्री कैलाश चन्द्र मेघवाल, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री अध्यक्ष: मैं सभी विधायकगण से निवेदन करता हूं कि इस विधान सभा में एक बार अध्यक्ष की रूलिंग हो जाये, उस रूलिंग को मानना प्रत्येक का कर्तव्य है। मुझे आज अचानक रूप से प्रतिपक्ष के नेता ने कहा कि हम इनको मंत्री नहीं मानते, जबकि शुरू से हम इनको मंत्री मानते आए हैं। सरकार अस्तित्व में है और एक नान-इश्यू को इश्यू बनाकर प्रतिपक्ष के नेता और सदस्य आज अनावश्यक रूप से एक कंट्रोवर्सी पैदा करके इस सदन की कार्यवाही में बाधा डाल रहे हैं। मैं फिर से उनसे निवेदन करूंगा कि आपने अपना आक्रोश व्यक्त कर दिया, अब सदन को शांति से चलने दीजिये।

श्री सांवरलाल जाट।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, हमारा आक्रोश यह नहीं है, हमारा संविधान के प्रति विश्वास है, संविधान के अनुसार ये आज की तारीख में मंत्री नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि वे पूरक सवाल करें, पूरक।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) यदि इतना ही है तो इनको दिल्ली में मंत्री बनाओ न।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आपकी तो संविधान के प्रति आस्था ही नहीं है। (व्यवधान) सांवर लालजी आज की तारीख में भी मंत्री हैं, पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि यह जो जवाब दिया, उसके खण्ड एक में कार्य धीमा चल रहा है। उसमें विभाग की कोई लापरवाही है या कम्पनी जो निर्माण कर रही है, उसकी लापरवाही है, इसका मुझे जवाब दीजिये।

दूसरा, रेनवाल कस्बा मेरे विधान सभा क्षेत्र का सबसे बड़ा कस्बा है। उसको आप तत्काल प्रभाव से बीसलपुर से जोड़ने की मंशा रखते हैं या नहीं रखते हैं?

वर्तमान में तीन कस्बे फुलेरा विधान सभा क्षेत्र के, सांभर, नरैना और फुलेरा जुड़े हुए हैं बीसलपुर से। उनका पानी आप बढ़ाना चाहते हैं या नहीं?

इन तीनों का मैं जवाब चाहता हूं।

(प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में नरैना, रेनवाल और सांभर तीन कस्बे हैं। मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके यहां नरैना के अन्दर पानी की मात्रा को बढ़ावा दूंगा। इसके अलावा, रेनवाल और दूसरे जो गांव हैं, उनको भी यथा शीघ्र, जल्दी से जल्दी, फुलेरा में भी पानी कम है, खारा है, इसलिए वहां पर भी बरसात होने के बाद, इस बीसलपुर का पानी मैं बढ़वा कर पर्याप्त पानी दिलवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): धन्यवाद, मंत्री महोदय। मैं मंत्रीजी से दो बात और पूछना चाहूंगा, सांभर में आपने जो एक्स ईएन कार्यालय खोला है उसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरा स्टाफ वहां नियुक्त है, वह सुचारु रूप से काम कर रहा है या नहीं, इसकी भी आप जानकारी लें। उसके लिए सरकार क्या मंशा रखती है? आप क्या मंशा रखते हैं? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): टैस्टिंग वाली जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को मैं सही करवाऊंगा। किसी अधिकारी पर जिम्मेदारी डालकर, हर महीने में एक बार जो पाइप ले-डाउन हुआ है, उसकी टैस्टिंग करवाकर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करे, इस प्रकार की व्यवस्था करवाऊंगा, जिससे डिले खतम हो जाये।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): बहुत-बहुत धन्यवाद, मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव। (व्यवधान) श्री राजेन्द्र सिंह यादव। (व्यवधान) इधर से कोई आप बोलें। श्री राजेन्द्र सिंह यादव अगला सवाल करेंगे। श्री राजेन्द्र सिंह यादव। (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष को हटाने की बात चल रही है। कांग्रेस में नेता प्रतिपक्ष को हटाने की बात चल रही है। (व्यवधान)

प्रश्न संख्या-49

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

(अनुपस्थितः कृपया आगे देखें)

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): इसलिए ये यहां जोरदार परफोर्मेंस दिखाना चाहते हैं। ये अपनी परफोर्मेंस दिखाना चाहते हैं। अपने आका को यह दिखाना चाहते हैं कि मैं मजबूत हूं और मैं विरोध दिखा सकता हूं। इनको हटाने की चर्चा चल रही है, इसलिए ये ऐसा कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री वासुदेव देवनानी। श्री वासुदेव देवनानी। अपना प्रश्न पुकारिये।

अजमेर शहर में बी पी एल श्रेणी के उपभोक्ताओं को जारी विद्युत कनेक्शन

50. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में अजमेर शहर में कितने उपभोक्ताओं को बी.पी.एल. श्रेणी में विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं? उपखण्डवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जिन उपभोक्ताओं के विद्युत कनेक्शन पूर्व के हैं तथा सरकार की योजनानुसार बी.पी.एल. श्रेणी में चयन बाद में हुआ है, ऐसे उपभोक्ताओं के कनेक्शन भी बी.पी.एल. श्रेणी में परिवर्तित करने का विचार

(श्री वासुदेव देवनानी)

रखती है? यदि हां, तो कब तक व किस प्रक्रिया के द्वारा व नहीं, तो क्यों? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

ऊर्जा मंत्री (श्री गजेन्द्रसिंह): (1) वर्तमान में अजमेर शहर में 3,567 उपभोक्ताओं को बी.पी.एल. श्रेणी में विद्युत कनेक्शन जारी किये गये हैं, जिनका उपखण्ड वार विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) उपभोक्ता द्वारा बी.पी.एल. कार्ड सम्बन्धित सहायक अभियंता कार्यालय में प्रस्तुत करने पर उपभोक्ता को बी.पी.एल. श्रेणी में परिवर्तन कर दिया जाता है। विद्युत उपभोक्ता का नाम तथा बी.पी.एल. कार्डधारी का नाम एक रूप होने पर ही उक्त सुविधा दी जाती है। नवीन बी.पी.एल. कार्ड धारी द्वारा बी.पी.एल. कार्ड प्रस्तुत करने पर उक्त सुविधा प्रदान की जाती है।

(विवरण के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): राजेन्द्रजी का नम्बर कहां गया?

श्री अध्यक्ष: मैंने आवाज दी थी, बोले नहीं। (व्यवधान) मैंने आवाज लगाई थी और आवाज लगाने के बाद रेस्पोंड नहीं करते तो मैं अगला प्रश्न नहीं लूंगा? कहां थे ये? मैंने आवाज लगाई थी। आप व्यवधान कर रहे थे। (व्यवधान) मैंने आवाज लगाई थी, तीन बार बोला था मैं। यह नहीं हो सकता कि आवाज लगाने के बाद आप बोलो नहीं और अगला प्रश्न लूं तो फिर एतराज करो। यह नहीं हो सकता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्षजी, बोला है इन्होंने।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था के खिलाफ कर रहे हैं।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्षजी, बोला है।

श्री अध्यक्ष: ले लेंगे। राजेन्द्रजी यादव का भी ले लेंगे। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर नगर निगम में, जानकारी के अनुसार, शहरी क्षेत्र में लगभग 25 हजार बी पी एल हैं, फिर भी राहत केवल 3,567 लोगों को दी जा रही है। आखिर क्या कारण है कि बाकी बी.पी.एल. इससे महरूम हैं? क्या सरकार शेष को सुविधा देने का विचार रखती है?

(श्री वासुदेव देवनानी)

नम्बर दो, कुछ बी.पी.एल. परिवारों ने मकान पहले बना लिये और कनेक्शन भी पहले ले लिये लेकिन बी.पी.एल. सूची में उनका नाम बाद में जुड़ा। उनको आज तक लाभ नहीं मिल रहा है। क्या सरकार उनको लाभांवित करने का कोई अभियान चलायेगी?

नम्बर तीन, अजमेर के 8 उपखण्डों में अलग-अलग नियम लागू किए जा रहे हैं। कोई तो इनके नियम का पालन करता है और कोई उपखण्ड नियम पालन नहीं कर रहा है। क्या सरकार सभी उपखण्डों में समान रूप से इसका पालन करवायेगी?

नम्बर चार...

श्री अध्यक्ष: इतने पूरक प्रश्न पूछ रहे हो। इनका जवाब आ जाने दीजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): नम्बर चार, आखिरी, कनेक्टिंग हैं सब, लुहार और इनके पट्टे नहीं हैं लेकिन इनके पास रसीदें हैं। आपका डिपार्टमेंट उनको सुविधा नहीं दे रहा है। क्या सरकार उनको सुविधा देने का विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर शहर में वर्तमान में कुल बी.पी.एल. कंज्यूमर्स हैं 20,500 और टोटल जो कंवर्ट किये गये हैं नोर्मल कनेक्शन से बी.पी.एल. में, जो नोर्मल कंज्यूमर थे, जिन्होंने बी.पी.एल. कार्ड प्राप्त किये, वह 1,090 के करीब इनको कंवर्ट किया गया, इनको बी.पी.एल. श्रेणी में लिया गया। टोटल जो बी.पी.एल. कनेक्शन हैं, वह आपने, अभी जो बताया कि कोई भी उपभोक्ता जो है, बी.पी.एल. का कार्ड लेकर आता है और वह सामान्य श्रेणी में है, उसको तुरन्त बी.पी.एल. श्रेणी में कंवर्ट कर दिया जायेगा और 85 पैसे का पहले 50 यूनिट का जो टैरिफ है, वह लागू हो जाएगा।

दूसरा माननीय विधायक जो प्रश्न उठाया था, हमारे जो 8 ए ईएन सब-डिविजन हैं, मैं इसके अन्दर पूरी जांच करूंगा कि यह अनियमितता नहीं होनी चाहिए, एक डिविजन के अन्दर एक मापदण्ड यूज कर दें और दूसरे के अन्दर दूसरा कर दें।

तीसरी चीज, डिपार्टमेंट यह आइडेंटिफाई नहीं करता है कि पूरे शहर में

(श्री गजेन्द्रसिंह)

टोटल बी पी एल कौन-कौन हैं। यदि आपको कुछ समस्या आती है तो हम एक एडवर्टाइजमेंट निकाल सकते हैं, टाइम टू टाइम, कि जितने भी बी पी एल परिवार हैं जो नोर्मल श्रेणी में हैं और अब बी पी एल बने हैं, उनको कनेक्शन तुरन्त दिया जाएगा। उनके अन्दर अवेयरनेस लायी जाएगी। इसके अन्दर आगे कोई प्रोब्लम नहीं आएगी।

आपने अलग-अलग सब-डिविजन का बताया, कोई अनियमितता है, आप मुझे पर्सनली बताइए कि क्या अनियमितता है। उन सबको, they have to operate under one rule and one standard.

श्री अध्यक्ष: आपके चार हो गये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न और है।

श्री अध्यक्ष: एक और।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैंने एक प्रश्न पूछा था कि कुछ परिवारों ने जो मकान पहले बना लिये थे, वे कार्ड ले जाने के बाद भी उनको लाभान्वित नहीं किया जा रहा है। मैंने लुहारों का उठाया था, उनके पास मकान की रसीद तो है लेकिन पट्टे निगम ने या ए डी एम ने नहीं दिये हैं। उनको यह सुविधा नहीं मिल रही है। क्या सरकार इनको देने का विचार रखती है?

इस योजना के लिए मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि इस योजना का सरलीकरण भी करें और इस योजना का प्रचार-प्रसार भी करें क्योंकि आज कई बी पी एल इसका लाभ उठाना चाहते हैं। आपके स्टेटमेंट से यह 3,500 को मिल रहा है और लगभग 20,900 हैं। तो लगभग यह एक तरह से 15 परसेंट लोगों को ही मिल रहा है। बाकी लोगों को भी लाभ मिले। साथ में, क्या सरकार कच्ची बस्तियों में रहने वालों को यह सुविधा देने का विचार रखती है?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, चाहे कच्ची बस्ती हो, चाहे पक्की बस्ती हो, चाहे वह कोई भी जाति का हो, the main issue involved is that he must have a BPL card. यह एक ही मापदण्ड है। यदि कोई आपके पेंडिंग कनेक्शन के कंज्यूमर हैं जो कहते हैं कि हमारे पास बी पी एल कार्ड है, हमें कनेक्शन नहीं दिया जा रहा है या उसको कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, आप हमें बताइए, हम उनको तुरन्त कनेक्शन दिला देंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): उनको सुविधा नहीं मिल रही है।

(श्री वासुदेव देवनानी)

बी पी एल कार्ड तो है, कनेक्शन भी है, उनको जो बिल में राहत मिलनी चाहिए, वह नहीं मिल रही है।

श्री अध्यक्ष: राजेन्द्र सिंहजी का प्रश्न है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मैं इसी से सम्बन्धित पूछ रहा हूं, क्योंकि यह डिफिकल्टी आ रही है। यह पी यू सी में एग्जामिन भी हमने बार-बार किया है। मापदण्ड के लिए जो परिपत्र जारी कर रहे हैं, उन तीनों में डिफरेंस आ रहा है और उसको इम्प्लीमेंट करने की एजेंसी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वह उसको अलग मान रहा है। डिफरेंस इसमें इसलिए आ रहा है। ट्राइबल सब-प्लान एरिया में भी आपके यही हो रहा है। टी एस पी एरिया में माडा एरिया को आपने इंक्लूड करके परिपत्र जारी नहीं किया है, जबकि केन्द्र सरकार से वह हो रहा है। आप पैसा यूज कर रहे हों टी एस पी का, यदि नहीं यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके खुद के सर्कुलर एग्जामिन करवा लें। अपने आप व्यवस्था ठीक हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्री महोदय।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्न है, we are talking about the BPL in cities. ग्रामीण के अन्दर है। सिटी के अन्दर तो तुरन्त राज्य सरकार उनको टैरिफ का फायदा देकर 2,500 रुपये में कनेक्शन दे रही है। माननीय सदस्य जो फरमा रहे हैं, राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र का मापदण्ड अलग है। टैरिफ सेम है। उसका पैसा राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना से आता है। यदि कोई ऐसे एरियाज हैं, आप मुझे हाइलाइट करिए, आप मुझे बताइए we will take immediate action. और आपके जो भी कनेक्शन रह गये हैं, माननीय अजमेर से पधारने वाले सदस्य, आप बताइए, it will be...(interruption)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र यादव। (व्यवधान) इनका सवाल रह जाएगा। श्री राजेन्द्र यादव।

डेयरी प्लांटों में मिलावटी दूध के सैम्पलों की जांच

49. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विगत तीन वर्षों में प्रदेश के सरस डेयरी प्लांटों पर दूध में मिलावट किये जाने के तथ्य उजागर हुए हैं? यदि हां, तो किस-किस डेयरी प्लांट में? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

(2) गत तीन वर्षों में सरस डेयरी के किस-किस प्लांट से दूध के कितने सैम्पल लिये गये एवं उनमें से कितने सैम्पलों में मिलावट पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) मिलावटी दूध किन-किन दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा आपूर्ति किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार प्रदेश की आम जनता को मिलावटी दूध से होने वाले नुकसान से बचाव हेतु पुख्ता व्यवस्था सुनिश्चित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या तथा कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

डेयरी मंत्री (श्री प्रभू लाल सैनी): (1) जी नहीं। मात्र सवाई माधोपुर डेयरी प्लांट से लिये गये दूध के दो सैम्पलों में फैट एवं एस एन एफ निर्धारित मानक स्तर से कम पाया गया।

(2) गत तीन वर्षों में सरस डेयरी प्लांटों से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा लिये गये दूध के सैम्पलों का विवरण एवं उनमें से जिन सैम्पलों में मिलावट पाई गई, का विवरण प्रदर्श-क पर संलग्न है।

(3) अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, भरतपुर, बीकानेर, चित्तौड़गढ़, चूरू, जयपुर, झालावाड़, श्रीगंगानगर, कोटा, सीकर, टोंक एवं उदयपुर दुग्ध संघों से सम्बद्ध दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों द्वारा मिलावटी दूध की आपूर्ति की गई, जिसे दुग्ध संघों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। विवरण प्रदर्श-ख पर संलग्न है।

(4) जी हां। इस सम्बन्ध में पूर्व से ही डेयरी फेडरेशन एवं इससे सम्बद्ध जिला दुग्ध संघों में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जो विविध अत्याधुनिक परीक्षक उपकरणों से जांच द्वारा दुग्ध की गुणवत्ता सुनिश्चित करती है। जिला दुग्ध संघों के डेयरी प्लांटों पर मिलावटी दूध आने पर तुरन्त ही ऐसे दूध को नष्ट कर दिया जाता है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो डेयरी का बता रहे हैं, सबसे पहले मंत्री महोदय से यह पूछूंगा, इन्होंने कहा है कि खाली सवाई माधोपुर, अलवर में भी इस तरह का पाया गया है। डेयरी

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

प्रबंधन ने इसको माना है। दूसरा, पूरे 33 जिलों में से 14 जिलों में इस तरह की घटनाएं सारे संघों से आयी हैं। उनके लिए कठोर कानून बनाकर करना चाहिए। खाली डेयरी के दूध लेकर आते हैं। जितने भी सहकारी संघ हैं, उनको खाली चेतावनी देकर छोड़ा जाता है, जिससे उनका मनोबल बढ़ता है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसी कि माननीय सदस्य ने चिन्ता व्यक्त की है, वास्तव में यह चिन्ता वाजिब है। राजस्थान में 21 दुग्ध संघ बने हुए हैं। उनमें से समय-समय पर चिकित्सा विभाग द्वारा फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट, 2006 के अन्तर्गत उनके सैम्पल लेने की कार्रवाई चिकित्सा विभाग द्वारा समय-समय पर की जाती है। मैं आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा कि 12,336 के लगभग अभी राजस्थान में रजिस्टर्ड और प्रपोज्ड डेयरी कार्य कर रही हैं। मैं आपको एक निवेदन करना चाहूंगा कि दूध कलेक्ट एक मिल्क सोसाइटी से होता है, पहले प्राथमिक स्तर पर उसकी जांच होती है, उसके बाद दुग्ध संघ पर आता है। वहां पर पहले से एक पोस्ट बना रखी है, उसमें आकर उसकी जांच होती है और यदि इस बीच में वह सब-स्टैण्डर्ड पाया जाता है या उसमें कोई कमी होती है तो उसको स्वीकार नहीं किया जाता है, डेयरी के अन्दर नहीं आता।

यहां का मूल प्रश्न है, आपने जैसा कहा कि तीन वर्षों में सरस डेयरी प्लांटों में, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहूंगा, सिर्फ सवाई माधोपुर डेयरी प्लांट से दो सैम्पल चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा, इंस्पेक्टर्स द्वारा लिये गये थे। उनमें भी जो जांच का परिणाम आया है, उस जांच परिणाम में सिर्फ एस एन एफ और फैट की कमी पायी गयी है। मिलावट का वहां भी नहीं है। फिर भी वे दोनों प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं।

जहां माननीय सदस्य ने चाहा, अलवर के बारे में जानकारी चाही है, मैं निवेदन करना चाहूंगा अलवर में जो सैम्पल प्राप्त हुए, उनमें सबसे ज्यादा 300 से ज्यादा सहकारी सोसाइटीज हैं, उनकी मिलावट की शिकायतें कई बार मिलती रहती हैं। लेकिन हम उनकी जांच करके, उनके ऐसे दूध को, जिसमें मिलावट की मात्रा की पहले से ही हमें जानकारी हो जाती है, हम उसको स्वीकार नहीं करते हैं। एक मामले में अलवर में 21.06.2011 को एक सैम्पल जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिया गया था, उसका जांच परिणाम आया है, उसमें मिलावट नहीं पायी गयी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जो उत्तर आया है, वह मैंने माननीय सदस्य के पास देखा था, कई मामलों में चेतावनी देकर लोगों को छोड़ा गया है। मैं इसे अनुचित मानता हूं। जब आप संतुष्ट हो गये कि मिलावट थी, उसके बाद आपको चेतावनी देने की क्या आवश्यकता थी? आपको ब्लैकलिस्ट करना चाहिए था, आपको क्रिमिनल एक्शन लेना चाहिए था।

मंत्री महोदय, आज सरस एक ब्राण्ड नेम बन गया है और जयपुर और हर एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस दूध का इस्तेमाल करते हैं। (व्यवधान) प्लीज। यहां कांग्रेस-बी जे पी नहीं है। तो आप जहर पिलाओगे क्या? कांग्रेस के राज में पी लिया तो क्या अब भी जहर पिलाओगे क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आसन को सम्बोधित करें।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): इसको कांग्रेस व बी जे पी का प्रश्न मत बनाइए। कृपया इसको मत बनाइए। कुछ चीजें राजनीति से ऊपर सबको सोचनी पड़ेगी। राजनीति से ऊपर होकर आप नहीं सोचेंगे?

आज जयपुर की मैजोरिटी पोपुलेशन में, हम स्वयं सरस का दूध इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत से लोग कह रहे हैं। मेरे कहने का मकसद है कि इसकी गुणवत्ता बनी रहे, इसके लिए आपको कुछ स्ट्रिंजेंट मैजर्स लेने पड़ेंगे। अध्यक्ष महोदय, आपको स्वयं को ध्यान होगा, कुछ समय पहले अखबारों में सरस डेयरी, जयपुर के बारे में बड़ी-बड़ी स्टोरीज आयी थीं। पता नहीं, वे सही थीं या गलत थीं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): मेरा मंत्री महोदय आपसे निवेदन है कि इसको राजनीति से मत जोड़िए, इसमें सुधार होना चाहिए। आप खाली मेडिकल हैल्थ डिपार्टमेंट के भरोसे मत रहिए। आप अपने स्वयं के डेयरी के स्तर पर अपना मेकेनिज्म डवलप करिए कि मिलावट बिलकुल नहीं हो। यही मेरा आपसे निवेदन है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की चिंता व्यक्त की है, मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि सरस का जो हमारा प्रोडक्ट है, विश्वसनीयता और गुणवत्ता ही हमारा मूल आधार है। राष्ट्रीय ही नहीं, अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर भी, चाहे वह सिंगापुर का हो या यू.ए.ई. का हो, हमारे प्रोडक्ट में कहीं भी किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई जाती है, चूंकि हम लोगों ने हर स्टेज पर दूध के निरीक्षण और परीक्षण की हमारी प्रयोगशालाएं स्थापित कर रखी हैं।

(श्री प्रभू लाल सैनी)

जैसा आपने कहा कि आप लोगों ने सिर्फ चेतावनी देने की बात कही है, this is the issue, यह पालिटिकल इश्यू नहीं है, यह एक सार्वजनिक इश्यू है, क्योंकि मिलावट एक सामाजिक अपराध है। यदि मिलावट होती है तो निश्चित रूप से सभी लोगों के लिए वह हानिकारक होती है। इसलिए सरकार ने इसको बहुत गम्भीरता से लिया है और आज भी हम गम्भीरता से लेते हैं। जहां चेतावनी की बात की है, तो सरस डेयरी या हमारी कोई भी को-आपरेटिव सोसाइटीज हैं, उनको किसी व्यक्ति को सज़ा देने या चालान पेश करने के पावर्स नहीं होते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि मेडिकल डिपार्टमेंट, फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट जो बना हुआ है, उसके अन्तर्गत जितने भी सैम्पल होते हैं उनकी जांच होती है, जांच में यदि वे अमानक पाये जाते हैं तो अमानक पाये जाने के बाद न्यायालय में उसका चालान पेश होता है और न्यायालय द्वारा उनको सज़ा देने की व्यवस्था की हुई है।

श्री अध्यक्ष: सपोटरा से आने वाले माननीय विधायक।

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, आपने चूरू की जो भी दूध आपूर्ति करने वाली मिलावटी समितियां थीं, उनको तो आपने हमेशा के लिए बन्द कर दिया, लेकिन भीलवाड़ा, भरतपुर, चित्तौड़ आदि दुग्ध संघों की समितियों जो मिलावट जांचों में आईं, उनको आपने बन्द क्यों नहीं किया?

दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि कोटा और जोधपुर में सैम्पल की जो जांचें हैं, आपने उत्तर में यह दिया है कि जांच रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई हैं, तो किस डेट में ये सैम्पल लिये गये थे? और यदि समय पर जांच रिपोर्ट नहीं आईं तो सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ आप क्या कार्यवाही करेंगे?

तीसरा, इसके साथ छोटा-सा क्वेश्चन यह है कि आपने यह कहा है कि हमारे पास आधुनिक उपकरण हैं, लेबोरेटरीज हैं और उसके बाद भी आपके सैम्पल फेल हो जाते हैं या दूध में मिलावट पाई जाती है। तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मुद्दा, दूध में मिलावट करना और उसको बेचना, यह मानवता के लिए खतरनाक इश्यू है। अभी मंत्री महोदय ने कहा कि हम न्यायालय में भेज देते हैं, तो ऐसा एक्ट लायें जिससे मानव के साथ ऐसा खतरा पैदा नहीं हो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री महोदय।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान

(श्री प्रभू लाल सैनी)

में 12,376 हमारी को-आपरेटिव मिल्क सोसाइटीज हैं, वे रजिस्टर्ड और कुछ प्रपोज्ड सोसाइटीज हैं। जो माननीय ने चिंता व्यक्त की है, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि हमारे जो डेयरी संघ हैं उन संघों पर लेटेस्ट टेक्नोलोजी, जिन पर जांच की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए, वह हम लोगों ने मिल्को-स्कैन एफटी-वन मशीन, जो हिन्दुस्तान की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलोजी की है, वह बड़े संघों पर हमने लगाकर इसमें एसिडिटी, फैट, एस एन एफ, प्रोटीन, लेक्टोस, टोटल सालिड्स, यूरिया, यूक्रोस एण्ड नमक, ये सारी जांच करने की व्यवस्था हो जाती है। तो मैं समझता हूं कि डेयरी में एक मात्र ऐसा प्रकरण आया जिसमें मिलावट पाई गई, वह एस एन एफ और फैट की है। इस प्रकार की यदि मिलावट आती है, तो हमने कई प्रकार के नये इक्विपमेंट्स अभी खरीदे हैं, मिल्को स्कैन एफटी-120 हमने लिया, मिल्को स्कैन माइनर लिया है, मिल्को स्कैन 133 बी लिया है।

मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि डेयरी के प्लांट्स में कहीं भी मिलावट वाला दूध नहीं है क्योंकि तीन जगह उसकी जांच होती है। पहले मिल्क सोसाइटी के स्तर पर मैन्यूअल उसकी जांच करते हैं; जब वहां पर गुणवत्ता पाई जाती है तो उसके बाद में प्रत्येक संघ की हमारी एक चैक-पोस्ट बना रखी है, वहां पर टैस्ट होता है और टैस्ट होने के बाद, यदि उसमें मिलावट नहीं पाई जाती है और मिलावट पाये जाने पर एक प्रतिशत भी हम उनको स्वीकार नहीं करते हैं। उसके बाद भी यदि किसी तरीके से बच जाता है तो, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो टैस्टिंग के मापदण्ड, पैरामीटर्स, लेबोरेटरीज हैं, उनमें हम टैस्ट करते हैं और उसकी गुणवत्ता के बाद ही हम उसको आम पब्लिक को, सबको मिल्क के रूप में देते हैं, प्रोडक्ट के रूप में देते हैं।

फिर भी मैं माननीय सदस्यों को सदन के माध्यम से आश्वस्त करना चाहूंगा कि इस विषय को....

श्री रमेश (सपोटरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं, उनका जवाब दे दें।

श्री अध्यक्ष: जो दिया है, उनका जवाब आ रहा है। जवाब आ रहा है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): मैं आ रहा हूं, आपकी बात पर भी आ रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: सीधा जवाब दो इनको इनके स्पेसिफिक क्वेश्चन का।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जांच का जहां तक प्रश्न है, तो तीन स्टेज का मैंने निवेदन किया कि हम जांच करते हैं।

आपने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दें, तो यह काम मुख्य रूप से चिकित्सा विभाग देखता है और वे समय-समय पर उसकी जांच भी करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करूं कि जांच करने पर 43 सैम्पल्स चिकित्सा विभाग के द्वारा फूड सेफ्टी एण्ड स्टैण्डर्ड एक्ट के अन्तर्गत लिये गये थे, 37 सैम्पल्स में निल आया है, उनमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं पाई गई है। उनके अलावा, चार सैम्पल्स ऐसे हैं जिनके रिजल्ट आने बाकी हैं और जिन दो सैम्पल्स में हमें मिलावट मिली है, उनके चालान न्यायालय में पेश किये हैं।

अब मैं आपको सभी की तरफ से और विश्वास दिलाता हूं कि इसमें कतई कोताही नहीं बरती जाएगी; जांच के दायरे को और बढ़ाया जाएगा और जो भी कार्यवाही करनी होगी, वह आगे हम करेंगे।

श्री अध्यक्ष: लक्ष्मणगढ़ से आने वाले माननीय विधायक, पूरक प्रश्न कीजिये आप।

श्री रमेश (सपोटरा): जांच रिपोर्ट और चूरू के बारे में बताइये। यह क्या बात हुई? अध्यक्ष महोदय, जवाब दिलवायें पूरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): चूरू वाला। चूरू शब्द ही नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: वह तो आ गया उनका। (व्यवधान) आप चाहो, वैसा जवाब नहीं आ सकता। (व्यवधान) आप अपना पूरक प्रश्न कीजिये। आप विराज जाइये। (व्यवधान) आपके अनुरूप जवाब नहीं आयेगा।

श्री रमेश (सपोटरा): मंत्रीजी जवाब नहीं दे सके हैं। चूरू की जो समितियां हैं, उनको हमेशा के लिए क्यों बन्द कर दिया गया? भरतपुर, अलवर की जितनी भी समितियां हैं, इनको बन्द क्यों नहीं किया गया? (व्यवधान) हमने जो जांच रिपोर्ट की दिनांक पूछी है, वह मंत्रीजी बता नहीं सके। क्या मंत्रीजी पढ़कर नहीं आते? मंत्रीजी को ज्ञान नहीं है? वैसे तो कहते हैं कि मंत्रीजी को बहुत ज्ञान है, बहुत अनुभव है, जवाब नहीं दे पा रहे हैं मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक साथ ही हो जाएगा, ज्ञान है न आपको? हम मानते हैं कि ज्ञान है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं...

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): क्वेश्चन नम्बर 51 ।

श्री अध्यक्ष: अभी विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप तो सीनियर हों, आप तो मंत्री बनने वाले हैं, फिर ऐसा क्यों कर रहे हों?

श्री अध्यक्ष: जल्दी करो, उनका क्वेश्चन आ रहा है। कृपया शांत रहिये। पूरक प्रश्न है, मंत्रीजी, ध्यान से सुनिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इतना ही आपके माध्यम से मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि आपके मंत्री बनने के बाद में आपने प्रदेश में सैम्पल की कितनी जांचें करवाईं? यह बताने का कष्ट करें। इसके अलावा अलवर सहित कितने मिलावटी प्रकरणों की जांच कराकर, इस प्रदेश में 6-7 महीने में कितनी दुग्ध समितियों का दूध खरीदने पर रोक लगाई? दो ही बात हैं, बस। चूरू वाली जैसी मत कर देना कि चूरू का आपने नाम ही नहीं लिया। मैंने चूरू का नहीं पूछा है।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्य ने जो ज्ञान की बात कही है, इस प्रश्न के मूल संदर्भ, ज्ञानवर्द्धन के पूरे डाक्यूमेंट, संदर्भ, इसके साथ लगाये गये हैं, जो शायद आपने नहीं पढ़े होंगे।

जहां तक प्रश्न है कि मेरे द्वारा कितनी जांच करवाई गई, तो यह हमारा सुओमोटू प्रतिदिन का काम है, कराने का काम नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिदिन जब भी दूध आता है तो प्रत्येक कैन की जांच कम्पल्सरी है। इसलिए मैं समझता हूं, डायरेक्शन देने की कोई जरूरत है। पर अगर आपको कोई शिकायत है, आपको कोई ऐसा लगता है तो मुझे बतायें, मैं स्पेसिफिक उन पर कार्यवाही करूंगा। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): बता रहा हूं न। अध्यक्ष महोदय, मैं बता रहा हूं न। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान) पहले उनका हो जाए, उसके बाद आपका है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ): अलवर की सरस डेयरी में 89 जांचें करवाईं, उसमें से 89 डिफाल्ट पाये गये। आपने 28 समितियों से दूध लेना बन्द किया। आपके कार्यकाल का है और उसके बारे में आपने बताया ही नहीं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: विद्याधर नगर से आने वाले माननीय विधायक, पूरक प्रश्न कीजिये।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से इतना ही पूछना चाहता हूं कि अखबारों में भी काफी पढ़ने को मिला है कि सरस के...(व्यवधान) यूरिया की मिलावट का दूध पकड़ा है। (व्यवधान) यूरिया की जांच भी उसमें हो जाए।

श्री छोटू सिंह (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, बी ए डी पी की अधूरी समिति के बारे में निवेदन था। (व्यवधान) जैसलमेर के सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के लिए यह क्वेश्चन बहुत जरूरी था। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जब नियमित जांच होती है तो फिर मिलावट क्यों होती है? (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): यह आप बतायें, आप हाईटेक इंस्ट्रूमेंट्स मंगायें ताकि यूरिया की जांच भी उसमें हो जाए। (व्यवधान)

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि अभी आपने कहा कि लेटेस्ट क्या टेक्नोलोजी आप अपनाने जा रहे हैं, क्या नई चीज आप करने जा रहे हैं,...(व्यवधान) आप रुको न पहले।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, नहीं, यह नहीं है। मेरा सवाल है कि आपके मंत्री बनने के बाद में कितने न्यायालय में चालान पेश हुए? आप कह रहे हैं कि नियमित जांचें हो रही हैं, तो कितने दूध के कितने नमूनों में मिलावट पाई गई? और अलवर में कितनी दुग्ध सहकारी समितियों का दूध लेना मिलावट के कारण से रोका है? यह बता दें।

श्री प्रभू लाल सैनी (कृषि मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा है, शायद हमारे उप सचेतक उस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, प्रतिदिन प्रत्येक दूध के सैम्पल का, जो भी मिल्क सोसाइटी देती है, जांच करने की व्यवस्था है। नम्बर दो, अलवर, भरतपुर का जहां प्रश्न है, निश्चित रूप से मैं यह मान सकता हूं कि वहां पर मिलावट की काफी शिकायतें हैं, लेकिन डेयरी प्लांट्स में...

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): कितनी आईं, सर? संख्या पूछ रहा हूं मैं तो। आपके मंत्री बनने के बाद में अलवर डेयरी में कितनी मिलावट पाई गई, कितनों का दूध रोका गया और कितनों का चालान किया गया? (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत (लाडपुरा): माननीय मंत्री महोदय, इन मिलावटियों को जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है। इनके राज में सरस घी में मिलावट का बड़ा मामला पकड़ा गया था। (व्यवधान) बाबू लालजी नागर तो अभी भी अन्दर हैं। इनके डेयरी मंत्रीजी थे उस समय के। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। आप विराजिये। प्रश्न काल समाप्त।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:-

(1) श्री सुखराम विश्नोई, सदस्य की ओर से सांचौर नर्मदा नहर परियोजना की भीमगढ़ा वितरिका की 9 किलोमीटर लम्बाई में दोनों तरफ की नहर कच्ची होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(2) श्रीमती शकुन्तला रावत एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र बानसूर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(3) श्री मनोज कुमार, सदस्य की ओर से राज्य सरकार की आबकारी एवं डोडा-पोस्ट नीति गलत होने से डोडा-पोस्त का कारोबार बढ़ जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में;

(4) डा. किरोड़ी लाल, सदस्य की ओर से आर पी एम टी परीक्षा में हुई अनियमितता से प्रतियोगी परीक्षा में शामिल छात्रों में व्याप्त भारी असंतोष एवं आक्रोश के सम्बन्ध में;

(5) श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा बार-बार निरस्त की जा रही परीक्षाओं से प्रतियोगी छात्रों में व्याप्त आक्रोश एवं असंतोष के सम्बन्ध में; व

(6) श्री घनश्याम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में विद्युत लाइनें झूलने व अधिकांश ट्रांसफार्मर भूमि पर रखे होने से हो रही दुर्घटनाओं के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री सुखराम विश्नोई, श्रीमती शकुन्तला रावत, श्री

(श्री अध्यक्ष)

मनोज कुमार, डा. किरोड़ी लाल, श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री घनश्याम को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री ओम प्रकाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुवा में राजकीय महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

(2) डा. बालूराम चौधरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की जिन्दल शा लिमिटेड, भीलवाड़ा द्वारा खनन हेतु एम ओ यू में उल्लिखित शर्तों एवं अनुबन्धों की अवहेलना करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री हरिसिंह रावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भीम की सभी ग्राम पंचायतों के राशन कार्डों का शीघ्र दुरस्तीकरण कराकर वितरित करने के सम्बन्ध में।

(4) श्री नारायण सिंह देवल, सदस्य की ओर से जालोर-सिरोही दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, रानीवाड़ा व अध्यक्ष, आर सी डी एफ, जयपुर द्वारा की गई कथित अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री सुशील कटारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौरासी के ग्रामों को गुजरात के कडाणा बांध का बैकवाटर उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(6) श्री नवनीत लाल नीनामा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र घाटोल में ग्राम पंचायत बड़ान से ग्राम पंचायत बामनपाड़ा के बीच की सड़क का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अमराराम, सदस्य की ओर से बालोतरा की जनता की भावना को मध्य नजर रखते हुए बालोतरा को नया जिला बनाने के सम्बन्ध में।

(8) श्री राजेन्द्र सिंह यादव, सदस्य की ओर से जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस संसाधनों की भारी कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(9) श्री धीरज गुर्जर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर में विद्युत आपूर्ति, उपकरण आपूर्ति, ट्रांसफार्मर चोरी, अनियमितता, आदि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री मदन राठौड़, सदस्य की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग-14 पर स्थित सांडेराव में ट्रोमा यूनिट खोलने के सम्बन्ध में।

(11) श्रीमती कमसा मेघवाल, सदस्या की ओर से विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की जाजिवाल कलां ग्राम पंचायत के उच्च जलाशय (एस.आर.) का निर्माण कार्य पूर्ण कराने के सम्बन्ध में।

(12) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के अधीन संचालित नवजीवन योजना में आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से बहुत पिछड़ी कतिपय जातियों को शामिल करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

चार माननीय सदस्य पर्ची के द्वारा बोलेंगे। वे हैं,

1. श्री मानसिंह, गंगापुर सिटी शहर एवं ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में;
2. श्री केसाराम चौधरी, मारवाड़ जंक्शन विधान सभा क्षेत्र में से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-14 पर हो रहे निर्माण कार्यों में रही कमियों के सम्बन्ध में;
3. श्रीमती द्रोपती, राजस्व अपील अधिकरण का सम्भाग स्तर पर कार्यालय खोलने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में;
4. श्रीमती अनिता भदेल, आवासन मण्डल द्वारा अजय नगर में बनाई गई कालोनी में व्याप्त समस्याओं के सम्बन्ध में।

श्री सुखराम विश्नोई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति हो तो एक सेकण्ड, एक सेकण्ड। हम 15 माननीय सदस्यों ने, विपक्ष के लोगों ने एक स्थगन प्रस्ताव दिया था...

श्री अध्यक्ष: उनको बोलने दीजिये। वह स्थगन प्रस्ताव नियमित नहीं था।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): उस पर व्यवस्था नहीं आई। उस पर व्यवस्था नहीं आई।

श्री अध्यक्ष: आप बैठिये, मैं बता देता हूं, मैं आपको बता देता हूं। एक सदस्य एक ही दिन में दो स्थगन प्रस्ताव नहीं दे सकता। हमारे यहां जो सूचना देने का अधिकार है, उसमें जो पहला नाम होता है, उसी के आधार पर सूचना मानी जाती है और शकुन्तलाजी रावत का हमने पहले स्वीकार कर लिया। इसलिए दूसरी बार उस पर व्यवस्था नहीं दी जा सकती। यह मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

हां, सुखरामजी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, वह व्यवस्था नहीं दी।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था के लिए नहीं लिया है। तो कैसे लूंगा मैं? एक सदस्य कैसे दो बार स्थगित करायेगा? आप मुझे बताइये ना। नहीं, आप विराजें। आप विराजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): जो आपका आदेश है... (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक बहुत नम्र सुझाव है। आप स्थान ग्रहण करें तो मैं बोलूं। (व्यवधान) आप खड़े रहेंगे तो मैं बोल नहीं सकता।

मेरा एक सुझाव था, क्योंकि यह मामला बड़ा सेंसिटिव था, यहां सरकार के वरिष्ठ मंत्री विराजमान हैं, अगर सरकार की तरफ से सुओमोटो स्टेटमेंट कल-परसों में आ जाये तो सारी स्थिति साफ हो जायेगी। मैं यहां किसी का नाम नहीं ले रहा। आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं। (व्यवधान) अगर आप नाम लिवाना चाहते हैं तो मुझे नाम लेने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाहता। अगर सरकार इस पर... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपने अपना सुझाव दे दिया। (व्यवधान) नहीं, ऐसा है, जब मैंने वह रिजेक्ट कर दिया, उस पर व्यवस्था ही नहीं दी है, उस बारे में आप अपना सुझाव दे सकते हैं, लेकिन उस पर वाद-विवाद नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): सुझाव ही दिया है, सर।

श्री अध्यक्ष: नहीं, सुझाव नहीं दिया है आपने। सरकार ने सुन लिया है। (व्यवधान) आप वरिष्ठ सदस्य हैं और वे सदस्य अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोल रहे हैं। मैं आपसे विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूं कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये। आपके जो कनिष्ठ विधायक हैं, उनको बोलने का अवसर दीजिये।

हां, सुखरामजी विश्नोई।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव की व्यवस्था आई ही नहीं सदन में।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। आप विराजिये। मैंने व्यवस्था में ही नहीं लिया है। आप विराजिये। आपको कारण बता दिया। वैसे कारण बताना जरूरी नहीं है, मैं आपको यह भी बता दूं। मेरे लिए जरूरी नहीं है कि मैं जिस स्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर रहा हूं, उसका आपको कारण बताऊं। यह रूलिंग इसी विधान सभा में हो चुकी है। इसलिए आप शांत रहिये, मेरा आपसे निवेदन है।

हां, सुखरामजी। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

सांचौर नर्मदा नहर परियोजना की भीमगढ़ा वितरिका की कच्ची नहरें

श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 50 के तहत, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा नहर का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, उसमें से भीमगढ़ा वितरिका निकलती है। वितरिका पिछली भाजपा सरकार में बनी थी। वह कहीं 10 फीट ऊंची है, कहीं 15 फीट ऊंची है और व्यवस्थित नहीं बनने से, सही तरीके से नहीं बनने से उस नहर के दोनों तरफ पानी का रिसाव, सीपेज होने से किसानों की कीमती जमीन खराब हो रही है। वहां जो सरकारी और प्राइवेट रेट जमीन की चल रही है, पांच लाख रुपये सरकारी बीघा की चल रही है। दोनों तरफ गरीब किसान परिवार, ओ बी सी परिवार के लोग आये हुए हैं। किसी के पास चार बीघा जमीन है, किसी के पास दो बीघा जमीन है। एक किलोमीटर तक दोनों तरफ, माननीय अध्यक्षजी, जमीन हमारी खराब हो गई, खारी हो गई और ओवर पानी रिस रहा है।

(श्री सुखराम विश्नोई)

किसानों ने धरने दिये, भूख हड़ताल की, कई तरह की मांगें रखीं। मंत्री लोग आये, उनके सामने मांगें रखीं। आज दिन तक वह जो नहर सीपेज हो रही है, न तो मरम्मत की गई, न मरम्मत का प्रस्ताव लिया गया है।

बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी मार्फत आश्वस्त होना चाहूंगा सरकार से, नौ किलोमीटर लम्बी नहर है और उस नौ किलोमीटर के दोनों तरफ खेत किसानों के आये हुए हैं। खेत खराब होने के बाद वे ठीक नहीं होंगे। जिन लोगों के पास कम जमीन थी, वे बाहर जाकर बिना जमीन रह रहे हैं। मेरा, अध्यक्षजी, आपके मार्फत निवेदन है, उस नहर को पक्की किया जाय, व्यवस्थित की जाय, उसका सीपेज बंद किया जाय ताकि जो किसानों के खेत खराब हो रहे हैं, वह रोके जा सकें।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती शकुन्तला रावत।

बानसूर के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अध्यक्ष महोदय, मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगी कि जो स्कूल बानसूर विधान सभा क्षेत्र में, अभी जो यह विद्यार्थी मित्र का मैटर चल रहा है, कई विद्यालय ऐसे थे जो कि विद्यार्थी मित्रों के कारण ही संचालित हो रहे थे। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, बिलाली में जो गेट के पास स्कूल था, उसमें दो विद्यार्थी मित्र लगे हुए थे, अब उसमें एक लगा है। तो तीन-चार दिन से स्कूल बंद था। मैंने खुद ने व्यवस्था के तौर पर उसको खुलवाया है। अगर इसी तरीके का चलता जाएगा, जैसे रामपुर बालिका विद्यालय, बानसूर बालिका विद्यालय, बासदयाल बानसूर बालिका विद्यालय, बिलाली और चतुरपुरा, हरसोरा, चूला तो इस तरीके से बहुत विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बहुत ही ज्यादा अव्यवस्था है। वहां ना सब्जेक्ट टीचर्स हैं, ना प्रधानाध्यापक हैं, ना प्रिसिंपल हैं। तो बच्चे टी सी निकाल करके जा रहे हैं। जैसे रामपुर में तो सौ बालिकाएं हैं।

तो इस तरीके की जो अव्यवस्था है, उसके लिए आप कृपया अभी प्रजेंट में व्यवस्था करायें। क्योंकि फर्स्ट टैस्ट आने वाला है। इस तरीके से स्कूल बंद हो जाएगा। जैसे आपने कहा कि साल भर तक व्यवस्था होगी, तो व्यवस्था के तौर पर आप किसी भी तरीके से यहां दो-दो, चार-चार टीचर्स तो कम से कम लगवायें। जो हायर सेकण्डरी स्कूल है रामपुर में, उसमें बहुत ज्यादा कमी है। बासदयाल में भी नहीं है। तो ऐसे जो विद्यालय हैं, उनमें चाहें

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

तो मैं आपको पूरी लिस्ट अवेलेबल करवा दूंगी, इन सभी जगह जल्दी से जल्दी यह व्यवस्था करवाई जाएं जिससे कि बच्चों का हित हो सके और उनकी लाइफ खराब नहीं हो। खासकर, ग्रामीण क्षेत्र में बालिकाएं पढ़ती हैं, तो बालिकाओं का ध्यान रखते हुए, मैं उम्मीद रखती हूं कि आप इसमें व्यवस्था जल्दी से जल्दी करेंगे।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह चाहती हूं कि यह व्यवस्था करें मंत्री महोदय। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: रेस्पोंस करेंगे आप?

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि आपके यहीं नहीं, पूरे प्रदेश में विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं। उनको जल्दी से जल्दी भरने की कोशिश कर रहे हैं। आपके जो-जो विद्यालय, जहां बिलकुल हालत खराब हो, उनकी लिस्ट मेरे को दे दीजिएगा, उनको हम भर देंगे।

श्री अध्यक्ष: मनोज कुमार।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, कहां से भरोगे? टीचर हैं नहीं, विद्यार्थी मित्रों को बाहर कर दिया। भरोगे कैसे? कहां से लाओगे? थर्ड ग्रेड के भर नहीं रहे।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आपके किये गये कर्मों को हम भुगत रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपके किये को हमने भुगता था ना पांच साल। 2003 से 2008 आपने जो कर्म किया, हमने भुगता है पांच साल।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): पांच साल में आपने जो कर्म किये हैं, उनको ठीक करने में एक साल कम से कम लगेगा।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप दोनों ही एक दूसरे का भुगत रहे हों।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): आप लिस्ट दे देना मेरे को।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, इनको इनकी जगह और इनको इनकी जगह दे देना, तब तो ठीक चलेगा।

राज्य सरकार की गलत नीति के चलते डोडा पोस्त का बढ़ता कारोबार

श्री मनोज कुमार (सादुलपुर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार ने आबकारी नीति डोडा पोस्त के लिए ठेके के लाइसेंस की जो दुकानें दी हैं, उन दुकानों को लाइसेंस देने के बाद जो डोडा पोस्त खाने के आदी व्यक्ति हैं, उन लोगों का सरकार ने लाइसेंस नवीनीकरण नहीं किया है। लाइसेंस नहीं नवीनीकरण करने के कारण डोडा पोस्त खाने के जो लोग आदी हो चुके हैं, इस आबकारी नीति में तीन क्वांटिटी हैं जिनमें अपराध माना जाता है, स्माल क्वांटिटी, बिलो-कामर्शियल और कामर्शियल, अगर डोडापोस्त खाने वाला व्यक्ति 100 ग्राम भी अगर खरीद लेता है तो वह अपराध की श्रेणी में आता है। उसकी मजबूरी है कि उसका अगर लाइसेंस नवीनीकरण नहीं होता है तो उसको अवैध रूप से डोडा पोस्त खरीदना पड़ता है। सरकार अगर लाइसेंस नवीनीकरण नहीं करती है तो इन डोडा पोस्त की दुकानों को भी सरकार को बंद कर देना चाहिए, या इन गरीब लोगों के लिए लाइसेंस का तुरन्त प्रभाव से नवीनीकरण किया जाए जिससे ये गरीब असहाय लोग पुलिस की कार्यवाही से वंचित रहे। क्योंकि पुलिस इन लोगों को थोड़ी मात्रा मिलते ही गिरफ्तार कर लेती है और इनको मुकदमों को भुगतना पड़ता है।

ऐसी स्थिति में, सरकार तुरन्त प्रभाव से, माननीय मंत्री महोदय से, कहना चाहता हूं कि आप इन दुकानों को बंद करने की व्यवस्था रखते हैं या डोडा पोस्त खाने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस का नवीनीकरण करने की आपकी क्या व्यवस्था है और कब तक आप करने की मंशा रखते हैं? माननीय मंत्री महोदय, आप इसके लिए हमें जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि डोडा पोस्त का सेवन हमारे समाज में एक मान्यता प्राप्त नशा हो गया और यह भी सही है कि इस डोडा पोस्त को बंद करने के लिए यू एन ओ के माध्यम से कुछ देशों ने एक ट्रीटी की थी। उस ट्रीटी के माध्यम से 31 अप्रैल, 2015 को पूरे हिन्दुस्तान के अन्दर डोडा पोस्त को बंद करने हेतु एक जो हमारे एन डी पी एस एक्ट, 2012 है, इसके अन्दर एक पालिसी के अन्दर यह बदलाव किया गया था।

श्री अध्यक्ष: नशा-मुक्त विश्व।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नशा-मुक्त प्रदेश हो

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और, माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको बंद करने से पहले एम्स की एक टीम आई थी। 2009 में उस टीम ने जो सर्वे किया कि कहीं इनको चिकित्सकीय जरूरत तो नहीं है यह; इनके शरीर में, इनको बचाने के लिए अगर इसका सेवन नहीं करेंगे तो विपरीत प्रभाव तो नहीं पड़ेगा। उस एम्स की टीम ने यह कहा कि डोडा पोस्त सेवन करने वाले को अगर डोडा नहीं मिले तो उनके शरीर पर, शारीरिक स्थिति पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय, 2001 के बाद, यह सही है, 2001 के बाद एक भी परमिट का नवीनीकरण नहीं हुआ और यह बात भी सही है कि पिछले वर्षों में डोडा पोस्त के परमिटधारी जो थे, उनकी हर बार बीस-तीस प्रतिशत कम करते-करते, उनको शून्य पर ले जाने की सरकार की योजना है। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ लोग तो वे परमिटधारी हैं और लगभग 17 हजार 400 लोग वे हैं जिनको परमिट दिया गया था। उनका परमिट का नवीनीकरण इसलिए नहीं किया गया कि सरकार की पालिसी, पालिसी भी भारत सरकार की कि इनको शनैःशनैः कम किया जाए।

आज की तारीख में माननीय सदस्य कह रहे हैं कि डोडा पूरा उपलब्ध नहीं होगा। यह जो डोडा पोस्त है, उसके अन्दर जितनी आवश्यकता है, क्योंकि हमारे पास वैध लाइसेंसधारी 22 हजार 473 हैं और इस वर्ष 2 हजार 641 हैक्टेयर के अन्दर यह अफीम की खेती हुई है और 13 हजार 209 क्विंटल इसमें पैदा होगा और 9 हजार 840 क्विंटल पहले...। अध्यक्ष महोदय, इसमें इस बार, चूंकि नशा-मुक्त हो, सरकार ने योजना बनाई है और इस योजना के अनुसार हम इस वर्ष 648 कैम्प आयोजित करेंगे 17 डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल और सभी मेडिकल कालेजों की सहायता से और इसके लिए एन जी ओज के माध्यम से, उनका सहयोग भी हम ले रहे हैं। और 11 करोड़ 66 लाख रुपये इसके लिए प्रावधान किया गया है। बायतू से आने वाले माननीय सदस्य ने और कुछ लोगों ने तो इस प्रकार के कैम्प आयोजित करके नशा-मुक्त करने में सरकार का सहयोग देना भी प्रारम्भ किया है।

मैं आश्वस्त करना चाहता हूं कि डोडा पोस्त में जो ज्यादा पैसा लिया जा रहा है, जो 500 रुपये की रेट से ज्यादा, उस पर भी सरकार अंकुश लगाएगी और कोशिश यह होगी कि जो वैध परमिटधारी हैं, उनको उनकी क्वांटिटी के अनुसार डोडा मिले। डोडा पोस्त की जो आप कालाबाजारी की बात

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कर रहे हों, इसको भी सरकार सख्ती से बंद करेगी और पूरी कोशिश होगी, नशा-मुक्त भारत के अन्दर राजस्थान का भी सहयोग हो।

राजस्थान की सरकार ने इसकी व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए भारत सरकार से अनुरोध किया है कि जो 31 मार्च, 2015 की तिथि है, इसको पांच साल बढ़ाया जाए। क्योंकि लगभग डेढ़ लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो इस डोडा पोस्त का सेवन करते हैं, परन्तु उनके नाम न तो लाइसेंस है, न पहले बना और बाद में लाइसेंस बना। यह बहुत बड़ी व्यापक समस्या सरकार के सामने है। अभी जब हम सरकार-आपके-द्वार कार्यक्रम में गए थे, तब भी यह बात आई थी। तो भारत सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं, उनके अन्दर पांच साल का समय और दिया जाए, ताकि नशा-मुक्ति के लिए कैम्प लगाकर इनको धीरे-धीरे नशे से दूर किया जाए।

श्री अध्यक्ष: डा. किरोड़ी लाल। नहीं, सवाल-जवाब नहीं।

आर.पी.एम.टी. परीक्षा में हुई अनियमितता से अभ्यर्थियों में व्याप्त असंतोष

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी राजस्थान में आर पी एम टी की जो परीक्षा है, वह रद्द हो गई। यहां तो सब कुछ रद्द होता जा रहा है। आर पी एस सी की परीक्षाएं भी रद्द होती जा रही हैं और आर पी एस सी में छह दिन में दो-दो परीक्षाएं रद्द हो गईं। लेकिन आखिर में इन सबके लिए जिम्मेदार कौन है, यह सरकार चिह्नित नहीं कर रही है। अबकी बार आर पी एम टी में राजस्थान में करीबन 40 हजार छात्रों ने अपना भविष्य तलाशा और एक अनुमान, जो कोचिंग से एक एस्टिमेट लिया, उससे पता लगा है कि छात्रों ने, जो पी एम टी में पार्टिसिपेट करना चाहते थे, करीबन 400 करोड़ रुपए कोचिंग पर खर्च किये हैं। इतना रुपया खर्च करने के बाद पी एम टी रद्द हो जाए। पी एम टी का रिजल्ट 05 जून की रात को आया तो सुबह पता लगा कि 86 प्रश्न गलत हैं। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार कह रहे हैं, जिसमें डा. डी.के. गुप्ता हैं संयोजक आर पी एम टी; रजिस्ट्रार हैं, अनुप्रेरणा कुंतल; वाइस-चांसलर हैं राजा बाबू; वे कह रहे हैं, ना हमारी गलती है, ना हमें पता कौन दोषी है।

तो, मंत्रीजी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वे मना कर रहे हैं, ऐसे में माननीय मंत्रीजी का बयान आया कि यूनिवर्सिटी एक स्वायत्तशासी निकाय है;

(डा. किरोड़ी लाल)

गड़बड़ी की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ ...

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): अध्यक्ष महोदय, आपस में बात कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आपस में बात नहीं करें, वक्ता की ओर भी ध्यान रखें और वक्ता से निवेदन है कि आसन को सम्बोधित करें। आपस में बात नहीं करें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं तो आपको ही कर रहा हूं, साहब। मैं तो उधर मुंह ही नहीं फेर रहा हूं।

माननीय मंत्रीजी का एक बयान आया कि यूनिवर्सिटी एक स्वायत्तशासी निकाय है; कोई शक नहीं है; गड़बड़ी की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे; अब तक कुछ हुआ नहीं।

अध्यक्ष महोदय, इसमें एम सी आई की गाइडलाइंस में जो परीक्षा आयोजित करायी, उसमें भी एम सी आई की गाइडलाइंस का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन हुआ। एम सी आई की गाइडलाइन हैं, एम सी आई रेग्यूलेशन आफ ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन, 1997 के सेक्शन-52 के अनुसार प्रतियोगी परीक्षा समान मूल्यांकन प्रणाली और एक ही बैच पर आधारित होनी चाहिए, जो नहीं की गई। एम सी आई की गाइडलाइंस का इन्होंने उल्लंघन किया। 35 साल बाद पहली बार पी एम टी की परीक्षा रद्द हुई है। मैंने भी पी एम टी दी थी, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: और आप पास हुए थे उसमें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): हां, मैं पास हुआ था। (व्यवधान) नकल कराने राठौड़ साहब, हमारे प्रेसिडेंट थे यूनिवर्सिटी के, ये आये थे।

अध्यक्ष महोदय, पैंतालीस साल बाद; 1969 से यह परम्परा चल रही है पी एम टी की, कभी प्रश्न पत्र रद्द नहीं हुआ, न लीक हुआ। लेकिन यह हुआ। उसके बारे में जज क्या कहते हैं, हाई कोर्ट के, 'परीक्षा में बेस्ट स्टूडेंट का चयन हुआ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता।' मंत्रीजी, जज साहब कह रहे हैं कि हम विशेषज्ञ नहीं हैं लेकिन विशेषज्ञ को भी परसेंटाइल फार्मूले पर संदेह है। यूनिवर्सिटी अपना उद्देश्य पूरा करने में विफल रही है। कोर्ट कह रहा है,

(डा. किरोड़ी लाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, परीक्षा और परिणाम अवैध एवं असंवैधानिक हैं, अनकांस्टिट्यूशनल हैं। अध्यक्षजी, यह कोर्ट कह रहा है, इसमें समानता के अधिकार का उल्लंघन हुआ है, हनन हुआ है। कोर्ट कह रही है और कोर्ट ने तीन-चार सवाल और उठाये हैं। कोर्ट ने कहा कि 86 प्रश्न हटा कर, 62 उत्तर बदल कर और अंत में परसेंटाइल फार्मूले से रिजल्ट देना डाउटफुल है। परीक्षा आयोजन एजेंसी ने परसेंटाइल फार्मूले की जानकारी नहीं दी। इस गलती को स्वीकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट कह रही है, किसी को जानकारी नहीं है, इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ए आई पी एम टी 6 लाख स्टूडेंट एक ही प्रश्न पत्र से परीक्षा दे सकते हैं तो यहां परसेंटाइल फार्मूला लागू करने की बात क्या थी?

इसमें बात यह थी, अध्यक्षजी, माननीय मंत्री महोदय थोड़ा ध्यान से सुनें, जिनके अधिक अंक थे उनको परसेंटाइल से कम कर दिया गया और जिनके कम अंक थे, उनको परसेंटाइल से ज्यादा बढ़ा दिया गया। कम को ज्यादा और ज्यादा को कम करके जो घालमेल हुआ है, मंत्रीजी, और आप लम्बे पूरे भाषण दे रहे हैं। जब हुआ था, तब आप बीकानेर में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में थे जब यह शोर मच रहा था।

यह मेडिकल यूनिवर्सिटी 2007 से चल रही है और यह परीक्षा करा रही है। इस मेडिकल यूनिवर्सिटी की परीक्षा का जो तरीका है उसमें जो व्यक्ति घेरे में आ रहे हैं? वे क्या कह रहे हैं? उनका दोष क्या है? डा. राजा बाबू पंवार।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): कौन हैं ये?

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ये डा. राजाबाबू पंवार वाइस-चांसलर हैं। मैं जानता हूं इनको, मेडिकल कालेज, बीकानेर में थे। मैं भी वहीं से पढ़ा हूं। ''एम सी आई नियमों के विपरीत आर पी एम टी 6 बैच में कराये जाने के सूत्रधार डा. राजा बाबू पंवार; ''एम सी आई की गाइडलाइंस का उल्लंघन;'' 'पर्याप्त कम्प्यूटर नहीं होने के बावजूद भी आन-लाइन परीक्षा कराई गई। 'ए आई पी एम टी जैसी परीक्षा में आन-लाइन के साथ-साथ आफ-लाइन का भी विकल्प होता है, लेकिन आर पी एम टी में यह विकल्प नहीं था।

परसेंटाइल फार्मूला एक विवादों की जड़ है। आखिर में यह क्यों लाया गया? क्यों राजस्थान में ही लाया गया? और किसी स्टेट में यह परसेंटाइल फार्मूला नहीं आया। परीक्षा में इस काल-बैक आप्शन का विकल्प ही नहीं देना

(डा. किरोड़ी लाल)

चाहिए। सरकार ने हस्तक्षेप किया तो ये विकल्प दिया। इन्होंने हस्तक्षेप किया, मंत्रीजी ने, फिर यह विकल्प आया।

यह जो अनुप्रेरणा कुंतल हैं, ये आर पी एम टी से सम्बन्धित सैकड़ों परिवेदनाएं सामने आने के बावजूद भी निश्चित रहीं। किसी की परिवेदना पर, अध्यक्ष महोदय, कोई सुनवाई नहीं की। आर पी एम टी से पहले करवाई विभिन्न परीक्षाओं में भी गड़बड़ी के आरोप इस रजिस्ट्रार पर लगे हुए हैं। परसेंटाइल फार्मूला क्या है, अभी तक न तो अधिकारियों को जानकारी दी, न सरकार को दी, न प्रतियोगी छात्रों को दी गई। परीक्षा की हर प्रक्रिया में खुद शामिल रहीं और मिल कर घालमेल किया गया। मेरे को तो जानकारी में यह आया है, मंत्रीजी अगर बुरा नहीं मानें तो, मैंने 273 का नोटिस तो नहीं दिया, कि कहीं आपके स्तर से तो इस घपले-घोटाले को रेग्यूलेट नहीं किया गया? मेरे को जवाब दें इस बात का।

आर पी एस सी में भी घपला-घोटाला, परीक्षाएं रद्द हो जाना; गुलाबजी आपके बगल में बैठे हैं; आर पी एम टी में हो जाना पैंतालीस साल बाद। आखिर में इसमें आप गम्भीरता कब बरतेंगे, मंत्रीजी? जिस आर पी एस सी का राजस्थान में बहुत बड़ा नाम था, वह आर पी एस सी चारों तरफ से बदनाम हो रही है। जिसमें छापा मारने तक पिछली सरकार में पहुंच गये थे, लेकिन पिछली सरकार के प्रभाव के कारण आर पी एस सी का चेयरमैन बच गया, आप उस आर पी एस सी के चेयरमैन को क्यों बचाना चाहते हैं, जिसके पीरियड में 6 दिन में दो-दो बड़ी परीक्षाएं रद्द हो गईं और एक व्यक्ति के, एक ही परिवार के 32 लोग, नातेदार-रिश्तेदार, उसमें सलेक्ट हो गये, अमृत मीणा के? मैं पूछना चाहता हूं, आप किस कारण से उनको बचाना चाहते हैं?

मैं, प्रतिपक्ष के नेता सहित, हम सारे आपसे मांग करते हैं कि आर पी एस सी के बारे में सरकार जल्दी से जल्दी बयान दे। जो आर पी एस सी में घपलेबाजी हो रही है और आर पी एम टी में जो घपलेबाजी की है, यह चार हजार बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जिन्होंने चार सौ करोड़ रुपये अपनी जेब से खर्च कर डाले, वे परेशान हैं, सड़कों पर घूम रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं। ऐसे बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश की है, वह रजिस्ट्रार आपकी क्या लगती है, वह वाइस-चांसलर आपका क्या लगता है? बाकी के दोषी आपके क्या लगते हैं? उन सबको निलम्बित करके, ए सी बी में देने की बजाय, उनको बारेताणी में भेजने का काम करो, मंत्रीजी, वरना ये व्यवस्थाएं जो बिगड़ रही हैं राजस्थान में, ये आपकी सरकार को कलंकित कर देंगी।

(डा. किरोड़ी लाल)

मैं चाहूंगा आपके माध्यम से, मंत्रीजी इस पर कुछ बयान दें, मेरे को संतुष्ट करें, सदन को संतुष्ट करें।

श्री अध्यक्ष: आप संतुष्ट करेंगे क्या इनको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हां, करूंगा।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बड़ा सीरियस मामला है। आज सदन को चलते-चलते पांच-सात दिन हो गये। सरकार का यह दायित्व था, धर्म था कि सरकार को सुओमोटू आर पी एस सी, आर पी एम टी के मामले में सदन में एक निश्चित वक्तव्य देना चाहिए था और इस पर आप समय निकाल कर चर्चा करायें।

आर पी एस सी सीरियस मैटर है, मैंने आपसे निवेदन भी किया था। मैं आपके चैम्बर में भी मिला था और मैंने आपसे निवेदन भी किया था कि राजस्थान के इतिहास में आर पी एम टी और आर पी एस सी के अन्दर जो घपला हुआ है, जितनी इसकी निन्दा की जाए; क्या जांच करायेंगे? आप सी बी आई से जांच कराइये इसकी। इसकी जड़ में कौन लोग हैं? आप सी बी आई को जांच दो इसकी। जो दोषी हैं, उनको सज़ा तो मिले। कम से कम भविष्य में इन चीजों की पुनरावृत्ति तो नहीं हो। यह बड़ा गम्भीर मामला है और सरकार इतने दिन से शांत बैठी हुई है, इसके ऊपर कोई वक्तव्य नहीं आया है। मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से इसके बारे में वक्तव्य दिया जाए और इस मामले की आप सी बी आई से जांच करायें जिससे ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो।

आर पी एस सी का तो पिछले बीस साल में हमने राजनीतिकरण कर दिया। कहीं सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। इस तरह से लोग लगाये जा रहे हैं। जिसमें नार्लीकर सरीखे चेयरमैन रहे, आज हाल क्या हो गया इस आर पी एस सी का। अब तो कोई लड़के विश्वास नहीं करेंगे आर पी एस सी के मामले में। अगर सही परीक्षा भी होगी तो साल- दो साल तक तो यही चर्चा होगी कि घपला हो रहा है, पैसे खाये जा रहे हैं।

तो आज राजस्थान की इज्जत का सवाल है, राजस्थान के सम्मान का सवाल है। इस मामले में सरकार को वक्तव्य देना चाहिए और इस मामले की सी बी आई से जांच करानी चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि बीस साल से आर पी एस सी का राजनीतिकरण कर दिया। सोशल इंजीनियरिंग हो रही है। योग्य लोगों को लगाया नहीं जा रहा है। इस जाति का लगा दो, उस

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

धर्म का लगा दो, उस पांत का लगा दो। आर पी एस सी में तो कम से कम यह नहीं हो। यही मेरा आपसे अनुरोध है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: सरकार को गम्भीरता से लेना चाहिए हमारे माननीय सदस्य के वक्तव्य को।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं भी अपनी बात कहना चाहता हूं दो मिनट। आर पी एम टी के द्वारा जो एग्जाम हुए थे, हैल्थ यूनिवर्सिटी ने जो एग्जाम कराये, उनकी शिकायत मिली। शिकायत पर सरकार ने कमेटी बनाई। कमेटी ने जब यह तय किया कि इसमें विसंगतियां रही हैं। तो उसके कारण यह परीक्षा परिणाम रद्द कर दिया और रद्द होने के बाद दुबारा जो एग्जाम हो रहा है, इससे जो अभिभावक हैं उनको बड़ी तकलीफ हुई है और जो स्टूडेंट इसमें पास हो गये या फेल हो गये, उनके साथ भी बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।

मैं भी माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि सिर्फ इस परीक्षा को दुबारा करने से इस समस्या का हल नहीं हो सकता। अगर हम इस समस्या का हल करना चाहते हैं तो जो लोग इसमें दोषी हैं, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। पिछले पांच साल का भी, जो परीक्षाएं हुई हैं, उनकी भी जांच कराकर, इस तरह से बार-बार एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, उसके बारे में भी, माननीय मंत्रीजी, आप इसकी जांच करवाकर कार्यवाही करें। यह आपसे हमें पूरी उम्मीद है।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी आर पी एस सी से सम्बन्धित है। फिर बाद में साथ ही दो।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): अध्यक्ष महोदय, इससे भी गम्भीर विषय जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर का है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): जवाब साथ आ जाएगा। (व्यवधान) मेरी नोलेज में है। एक साथ आ जाएगा जवाब। जयनारायण विश्वविद्यालय विषय भी बहुत गम्भीर विषय है और इस विश्वविद्यालय में अनियमितताएं हुई हैं। इतनी अनियमितताएं शिक्षा के क्षेत्र में हुई हैं, परीक्षाएं रद्द हुई हैं, पर्चे लीक हुए हैं कि उसकी विश्वसनीयता पूर्ण रूप से समाप्त हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए।

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इस बारे में भी गम्भीरता से विचार कर कोई न कोई निर्णय लें।

श्री अध्यक्ष: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्षजी, हमारे यहां भी ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रतिपक्ष के नेता।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यूनिवर्सिटी की यही स्थिति है। इसलिए जब मंत्रीजी जवाब दें तो यह भी इसमें इन्क्लूड करें।

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप। प्रतिपक्ष के नेता।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जो यह मामला उठाया, यह अपन सबके लिए, सदन के लिए बहुत ही गहनता का विषय है और इसको अपने को विचार करना चाहिए। लोगों की आस्था आर पी एस सी और आर पी एम टी में थी, वे आशाएं बिलकुल इस प्रकरण से धूमिल हुई हैं।

माननीय सदस्यों ने कहा, सरकार को इस पर पूरी चिंता करनी चाहिए। हम सबका दायित्व बनता है। जिस तरीके से अभी राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि यदि सही परीक्षा भी, आगे सही चलेंगी, उसमें भी आम जन की जिस तरीके से आस्था थी वह आस्था बिलकुल खतम होगी।

उसमें जिस तरीके से करप्शन हुआ, किसी के माध्यम से पैसे लेकर उसमें पेपर आउट हुए और पेपर आउट होने के बाद, अपने परिवार के सदस्यों को जिस तरीके से आर पी एस सी में लगा दिया, तो आने वाले समय में यदि ऐसा होगा तो इसमें कई माफियां पनपेंगे। क्योंकि इस तरीके से एग्जाम देने वाले जो लड़के हैं, जो परिवार उन्हें जानते हैं कि इसमें कहीं न कहीं घपला है, उसमें कई माफियां पनपेंगे और उनके पीछे वे लड़के चक्कर लगाएंगे।

इसलिए कहीं न कहीं पूरी व्यवस्था, अपने पूरे सदन का पूरा दायित्व बनता है कि इसमें गहनता से विचार कर, सी बी आई की जिस तरीके से मांग की गई, यह बिलकुल वाजिब है, सी बी आई से इसकी जांच होनी चाहिए। इसमें सरकार सख्त, कठोर निर्णय लेकर कोई न कोई व्यवस्था जरूर करे।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, लालसोट से आने वाले माननीय सदस्य और नेता प्रतिपक्ष ने जो भावना

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

व्यक्त की है, मैं समझता हूं कि हर संवेदनशील सरकार का कर्तव्य भी है कि इस प्रकार संस्थाओं में जो परीक्षाएं हों, वे ठीक हों।

श्री अध्यक्ष: मूल रूप से किरोड़ी लालजी की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आर पी एम टी तक ही अपनी बात को सीमित रखूंगा। यह सही बात है कि लम्बे अन्तराल के बाद आर पी एम टी की परीक्षाएं दुबारा करानी पड़ीं। राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय की विज्ञप्ति 9 अप्रैल को जारी हुई थी, 3 मई तक सबकी आन-लाइन एप्लिकेशंस ली गईं। यह भी सही है कि 41,911 विद्यार्थी इस परीक्षा में बैठे। यह भी सही है कि दो स्लाट में आन-लाइन परीक्षा आयोजित की गई, 28, 29 और 30, अध्यक्ष महोदय, यह भी सही है कि 200 नम्बर के पेपर थे, केमिस्ट्री, फिजिक्स, जूलोजी और बाटनी। उसकी आंसर की, क्योंकि आन-लाइन के अन्दर जिस दिन परीक्षा का अंतिम सत्र समाप्त हुआ, उसी दिन उस कम्प्यूटर पर यह अपलोड कर दिया गया, आंसर की के बारे में और उसके बाद परिवेदनाएं विश्वविद्यालय ने आमंत्रित कीं, 30 तारीख को परिवेदना आना प्रारम्भ हुई। विश्वविद्यालय ने प्रो-वाइस चासंलर, अशोक भण्डारी की चेयरमैनशिप में एक कमेटी बनाई कि ये जो ग्रीवेंसेज आ रहे हैं, इनका निस्तारण कैसे हो। पहले दिन ही 103 ग्रीवेंसेज आ गये और जब यह पूरा मामला सरकार के ध्यान में आया तो हमने कहा कि अब ग्रीवेंसेज आ गए हैं तो इसकी तिथि और बढ़ाओ। कुल मिलकार, 476 ग्रीवेंसेज सरकार के सामने आए। इस कमेटी ने जब यह देखा कि 86 प्रश्न गलत आ गए, उसके साथ ही आंसर-की अपलोड हुई थी, उसमें 62 आंसर गलत थे।

इन सारी चीजों को देखते हुए, राज्य सरकार ने 10.6.2014 को एक कमेटी बनाई। उस कमेटी में उन लोगों को लिया गया जो पहले कन्वीनर रहे थे आर पी एम टी के, डा. राजेश शर्मा, डा. संदीप माथुर, डा. रवीन्द्र मोर और एक आई टी के प्रोफेसर को लिया गया। अध्यक्ष महोदय, 15.6.2014 को सरकार को जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जांच रिपोर्ट में जो मोटे-मोटे बिन्दु थे, उनमें यह था कि 86 प्रश्न त्रुटिपूर्ण पाये गये और प्रत्येक स्लाट में इनकी संख्या अलग-अलग थी। प्रत्येक स्लाट में भिन्न-भिन्न संख्या में प्रश्नों के त्रुटिपूर्ण होने के कारण परीक्षा परीणाम में बहुत अधिक विसंगतियां आ गयीं। प्रत्येक स्लाट में सफल छात्रों का प्रतिशत, आप बता रहे, हो वह भी सही है, अंतर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ज्यादा था। यह भी सही है, माननीय सदस्य जो आपने कहा, परसेंटाइल फोरमेट के पश्चात भी प्रत्येक स्लाट में सफल छात्रों के प्रतिशत में अंतर बना रहा।

इन सारी चीजों को देखते हुए, सरकार ने 18.6.2014 को पी एम टी की परीक्षा को रद्द करने के लिए फैसला लिया।

चूंकि यह सारा मामला पूरे देश में, जितने मेडिकल टैस्ट हो रहे हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कलेण्डर तय कर रखा है, उन्होंने तय कर रखा है कि इतनी तारीख को आप आवेदन पत्र लेंगे, इतनी तारीख को परीक्षा कराएंगे, इतनी तारीख को आप परीक्षा का परिणाम देंगे, इतनी तारीख को आप काउंसलिंग करेंगे। इसलिए इस कलेण्डर के लिए, रिव्यू के लिए, हमने एक आई ए लगाई, इंटेरिम एप्लिकेशन लगाई कोर्ट के सामने, सर्वोच्च न्यायालय के सामने, 20.6.2014 को और उसी समय जो बच्चे इसमें पास हो गये थे, वे सुप्रीम कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट में चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को निर्देश दिया कि सारी रिट पीटिशंस को एक साथ क्लब करके आप 27.6.2014 से पहले निर्णय करें। हाई कोर्ट ने आर पी एम टी को गलत ठहराया। इसको स्वीकार करने में मुझे कोई हर्ज नहीं है, हिचक नहीं है। वापस हम सुप्रीम कोर्ट में गये तो उन्होंने कहा, आप दुबारा कलेण्डर करके दुबार परीक्षा ले सकते हों।

अध्यक्ष महोदय, अब दुबारा आफ-लाइन परीक्षा 27.7.2014 को सरकार करा रही है; ओ एम आर शीट से करा रही है; 6 परीक्षा केन्द्रों पर एक ही बैच में हो रही है। ओ एम आर शीट के अन्दर, इसमें पारदर्शिता रहे, इसलिए तीन शीट इसमें एक साथ ले रहे हैं, जिनमें एक तो परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए होगी, एक प्राथी स्वयं देख लेगा उसने क्या किया है, और एक कार्यालय के रिकार्ड के लिए। नरपतसिंह शेखावत जो इस मेडिकल कालेज के प्राचार्य हैं, एस एम एस में सुपरिटेंडेंट रहे हैं, जिनकी इन्टीग्रिटी के बारे में सारा सदन जानता है, उनको हमने इसका कन्वीनर बनाया है। इसमें जिला कलक्टर की अध्यक्षता में प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा है कि इसकी परीक्षा ठीक हो जाए। मेडिकल कालेज के जितने हमारे प्रिंसिपल हैं, उन सबको एक टास्क फोर्स के रूप में कोशिश की कि आर पी एम टी ने जो परीक्षा दुबारा कराने के निर्णय के साथ असमंजस की स्थिति पैदा हो गई, उसके बारे में करें।

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सही कह रहे हैं कि इसके बारे में निश्चित तौर पर, किनकी क्या भूमिका रही, कहां क्या गलती रही, मैं घोषणा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करता हूं कि प्रमुख शासन सचिव स्तर के अधिकारी से पूरे प्रकरण की जांच करवाएंगे; जो भी दोषी होंगे इसके अन्दर, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। परीक्षा की सैंक्टिटी बनी रहे, सरकार यह सुनिश्चित करेगी। भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं हो, इसके लिए जो भी हमें कदम उठाने पड़ेंगे, वे कदम उठाएंगे। मैं सदन के माध्यम से उन परीक्षार्थियों से क्षमा भी चाहूंगा जिनको दुबारा परीक्षा देनी पड़ रही है।

मैं, राजाखेड़ा और प्रतिपक्ष के नेता, आपसे सहमत हूं कि हमें इस बारे में राजनीतिक परिधि से ऊपर उठकर विचार करना पड़ेगा कि हमारी संवैधानिक संस्थाएं किस प्रकार काम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री हनुमान बेनीवाल।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अध्यक्ष महोदय, जो संदेह के घेरे में आये हैं, क्या उनका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क वहां चलता रहेगा?

श्री अध्यक्ष: विराजो आप। विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जांच के अन्दर जो भी दोषी पाये जाएंगे, चाहे वे कितने ही बड़े अधिकारी हों, कुछ भी हों, उन सबके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री अध्यक्ष: हनुमान बेनीवाल।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा निरन्तर निरस्त की जा रही परीक्षाओं से अभ्यर्थियों में व्याप्त असंतोष

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, पिछले 7 दिनों के अन्दर आर पी एस सी द्वारा आयोजित दो परीक्षाएं ...(व्यवधान) दो परीक्षाएं रद्द हो गईं और तीसरी परीक्षा जो सेकण्ड ग्रेड अध्यापक की है, वह रद्द होने के कगार पर है। उस परीक्षा के पेपर लीक हुए। उसमें पकड़े गए अमृतलाल को पुलिस ने कमजोर केस बनाकर पेश किया, उसकी जमानत हो गई। बाद में, आर ए एस-प्री के एग्जाम के अन्दर जो गोरखधंधा चलता था, उसने पूछताछ में बताया कि मैं अभी से काम नहीं कर रहा हूं, पिछले 10 साल में मैंने सैकड़ों लोगों को आर.ए.एस., आर.पी.एस. और आर.जे.एस. बना दिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से इस मामले में वक्तव्य

(श्री हनुमान बेनीवाल)

चाहूंगा। इस एक एग्जाम के रद्द करने से आर.पी.एस.सी. की विश्वसनीयता जनता के अन्दर और लोगों के अन्दर नहीं बनेगी। जितने भी दोषी इस मामले के अन्दर हैं, इस पूरे प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करें क्योंकि यह जो आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन हैं, इनको पिछली बार भी, जब एंटी-करप्शन ब्यूरो ने राजेश मीणा, एस.पी. को पकड़ा था और 12 पुलिस अधिकारियों के चालान किये, दलाल रामदेव ठठेरा, इनके मकान में रुका हुआ था और इससे लगातार, काल डिटेल के अन्दर, इस +++ से उसकी बात होती थी।, लेकिन पूर्व मुख्य मंत्री ने उसको बचाया, सरकार रहते हुए, जब वे वर्तमान मुख्य मंत्री थे, क्योंकि बहुत उनका नजदीकी था।

लेकिन अब तो हमको समझ में नहीं आ रहा है। सरकार बदल गयी, प्रधान मंत्री कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खातमे के लिए काम करेंगे, अब इससे बड़ा तो कोई भ्रष्टाचार नहीं मिल सकता। आर.पी.एस.सी. की दो-दो परीक्षाएं रद्द हो गईं, तीसरी रद्द होने के कगार पर है।

श्री अध्यक्ष: रिपीट मत कीजिए। बात समाप्त कीजिए, रिपीट मत कीजिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): स्थगन पर बोल रहा हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लड़के आते हैं हमारे पास। एक साल बाद लड़के मिलते हैं तो हम पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं कि आर.पी.एस.सी. के अन्दर हैडमास्टर बन गये; कैसे बने; तो बोलते हैं कि दस लाख रुपए देकर बन गया। एग्जाम से लेकर सलेक्शन तक का ठेका और आर.ए.एस., आर.पी.एस. और आर.जे.एस. बनाने में 50 लाख से लेकर एक करोड़ तक का ठेका लिया जाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक पुराने मेम्बर थे **+++** जिन्होंने खूब भ्रष्टाचार किया। उनका नाम आ रहा था। उससे पहले ही चुनावों के अन्दर उन्होंने आर.पी.एस.सी. से इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली और बी.जे.पी. के नेता हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, यह **+++** जब बीकानेर में एस.पी. थे, तब ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नाम मत लीजिए। नाम मत लीजिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): एक मिनट इनका पूरा रिकार्ड ही बता दूं आपको। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट। +++

श्री अध्यक्ष: नाम मत लीजिए। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): यह जो आर.पी.एस.सी. के चेयरमैन बीकानेर में जब एस.पी. थे, तब कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता का, युवा नेता का मर्डर हुआ था और उसमें जिस ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह नाम ड्राप कर लिया जाए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): जिस क्रिमिनल का नाम आया, रामकिशन सियार की हत्या हुई थी, कांग्रेस के नेता की, जिस अपराधी का षड्यंत्र में नाम आया, उसने 24 तारीख जो थी, उसमें उसने लगातार दस बार एस.पी. से बात की है और उस डाक्टर ने उन मुख्य अपराधियों से 15 बार लगातार एक दिन में बात की है।

श्री अध्यक्ष: पटरी से मत उतरिए।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ऐसे संदेहास्पद और अविश्वसनीय व्यक्ति के हाथों अगर आर.पी.एस.सी. की कमान सौंप दें, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब लोग तो हमको यह पूछने लग गये कि आर.पी.एस.सी. का एग्जाम दें या नहीं दें? कहीं दूसरा धंधा कर लें, प्राइवेट नौकरी कर लें, क्योंकि सलेक्शन तो होना नहीं? जो पढ़ते हैं, उनका तो सलेक्शन नहीं हो रहा है और दस साल में, मैं आपको बता दूं कि ऐसे हजारों उदाहरण होंगे जो टेंथ, टवेल्थ और ग्रेजुएशन में जिनके थर्ड डिविजन हैं, उन्होंने टाप टेन के अन्दर आर.ए.एस., आर.पी.एस. और आर.जे.एस. के अन्दर स्थान प्राप्त किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे बड़ी शर्मनाक घटना हो नहीं सकती। विधान सभा का सत्र चल रहा है, पूरी जनता और पूरे राजस्थान के युवा और छात्र हमारी ओर देख रहे हैं और आपकी ओर विशेष रूप से देख रहे हैं कि आप कोई ऐसा आदेश पारित करेंगे जिससे हजारों लड़कों का, छात्रों का भविष्य आर.पी.एस.सी. के माध्यम से सुरक्षित रहे।

अभी लालसोट से आने वाले हमारे माननीय विधायक ने आर.पी.एम.टी. का मामला उठाया। रजिस्ट्रार और कुलपति इतने क्या पावर-फुल हो गये!

श्री अध्यक्ष: वह हो गयी बात। वह विषय खतम हो गया।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पुरानी सरकार के टाइम भी उन्होंने

(श्री हनुमान बेनीवाल)

मौज की और इस सरकार के टाइम भी मौज कर रहे हैं। ऐसे क्या कारण हैं? हम जानना चाहते हैं, जनता जानना चाहती है और सत्र चल रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान की और देश की निगाहें आपके ऊपर और सरकार के ऊपर है। अगर वास्तव में सरकार भ्रष्टाचार का खातमा करना चाहती है तो सरकार वक्तव्य दे। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सरकार सुन नहीं रही है। सरकार तो बात कर रही है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजिये। वे बोल रहे हैं।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): पूरे प्रकरण की सी.बी.आई. जांच करवाएं और दोषी लोगों के खिलाफ सरकार सख्त कार्यवाही करे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। समाप्त कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तंत्र पूरी तरह से सड़ गया। हाई कोर्ट ने भी एक बार आदेश दिये थे कि इस सिस्टम को इम्प्रूव करें। हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी इस तंत्र में किसी प्रकार का कोई सुधार नहीं आया। इसलिए मैं सरकार से निवेदन करूंगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सुधार लाइये।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सुधार की दृष्टि से, नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वक्तव्य; वक्तव्य कि क्या सख्त कदम उठाये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: बस, विराजिए आप। श्री घनश्याम। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): वक्तव्य आ रहा है, साहब।

श्री अध्यक्ष: वक्तव्य दे रहे हैं? विराजिए आप। वे रेस्पांड कर रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्यों की भावना के साथ अपनी भावना मिला रहा हूं। अगर आर.पी.एस.सी. की इतनी दुर्गति हो, जिसको सुनकर के या पढ़कर अपने आप में दिल ठहर जाता है। जिस प्रकार की अनियमितताएं पिछले वर्षों में हुई हैं, वे वास्तव में बहुत ही शोचनीय है।

मैं सदन के सब माननीय सदस्यों को भी अपनी भावना के साथ जोड़कर, यह समस्या सामान्य नहीं है। हजारों नौ-जवानों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पर दुर्भाग्य यह है, कानून में ऐसा बाध्य कर रखा है कि हम

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

आर.पी.एस.सी. की संस्था के खिलाफ कुछ करने की स्थिति में नहीं हैं। भावना आपकी और मेरी, अगर मेरे हाथ में हो तो मैं आज ही इसका फैसला करा लूं, लेकिन मजबूर हूं कि वास्तव में कानून में जिस प्रकार का प्रावधान कर रखा है, आर.पी.एस.सी. की अपनी एक सैंक्टिटी है। उसका चयन तो हम करते हैं लेकिन उस पर कार्यवाही करने का हमारा कोई अधिकार संविधान में नहीं दिया हुआ है। संविधान में 217 के तहत जो दिया हुआ है, वह इतना हमको बाध्य कर देता है।

मैं फिर भी हाउस को इस बारे में आश्वस्त करता हूं कि जो कुछ भी इस सदन की, आपकी, मेरी और प्रशासनिक अधिकारियों की जो शक्तियां हैं, उस सारे का उपयोग, चीफ सेक्रेटरी के साथ बैठकर, कार्मिक विभाग के साथ बैठकर जो कुछ भी कार्यवाही की जा सकती है, वह हम निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन कानून हमको, मैं आपकी भावना से सौ प्रतिशत सहमत हूं लेकिन कानून हमको अपने रास्ते में एक बाधक के रूप है। यह कभी नहीं सोचा था कि आर.पी.एस.सी. जैसी संस्था की गिरावट इस स्तर तक चली जाएगी।

अब माननीय सदस्य ने कहा कि पिछले दस सालों से ऐसा हो रहा है ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): एक सेकण्ड, यह सही है, आपकी मजबूरी सही है; ...

श्री अध्यक्ष: भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): कानून में जिस ढंग का है, यह पढ़कर बता रहे हैं, सम्भव नहीं है, पर क्या ...(व्यवधान) जैसे ट्राई के मामले में एक्ट में परिवर्तन किया है ...(व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पूरा हो जाने दें, उसके बाद बोलना। नहीं, नहीं, वह वक्तव्य, बीच में आप इंटरवीन करेंगे तो दूसरे भी इंटरवीन करेंगे, तो फिर सदन की कार्यवाही नहीं चल सकती है। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ट्राई के मामले में एक्ट में परिवर्तन किया है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: लालसोट से आने वाले माननीय विधायक, आप आसन ग्रहण कीजिए।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): ऐसे ही सारा हाउस अपना कोई रास्ता निकाल सकता है।

श्री अध्यक्ष: आपने पूरा पूछ लिया। सुरानाजी, आप बोलेंगे?

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं थोड़ा सा कानून की पेचीदगी के बारे में बताना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो बात उन्होंने कही है, मैं उसी सम्बन्ध में कोई अलग बात कह रहा हूं जो महत्वपूर्ण है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप जानते हैं कि मैं अनावश्यक इंटरवेंशन नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल सही है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मेरा निवेदन यह है कि आप संविधान की जिन धाराओं का उल्लेख कर रहे हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी वह ही है और प्रांतों के पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए भी वही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक यू.पी.एस.सी. में, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में कभी किसी ने सुना नहीं कि किसी भी परीक्षा को रद्द करना पड़ा हो या किसी परीक्षा पर प्रश्नचिह्न लगाया गया हो। यदि भारत सरकार में आखिर, राजनीतिक है, ऐसा नहीं है कि वहां के नेता और वहां के मंत्री कोई राजनीति से ऊपर हैं। वह स्थिति कमोबेशी राजस्थान में भी है। लेकिन आपको आर.पी.एस.सी. में यदि पावर नहीं है तो राजस्थान की विधान सभा से आप स्पेशल पावर लीजिए और यह आर.पी.एस.सी. का गठन जो आपने अभी कर रखा है, वह किसी भी काम का नहीं है। इन सारे आर.पी.एस.सी. के अधिकारियों को, आप कमजोर हों तो विधान सभा में प्रस्ताव लाएं और इन सारों को कहें कि वे अपना इस्तीफा दें और विधान सभा के प्रस्ताव के बाद में कौन इस्तीफा नहीं देता है, इसको हम देखेंगे। किसी की ताकत नहीं है; यदि बड़े-बड़े राज्यपाल महोदय, जो पहले मुकर रहे थे कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, यदि उन्होंने भी इस्तीफे दे दिए हैं तो आर.पी.एस.सी. के हुक्मरानों की यह ताकत नहीं है कि विधान सभा के प्रस्ताव के बाद, और कोई संशोधन आप लाना चाहें, उसके बाद में वे रह सकें और अपनी आपाधापी चला सकें।

श्री गुलाबचन्द कटारिया (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): मैं आपकी भावना को समझ रहा हूं लेकिन यह जो भारत का संविधान है, यह

(श्री गुलाबचन्द कटारिया)

संविधान का अनुच्छेद 317, मैं इसको पढ़ रहा हूं, "लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य का हटाया जाना और निलम्बित किया जाना- (1) खंड-3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर किए गए राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसके पद से हटाया जाएगा जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उस न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 145 के अधीन इस निमित्त विहित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच पर, यह प्रतिवेदन किए जाने के पश्चात् किया गया है कि, यथास्थिति, अध्यक्ष या ऐसे किसी सदस्य को ऐसे किसी आधार पर हटाया जाए।''

''(2) आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को, उसके सम्बन्ध में खण्ड(1)…'', वही जो मैंने अभी ऊपर पढ़ा, ''...के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, संघ आयोग या संयुक्त आयोग की दशा में राष्ट्रपति और राज्य आयोग की दशा में राज्यपाल उसके पद से तब तक के लिए निलम्बित कर सकेगा जब तक राष्ट्रपति ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय का प्रतिवेदन मिलने पर अपना आदेश पारित नहीं कर देता है।'' हमारे लिए इस 317 में सब प्रकार से हमारी शक्तियां, यह सोचते हुए शायद उस समय कानून बनाया कि इतनी पवित्र संस्था है और इतनी सम्मानित संस्था है, इसमें इस प्रकार की गिरावट नहीं आयेगी लेकिन दुर्भाग्य से गिरावट आई है और इस कारण से, इस कानून को भी ध्यान में रखते हुए, इस प्रक्रिया को हम किस ढंग से करेंगे, ताकि हम, निश्चित रूप से कोई न कोई कठोर कदम लेकर इस अनियमितता को कैसे रोका जा सकता है। मैं आपकी भावना से 100 प्रतिशत, इवन 101 प्रतिशत सहमत हूं, क्योंकि अगर जिस संस्था के द्वारा आने वाले बच्चों का भविष्य बनना है, वही अगर गर्त में चली गई तो फिर बचेगा क्या? दुर्भाग्यपूर्ण है स्थिति तो, लेकिन कानून इतना बाध्य कर रखा है।

मैं आपकी भावना को अपनी भावना के साथ, मुख्य मंत्रीजी के साथ भी, अधिकारियों के साथ भी बैठकर जो कुछ भी रास्ता इसमें मुझे मिलेगा, मैं निश्चित रूप से उस रास्ते पर जाऊंगा और इस संस्था की जो सैंक्टिटी और जो सम्मान पहले बना रहा, वह बना रहे, उसके बारे में अगर जरूरत पड़ेगी तो दिल्ली से भी किसी से बात करनी पड़ेगी तो निश्चित रूप से बात करके इसका जो रास्ता है, वह निकालेंगे।

श्री अध्यक्ष: बहुत अच्छे। श्री घनश्याम महर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): I am on a point of clarification. अध्यक्ष महोदय, I am on a point of clarification. मुझे एक स्पष्टीकरण देना है।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट आप विराजिये।

स्पष्टीकरण

आर.पी.एम.टी. परीक्षा में हुई अनियमितता से अभ्यर्थियों में व्याप्त असंतोष

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी सदन में मैंने घोषणा की थी कि आर.पी.एम.टी. के सारे मामले की जांच मैं करवाऊंगा। अध्यक्ष महोदय, यह जो राजस्थान यूनिवर्सिटी आफ हैल्थ साइंसेज का जो एक्ट है 2005, उसमें 2013 में एक अमेंडमेंट हो गया था। इसकी जांच का अधिकार महामहिम राज्यपाल को है। मैं महामहिम राज्यपाल से निवेदन करूंगा कि इस सदन की भावना के अनुसार इस मामले की जांच करावें। इसलिए मैं स्पष्टीकरण दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: करेक्ट कर लिया आपने। घनश्याम जी।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

टोडाभीम में विद्युत लाइनें झूलने एवं ट्रांसफार्मर भूमि पर रखे होने से कारित दुर्घटनाएं

श्री घनश्याम (टोडाभीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र टोडाभीम में जो बिजली की समस्या है, उसको आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं। टोडाभीम विधान सभा क्षेत्र में बहुत सालों से जो बिजली के खम्भे और तार लगे हुए हैं, वे झूल-झूलकर नीचे तक आ गये हैं। उनसे आये-दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। दूसरी बात ट्रांसफार्मरों की है। ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद कई दिनों तक लोग आफिसों के चक्कर लगाते रहते हैं और उनको नियमित समय पर नहीं बदलते हैं। अगर बदलने की स्थिति जब बहुत दिनों बाद आती है तो अधिकारी कहते हैं कि ट्रोली लाओ और साधन लाओ, उसके बाद ही ये बदले जायेंगे। आये-दिन इस समस्या से बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। छह घंटे से ज्यादा बिजली नहीं दी जा रही है। बिजली की इस गर्मी में हालात ऐसे पैदा हो गये हैं कि आठ दिन से पूरे विधान सभा क्षेत्र में कभी दो घंटे, कभी एक घंटे, इस तरह बिजली आ रही है।

(श्री घनश्याम)

मैं मंत्री महोदय से भी कल मिला था। ट्रांसफार्मर जमीन पर रखे हुए हैं। कई जगहों की मैं मोबाइल पर फोटो खींचकर लाया और मैंने मंत्रीजी को बताया कि ये जमीन पर रखे हुए हैं, इनसे आये-दिन दुर्घटनाएं होती हैं। किसी की भैंस मर जाती है, किसी की बकरी मर जाती है। तो ट्रांसफार्मरों को नीचे नहीं रखा जाना चाहिये। अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में आये-दिन वहां दुर्घटनाएं होती हैं। तो इसे रोकने के लिये ट्रांसफार्मरों को ऊपर लगाया जाये।

दूसरी बात यह है कि जो लम्बी दूरी पर ट्रिपिंग हो जाती है और ट्रिपिंग होने से बिजली बार-बार जाने की समस्या रहती है। पुराने तारों को वहां जल्दी से जल्दी बदला जाये।

मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस समस्या से जल्दी से जल्दी छुटकारा दिलाया जाये।

श्री अध्यक्ष: नियम 295। श्री ओमप्रकाश हुडला। (व्यवधान) आप रेस्पांड कर रहे हैं?

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): हां, साहब। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने यह सही बात उठायी है कि जो तार झूल रहे हैं, यह अधिकांशत: राजस्थान की बहुत बड़ी समस्या है। हमने अभी जो फीडर सुधार कार्यक्रम शुरू किया है, जो आग्मेंटेशन कार्यक्रम, जिसके अन्दर हमारे पूरे डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम को स्ट्रेन्थन कर रहे हैं, ताकि 24 घंटे बिजली वह सहन कर सके। इसलिए निर्देश दिये गये हैं हर एक्स.ईएन. डिविजन को, उनको एक टाइम फ्रेम दिया गया है कि 30 सितम्बर तक राजस्थान में कोई भी शहर या ग्रामीण क्षेत्र में जो भी लूज वायर हैं, या तो उनको टाइट किया जायेगा। जहां पोल के बीच में गैप ज्यादा है, वहां पर पोल लगाया जायेगा, जिससे आपके झूलते हुए तार हैं और इससे जो एक्सिडेंट होते हैं, ये एक्सिडेंट्स नहीं हों।

जो दूसरी बात उठायी थी कि ट्रांसफार्मर्स जमीन पर रखे जा रहे हैं, इस पर जरूर उचित कार्यवाही की जायेगी because it is very dangerous and it will be very fatal too. जो जनता आस-पास निकलती है, बहुत भारी खतरा है। इसका अगर आपके पर्टिकुलर एरिये में कोई है, हाइलाइट कर सकें, मेरे को बतायें, उस पर तुरन्त कार्यवाही की जायेगी।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): एक निवेदन और है, अध्यक्ष महोदय। ट्रांसफार्मर जो जल जाते हैं, उनके लिये एक समय सीमा तय होनी चाहिये, इतने दिन में ट्रांसफार्मर बदले जाने चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आ गया। यह विषय कल भी आ गया, आज भी आ गया।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): इसका नहीं कहा कि ट्रांसफार्मर कितने दिन में बदले जायेंगे।

श्री अध्यक्ष: ऊर्जा मंत्रीजी इस बारे में गम्भीरता से कह रहे हैं।

श्री ओम प्रकाश।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी पर एक निवेदन करना चाहता हूं। इसी बिजली के विषय पर है। मंत्रीजी, मैं भी एक बार निवेदन कर दूं। मंत्रीजी, मैं एक निवेदन कर दूं, फिर साथ में उत्तर दे देना।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): सच्चाई यह है कि जहां पर चोरी कम हो रही है, वहां ट्रांसफार्मर की उपलब्धि में कोई प्राब्लम नहीं है। जहां चोरी बहुत ज्यादा हो रही है, वहां ट्रांसफार्मर्स ज्यादा जल रहे हैं और वहां हमें यह समस्या हो रही है। मैं माननीय विधायक महोदय से बोलूंगा कि कृपया हमारी मदद करके, चोरी पर रोकथाम लगाने में मदद करें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अध्यक्षजी, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले छह साल से फीडर सुधार कार्यक्रम चला और अभी भी तार ढीले हैं। यह, वास्तव में, वर्तमान मंत्रीजी धन्यवाद के पात्र हैं कि इन्होंने टाइम-बाउण्ड किया। पहले छह साल तक जो पैसा खर्च हुआ और हमारा दिवाला निकल गया, 15 हजार करोड़ से हम 75 हजार करोड़ रुपये के दिवाले पर चले गये और इस फीडर सुधार में हम लुटाते रहे, ठेकेदारों को पैसा देते रहे। उसकी भी थोड़ी जांच हो जाये तो किसानों पर बार-बार चोरी का आरोप लगता है, उस फीडर सुधार में कैसे लूटा माल, यह भी तो सामने आना चाहिये।

श्री अध्यक्ष: आपने अच्छा सुझाव दे दिया, धन्यवाद।

श्री घनश्याम (टोडाभीम): मंत्री महोदय ने कहा है कि ट्रांसफार्मर चोरी हो जाते हैं; अध्यक्ष महोदय, आम जनता का चोरी से कोई वास्ता नहीं है। जो चोरी करते हैं, उनके खिलाफ एफ आई आर दर्ज करायें, उन्हें जेलों में बंद कराओ। गरीब जनता और किसान उसके लिये क्यों परेशान हों? चोरी वाली बात के लिये कह रहा हूं मैं तो। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): एक मिनट दे दो, अध्यक्ष महोदय। आप महान है, आपका बड़ा दिल है। एक बार।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, सचेतक हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से कहना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि किसान या जो भी चोरी करता है, उसके ऊपर आप बतायें तो करें, तो जो फीडर सुधार या ट्रांसफार्मर खरीद रहे हों या जो भी सामान खरीद रहे हों, इस पर जो चोरी हो रही है, घपला हो रहा है, उसकी भी जांच कराओ। थोड़ा सदन को आश्वस्त करो कि हम जांच करायेंगे।

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): कैसे? आप बताइये मेरे को। आप मुझे बता दीजिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): पर्टिकुलर केस बता दूं। आपकी सी.एम.डी. की खुद की फैक्टरी है और वहां से बाध्य करके ट्रांसफार्मर लिये जा रहे हैं। वहां से बाध्य करके सामान लिया जा रहा है। उसकी भी तो जांच कराओ।

श्री अध्यक्ष: अब आप विराजिये। श्री ओम प्रकाशजी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

महुवा में राजकीय महाविद्यालय खोला जाना

श्री ओमप्रकाश (महुवा): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र महुवा में राजकीय महाविद्यालय नहीं खोलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में माननीय शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: आपने जो दिया है, लिखा हुआ, वही पढ़िये। भाषण नहीं।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): जैसा कि सर्व-विदित है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र महुआ काफी बड़ा क्षेत्र है। इसमें करीब 47 ग्राम पंचायतों के 150 से ज्यादा गांव आते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आज तक एक भी राजकीय महाविद्यालय नहीं खुला है। पूरे विधान सभा क्षेत्र के पढ़ने वाले छात्र और छात्राओं को बारहवीं की परीक्षा पास करने के बाद 65 किलोमीटर दूर दौसा या 120 किलोमीटर दूर जयपुर में आगे की पढ़ाई करने के लिए आना पड़ता है।

(श्री ओमप्रकाश)

इस कारण मेरे क्षेत्र में रह रहे गरीब मजदूर और किसान अपने बच्चे को, खासकर उनकी लड़कियों को आगे की पढ़ाई नहीं करा पाते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र महुआ के अन्दर प्राइवेट कालेज तो हैं लेकिन वे क्षेत्र की जनता से भारी भरकम फीस वसूलते हैं। इस कारण से गरीब आदमी अपने बच्चों को इन कालेजों में भी नहीं पढ़ा सकता है।

मेरा विधान सभा क्षेत्र शिक्षा के मामले में काफी पिछड़ा हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र महुआ में पिछले दो साल से पी पी पी मोड योजनान्तर्गत एक बिल्डिंग भी बनी हुई है। यदि सरकार चाहे तो उस भवन को अपने अधीन कर वहां राजकीय महाविद्यालय खोल सकती है। मेरे क्षेत्र में राजकीय महाविद्यालय खुलवाने के लिए क्षेत्र के दानदाता भी सरकार का सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

अतः इस अत्यन्त ही महत्वपूर्ण एवं जन हित के मुद्दे पर मैं आदरणीया मुख्य मंत्रीजी एवं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि जन हित में मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा में शिक्षा के क्षेत्र में आ रही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एक राजकीय महाविद्यालय खोलने की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री बालूराम चौधरी।

(13.00 बजे)

सहाड़ा में खनन कम्पनी जिन्दल शा लिमिटेड, भीलवाड़ा द्वारा एम ओ यू का उल्लंघन

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव के जरिये निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषय में निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में जिंदल शा लिमिटेड, भीलवाड़ा को सरकार द्वारा खनन के लिए आबंटित लीज में सरकार से जो एम.ओ.यू. साइन किया गया है, जिंदल शा लिमिटेड उन शर्तों की पालना न करते हुए मनमर्जी से कार्य कर रही है, जिनकी समय-समय पर शिकायत करने के बाद भी प्रशासन द्वारा कोई अपेक्षित कार्यवाही नहीं की गई है।

(श्री बालू राम चौधरी)

अध्यक्ष महोदय, अनुबन्ध में आसपास की पंचायतों की चरागाह की भूमि जो अवाप्त की गयी, इसके एवज में उतनी ही जमीन खरीद कर ग्राम पंचायत को उपलब्ध करायी जानी थी, जिसकी अनुपालना जिंदल शा लिमिटेड ने नहीं की है। फिर भी पिछली कांग्रेस सरकार द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया एवं कम्पनी से मिलीभगत कर अभी तक ग्राम पंचायत को जमीन उपलब्ध नहीं करायी है जिससे गांव के मवेशियों को चरने की कोई जगह नहीं बची है। वहां की जनता और मवेशी के बीच हाहाकार मचा हुआ है।

यहां यह उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के अनुसार किसी भी तालाब, नदी, नाले के बहाव क्षेत्र को बाधित नहीं किया जा सकता है; जबकि जिंदल शा लिमिटेड प्रशासन ने गांव के तालाब के कैचमेंट एरिया को मिट्टी डाल कर रोक दिया है एवं वहां डम्पिंग यार्ड बना दिया है जिससे तालाब में पानी आना रुक गया है। गांव वालों की शिकायत पर भी प्रशासन कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की श्रेणी में आता है।

जिंदल शा लिमिटेड के प्लांट के केमिकल बाइप्रोडक्ट सीधे जमीन में जाकर गांवों के कुओं को प्रदूषित कर रहे हैं एवं गांव के कुओं का पानी पीने-योग्य नहीं रहा है।

एम.ओ.यू. में आसपास की पंचायतें, जिनकी जमीन माइन्स के लिए अधिग्रहीत की गयी हैं, उन गांवों के युवाओं को जिंदल शा लिमिटेड में रोजगार दिया जाएगा, परन्तु आसपास की पंचायतों के युवाओं को किसी तरह का रोजगार नहीं दिया गया।

अनुबन्ध में यह भी कहा गया है कि जिस पंचायत की जमीन अधिग्रहीत की गयी है, उस ग्राम पंचायत के विकास के लिए कम्पनी समय-समय पर रेगुलर बेसिस पर आर्थिक सहयोग कर गांव के विकास में योगदान करेगी, लेकिन जिंदल शा लिमिटेड इस वादे से भी मुकर गई है एवं पंचायतों के विकास में किसी प्रकार का योगदान नहीं कर रही है।

अत: खान मंत्री से अनुरोध है कि कम्पनी शर्तो एवं अनुबन्धों की अवहेलना कर रही है। इसलिए इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवायी जाए ताकि वहां की जनता और पशुधन को तकलीफों से राहत और न्याय मिल सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री हरिसिंह रावत।

भीम की समस्त ग्राम पंचायतों में राशन कार्डों का शीघ्र दुरुस्तीकरण व वितरण

श्री हरिसिंह रावत (भीम): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के माध्यम से मेरे विधान सभा क्षेत्र भीम के सभी ग्राम पंचायतों एवं देवगढ़ नगरपालिका में बी.पी.एल. एवं सभी ए.पी.एल. के राशन कार्ड पिछले तीन माह से दुरुस्तीकरण हेतु जिला रसद अधिकारी कार्यालय में पड़े होने के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पिछले कई वर्षों से नवीन राशन कार्ड नहीं बनाये गये, जिसकी वजह से सभी राशन कार्ड धारियों को किसी भी प्रकार का राशन एवं अन्य सामग्री नहीं मिल रही थी और जब तीन माह पहले राशन कार्ड वितरित किये गये तो वे सभी अशुद्ध पाये गये। जब हमने शिकायत की तो वे अशुद्ध राशन कार्ड जिला रसद अधिकारी, राजसमंद के पास शुद्धिकरण हेतु भेज दिये गये, लेकिन अफसोस है कि वे त्रुटिपूर्ण राशन कार्ड अभी तक उपभोक्ताओं को शुद्धिकरण करा कर वापस मुहैया नहीं कराये गये, जिसकी वजह से मेरे विधान सभा क्षेत्र के सभी उपभोक्ता राशन एवं अन्य सामग्री से वंचित रह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जिला रसद विभाग को तत्काल निर्देशित कर अशुद्ध राशन कार्डों को शुद्ध करा कर जल्द से जल्द राशन कार्ड वितरण करावें एवं जिस किसी एन.जी.ओ. के अप्रशिक्षित कर्मचारियों की वजह से उपभोक्ता को परेशानी का सामना करना पड़ा है, इसके लिए सम्बन्धित एन.जी.ओ. को अर्थदण्ड देने की कार्यवाही करावें ताकि निकट भविष्य में उपभोक्ताओं को इस प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण सिंह देवल।

अध्यक्ष, जालोर-सिरोही दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, रानीवाड़ा व आर सी डी एफ जयपुर द्वारा कारित कथित अनियमितताएं

श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के तहत जालोर-सिरोही दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, रानीवाड़ा ...(व्यवधान) अध्यक्ष, आर सी

(श्री नारायण सिंह देवल)

डी एफ, जयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के क्रम में निवेदन करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, जालोर-सिरोही दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, रानीवाड़ा आर सी डी एफ, जयपुर के चेयरमैन के पद पर कार्यरत हैं जिन्होंने अपने पद का पूर्ण दुरुपयोग किया है। श्री बालोत रानीवाड़ा संचालक मण्डल के निर्वाचित अध्यक्ष हैं तथा उक्त संघ के प्रतिनिधि की हैसियत से निर्वाचित होकर राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर के संचालक मण्डल के अध्यक्ष पद पर आसीन हैं। उन्होंने दिनांक 20.03.2013 को रानीवाड़ा के संचालक मण्डल की एक बैठक आहूत की जिसमें संचालन मण्डल द्वारा उक्त बैठक प्रस्ताव संख्या 09 में यह निर्णय लिया गया कि संघ की स्वीकृत स्ट्रेन्थ में उप प्रबन्धक स्तर तक पदोन्नति के 100 प्रतिशत रिक्त पद आन्तरिक भर्ती प्रक्रिया से भरे जावें। परन्तु उक्त निर्णय जो प्रबन्ध निदेशक एवं बालोत के संयुक्त हस्ताक्षरों से जारी किया गया, उसमें हेराफेरी कर, लिया गया कि संघ के स्वीकृत स्टाफ में उप प्रबन्धक स्तर तक के 100 प्रतिशत रिक्त पद आन्तरिक भर्ती प्रक्रिया से भरे जावें। यह हेराफेरी अध्यक्ष, बालोत द्वारा निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु फर्जीकारी कर की गई है, जबकि वास्तविकता में, स्वीकृत स्ट्रेन्थ में, उप प्रबन्धक स्तर तक पदोन्नति के 100 प्रतिशत रिक्त पद आन्तरिक भर्ती प्रक्रिया से भरे जावें, ऐसा ही निर्णय लिया गया था।

जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, उनकी शिकायत पर रजिस्ट्रार, सहकारी समिति, जयपुर, श्री अनुराग भारद्वाज द्वारा जांच कर दिनांक 19.05.2014 का आदेश पारित कर आदेशित किया गया कि संघ के अध्यक्ष, बालोत द्वारा रिकार्ड में हेराफेरी की गई है, जिसके लिए वे दोषी हैं तथा इस हेतु उनके विरुद्ध कार्यवाही की जावे। सहकारी समितियां के अधिनियम की धारा 30 में प्रावधान है कि किसी सहकारी समिति का कोई भी सदस्य यदि ऐसा कार्य करता है, जिसमें समिति का सदस्य अपने कृत्यों को समुचित रूप से निर्वहन नहीं करता है, तो रजिस्ट्रार ऐसे सदस्य को उसे सुनवाई का मौका देकर हटा सकेगा। परन्तु विडम्बना है कि आज दिनांक तक इस प्रकार षड्यंत्र रच कर, रिकार्ड में हेराफेरी कर, पद का दुरुपयोग करने वाले व्यक्ति, जो भारतीय प्रशासनिक स्तर के अधिकारी की जांच में स्पष्ट रूप से दोषी पाया गया हो, के

(श्री नारायण सिंह देवल)

विरुद्ध विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर पाया है। चेयरमैन के उक्त कृत्य के विरुद्ध पुलिस थाना रानीवाड़ा में मुकदमा भी दर्ज है। इस प्रकार के कृत्य की समाचार पत्रों में सुर्खियों से विभाग की छवि खराब हो रही है।

मेरा सरकार एवं विभागाधिकारियों से इस विशेष उल्लेख के माध्यम से यह निवेदन है कि अधिनियम की धारा 30 के तहत उक्त सेवा के पद से कृत्य के आधार पर अयोग्य घोषित करते हुए, तत्काल पद से हटाकर रानीवाड़ा की सहकारिता की मूल भावना में विश्वास करने वाली जनता को न्याय प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री सुशील कटारा।

चौरासी के ग्रामों को कडाणा बांध का बैकवाटर उपलब्ध कराया जाना

श्री सुशील कटारा (चौरासी): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि गुजरात के कडाणा बांध के बैकवाटर का पानी राजस्थान की लाखों हैक्टेयर भूमि पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन इसका लाभ चौरासी विधान सभा एवं राजस्थान की जनता को नहीं मिल रहा है। इस जल का उपयोग न ही पेयजल एवं न ही सिंचाई हेतु, कुछ लिफ्टों को छोड़कर, किया जा रहा है। पानी इतना अधिक है कि इसका उपयोग पीने एवं कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। उक्त पानी का उपयोग गुजरात सरकार भी नर्मदा बांध परियोजना बन जाने के कारण नहीं कर पा रही है। गुजरात सरकार ने पेयजल हेतु बड़ी-बड़ी लिफ्टें लगाकर जिला अरावली एवं पंचमहल में तथा अन्य कई जिलों में कडाणा के पानी का लाभ लेकर जनता को राहत पहुंचाई है।

अतः हम भी हमारी धरती पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध इस जल को पीने एवं सिंचाई हेतु पंचायत समिति सीमलवाड़ा की निम्न ग्राम पंचायतों में पीने एवं कृषि कार्यों हेतु पूर्व में जनजाति परियोजना द्वारा लगायी छोटी लिफ्ट स्कीम के आधार पर बड़ी योजना बनाकर ग्राम पंचायत चिखली, जसेला, सालेड़ा, बावड़ी, बड़गामा, कोचरी, अम्बाड़ा, साकोदरा, गुन्दलारा, डूंगर, धनगांव, कुआं, सेण्डोला, दरियाटी, माला खोलडा, धोधरा, बोडमली, जोरावरपुरा,

(श्री सुशील कटारा)

डूंगरसारण, नई बाती बडगामा, पुनावाडा, गडामेडतिया, कसारिया, बाबाकि बार, नादिया, चितरी, बडगी, गलियाकोट, रातडिया, गरियाता, डुका, भचडिया, राममौर जुना, बांकडा, आदि ग्राम पंचायतों में इस पानी को लाने का प्रयास कर सकते हैं जिससे चौरासी एवं सागवाड़ा की लाखों की तादाद में जनता पेयजल एवं कृषि कार्यों हेतु पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध जल को प्राप्त कर सकती है। गुजरात सरकार द्वारा 35 करोड़ की योजना से गुजरात की जनता को पेयजल हेतु प्रचुर मात्रा में पानी उपलब्ध कराया जा रहा है।

अत: माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि राजस्थान की हजारों ह हैक्टेयर भूमि पर उपलब्ध पानी को राजस्थान की सरकार द्वारा जनता को पीने एवं सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की आशा से उक्त पानी का लाभ उन्हें आवश्यक रूप से दिलावें एवं बड़ी योजना व फिल्टर प्लांट लगाकर लोगों को राहत प्रदान करावें।

श्री अध्यक्ष: श्री नवनीत लाल नीनामा।

घाटोल में ग्राम पंचायतों बड़ाना-बामनपाड़ा के मध्य सड़क निर्माण

श्री नवनीत लाल (घाटोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र घाटोल में ग्राम पंचायत बड़ाना से ग्राम पंचायत बामनपाड़ा के बीच 4 किलोमीटर की सड़क का निर्माण करने से-

1. पंचायत बड़ाना की जनसंख्या	6,066
2. पंचायत बामनपाड़ा की जनसंख्या	4,423
3. पंचायत पड़ोली राठोड़ की जनसंख्या	4,786
4. पंचायत पड़ोली गोरधन की जनसंख्या	7,552
योग	**22,827**

4 ग्राम पंचायतों के 14 गावों की 22,827 जनसंख्या को आवागमन की सुविधा होगी।

अत: प्रस्ताव प्रस्तुत कर आग्रह है कि उक्त विवरण की ग्राम पंचायतों की ग्रामीण जनता को आवागमन हेतु, जानकारी करा, ग्राम पंचायत बड़ाना से ग्राम पंचायत बामनपाड़ा के हैड-क्वार्टरों को जोड़ने पर ग्राम पंचायत

(श्री नवनीत लाल)

बड़ाना, बामनपाड़ा, पड़ोली राठोड़, पड़ोली गोरधन मोग की 4 ग्राम पंचायतों के 14 गांवों की 22,827 आबादी को आवागमन की सुविधा होगी। इसी आशा व विश्वास के साथ प्रस्ताव प्रस्तुत है। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमराराम चौधरी।

बालोतरा को जनभावना के मद्देनजर नया जिला बनाया जाना

श्री अमराराम (पचपदरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के तहत निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के शहर बालोतरा की जनसंख्या एवं भौगोलिक स्थिति को मद्देनजर रखते हुए इसे जिला घोषित किया जाये।

मान्यवर, मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूं उसका एक प्राचीन इतिहास है। मेरे विधान सभा क्षेत्र का नाम वर्तमान में पचपदरा है लेकिन भौगोलिक नक्शे अनुसार पुराना नाम पचभदरा था। कालांतर में धीरे-धीरे इसको पचपदरा कर दिया गया। संस्कृत में भद्र का नाम नदी से है, जहां पर 5 नदियों का संगम होता था।

पचपदरा क्षेत्र बाड़मेर जिले का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है, जहां बालोतरा सब-डिविजनल मुख्यालय है तथा इसके साथ में बालोतरा में जिला एवं सत्र न्यायालय भी है। आजादी के पूर्व और उसके पश्चात् 1974 तक बालोतरा जिला एवं सत्र न्यायालय जालोर जिले का भी था। वर्ष 1973 से पहले जालोर में अतिरिक्त जिला न्यायालय था तथा बाड़मेर में भी अतिरिक्त न्यायालय 1973 के बाद में बना था।

बाड़मेर जिला भौगोलिक दृष्टि से एक विशाल जिला है जिसका क्षेत्रफल 28 हजार वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। यह राजस्थान प्रदेश का दूसरा बड़ा जिला है।

बाड़मेर जिला इतना विशाल होने के कारण, भौगोलिक व प्रशासनिक दृष्टि से पूरे जिले की समस्याओं का आसानी से एक जिला कलक्टर के द्वारा समाधान करना अत्यन्त कठिन है। जिला मुख्यालय से बाड़मेर जिले के गांव सामूजा, बलाऊ जाटी और काठाडी, आदि 200 किलोमीटर से भी अधिक दूरी पर हैं। इन गांवों से जोधपुर, जालोर एवं पाली बहुत नजदीक हैं, लेकिन बाड़मेर अत्यन्त दूर है। राजस्थान प्रदेश में बाड़मेर जिले से कई छोटे-छोटे जिलों को दो भागों में विभाजित कर नये जिले बनाये गये हैं, जिनमें से कई जिलों का

(श्री अमराराम)

क्षेत्रफल 5-6 हजार वर्ग किलोमीटर से कम है। उदाहरण के लिए हनुमानगढ़, दौसा, करौली, प्रतापगढ़, धौलपुर, आदि जिले हैं।

बालोतरा एक औद्योगिक कस्बा है, जहां अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, रीको का कार्यालय, जलदाय विभाग के अधिशासी अभियंता और सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता और केन्द्र सरकार के आयकर अधिकारी बैठते हैं। बालोतरा में बाड़मेर जिले के सत्र न्यायालय के अलावा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रैक का भी न्यायालय है। बालोतरा से जोधपुर करीब 105 किलोमीटर है जबकि बालोतरा से बाड़मेर 117 किलोमीटर दूरी पर है।

कई जन-प्रतिनिधियों द्वारा और कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा बालोतरा को जिला बनाने के लिए सन् 1980 के पूर्व से आज दिन तक मांग होती रही है। धार्मिक दृष्टि से भी नाकोड़ा ब्रह्मधाम, खेड़, तिलवाड़ा और रानी भटियाणी का मंदिर प्रसिद्ध है। तिलवाड़ा में हिन्दुस्तान का सबसे प्रसिद्ध पशुओं का मेला सैकड़ों वर्षो से लग रहा है, जहां मलाणी के घोड़े प्रसिद्ध हैं।

यह कि बालोतरा जिला बनाने के लिए तत्कालीन जिला कलक्टर, श्री मुकेश शर्मा द्वारा करीब 15 वर्ष पूर्व ही लूणी नदी के दक्षिणी किनारे पर 932 बीघा जमीन अवाप्त की जा चुकी थी और इसी आरक्षित जमीन पर मेगा हाइवे (रामजी के गोल से फलौदी) का उद्‌घाटन भी माननीय मुख्य मंत्री महोदया के कर-कमलों द्वारा हो चुका था। हाल ही में लोक सभा के चुनावों के दौरान इसी आरक्षित 932 बीघा भूमि में हमारे भारत के वर्तमान माननीय प्रधान मंत्रीजी की चुनावी सभा भी हुई थी और आम जनता की यही मांग थी कि जिस जगह मोदीजी ने प्रधान मंत्री बनने से पूर्व जनता को सम्बोधित किया, उसी स्थान पर एक सुंदर मिनी सचिवालय बने, उसी स्थान पर जिला कलक्टर बैठे और नवीन जिले के सारे कार्यालयों का मिनी सचिवालय बने।

मैं सरकार से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि उपरोक्त सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए बाड़मेर जैसे विशाल और महत्वपूर्ण जिले के दो जिले बनायें ताकि जनता द्वारा वर्षों से लगायी गयी आस पूरी हो सके। माननीय मोदीजी द्वारा प्रधान मंत्री बनने से पूर्व जिस स्थान पर क्षेत्र की 2.5 लाख जनता को सम्बोधित किया गया था, उसी स्थान पर जिला बालोतरा को नवीन जिला बनाकर कलक्टर को बैठाया जाये तो इस क्षेत्र की जनता सरकार की बहुत-बहुत आभारी रहेगी तथा विकास का एक नया इतिहास बनेगा। माननीय

(श्री अमराराम)

प्रधान मंत्री, श्री नरेन्द्र मोदीजी द्वारा जिस मंच से जनता को भारत के विकास करने की कल्पना प्रदान की गयी थी, उस कल्पना को साक्षात रूप में मूर्त रूप देने का हमारी सरकार पूरा प्रयास करेगी।

मैं यह अपेक्षा करता हूं कि बालोतरा की जनता की भावना को मद्देनजर रखते हुए बालोतरा को नया जिला बनाने के निर्देश फरमावें।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र सिंह यादव।

जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस संसाधनों की कमी

श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत में निवेदन करना चाहता हूं और राज्य सरकार एवं माननीय गृह मंत्रीजी का ध्यान जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस संसाधनों की भारी कमी की ओर इंगित करते हुए पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि कोटपूतली में एक नया सदर थाना खोला जाये तथा साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित किया जाये ताकि अपराधों पर अंकुश लग सके एवं आम जन में पुलिस के प्रति विश्वास जाग्रत हो सके।

जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की आबादी लगभग 30 लाख होने के बावजूद जयपुर शहर की तुलना में पुलिस विभाग में अधिकारियों/कर्मचारियों के पद बहुत ही कम मात्रा में सृजित हैं, न ही वाहन एवं अन्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये हुए हैं जिसके कारण असामाजिक तत्वों, भू-माफियाओं एवं आपराधिक प्रवृत्ति वाले बदमाशों पर शिकंजा कसना मुश्किल भरा कार्य है। जब हम जयपुर पुलिस कमिश्नरेट से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की तुलना करेंगे तो स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की आबादी कमिश्नरेट क्षेत्र के लगभग समान होते हुए भी संसाधनों के मामले में ग्रामीण क्षेत्र की अनदेखी की जा रही है। कमिश्नरेट में कुल थाने 62 हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 21 ही हैं। इसी प्रकार, कमिश्नरेट में कांस्टेबलों की कुल संख्या 8,000 के लगभग है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 1,400 ही हैं। यही स्थिति पुलिस विभाग के अन्य पदों की है, चाहे वह पुलिस अधीक्षक के पद हों या फिर पुलिस निरीक्षक या हैड कांस्टेबल्स के पद हों। वाहनों की अगर हम बात करें तो कमिश्नरेट में कुल वाहन 659 हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्र में मात्र 136 ही उपलब्ध कराये हुए हैं।

ऐसी स्थिति में, जनसंख्या लगभग समान होते हुए भी संसाधनों की

(श्री राजेन्द्र सिंह यादव)

दृष्टि से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र काफी पिछड़ा हुआ है। जबकि क्षेत्रफल के आधार पर हम देखेंगे तो जयपुर शहर से 20 गुणा अधिक एरिया कवर करने के साथ ही, अन्य जिलों की सीमाएं ग्रामीण क्षेत्र से लगी हुई है एवं हरियाणा राज्य की सीमा से भी यह क्षेत्र जुड़ा हुआ है। साथ ही, मेवात एरिया नजदीक होने से अपराधों की रोकथाम में पुलिस अधिकतर मामलों में नाकाम ही साबित होती है, हालत यह है कि विगत छह महीनों में ही 500 से अधिक एफ.आई.आर. कोटपूतली थाने में दर्ज हो चुकी हैं।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के मद्देनजर मैं राज्य सरकार एवं माननीय गृह मंत्रीजी से जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की जनता की ओर से मांग करता हूं कि कोटपूतली में एक नया सदर थाना खोला जाये एवं पुलिस कंट्रोल रूम स्थापित करने की आज ही घोषणा करें एवं ग्रामीण क्षेत्र में पुलिस विभाग में आवश्यकता एवं मानदण्डों के अनुरूप पद सृजित किये जायें व नये वाहन एवं अन्य संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराये जायें। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री अध्यक्ष: श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर)।

जहाजपुर में विद्युत उपकरणों की चोरियां व अनियमितताएं

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि राज्य सरकार द्वारा...

श्री अध्यक्ष: कहना नहीं, आपने जो कुछ लिखकर दिया है वह पढ़िये।

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ...सुराज संकल्प यात्रा के दौरान प्रत्येक नगर, ग्राम पंचायत, इत्यादि इकाइयों में 24 घण्टे घरेलू विद्युत आपूर्ति एवं 8 घण्टे कृषि विद्युत आपूर्ति की लम्बी-चौड़ी घोषणा की गई थी, किन्तु वर्तमान में राजस्थान में कहीं भी 24 घण्टे बिजली आपूर्ति नहीं की जा रही है एवं कृषि थ्री फेज में तो 8 घण्टे की अपेक्षा मात्र 3-4 घण्टे ही बिजली सप्लाई की जा रही है। वह भी बार-बार कटने से किसान का भारी नुकसान हो रहा है। खासकर जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में बिजली आपूर्ति, उपकरण आपूर्ति, ट्रांसफार्मर चोरी एवं ट्रांसफार्मर की आपूर्ति सहित कृषि व घरेलू कनेक्शनों में अनियमितता, धांधली व भ्रष्टाचार की इन्तहा हो चुकी है। जिला कलक्टर मजबूर होकर एम डी, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर को जहाजपुर सहायक अभियंता को निलम्बित करने की अनुशंसा भी कर चुके हैं।

(श्री धीरज गुर्जर)

मैं सदन के माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जहाजपुर में अघोषित बिजली कटौती के कारण उप-खण्ड मुख्यालय पर 10 से 12 घण्टे एवं ग्रामीण क्षेत्र में 7 से 8 घण्टे ही सिंगल फेज घरेलू आपूर्ति हो पा रही है एवं कृषि क्षेत्र में तो हालात और भी दयनीय हैं। विद्युत उपकरणों की आपूर्ति समय पर नहीं होने के कारण डिमांड जमा कराने के बाद भी छह-छह महीने तक कृषि कनेक्शन नहीं हो पा रहे हैं।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि जले हुए ट्रांसफार्मर तीन दिन में बदल दिये जायेंगे, जबकि एक-एक, दो-दो महीने में भी उक्त ट्रांसफार्मर नहीं बदले जा रहे हैं और इसके बदले भी खुले आम पांच-पांच हजार रुपये की रिश्वत ली जा रही है। इस स्थिति से किसान त्रस्त हो रहा है। मैं इस खुले भ्रष्टाचार की जांच की मांग करता हूं। साथ ही, चोरी हुए ट्रांसफार्मर की विद्युत विभाग रिपोर्ट नहीं लिखवाता है एवं आम किसान विभाग के चक्कर लगाता रहता है। अगर यही स्थिति चलती रही तो विद्युत आपूर्ति एवं भ्रष्टाचार के खिलाफ जहाजपुर विधान सभा क्षेत्र में आमजन एवं आम किसानों द्वारा भारी जन आंदोलन होगा जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी सरकार की होगी।

वर्तमान में लोड शेडिंग के नाम पर सायं 7 से 11 बजे तक जहाजपुर तहसील में अघोषित विद्युत कटौती की जा रही है। या तो इस कटौती की घोषणा करें अथवा जहाजपुर तहसील में विद्युत आपूर्ति बहाल हो। साथ ही, मंत्रीजी से निवेदन है कि जहाजपुर क्षेत्र अजमेर निगम क्षेत्र में आता है किन्तु आपूर्ति दूणी 220 के वी ग्रिड से होने के कारण तहसील जहाजपुर की विद्युत आपूर्ति काटी जाती है। लम्बे समय से मांग है कि जहाजपुर की आपूर्ति शाहपुरा-भीलवाड़ा से जोड़ दी जाये। इस हेतु विभाग का प्रस्ताव भी सरकार के पास आया हुआ है। कृपया आम जन को राहत देने के लिए विशेष कार्यवाही करें।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

राष्ट्रीय राजमार्ग 14 पर सांडेराव में ट्रोमा यूनिट की स्थापना

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर स्थित सांडेराव में ट्रोमा यूनिट खोलना आवश्यक है। इस मार्ग पर ब्यावर से पिंडवाड़ा

(श्री मदन राठौड़)

तक लगभग 240 किलोमीटर सड़क मार्ग पर इन दिनों निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण अधूरा है। सड़क पर सुरक्षा के पर्याप्त संकेतक भी नहीं हैं। जगह-जगह निर्माण सामग्री अव्यवस्थित पड़ी रहती है। कुछ मार्ग तो आने-जाने के लिए अलग-अलग हैं, जबकि कुछ मार्गों पर एक साइड की सड़क पर आमने-सामने, एक ही मार्ग पर दोहरा यातायात चलाया जा रहा है। ऐसी स्थिति में वाहन चालक भ्रमित हो जाता है और वाहन दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही हैं।

दुर्घटनाओं से लोग घायल हो जाते हैं लेकिन उक्त पूरे 240 किलोमीटर सड़क मार्ग पर चिकित्सा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। पाली से सिरोही के बीच 120 किलोमीटर क्षेत्र में गुन्दोज, सांडेराव, सुमेरपुर, शिवगंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तो हैं लेकिन उनमें भी इन घायलों को पर्याप्त चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है। इस मार्ग पर स्थित गुन्दोज, सांडेराव व सुमेरपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को अपग्रेड कर उनमें ट्रोमा यूनिट की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि दुर्घटनाग्रस्त घायलों की रक्षा की जा सके। उक्त मार्ग पर किसी दुर्घटनाग्रस्त नागरिक को स्थानीय स्तर पर यथा समय चिकित्सा के अभाव में गुजरात के पालनपुर या जोधपुर तक ले जाना पड़ता है। तब तक उक्त घायल की स्थिति गम्भीर हो जाती है एवं उसे बचा पाना असम्भव हो जाता है।

अत: गुन्दोज, सांडेराव व सुमेरपुर में ट्रोमा यूनिट स्थापित की जावें। साथ ही, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 पर 'चल चिकित्सा इकाई' प्रारम्भ करवानी चाहिए जो 'आन-काल' तत्काल राहत पहुंचा सके।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमसा मेघवाल।

जाजिवाल कलां ग्राम पंचायत (भोपालगढ़) में उच्च जलाशय का निर्माण कार्य

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ की ग्राम पंचायत जाजिवाल कलां में तीन-चार साल से उच्च जलाशय (एस.आर.) का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। उक्त ग्राम के नजदीक ही सेना का एरिया होने के कारण कार्य बंद पड़ा है। सैन्य विभाग की अड़चनों के कारण पानी की

(श्रीमती कमसा)

टंकी का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा है जिसके कारण दस से पन्द्रह ग्राम पंचायतों में पानी की भारी किल्लत उत्पन्न हो रही है।

अत:, माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सम्बन्धित विभाग को निर्देशित कर, उक्त कार्य को शीघ्र पूर्ण करवाकर, समस्त ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करवाने का श्रम करें।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

(अनुपस्थित)

श्री मान सिंह गंगापुर सिटी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

गंगापुर सिटी में पेयजल की अव्यवस्था

श्री मान सिंह (गंगापुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र का गंगापुर सिटी शहर, जो करीब 1 लाख 60 हजार की आबादी का शहर है, उसमें कम से कम डेढ़ लाख लीटर पानी पर-डे की आवश्यकता है और हमारे पास, सरकार के पास उपलब्धता केवल पैंतालीस हजार लीटर की है। ऐसी स्थिति में, पानी की भारी किल्लत शहर के अन्दर है और जिस प्रकार से शहर में पुरानी लाइनें बिछी हुई हैं, वे 1968 की बिछी हुई हैं। इस समय उन लाइनों में गटर का पानी कभी-कभी मिल जाता है और इतनी भारी समस्या है कि जगह-जगह शहर में इस बात की बिलकुल विकट समस्या है।

इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि गंगापुर शहर की पेयजल व्यवस्था, जिसका पूर्णत: निदान चम्बल का पानी आने पर ही हो सकेगा, लेकिन किस प्रकार की अनियमितताएं रही हैं। अभी गर्मी के समय में पूरे राजस्थान में टैंकरों की व्यवस्था की गई, लेकिन गंगापुर के अन्दर टैंकरों की व्यवस्था इसलिए नहीं हुई कि वहां पर जिस पी एच ई डी के एक्स ईएन को बिठाया था, उस एक्स ईएन के पास में किसी प्रकार के पावर नहीं होने से उसने टेण्डर नहीं किये। सवाई माधोपुर जिला हैडक्वार्टर पर बैठने वाले एक्स ईएन ने इसलिए टेण्डर नहीं किये कि वह एक्स ईएन कहता है कि वह दूसरा है। ऐसी स्थिति में, 24 जून तक वहां टेण्डर की प्रक्रिया शुरू नहीं हो

(श्री मान सिंह)

पायी और पानी के टैंकर जनता को नहीं मिल पाने के कारण पानी की समस्या बनी हुई है। पिछली सरकार ने जो एक्स ईएन बिठाया था, उस एक्स ईएन को कोई पावर नहीं मिलने के कारण, उसके दफ्तर की व्यवस्था नहीं होने के कारण, टैंकरों की व्यवस्था में देरी हुई।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि गंगापुर के लिए विशेष गंगापुर-नादौती-सवाई माधोपुर की वृहद् परियोजना है, चम्बल परियोजना है, उस चम्बल परियोजना के बारे में सरकार से आग्रह करना चाहूंगा कि पिछले 5 साल से जिस धीमी गति से इसका कार्य हो रहा है और यह कहना चाहिए कि इंटेक वेल का कार्य तो बिलकुल ठप पडा हुआ है। 5 साल तक इंटेक वेल पर कोई काम इसलिए नहीं हुआ कि सरकार ने आवश्यक राशि का भुगतान उसके अन्दर नहीं किया और आवश्यक राशि का भुगतान नहीं करने के कारण, वह चम्बल का पानी गंगापुर की जनता को जो 2014 में मिल जाना चाहिए था, आज भी ऐसी स्थिति है कि 2016 तक मिल जाये तो हम अपने आपको धन्य मानेंगे।

माननीय जल संसाधन मंत्रीजी यहां उपस्थित हैं, मैं उनसे अनुरोध करना चाहूंगा कि जिस एस पी एम एल कंपनी को ठेका दे रखा है, उस एस पी एम एल कंपनी को ताकीद किया जाय कि गंगापुर तक लाइन का काम पूरा हो चुका है, वहां पर पूरा का पूरा गंगापुर में पम्प हाउस बनना है, वह पम्प हाउस पूरा है, केवल इंटेक वेल जो पिछले 5 साल से बंद पड़ा था और अभी भरतपुर सम्भाग में सरकार गयी, माननीया मुख्य मंत्रीजी से हमने अनुरोध किया और माननीया मुख्य मंत्रीजी के निर्देश पर वहां इंटेक वेल का काम शुरू हुआ, जो अभी तक केवल 9 मीटर बना है। अगर इंटेक वेल के काम में थोड़ी तेजी लायी जाय तो निश्चित रूप से गंगापुर की जनता को 2016 के अन्दर पानी मिल सकेगा; उससे शहर ही नहीं, गंगापुर के 113 गांवों को पानी मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारी इस पानी की व्यवस्था के लिए शहर में 3 किलोमीटर लाइन परिवर्तन के आप आदेश प्रदान करें; वहां के एक्स ईएन को पावरफुल बनाएं; उसको संसाधन देकर वहां की जो व्यवस्था है, चाहे वह वजीरपुर हो, चाहे गंगापुर हो, उनकी व्यवस्था को दुरुस्त करने का काम करें। यह मेरा अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी।

श्री मान सिंह (गंगापुर): मंत्रीजी को रेस्पोंड करने दो, साहब।

श्री अध्यक्ष: आप रेस्पोंड कर रहे हैं?

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की चिन्ता वास्तव में स्वाभाविक है। इस योजना को बहुत लम्बा समय हो गया है और गत 5 साल का जो राज का समय निकला है...

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): मालूम है, बैठ जाओ ना। सुनने की क्षमता नहीं है क्या? ज्यादा हो रहे हों क्या? पहली बार आये हों विधान सभा में। ज्यादा बोलना सीख रहे हों। पता नहीं क्या बोल रहे हों?

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): आप इनको लोक सभा में मंत्री बना दो। (व्यवधान)

श्री मान सिंह (गंगापुर): अध्यक्ष महोदय, इनके कांग्रेस के अध्यक्ष इनके सामने खड़े हुए थे, उनकी हार को ये नहीं पचा पा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर): ×××

श्री धीरज गुर्जर (जहाजपुर): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री हीरालाल (निवाई): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बार-बार व्यवधान करके नान-इश्यू को इश्यू बना रहे हैं। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, गंगापुर सिटी के अन्दर पाइपलाइन की आवश्यकता होगी, वह उपलब्ध कराकर लोगों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। (व्यवधान) वह कार्य होने के बाद पानी की व्यवस्था ठीक हो जाएगी। यही मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): बार-बार व्यवधान करना, नान-

(श्री सांवर लाल)

इश्यू को इश्यू बनाना, इनका काम है। (व्यवधान) ये सदन का समय जाया कर रहे हैं। राजस्थान की जनता देख रही है। राजस्थान की जनता ने 163 सीटें दी हैं। (व्यवधान) ये इतनी कम संख्या में आये हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है।

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): ×××

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नेता, प्रतिपक्ष): ×××

श्री मान सिंह (गंगापुर): ×××

श्री सांवर लाल (जल संसाधन मंत्री): इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री केसाराम चौधरी। (व्यवधान) आप बैठिए। हाउस आर्डर में आ गया है। केसारामजी बोलेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): आन ए पाइंट आफ आर्डर सर।

श्री अध्यक्ष: विराजिए। पाइंट आफ आर्डर है।

व्यवस्था का प्रश्न

किसी विषय पर अध्यक्ष की व्यवस्था पश्चात् उसे सदन में पुन: उठाना नियम व परम्परा विरुद्ध

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न इस मुद्दे पर उठा रहा हूं कि माननीय सांवर लालजी के बारे में विपक्ष के नेता ने यह मुद्दा आपके समक्ष पहले भी उठाया, आपकी रूलिंग भी इसमें हो गई, रूलिंग के बाद स्पष्टीकरण हो गया। उसके बाद विपक्ष के नेता, मय अपनी पार्टी के प्रमुख लोगों के, जिनमें पूर्व मुख्य मंत्री भी थे, गवर्नर महोदय से भी मिल लिये और गवर्नर महोदय ने प्रकरण एडवोकेट जनरल को भी भेज दिया कानूनी सलाह के लिए। जब यह प्रकरण उठ चुका और वापस राज्यपाल महोदय की परिधि में है। जब आपने डिस्पोजल कर दिया तो वापस इस मुद्दे को बार-बार उठाने की कोई व्यवस्था इस सदन में नहीं है।

इसलिए विपक्ष के नेता से मेरा नम्र निवेदन होगा कि यह वैधानिक

(श्री मानिक चन्द सुराना)

प्रश्न है और यदि आप यह महसूस करते हैं कि सांवर लालजी जाट सदस्य नहीं है और अब 11 मंत्री रह गये हैं तो यह राजस्थान हाई कोर्ट खुला पड़ा है, आप रिट दायर करिए और हाई कोर्ट का फैसला आ जाएगा व सरकार को जो भी उसमें करना होगा, करेगी।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ×××

व्यवस्था

अध्यक्ष की व्यवस्था नियमान्तर्गत व सदन के निर्बाध संचालन के दृष्टिकोण से अंतिम

श्री अध्यक्ष: आप विराजिए। मुझे रूलिंग देनी है, आब्जेक्शन आया है। (व्यवधान) आप बैठिए। (व्यवधान) नहीं होगा आपका। (व्यवधान) आपका नहीं होगा।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): ×××

श्री अध्यक्ष: आप बैठिए। एक मिनट। नहीं होगा आपका। आपका नहीं होगा। बैठिए। मैं पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था दे रहा हूं, आप बैठ जाइये। मैं पाइंट आफ आर्डर पर व्यवस्था दे रहा हूं। यह क्या मतलब है? बैठ जाइये। यह क्या मतलब है कि जब चाहो, तब उठ जाओ? यह सदन है या आपके घर की दुकान है? आइंदा आप खड़े होंगे तो इनका एक शब्द नोट नहीं किया जाए; जो भी हनुमान बेनीवाल बोलें, उसको नोट नहीं किया जाए। आप बैठ जाइये। मैं कह रहा हूं कि बैठ जाइये। (व्यवधान) बैठ जाइये। यह क्या है? जैसे नीचे स्प्रिंग लग रही हो, जब चाहे तब खड़े हो जाएं। (व्यवधान)

लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण औचित्य का प्रश्न उठाया है और उनकी जो भावना है, उस भावना के अनुरूप मैंने तीन बार रूलिंग दे दी है। मुझे अफसोस है कि हमारी विधान सभा जिन नियमों के अन्तर्गत चलती है, उसमें स्पीकर की रूलिंग को फाइनल माना जाता है और फाइनल माने जाने के साथ ही अगर व्यवस्था ठीक चलानी है, हाउस को आर्डर में चलाना है तो इन नियमों का पालन करना चाहिए। मैं लूणकरणसर से आने वाले माननीय विधायक का औचित्य प्रश्न स्वीकार करता हूं और प्रतिपक्ष से निवेदन करता हूं कि वे अब इस विषय को इस विधान

(श्री अध्यक्ष)

सभा में नहीं उठायेंगे, अन्यथा मुझे आगे कार्यवाही करनी पड़ेगी। (व्यवधान) बैठ जाओ। बैठ जाओ आप। मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा इस हाउस को ठीक चलाने के लिए। इसको सब्जी मण्डी नहीं बनने दूंगा। चार बार मैं रूलिंग दे चुका हूं और बार-बार वही प्रश्न।

सांवर लाल मान्यता प्राप्त विधायक थे, जिस रोज ओथ ली उस रोज, और उसके बाद लगातार मंत्रिमण्डल के 12 सदस्यों की टीम में हैं। उनको मान्यता दे दी गई, शुरू से दे दी गई। अगर आपको बायकाट करना होता है तो आते ही क्यों हों आप? बार-बार आप इसको उठा रहे हैं। यह सारे हाउस को चलने नहीं दिया जा रहा है। अब सांवर लालजी के बारे में कोई कुछ भी बोले, एक शब्द भी अंकित नहीं होगा।

केसारामजी चौधरी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

जाड़न ग्राम (मारवाड़ जंक्शन) से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 पर अण्डरब्रिज का निर्माण

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव जाड़न के बीचों-बीच से गुजर रहा है और उसके बीच में से गुजरने से वहां ऐसी परिस्थिति हो गई है कि गांव दो पार्ट में बंट गया है।

इसलिए उसमें आये-दिन एक्सिडेंट हो रहे हैं। अभी 6 जुलाई को भी एक ओमप्रकाश हीरागर की मौत हो गई, उसकी वजह से रोड जाम हुआ और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

उस गांव के बीच में एक अण्डरब्रिज देने की व्यवस्था है। कलक्टर और सब ने माना है कि गांव जो दो भागों में बंट गया है, एक तरफ का आधा गांव इधर है और पानी की टंकी, स्कूल, श्मशान दूसरी तरफ हैं, जिससे हर टाइम लोगों को उस सड़क को क्रास करना पड़ता है। स्कूल के बच्चों का कई बार इसके पहले भी एक्सिडेंट हो चुका है।

इसलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत निवेदन करना चाह रहा हूं कि वहां पर जो अण्डरब्रिज स्वीकृत है, उसको तुरन्त प्रभाव से बनाया जाए और उसके दोनों तरफ जो सर्विस रोड अधूरी हैं, उनको तुरन्त

(श्री केसाराम चौधरी)

प्रभाव से पूरा किया जाए; उसके साइड में पानी के लिए नाले बनाने हैं, वे भी बनवाये जाएं। रात को मारवाड़ जंक्शन क्षेत्र और पूरे पाली जिले में जोरदार बारिश हुई है, उसकी वजह से पानी भर गया है और उस पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। ऐसी सूरत में उस गांव के दोनों तरफ आने-जाने के लिए अण्डरब्रिज की आवश्यकता है।

इसी के आगे, मारवाड़ जंक्शन को जाने वाले स्टेट हाइवे 61 नम्बर पर भी पाली से 20 किलोमीटर, सोजत से 20 किलोमीटर, मारवाड़ जंक्शन से 20 किलोमीटर और सरदारसमन्द से 20 किलोमीटर का चौराहा पड़ता है। उस चौराहे पर ओवरब्रिज तो बना है मगर उस ओवरब्रिज की हाइट बहुत कम ली है जिससे जो ट्रक जाते हैं और उनमें जो लाइटें लगी हैं, वे टूट चुकी हैं। आने वाले समय में मारवाड़ जंक्शन में कोरिडोर का कंटेनर डिपो बनने जा रहा है और उस कंटेनर डिपो की वजह से, जोधपुर से कंटेनर सीधे मारवाड़ जंक्शन ट्रकों के द्वारा आयेंगे। तो उस कंटेनर के भरे हुए ट्रक उस पुल से क्रास नहीं हो सकेंगे। इसलिए उस पुल को भी बड़ा किया जाए।

साथ ही, इस रोड के किनारे जाड़न के पास ही विश्व गुरुकुल आश्रम बना हुआ है और उसकी पुराने समय से बाउंडरी भी बनी हुई है। उसकी बाउंडरी को बचाया जा सकता है। इतनी बड़ी बाउंडरी, उस विश्व गुरुकुल आश्रम की बाउंडरी को नहीं तोड़ने की मैं मांग करता हूं और निवेदन करता हूं कि किसी भी सूरत में जाड़न के अन्दर अण्डरब्रिज और विश्व गुरुकुल आश्रम की यह जो बाउंडरी है, उसको बचाने की मांग करता हूं।

माननीय मंत्रीजी विराजे हुए हैं, मैं मंत्रीजी से अनुरोध करता हूं कि इन समस्याओं का निवारण कर जाड़न के ग्रामवासियों को तुरन्त प्रभाव से राहत दिलाने की व्यवस्था करावें ताकि एक्सीडेंट से जो मौतें हो रही हैं उनसे जनता को बचाया जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिये।

श्रीमती द्रोपती।

आप रेस्पोंड करेंगे क्या?

श्री युनुस खान (सार्वजनिक निर्माण मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मारवाड़ जंक्शन से आने वाले माननीय सदस्य ने जो जाड़न गांव की समस्या बताई है, वह वास्तव में सही है। इसमें आज ही संवेदक को निर्देश जारी कर दिये जायेंगे और इस काम को अतिशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

(श्री युनुस खान)

आपने दो इश्यू और उठाये हैं। एक कोई धार्मिक स्थल का है और दूसरा, पुल का निर्माण जो हो चुका है वह नीचा है। माननीय सदस्य को मैं बताना चाहूंगा कि जो डी एम आई सी आ रहा है, जो कोरिडोर बनेगा, उसका सब कुछ डेडिकेटेड अलग से बनेगा। इसलिए वह समस्या नहीं आयेगी। फिर भी इसको एक बार दिखवाकर इसका उपचार करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती द्रोपती।

राज्य में जिला मुख्यालयों पर स्थापित RAA न्यायालयों का प्रस्तावित विघटन व इसके कार्यों का सम्भागीय आयुक्तों को हस्तान्तरण

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि राजस्थान में जिला मुख्यालयों पर स्थापित आर.ए.ए. न्यायालयों का विघटन किया जाकर इन न्यायालयों की शक्तियों हेतु सम्भागीय आयुक्त न्यायालय को अधिकृत किया जा रहा है। इससे उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में बताना चाहूंगी। जन-भावना एवं मेरी राय में ऐसा किया जाना जन हित एवं न्याय हित में न्याय नहीं है जिनका कारण निम्न है:-

सम्भागीय आयुक्त को राजस्व अपील की शक्तियां देने पर बीकानेर या हर सम्भाग में लम्बित लगभग 12-13 हजार प्रकरण सम्भागीय आयुक्त को हस्तांतरित होंगे। इसलिए कार्य अधिकता को देखते हुए समय पर सुनवाई एवं निस्तारण सम्भव नहीं है। शक्ति हस्तांतरण होने पर सम्भाग के प्रत्येक जिले के अपीलार्थियों को अत्यधिक दूरी तय करनी होगी, जबकि वर्तमान में जिला मुख्यालयों अथवा कैम्प कोर्टों में जाने के लिए कम दूरी तय करनी होती है।

अत:, माननीय अध्यक्षजी, मैं आपके माध्यम से राजस्व मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि वर्तमान व्यवस्था को सुचारु रखा जाए या भ्रष्टाचार कम करने के लिए प्रत्येक जिला स्तर पर न्यायाधीश का पद सृजित किया जा सकता है या प्रशासनिक स्तर का अधिकारी आई.ए.एस. लगाया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष: अच्छा, आप रेस्पोंड कीजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पीलीबंगा से आने वाली माननीय सदस्या ने यह सवाल खड़ा किया है

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

कि राजस्थान में आर.ए.ए. कोर्ट का विघटन करके सारी शक्तियां सम्भागीय आयुक्तों को दे रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट में सैक्शन 20 (क) के अन्दर अपील का अधिकार आर.ए.ए. को है; यह भी सही है कि टीनेंसी एक्ट के सैक्शन 222 में तहसीलदार और कलक्टर की अपील सुनने का अधिकार भी आर.ए.ए. को है और यह भी सही है कि इस वक्त 16,887 प्रकरण, जो हमारे यहां 23 आर.ए.ए. हैं, उनके यहां दर्ज हैं। परन्तु अब तक किसी भी प्रकार का नीतिगत निर्णय सरकार ने नहीं लिया है कि सम्भागीय आयुक्त को ये सारे अधिकार आर.ए.ए. का विघटन करके दें।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह भ्रम दूर हो जाए कि सरकार ने कोई नीतिगत निर्णय ले लिया। नीतिगत निर्णय बिलकुल नहीं लिया है और अभी तक जो पूर्ववर्ती व्यवस्था थी, वह एज-इट-इज लागू रहेगी।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह अखबारों में आया हुआ है। अभी तक लिया या नहीं, लेकिन अखबारों में आया हुआ है। तो मैं एश्योर कराना चाहूंगी इस सदन के माध्यम से कि ये नहीं ले रहे हैं। स्पष्टीकरण दीजिये।

श्री अध्यक्ष: स्पष्टीकरण आ चुका है। अखबार के माध्यम से नहीं, अपने मंत्रीजी के वक्तव्य में है।

श्रीमती द्रोपती (पीलीबंगा): थैंक यू, सर।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल।

अजय नगर (अजमेर) में सीवर लाइन का खस्ता हाल

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के अजय नगर, जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा बसाई गई कालोनी थी, उसके बारे में निवेदन करना चाहूंगी।

कुछ सालों पूर्व आवासन मण्डल द्वारा अजय नगर के नाम से एक हाउसिंग बोर्ड कालोनी बसाई गई। हाउसिंग बोर्ड कालोनी बसाते समय विभाग के अधिकारी पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं करते, लेकिन सीवरेज जरूर डालते हैं। वहां पीने के पानी तक की व्यवस्था नहीं होती, लेकिन घरों से निकलने वाले गंदे पानी की निकासी के लिए सीवरेज लाइन डालने का काम उस प्रोविजन में लेते हैं। उसके कारण से सबसे बड़ी परेशानी यह होती है कि जब कालोनी बसने लगती है, कालोनी में लोग रहने लगते हैं तो चूंकि पेयजल की

(श्रीमती अनिता भदेल)

व्यवस्था भी वहां नहीं होती है, इस कारण से उस सीवर लाइन को साफ रखने के लिए जितने पानी की मात्रा की आवश्यकता होती है, वह पानी कम होता है और कम होने के कारण से धीरे-धीरे सीवर लाइन गंदगी से अट जाती हैं, चोक होने लगती हैं, चैम्बर से गंदगी बाहर आने लगती है। यही हाल इस कालोनी का भी हुआ है। पिछले कुछ सालों में इस कालोनी में जो सीवर लाइन डाली गई थी, वह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। आज की तारीख में उस कालोनी को साफ करने के लिए आवासन मण्डल के पास कोई कर्मचारी/अधिकारी नहीं हैं। संसाधन भी आवासन मण्डल के पास नहीं होने के कारण से उस सीवरेज लाइन को ठीक नहीं किया जा सकता। इसके साथ ही, उस सीवरेज लाइन से जुड़े हुए जो टैंक हैं, वे टैंक भी समय-समय पर नियमित रूप से खाली होने चाहिए लेकिन लगातार कई सालों से उन टैंकों की सफाई नहीं होने के कारण से, सारे टैंकों की पट्टियां टूट गई हैं। आवारा जानवर उनमें गिरते हैं। कई टैंकों की स्थिति तो यह है कि वे टैंक पूरी तरह से गंदगी से इतने ठोस हो चुके हैं कि आज की तारीख में नगर निगम का जो ट्रक है, वह भी उस सेफ्टी टैंक को खाली नहीं कर सकता।

ऐसी स्थिति में, कुछ लोगों ने, जिनके पास पैसा था, जिनके पास अपने मकान में स्पेस था, उन्होंने अपने व्यक्तिगत सेफ्टी टैंक बनवा लिये, लेकिन दूसरी ओर जो आदमी गरीब हैं, जिसके मकान में जगह नहीं है, वह सेफ्टी टैंक बना नहीं सकता। उसके घर की गंदगी तो आज भी उसी सीवर लाइन में जा रही है, जो आलरैडी चोक पड़ी है। इसका नतीजा यह हुआ कि सीवर लाइन टूट-फूट गई है। अब गंदगी को बहने के लिए मार्ग तो चाहिए, तो कहीं न कहीं चैम्बर से बाहर निकलती है और कहीं न कहीं वह अस्त-व्यस्त होकर, आज की स्थिति यह है कि पी एच ई डी की जो लाइनें हैं, उन पी एच ई डी की लाइनों में भी वह गंदा पानी जाने लगा है।

अब वहां के लोगों के लिए एक समस्या तो दूर हुई नहीं, दूसरी समस्या और खड़ी हो गई कि अब पी एच ई डी की लाइन में भी उन सीवर लाइनों का जो वेस्ट पानी है, वह जाने लगा है। उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि उसमें पेयजल की समस्या खड़ी हो गई। अब विभाग के अधिकारियों से बात करते हैं तो यह जवाब आता है कि नगर निगम द्वारा आर यू आई डी पी द्वारा जो नई लाइन डाली गई है, उसमें हम कनेक्शन शिफ्ट कर देंगे तो समस्या ठीक हो जायेगी। पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी कि यह डे-टू-डे

(श्रीमती अनिता भदेल)

की समस्या है। हम इसके लिए दो साल, तीन साल इंतजार नहीं कर सकते। जो सीवर लाइन आर यू आई डी पी द्वारा डाली गई है, उस सीवर लाइन में आज तक कनेक्शन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि उसका जो एस टी पी बनना है, वह एस टी पी आज तक पूर्ण नहीं है। ऐसी स्थिति में, एस टी पी कब पूर्ण होगा, कब उन सीवर लाइनों के कनेक्शन शिफ्ट होंगे, यह अभी कोई नहीं कह सकता।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जहां हम इस स्थिति में ठीक नहीं कर सकते, नई लाइन डाल नहीं सकते क्योंकि आलरैडी आर यू आई डी पी द्वारा नई लाइन डाल दी गई है, तो एक-डेढ़ साल के लिए जिन लोगों ने घरेलू सेफ्टी टैंक बना लिये हैं, उन सेफ्टी टैंक का गंदा पानी जो निकलता है, वह भी आज सड़क पर ही बहता है क्योंकि सीवर में कनेक्शन उन्होंने नहीं किया है। सीवर के कनेक्शन से परेशान होकर उन्होंने व्यक्तिगत सेफ्टी टैंक बनाये थे। ऐसी स्थिति में, यदि हाउसिंग बोर्ड के लोग या नगर निगम इस पूरी कालोनी में नाली का निर्माण करके उस गंदे पानी को चैनलाइज करके कालोनी के बड़े नाले में निकाल देते हैं तो शायद समस्या समाप्त हो सकती है।

इसके अतिरिक्त, इस कालोनी में हाउसिंग बोर्ड ने जितने भी पार्क बनवाये थे, उन पार्कों के अन्दर ही सेफ्टी टैंक बनवाये गये हैं, जो हाउसिंग बोर्ड द्वारा बनवाये गये हैं। ऐसी स्थिति में, चूंकि वे सेफ्टी टैंक पूरी तरह से टूट गये हैं, गंदगी भरी पड़ी है, बच्चे खेलने नहीं जा सकते, लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो उन सेफ्टी टैंकों को समाप्त करके, उन पार्कों के जीर्णोद्धार का काम क्या आवासन मण्डल द्वारा कराया जायेगा?

तीसरा विषय है, आवासन मण्डल की कालोनी में मकान रहने के लिए बनाये जाते हैं। धीरे-धीरे इस कालोनी के मुख्य मार्ग पर जितने भी मकान हैं, वे कामर्शियल काम्प्लेक्स के रूप में बदल गये हैं और जो लोग पीछे रह रहे हैं, उन लोगों की आपत्ति यह है कि हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है, मकान रहने के लिए लिया था, काम्प्लेक्स बनाने के लिए नहीं लिया था। पार्किंग की समस्या है, और अन्य समस्याएं हैं। इसलिए लोग कोर्ट में जाते हैं, झगड़ा करते हैं और आपस में लड़ाइयां होती हैं। नगर निगम को कम्प्लेंट करते हैं तो नगर निगम कहता है, हाउसिंग बोर्ड की कालोनी है, इसलिए हाउसिंग बोर्ड एक्शन ले। हाउसिंग बोर्ड को कहते हैं तो हाउसिंग बोर्ड वाले कहने लगे कि हमने

(श्रीमती अनिता भदेल)

हस्तान्तरित कर दी, पत्रावली वहां भेज दी, इसलिए नगर निगम एक्शन ले। अब ऐसे विभागों के पाटों में यह कालोनी फंसी हुई है। तो मेरा निवेदन है माननीय मंत्री महोदय से, एक तो यह निर्णय करा दें कि यह कालोनी कौन देखेगा अब। यदि नगर निगम इस कालोनी को देखने वाला है तो सारी पत्रावलियां, क्योंकि हाउसिंग बोर्ड वाले एक पत्र निकालकर कह देते हैं कि यह कालोनी हस्तान्तरित की जाती है और पत्रावली वहां भेजते नहीं हैं, पत्रावलियां भेजी जायें।

श्री अध्यक्ष: आ गया विषय आपका। आपका विषय आ गया, अब समाप्त कीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): हां, मेरा निवेदन इतना सा है...

श्री अध्यक्ष: आपका सारा निवेदन आ गया, समाप्त कीजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): महोदय, मुझे कोई इसमें आश्वासन मिल जाये किसी तरह का।

श्री अध्यक्ष: अब आश्वासन क्या, सरकार ने सारा सुन लिया है। आप व्यक्तिगत भी मिल लेना, मुख्य मंत्रीजी से भी मिल लेना। सब आश्वासन आपको मिलेगा। विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): इसके पार्क जो बने हुए हैं, उनके टैंक समाप्त होकर के, उन पार्कों का तो मेंटीनेंस हो जाये कम से कम। उस सीवर का जो पानी निकलता है चैम्बर से, उसके लिए नाली निर्माण करा देते।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचनाएं। श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान) आ गये, आ गये, दौड़कर आ गये।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचनाएं

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित उपनिवेशन विभाग की तीन एवं राजस्व विभाग की छह अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

उपनिवेशन विभाग

1. अधिसूचना संख्या : एफ.4(27)उप/1984 दिनांक 17 जून, 2014, जिसके द्वारा अधिसूचना दिनांक 12.9.2008 एवं 30.9.2011 के क्रम में राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम, 1954 की धारा-13-क की उप धारा-(1) के अन्तर्गत भूमि की अन्तरणों की विधि मान्यकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की कालावधि दिनांक 31.12.2014 तक बढ़ाई गई है;
2. अधिसूचना संख्या : एफ.4(06)उप/2010 दिनांक 23 जून, 2014, जिसके द्वारा इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र, भाखड़ा नहर क्षेत्र एवं गंग नहर क्षेत्र के अस्थायी काश्तकारों (टीसी लीज-होल्डर्स) को टी सी पर आवंटित भूमि को नियमानुसार पुख्ता आबंटन करने के लिये छूट हेतु जारी निर्देश की अवधि को दिनांक 31.5.2011 से बढ़ाकर दिनांक 31.12.2014 किया गया है; एवं
3. अधिसूचना संख्या : एफ.3(151)उप/1997 दिनांक 18 जून, 2014, जिसके द्वारा समसंख्यक पत्र दिनांक 19.5.2006 की शर्तों के अध्यधीन तहसील पूगल, जिला बीकानेर में दिनांक 24 सितम्बर, 1990 को आबंटित की गई भूमि के नियमितीकरण/खातेदारी अधिकार की अवधि को सशर्त दिनांक 30.6.2006 से बढ़ाकर 31.12.2014 तक किया गया है।

राजस्व विभाग

1. अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/1 दिनांक 10 फरवरी, 2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-260 एवं धारा-135 के अन्तर्गत एवं अधिसूचना संख्या : एफ.5(21)राज-4/80/35 दिनांक 4 सितम्बर, 1982 के तहत नामान्तरण के मामलों को भरतपुर सम्भाग में ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर राजस्थान तहसीलदार सेवा के अधिकारियों को उनके क्षेत्राधिकार में प्रयोग करने हेतु प्रदान की गई हैं, जो दिनांक 10.2.2014 से 19.2.2014 तक प्रभावी रहेगी;
2. अधिसूचना संख्या : एफ.16(1)राज-6/2004/2 दिनांक 10 फरवरी, 2014, जिसके द्वारा आबंटन सलाहकार समिति के मनोनीत सदस्य का मनोनयन निरस्त किया गया है;
3. अधिसूचना संख्या : एफ.16(1)राज-6/2004/3 दिनांक 19 फरवरी,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

2014, जिसके द्वारा भू-आबंटन नियम, 1970 के अन्तर्गत जिलों में उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में गठित भू-आबंटन सलाहकार समिति में पूर्व में किये गये सभी गैर-सरकारी सदस्यों का मनोनयन तुरन्त प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है;

4. अधिसूचना संख्या : एफ.2(5)राज-6/2010/पार्ट/4 दिनांक 9 अप्रैल, 2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-दान यज्ञ अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत भू-दान मंडल के गठन हेतु सचिव एवं कतिपय सदस्यों का मनोनयन किया गया है;

5. अधिसूचना संख्या : एफ.6(25)राज-6/14/5 दिनांक 16 जून, 2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (स्कूलों, कालेजों, डिस्पेंसरियों, धर्मशालाओं और अन्य लोकोपयोगी निर्माण हेतु बिना कब्जे की सरकारी कृषि भूमियों के आबंटन) नियम, 1963 के नियमों में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिबन्धित भूमियों को छोड़कर शेष किस्म की भूमियों का आबंटन राजकीय विभागों को नियम-4 में वर्णित आबंटन प्राधिकारी राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना दिनांक 31 मार्च, 2015 तक कर सकेगा; एवं

6. अधिसूचना संख्या : एफ.9(112)राज-6/2012/6 दिनांक 16 जून, 2014, जिसके द्वारा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा-260 एवं धारा-135 के अन्तर्गत नामान्तरण के मामलों में बीकानेर सम्भाग में ग्राम पंचायत की शक्तियां ग्राम पंचायतों के स्थान पर तहसीलदार को दी गई हैं, जो दिनांक 19.6.2014 से 15.7.2014 तक प्रभावी रहेगी।

श्री अध्यक्ष: श्री गजेन्द्र सिंह।

प्रतिवेदन एवं लेखे

श्री गजेन्द्रसिंह (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, ऊर्जा विभाग के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण सदन की मेज पर रखता हूं :-

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

1. विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा-105 (2) के अन्तर्गत राजस्थान

(श्री गजेन्द्रसिंह)

विद्युत विनियामक आयोग, जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013;

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे (वर्ष 2012-13)

2. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 13वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे वर्ष 2012-2013; एवं

राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन (वर्ष 2012-13)

3. कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड का 18वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2012-2013.

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्रजी राठौड़ का नाम दुबारा पुकारना पड़ रहा है।

राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण (वर्ष 2012-13)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-619-ए के अन्तर्गत राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेंट एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन लिमिटेड का 44वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2012-2013 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री रामेश्वर लाल जी डूडी।

समिति प्रतिवेदन

जन लेखा समिति (वर्ष 2014-15) (क्र.सं. 1 से 23)

श्री रामेश्वर लाल डूडी (नोखा): अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2014-2015 के निम्नांकित 23 प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

1. जन लेखा समिति, 2011-12 के 112वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा)

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का प्रथम प्रतिवेदन;

2. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट युवा मामले एवं खेल तथा प्राथमिक शिक्षा विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 2.3 से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का द्वितीय प्रतिवेदन;

3. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित अनुच्छेद संख्या 3.2.5 एवं 3.2.6 तथा श्रम एवं नियोजन विभाग से सम्बन्धित वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 3.4.2 से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का तृतीय प्रतिवेदन;

4. जन लेखा समिति, 2012-13 के 200वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का चतुर्थ प्रतिवेदन;

5. जन लेखा समिति, 2012-13 के 218वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का पंचम प्रतिवेदन;

6. जन लेखा समिति, 2012-13 के 197वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफ़ारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का षष्ठम प्रतिवेदन;

7. जन लेखा समिति, 2011-12 के 125वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 7वां प्रतिवेदन;

8. जन लेखा समिति, 2006-07 के 193वें प्रतिवेदन (बारहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 8वां प्रतिवेदन;

9. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2007-08 में समाविष्ट परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 9वां प्रतिवेदन;

10. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2008-09 में समाविष्ट परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 10वां प्रतिवेदन;

11. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) वर्ष 2009-10 में समाविष्ट परिवहन विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 11वां प्रतिवेदन;

12. सी.ए.जी. प्रतिवेदन (राज्य वित्त) वर्ष 2010-11 के अनुच्छेद संख्या 2.5 जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग से सम्बन्धित मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 12वां प्रतिवेदन;

13. विनियोग लेखे वर्ष 2010-11 में बताये गये दत्तमत्त अनुदानों एवं प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 13वां प्रतिवेदन;

14. जन लेखा समिति, 2012-13 के 161वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 14वां प्रतिवेदन;

15. जन लेखा समिति, 2012-13 के 174वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 15वां प्रतिवेदन;

16. जन लेखा समिति, 2012-13 के 184वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 16वां प्रतिवेदन;

(श्री रामेश्वर लाल डूडी)

17. जन लेखा समिति, 2012-13 के 196वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 17वां प्रतिवेदन;

18. जन लेखा समिति, 2012-13 के 201वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 18वां प्रतिवेदन;

19. जनलेखा समिति, 2012-13 के 208वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जनलेखा समिति वर्ष 2014-15 का 19वां प्रतिवेदन;

20. जन लेखा समिति, 2012-13 के 217वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 20वां प्रतिवेदन;

21. जन लेखा समिति, 2012-13 के 219वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 21वां प्रतिवेदन;

22. जन लेखा समिति, 2012-13 के 168वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 22वां प्रतिवेदन; एवं

23. जन लेखा समिति, 2013-14 के 247वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर क्रियान्विति विषयक जन लेखा समिति वर्ष 2014-15 का 23वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

याचिका

सूरसागर स्थित कालोनी बाम्बे योजना में मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धि

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र में जोधपुर विकास प्राधिकरण की योजना क्षेत्र की कालोनी बाम्बे योजना में मूलभूत सुविधाओं,पेयजल, सीवरेज, सी सी सड़क, रोड लाइट की स्थापना हेतु एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन राठौड़।

प्रत्येक आवास में शौचालय निर्माण हेतु सरकारी मदद

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, आपकी अनुमति से, प्रत्येक परिवार को अपने आवास में शौचालय निर्माण करने हेतु सरकारी मदद बाबत एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-2015 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद। आज के वादविवाद का प्रारम्भ करेंगे, शाहपुरा के माननीय विधायक राव राजेन्द्र सिंहजी।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। यह मेरा सौभाग्य है, अध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद पर अपनी बात आरम्भ करने के समय आप आसन पर विराजमान हैं।

मैं इस वाद-विवाद को संविधान के उस दायरे में रखते हुए आपका ध्यान उन अनुच्छेदों पर आकर्षित करना चाहता हूं, जिनकी गरिमा से इस विधान सभा के सम्पूर्ण सदन को और यहां के माननीय सदस्यों को इस जनता की स्वयं की महती मेहनत से किए हुए धन के संग्रह करने का सर्वाधिकार प्राप्त है। हम जिस विषय पर यहां चर्चा कर रहे हैं, उस विषय को

(14.00 बजे)

हम बजट के नाम से पहचानते और जानते हैं। आदरणीय, इस बजट का उल्लेख संविधान के आर्टिकल 202 के माध्यम से हमें मिलता है। 202 का

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आर्टिकल इस बात को स्पष्ट करता है कि राजकाज के कोष में एक-एक पाई के पैसे पर अगर अधिकार है तो इस राजस्थान की जनता का है और राजस्थान की जनता इन 200 चुने हुए जन-प्रतिनिधियों के माध्यम से उस पैसे को खर्च करने का अधिकार इलेक्टिव एक्जीक्यूटिव को देती है। जब इस सदन में बजट के विषय पर अपनी बात हम अभिव्यक्त करते हैं तो संविधान की उस मर्यादा को भी हमें ध्यान में रखने की बाध्यता होती है। यहां दलों की मर्यादा को पहले ध्यान में रखा जाता है और संविधान की मर्यादाओं को अनदेखा करने की हम भूल कर लेते हैं। इस सदन का सदस्य होने के नाते मैं तीन चीजों का उल्लेख करना चाहूंगा, जो आज तक इस सदन के अन्दर उप-स्थापित होने में हमने कतिपय उदासीनता व्यक्त की है।

मैं आपका ध्यान, अध्यक्ष महोदय, संविधान के 202 के उस अनुच्छेद पर ले जाना चाहूंगा, जहां यह स्पष्ट कहा गया है कि बजट जब हम पेश करते हैं तो हमें लेखा-जोखा के माध्यम से एस्टिमेट्स पेश करने पड़ते हैं। अब, आदरणीय, आप बताइए, ऐसी कौनसी पुस्तिका है, ऐसे कौनसे दस्तावेज हैं जिन दस्तावेज के माध्यम से इस जनता के पैसे का जो खर्च का लेखा-जोखा हम पेश करते हैं, वह सत्यापित किया जा सके? और ऐसा कौनसा दस्तावेज है कि जनता के कोष में कितना धन आया? उस दस्तावेज का परीक्षण कर हम यह सत्यापन कर लें कि अभिलिखित जो दस्तावेज इस सदन में पेश किए जाते हैं, उनकी सत्यता पर कोई प्रश्न नहीं लगा सकता।

मैं उदाहरण के लिए आपके सामने एक विषय प्रस्तुत करना चाहता हूं। आपकी दो ऐसी संवैधानिक इकाइयां, एक इकाई संविधान के फेडरल्स स्ट्रक्चर की वजह से राजस्थान की सरकार है जिसको हम इलेक्टिव एक्जिक्यूटिव कहते हैं और राजस्थान की सरकार के पास वित्त विभाग है, जो आपके अभिलेखों को पेश करता है। संविधान ने एक ओर ऐसी संस्था को मान्यता दी है जिसको हम कम्प्ट्रोलर और आडिटर जनरल या महालेखाकार के नाम से पुकारते हैं। आदरणीय, ताज्जुब तो यह होता है कि जब हम महालेखाकार के आंकड़ों को देखते हैं और वित्त विभाग के आंकड़ों को देखते हैं तो उनमें समानता नहीं मिलती है। दोनों ही संवैधानिक मर्यादा से प्राप्त सुसज्जित अधिकार और कर्तव्यों को परिणाम में परिवर्तित करने के उद्देश्य से स्थापित किये गये हैं और दोनों ही अभिलेख इस सदन में पेश होते हैं। अगर

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

इन दोनों अभिलेखों में विरोधाभास हो, तो हम किस अभिलेख या अभिलेखों को सत्य मानें?

मैं आपका ध्यान, क्योंकि आप विराजे हुए हैं, इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए मैं उस बात को आपके बीच में निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय, सी ए जी की साइट्स से उतारा हुआ है। सी ए जी हर महीने का लेखा-जोखा सरकार से लेती है और अपने यहां सीनियर अकाउंटेंट जनरल के पास अभिलिखित करती है। अब बजट-एट-ए-ग्लांस की यह जो किताब हमें पेश की गई है, अगर इस किताब की तरफ आप देखते हैं आदरणीय, मैं यह व्यवस्था के माध्यम से कह रहा हूं, ट्रैजरी बेंचेज का व्यक्ति हूं, हो सकता है, कुछ लोग-बाग़ इसको गलत प्रकार से परिभाषित करने का और परिवर्तित करने की कोशिश करें, लेकिन मैं किसी व्यवस्था में सुधार करने के कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। इस बजट-एट-ए-ग्लांस में आप देखें, हुकूम, बजट-एट-ए-ग्लांस में और बजट की स्पीच में, इन दोनों में हम यह मानते हैं कि ढाई हजार करोड़ का राजस्व घाटा है, बीते वित्तीय वर्ष में, और जब मैं कम्प्ट्रोलर और आडिटर जनरल के बजट एस्टिमेट्स की साइट निकालता हूं तो, आदरणीय, यही घाटा 5 हजार 328 करोड़ का दिखता है। यह बी.ई. का घाटा है और बी.ई. होने के बाद आर.ई. हुई और आर.ई. होने के बाद में 31 मार्च से लगाकर आज जुलाई के अंतिम पड़ाव पर हम हैं। अगर आप इन दोनों अभिलेखों का तुलनात्मक विश्लेषण करेंगे तो चाहे कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, चाहे कैपिटल रिसीट्स हों, चाहे रेवेन्यू रिसीट्स हों, हरेक के उप-नाम और उप-शीर्षक में आपको भिन्न-भिन्न आंकड़े मिलेंगे।

राइट-टू-इन्फोर्मेशन, सूचना का अधिकार, 2005 के बाद में क्रांति के रूप में आया और सदन के पास में तो सूचना का अधिकार संविधान की स्थापना के उपरांत प्रश्नों के माध्यम से, चर्चाओं के माध्यम से, वादविवाद के माध्यम से उपलब्ध है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर प्रेषित आंकड़े, जो इस सदन के पटल पर भी रखे जाते हैं, जो आमजन के सामने भी जाते हैं और जो कम्प्ट्रोलर और आडिटर जनरल का जो अभिलेख होता है, अगर उनमें भिन्नता हो तो आसन उस पर कम से कम व्यवस्था अपनी प्रदान करे कि ये 200 सदस्य और 6 करोड़ 85 लाख की यह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जनता किस अभिलेख पर विश्वास कर राज्य सरकार की और राज्य की वित्त स्थिति के सम्बन्ध में अपना मंतव्य स्थापित करें।

मैं तीन चीजें आपको कहूंगा, मैं न तो अर्थशास्त्री हूं, न मैंने अर्थशास्त्र में कोई पीएच.डी. की है लेकिन मैं सिर्फ देख रहा हूं, आदरणीय, दो अभिलेख हमारे पास में हैं। क्योंकि बाकी सारे विषय पर बहुत से लोग-बाग, बोल चुके हैं और बहुत से लोग-बाग बोलेंगे, लेकिन मैं कुछ ऐसी बातें आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं और मैं भी एक इंसान हूं I am subject to correction, अगर मेरी बात में कहीं कोई गलत चीज है तो जो मुझे सूचना मिली है, मैं उसी के माध्यम से आपको बता रहा हूं। अगर हम हाफ यीअरली बजट एस्टिमेट्स का देखते हैं और हाफ यीअरली सी ए जी की देखते हैं, तो सी ए जी ने तो 9/2013 को जब अपनी साइट अपडेट की थी तब भी 2,066.88 करोड़ का राजस्व घाटा बता दिया और उस वक्त तक की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स सिर्फ 3,918 करोड़ की थीं, जो हम सितम्बर के मध्य में लेकर के आये। आदरणीय, उसके बाद में 5,200 करोड़ की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स वर्तमान सरकार को बाध्य होकर पिछली वित्तीय व्यवस्था के कुप्रबंध से और लेनी पड़ीं। यानी, हम 10 हजार करोड़ रुपये सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के माध्यम से ले गये और जब सप्लीमेंट्री ग्रांट्स से हम 10 हजार करोड़ से ज्यादा ले गये तो परिस्थिति और पृष्ठभूमि दोनों बिगड़ीं।

हमने जिस वक्त अभिलेख पेश किया था, 2013-14 के इसी सत्र में, मैं आपका ध्यान बजट मेन्यूअल, परिवर्तित नवीन बजट मेन्यूअल की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, बजट मेन्यूअल बजट के प्रोविजंस को और बजट के पासिंग शिड्यूल को मान्यता देता है। उसमें फाइनेंस मिनिस्टर की बजट स्पीच, अकाउंट्स-एट-ए-ग्लांस, एप्रोप्रिएशन बिल्स, फाइनेंस बिल और ये किस प्रकार से पारित होंगे, उन सबको डिटेल्ड करता है। आदरणीय, बजट स्पीच आज के इस बजट का, जैसे वर्तमान के बजट का एक अभिन्न अंग है, उस वक्त जब बजट पेश हुआ था, उसका भी अभिन्न अंग था। उस वक्त हमें गलत आंकड़े दिये गये और 1,025 करोड़ का राजस्व आधिक्य बताया गया। मध्यकालीन जब हम लोग इस विश्लेषण पर तो सी ए जी की वेबसाइट 2,066 करोड़ का राजस्व घाटा बता रही थी।

यहीं इसी सदन में वर्तमान संसदीय कार्य मंत्री, जो वित्त मंत्री के

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

जवाब भी पेश कर रहे थे, यह बात कह रहे थे कि हमने राज्य के कोष से जो पैसा अधिक खर्च किया, वह कंटिंजेंसी से किया। आदरणीय, कंटिंजेंसी का भी आर्टिकल डिफाइंड है। कंटिंजेंसी का पैसा जो आपका कोरपस फंड है, 300 करोड़ रुपये रहता है। इस 300 करोड़ रुपये में से सिर्फ आप वह पैसा व्यय कर सकते हों, जो आपने कभी फोरसी ही नहीं किया हो। जब आपके अभिलेखों में चीज चिह्नित थी, जो खर्चा आपने वहां पहले से चिह्नित कर रखा था, अगर आपके पास में राजकोष में उसका पैसा नहीं था, तो कंटिंजेंसी से पैसा लेने का अधिकार न तो इस सदन ने आपको दे रखा है और न ही संविधान ने दे रखा है। निवर्तमान सरकार ने संविधान का घोर उल्लंघन किया है। उन्होंने संविधान की भी अवमानना की और इस सदन की गरिमा की भी अवमानना की।

मैं यह बात भी आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, और अगर मेरी बात को कोई सत्य नहीं माने तो आपके आर्काइटज में सितम्बर, 2013 के सेशन में स्वयं वित्त मंत्री का जवाब देते हुए निवर्तमान संसदीय कार्य मंत्री ने यह बात कह दी थी और उन्होंने तो यहां तक कह दिया था कि कंटिंजेंसी फंड में पांच हजार करोड़ होता है। अब, आदरणीय, कंटिंजेंसी फंड में कभी पांच हजार करोड़ रुपये होता है क्या? कोरपस फंड ही जिसका तीन सौ करोड़ है।

इस प्रकार की हम यहां अभिव्यक्तियों को लिखित करा देते हैं और जो चाहें, वह बोल कर चला जाता है। आसन इस बात के लिए आश्वस्त करे कि यहां कही हुई बात, अभिलिखित जो भी बात पेश होती है और अभिव्यक्ति की जो भी बात यहां की जाती है, चाहे सदस्य द्वारा की जाए, चाहे मंत्री द्वारा की जाए, चाहे सदन के किसी भी सम्माननीय सदस्य द्वारा की जाए, उसमें सच्चाई का पुट 99 परसेंट नहीं, आदरणीय, सौ परसेंट होना चाहिए। क्योंकि संविधान आपसे और हम सबसे कर्तव्य और निष्ठा का पालन करने के लिए सत्य की पराकाष्ठा को, सत्य की कसौटी पर, पारंगतता के हिसाब से पेश करना चाहता है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि विश्व के एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, जिनका नाम गुनर माडल था, उन्होंने बहुत बड़ा ग्रन्थ लिखा, 'द ग्रेट एशियन ड्रामा' और इस 'ग्रेट एशियन ड्रामा' में उन्होंने एशिया के बारे में लिखा। यह आपका और हमारा सौभाग्य है कि जिस कंटिनेंट के बारे में वे

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

लिख रहे थे, उस कंटिनेंट के, देश के आप और हम नागरिक हैं। उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति, जो सभ्यता अपनी भाषा में नहीं बोलती, अपनी भाषा में नहीं सोचती, उसकी समय-समय पर दुर्गति होना अवश्यम्भावी है। शायद यही हुआ कि उपनिवेशनकाल में जिन कानूनों का आविष्कार हुआ था, आज डेढ़ सौ वर्ष बाद भी वह कानून इस देश में प्रचलित है, क्योंकि न तो हम अपनी भाषा में सोचते हैं, न ही अपनी भाषा में अपने शास्त्रों द्वारा लिखित उस चरित्र का उत्पादन करते हैं जिसने विश्व गुरु जैसी उपाधि तक का अलंकरण प्राप्त करा दिया और हर चीज को हम पाश्चात्य सभ्यता की व्यवस्थाओं से तुलनात्मक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा दो ऐसी विशेष योजनाएं हैं, पूर्ववर्ती सरकार ने जिनका ढिंढोरा खूब पीटा, जिनको यहां लाकर, प्रतिपादित करके और आज भी जिसको बता-बता कर अपना रोष व्यक्त करते हैं, उसमें एक योजना थी, आदरणीय, और वह योजना थी, मुफ्त दवाई। आपको मैं बताना चाहता हूं कि मुफ्त दवाई के अन्दर खर्चा कितना हुआ। इस योजना की बी.ई. और आर.ई. है, उसमें मैं फर्क बता देता हूं आपको। बी.ई. तो इससे बहुत ज्यादा थी। 2012-13 में जब रिवाइज्ड एस्टिमेट हुआ तो इस योजना के अन्दर मुफ्त दवाई में 126 करोड़ रुपये खर्च होने की बात थी। वास्तव में इसमें खर्च हुआ था सिर्फ 96 करोड़। जब डायग्नोस्टिक, जिसको हम मुफ्त जांच की बात कहते हैं, मुफ्त जांच की बात करने के लिए आपने बी.ई. के बाद आर.ई. में 178.47 करोड़ रुपये की बात कह दी और आपने मुफ्त जांच कराई कितनी, 21.55 करोड़ की। तो 305.44 करोड़ की 2012-13 की आर.ई., वास्तव में 113 करोड़ रुपये।

अब मैं आपसे निवेदन करता हूं कि राज्य कर्मचारी कितने हैं इस पूरे प्रदेश में, साढ़े सात लाख के आसपास कर्मचारी हैं और एक-एक कर्मचारी के वेतन से प्रति माह चार सौ रुपये मेडिकल के नाम निकलता है, मेडिकल एड के नाम पर निकलता है। तो चार सौ अगर एक-एक कर्मचारी के हैं और साढ़े सात लाख हों, तो तीस करोड़ रुपये प्रति माह हम लोग उन राज्य सेवा के कर्मचारियों के वेतन से काट रहे हैं और तीस करोड़ अगर हम काटें तो बारह महीने में कितने हुए, 360 करोड़। और आप मुफ्त दवाई देकर 113 करोड़ में ही ढिंढोरा पीट रहे हों। पैसा तो आपके पास में पहले ही था। कौनसी अचरज

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

भरी इन्होंने सामान्य आदमी को ऐसी व्यवस्था दी, जिसके बारे में ये सरकार में दुबारा आने के सपने देख रहे थे?

मैं, आदरणीय, एक निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार ही कर की चोरी करने लग जाए तो जन सामान्य का क्या होगा? और अगर सरकार ही कानून का उल्लंघन करने लग जाए तो आम आदमी का क्या होगा? और अगर सदन यह देख कर भी मौन बैठा रहे तो फिर आम आदमी के विश्वास का क्या होगा? पिछली सरकार ने ये दोनों काम किये। चोरी करके और क्षमा मांग लेना अपराध को कम करना नहीं है। यह हमारे ऊर्जा मंत्रीजी यहां नहीं विराज रहे हैं, इनके विभाग ने ही कर चोरी की पिछली सरकार के समय। आदरणीय, यूजर चार्ज के नाम पर नगर निगम जयपुर, नगर निगम जोधपुर से, आम जन से, यूजर चार्जेज के नाम पर बिजली के बिलों के माध्यम से 13 करोड़ रुपये तो इन्होंने सृजित किये जयपुर नगर निगम से और सात करोड़ रुपये के आसपास किये जोधपुर नगर निगम से। बीस करोड़ रुपये ले गये। अब जितने डिस्काम्स इनके हैं, ये तो लिमिटेड कम्पनीज हैं, इनके आर्टिकल आफ एसोशिएशंस हैं। इनकी खुद की सर्विसेज और इनके कर्तव्य और इनकी ड्यूटीज संविधान के आर्टिकल के, उनके कारपोरेटेड आर्टिकल्स के संविधान से रेस्ट्रिक्टेड हैं और उनमें कौनसा ऐसा आर्टिकल है जो इनको यह अधिकार देता था कि यूजर चार्जेज नाम की चीज डिस्काम वसूल कर सकती हैं? इसमें सिर्फ दो ही अमेंडमेंट हुए हैं, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 में, एक तो वाटर कंजर्वेशन चार्जेज और अरबन चार्जेज। इनके अलावा, यूजर चार्जेज का न तो इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, 2003 में परिवर्तन हुआ, न संशोधन हुआ। उसके बाद भी आम जनता से 17 करोड़ के आसपास इन्होंने वसूल लिये और वसूले भी उन कम्पनियों ने जो स्वयं घाटे में चल रही थीं और उसमें से दस करोड़ रुपये नगर निगम को आपने हस्तांतरित भी कर दिये। पहले तो वसूल करने का अधिकार नहीं था और जब वसूल करने का अधिकार था तो कम्पनीज ला यह कहता है कि जो स्वयं घाटे में चल रहा हो, वह दूसरे को दान कैसे दे सकता है? जिन कम्पनियों पर साठ हजार करोड़ रुपये का घाटा चल रहा हो, वह अपने ही खातों से दस करोड़ रुपये वापस किसी नगर निगम को दे दें और, आदरणीय, अगर इस प्रकार का संशोधन आप और हम और सदन स्वीकार भी कर ले, तो केन्द्र सरकार ने इस प्रकार की गतिविधियों पर सर्विस टैक्स नाम की चीज लगा रखी है। आप और हम अगर इस प्रकार का कोई काम करें तो वह इस काम से उपार्जित जो हमारी आमदनी होती है, उस पर सर्विस टैक्स देना पड़ता

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

है। सर्विस टैक्स देने के लिए आपको टैक्स का पिन नम्बर देना पड़ता है । बता दीजिए, ये तीन डिस्काम्स हैं, इन्होंने यूजर चार्जेज इकट्‌ठे भी किए, यूजर चार्जेज कटने पर 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का उल्लंघन भी हुआ; उसको भी अगर आप माफ कर देते हैं, तो केन्द्रीय कर, जो इनको सर्विस टैक्स के हिसाब से देना चाहिए था, न तो अपने आपको पंजीकरण कराया, न उस कर का भुगतान केन्द्र को किया।

जब सरकार ही कर चोरी कर रही हो, तो आप और हम यहां बहस किस बात की कर रहे हैं? उनकी दुर्गति जिस प्रकार से होनी थी, वह जनता ने तो कर दी लेकिन इनका जो किया हुआ गलत कार्य है, वह पुन: नहीं दोहराया जाए और जिन्होंने यह कार्य इनसे करवाया, वह नौकरशाही में बैठने वाले लोगों पर आपको प्रताड़ना के रूप में किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था देनी पड़ेगी। कोई न कोई व्यक्ति इलेक्टेड एक्जीक्यूटिव जनता के पास जाकर अपनी परीक्षा का परिणाम प्रशिक्षण के हिसाब से और अपने आपको वहां लाकर, उनके सामने खड़ा करके, उसका परिणाम प्राप्त कर लेता है। इलेक्टेड एक्जीक्यूटिव को या तो जनता बरखास्त कर देती है या वापस, लेकिन जो इस इलेक्टेड एक्जीक्यूटिव से व्यवस्थाओं की त्रुटि के माध्यम से इस प्रकार के कार्य करवा देता है, वह यथास्थान पर बैठकर भी प्रताड़ित नहीं हो? मेरा उद्देश्य तो यह है कि इस प्रकार की चीज को आप जैसा व्यक्ति आसन पर बैठकर स्वीकार कर ले और सदन इस बात से बेरुखी कर ले कि यहां कुछ भी कहा जाए, यहां कुछ भी अपलिखित किया जाए, यहां किसी भी प्रकार का आंकड़ा पेश किया जाए, कोई मायने इसलिए नहीं रखता क्योंकि कही हुई बात सिर्फ यहां के आरथइव्ज तक सीमित रहती है। आदरणीय, संविधान के उल्लंघन पर तो आसन भी बाध्य है, आसन भी सदन पर छोड़ता है। आसन भी संविधान से बाध्य है कि संविधान के किसी भी विषय पर आसन की व्यवस्था नहीं, सदन की व्यवस्था होती है।

आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, इस पुस्तिका पर लिखा हुआ एक-एक अक्षर एक ऐसे व्यक्ति की याद दिलाता है जिस व्यक्ति की दुर्भाग्यवश अल्प आयु में ही हत्या कर दी गई। मैं अमेरिका के उस व्यक्ति की बात आपको बता रहा हूं जिसको हम मार्टिन लूथर किंग के नाम से जानते हैं। रंग भेद का जो समय चल रहा था, मार्टिन लूथर किंग का ड्रीम स्पीच का वह अंश,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

वह लाइन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं जब उन्होंने अमेरिका वासियों से कहा था, जो रेशियलाइजेशन, के खिलाफ एक सिविल राइट्स मूवमेंट में भाषण दे रहे थे कि ''I should not be tested by the colour of the skin but I should be tested by the contents of my character.'' इस किताब के रंग से आप प्रभावित न हों। इस किताब के कन्टेंट का करेक्टर इस बात को कहता है, अगर मार्टिन लूथर किंग ने सिविल राइट्स का मूवमेंट किया था, तो इस किताब में अभिलिखित, वर्तमान वित्त मंत्री ने सम्पूर्ण राजस्थान को विकास के पथ पर लेकर आने का वह कन्टेंट आफ करेक्टर पेश किया है जिसको हम भविष्य में विकास के नाम से जानेंगे।

छोटी सी व्यवस्था है, पता नहीं, मुझे कहां से समझ में आ गई, आप अगर मुझे आज्ञा दें तो वह मैं पेश कर दूं आपकी खिदमत, में, कि,

''आशाओं के महल में...,
आशाओं के महल में आशंकाओं के अंधेरे होते हैं;
आशाओं के महल में आशंकाओं के अंधेरे होते हैं,
अरे, चोरों के घरों में;
इंसानियत के अंधेरे होते हैं।
अरे, जिनकी सोच ही बंजर हो,
उनमें कहां भी विकास के फेरे होते हैं।''

यह व्यथा उनकी थी, कथा मेरे श्रीमुख से नहीं निकली। अभिव्यक्ति के स्वरूप में एक मैंने आपसे निवेदन किया कि जब सोच ही बंजर हो तो अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा, विकास की फसल उगती हुई नजर नहीं आएगी। दुर्भाग्य तो यह है कि यह अंधे भी हुए तो सावन में।

श्री अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं एक-दो चीजें और निवेदन करना चाहता हूं। आदरणीय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे बजट में आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने बहुत सी बातें कीं, लेकिन एक बात हम भूल गए, जो मैं उनसे हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं। हम गरीब की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं, हम चाहे कोर्ट कचहरी में बैठे हुए बार एसोसिएशन की बात करें। सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की भी हम बात करते हैं; आदरणीय, सस्ता और सुलभ न्याय कैसे दिलाया जा सकता है, सुप्रीम

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

कोर्ट में तो जाने की अच्छे-अच्छों की परिस्थिति नहीं है। 2008 में ग्राम न्यायालयों की बात की गई थी और ग्राम न्यायालयों का एक्ट पास होकर जब 2009 में आया तो इस अवधारणा से आया था कि 2008 के इस ग्राम न्यायालय के एक्ट को हम आमजन के द्वार तक ले जाकर, न्याय उसके द्वार तक पहुंचा देंगे। दुर्भाग्य तो यह है कि राजस्थान में सिर्फ 48 ग्राम न्यायालय हैं।

(14.26 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

केन्द्र वित्त पोषित हैं। पूरा का पूरा अगर इन ग्राम न्यायालयों को हम लोग और विकसित कर दें और केन्द्र में सरकार भी हमारी है, इनको और विकसित करके और ज्यादा ग्राम न्यायालय खोल दें तो सस्ता, सुलभ और सरल न्याय इस जनता को मिल सकता है। इसलिए इस बजटीय भाषण में न्याय सुलभता से मिले, सस्ता मिले और सरल मिले, इसके लिए ग्राम न्यायालयों के माध्यम से ग्राम न्यायालयों की वृद्धि इस राज्य के हित में होगी, आमजन के हित में होगी। मैं यही बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

क्योंकि सीमित समय है और सीमित समय में मैं और कुछ नहीं, आपसे निवेदन करके आपको परेशानी में नहीं डालना चाहता।

लेकिन एक बात कही है, आदरणीय, हम नदियों के जोड़ने की बात करते हैं। आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय पारित किया था और हाई पावर कमेटी बनाकर केन्द्र सरकार को बाध्य किया था कि आपको नदी का पानी जोड़कर, ऐसे राज्यों में जहां पानी की कमी है, आपको ले जाना पड़ेगा और हर दो महीने बाद वह मीटिंग काल करके आप सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देंगे। यह आखिरी वर्ष में जब बात कर रहे थे ना कि हम नदी से नदी जोड़ने की बात करेंगे, उनका कोई विवेक जागृत नहीं हुआ था, यह सुप्रीम कोर्ट की बाध्यता थी।

मैं आपको यह बता दूं कि यहां का और इस जनता का पैसा कहां है? मैं आसन से पूछना चाहता हूं कि जिस मेट्रो की हम बात कर रहे हैं, इस मेट्रो में 9 हजार करोड़ रुपये का व्यय होगा; ढाई हजार करोड़ से ज्यादा का व्यय हो चुका। आदरणीया, उसके लेखे-जोखे ही पेश नहीं हुए इस विधान सभा में आज तक। मुझे नहीं मालूम, लेकिन इनकी वेबसाइट पर फोर्थ एनुअल रिपोर्ट है सितम्बर 2013 की, आपके सदन में तो आज तक पेश नहीं हुई, अगर फोर्थ

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

एनुअल रिपोर्ट है तो एनुअल रिपोर्ट-वन भी होगी, एनुअल रिपोर्ट-टू भी होगी, एनुअल रिपोर्ट-थ्री भी होगी। यह कारपोरेट है, 3 हजार करोड रुपया राजस्थान की जनता का इस रेल के अन्दर व्यय हो चुका है, सी ए जी भी चिट्ठी लिख रही है कि हमें आडिट करने के लिए आपके लेखे-जोखे दें। हम यह मानते हैं, कि मेट्रो की सोच, हो सकता है कि क्रियान्वित करने में वर्तमान प्रतिपक्ष की रही होगी, लेकिन यह जनता की खरी कमाई का पैसा है, आखिर ये मेट्रो रेल के अधिकारी इस सदन में लेखे-जोखे क्यों नहीं पेश कर रहे? इससे बड़ी अवमानना इस सदन की हो क्या सकती है?

एक चीज पर, जिस पर सदन भी अंकुश नहीं लगा रहा और न ही राज्य सरकार अंकुश लगा रही है, ऐसे कई कारपोरेशंस को आप इस राजस्थान की परिसम्पत्तियां हस्तांतरित करते हैं, 123 एकड़ जमीन इस मेट्रो रेल कारपोरेशन को आपने हस्तांतरित करने की व्यवस्था की है, 50 एकड़ जमीन आप कर चुके हैं, बाकी आप करने जा रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इन परिसम्पत्तियों के निर्माण में इस राजस्थान की जनता का पैसा लगा, आखिर विधान सभा से अनुमति आज तक क्यों नहीं ली गई? ऐसी कई परिसम्पत्तियां हैं जो हम हस्तांतरित कर देते हैं इन उपक्रमों को, लेकिन इन परिसम्पत्तियों को हस्तांतरित करने से पहले इस सदन की अनुमति लेना अनिवार्य है। हम यह गैर-संवैधानिक कार्य कर रहे हैं। इस प्रचंड बहुमत से आई हुई सरकार से हम अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की जो पहले सरकारों ने परम्परा डाल रखी है, इस सदन के सर्वाधिकार की गरिमा को बनाकर रखने के लिए हमें इन पर अंकुश लगाना पड़ेगा।

कहने को तो, आदरणीया, बहुत था लेकिन क्योंकि मैं आपके श्रीमुख से अब यह नहीं सुनना चाहता कि आप बैठ जाइए, आपके हाव-भाव से मैं यह जानकारी ले चुका हूं, मैं बहुत-बहुत आपको धन्यवाद देते हुए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं, आप बोलिए। बोलिए। आप और भी कुछ बोलना चाहें तो बोलें। आप बहुत इन्फार्मेटिव बोल रहे हैं। बोलिए और कुछ।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं दो चीज और निवेदन करना चाहता हूं।

हमने वैट कम करने की बात कही थी। आदरणीय शिक्षा मंत्री महोदय, यहां पर हनुमानगढ़, गंगानगर और बीकानेर जिले के बहुत से माननीय सदस्य हैं, कभी आपने यह सोचा है, आस-पड़ोस के प्रदेशों के पेट्रोल और डीजल प्राइस

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

में तो कमी इसलिए होती है कि वैट कहीं पर ज्यादा है और कहीं पर कम है, लेकिन गंगानगर में डीजल ढाई रुपए महंगा मिले और जयपुर में ढाई रुपए सस्ता मिले। यह किसने लगा दिया? ये आयल कम्पनियां अपने डिपो बंद कर-करके एक जगह पर अपना यार्ड बना रही हैं और फिर ट्रांसपोर्ट के नाम से आम जनता से यह पैसा वसूल कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदया, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आप इन सम्पूर्ण चीजों की जांच करवाएंगे तो आपके पास में चौकाने वाले आकड़े आएंगे। इस सम्पूर्ण में जो फर्क है, वह मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं। हम पूरा का पूरा जो वैट निर्धारण करते हैं, सरकार का काम है पैसा बढ़ाना, लेकिन सरकारी कम्पनियां पैसा बढ़ा रही हैं और सरकारी कम्पनियां पैसा बढ़ाकर, बगैर सरकार की अनुमति से, डेढ़ रुपए से दो रुपये प्रति लीटर ज्यादा हासिल कर रही हैं। आखिर इन कम्पनियों की हैसियत कैसे हो गई कि आम जनता से ये ज्यादा पैसा वसूल कर लें?

हम 163 हैं और 163 होने के उपरांत भी हमारी सदन की नेता को इतना विश्वास नहीं दिला पाएं कि आप जो निर्णय लेंगे, 163 पूरे के पूरे आपके पीछे खड़े मिलेंगे। तो, आदरणीया, आपको 703 करोड़ रुपया ही तो पेट्रोल से मिलता है, साल का। 703 करोड़ रुपया पेट्रोल से मिलता है, 15 रुपये 50 पैसे प्रति लीटर सरकार के खजाने में जाता है। मुझे नहीं मालूम, किस अर्थव्यवस्था से प्रभावित होकर हमारे अधिकारियों ने इस सदन की नेता के हाथ रुकवा दिए, वरना आस-पड़ोस के प्रदेशों की वैट विसंगतियों को दूर करना तो अपनी जगह है, हो सकता है कि सरकार की कोई बाध्यता रही हो, लेकिन पेट्रोल कौन खर्च करता है, आदरणीया, आज की तारीख में, दु-पहिया वाहन; तीन-पहिया वाहन; आम स्टूडेंट, विद्यार्थी। मेरा विनम्र निवेदन है, और हो सकता है कि इस निवेदन को तोड़-मरोड़ कर सदन की नेता के सामने पेश भी किया जाए, लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस व्यापक जन समर्थन की उदारता को ध्यान में रखते हुए मैं इतनी बात भी निवेदन करना चाहता हूं, अगर किसी भी वित्त अधिकारी को इस बात पर कदापि आशंका हो तो एक सदस्य के रूप में इस बात के लिए दण्ड भी लेने का भागीदारी बनूंगा, क्यों न आम जन के हित में पेट्रोल पर कर ही समाप्त कर दिया जाए? 700 करोड़ का टोटल खेल है। 700 करोड़ का जब आप टैक्स समाप्त करोगे तो इसमें इसकी बिक्री का वाल्यूम ही इतना बढ़ जाएगा कि उसका परिदृश्य ही कुछ और होगा। एक।

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

खाद्य मंत्रीजी यहां पर विराजे हुए हैं तो मैं उनको भी निवेदन करना चाहता हूं। 2001 से बैरल पाइंट बंद करने का निर्देश केन्द्र का आ गया। पिछली सरकार तक हम कहते रहे कि बैरल पाइंट जहां पर चल रहे हैं, असंवैधानिक हैं, बैरल पाइंट बंद करने का निर्णय आ चुका है, आप बैरल पाइंट बंद करवा दीजिए। किसान विकास केन्द्र के नाम पर नई योजना आई हुई है, हमारे समय हमने इस योजना को पूरा क्रियान्वित किया था लेकिन इस योजना का पिछली सरकार ने नहीं किया। इन बैरल पाइंट्स के माध्यम से एडल्टरेशन होता है। उनको नियमित करने के लिए किसान विकास केन्द्र खुलवा कर, यह जो खुला उल्लंघन केन्द्र की नीति और नियम का हो रहा है, इस पर हमको कम से कम अंकुश लगाना पड़ेगा।

और एक बात मैं कहता हूं, विपक्ष नहीं है, 'भामाशाह' के नाम पर इन्होंने हंसी-मजाक करने की कोशिश की है। शायद इनमें से एक व्यक्ति भी 'भामाशाह' योजना का सम्पूर्ण स्वरूप पढ़ लेता तो यहां पर इस प्रकार से आलोचना नहीं करता। अगर भामाशाह के वास्तविक स्वरूप को किसी ने अभिलिखित किया है तो उस वक्त की सरकार और आज की मुख्य मंत्री की वह भावना है जिसकी सोच के आधार पर आधार कार्ड बना। वह सिर्फ महिलाओं के सशक्तिकरण तक ही सीमित नहीं है। आदरणीया, वह निर्धन परिवार को व्यवस्थित करने के लिए और निर्धन परिवार में महिलाओं के माध्यम से लघु और सीमांत काश्तकार तक उस व्यवस्था को पहुंचाकर उनको लाभान्वित करने की योजना है। उस योजना का अगर मैं पूरा प्रारूप पढ़ूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन अगर उस योजना को लागू कर देते तो आज की तारीख में 6 करोड़ 85 लाख की जनता में से 3 करोड़ लोगों को, यानी, 92 लाख से एक करोड़ परिवारों को और अगर एक करोड़, या 92 लाख परिवार, परिवार की चार की परिभाषा भी हो तो इतने लोगों के घरों में हम ऐसी व्यवस्था कर देते कि बीमारी के समय में 30 हजार रुपए मिल जाते और ज्यादा बीमार होकर कोई गम्भीर बीमारी से अगर वह प्रभावित होता तो उसको तीन लाख रुपए मिल जाते।

इन्होंने एक कमेटी बनाई, आदरणीया, इनकी सरकार आने के बाद में इन्होंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाकर, 2009 में फरवरी में हाई पावर कमेटी बनाई पांच मंत्रिमण्डल सदस्यों की, उन्होंने कहा कि इस 'भामाशाह' योजना की पूरी तरीके से जांच करो। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

उस कमेटी की आखिरी जो दो मीटिंग्स हुईं, उन आखिरी दो मीटिंग्स के मिनट्स कहां पर हैं? ये अधिकारी तो वे के वे हैं, इनसे पूछिये, उस हाई पावर कमेटी, जो कांग्रेस ने बनाई थी, जिसको 'भामाशाह' योजना पर अपनी व्यवस्था देनी थी, उसकी आखिरी दो मीटिंग्स के मिनट्स कहां पर हैं? मीटिंग के मिनट्स भी इन्होंने खुर्द-बुर्द कर दिए। बार-बार सी.ए.जी. के कहने के उपरांत भी वह हाई पावर कमेटी की मीटिंग के मिनट्स नहीं आये और पांच साल तक वे इसको लेकर बैठे रहे। अगर 'भामाशाह' योजना ऐसी ही थी तो क्यों तो पांच कैबिनेट मंत्रियों की मंत्रिमण्डलीय समिति बनती? और कभी भी किसी शासन में इतना दुर्भाग्य किसी जनता का नहीं रहा कि हाई पावर कमेटी जैसी बनी हो, और मुख्य मंत्री के आदेश से बनी हो, उसके मिनिट्स तक कहीं इसमें नहीं। मैं आसन से यह व्यवस्था चाहता हूं कि उन पांच मीटिंग्स में से जो लास्ट दो मीटिंग्स हैं, उनके मिनट्स को सदन पटल पर रखने का आदेश आप फरमाएं, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा; कितना पानी विपक्ष में है और कितना साफ, स्वच्छ दूध आज की सरकार में है, यह आकर आपके सामने हो जाएगा और वह खुद कटघरे में खड़ा हो जाएगा।

मैं यही कहते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। आपने मुझे इतना मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री अशोकजी परनामी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): माननीय सभापति महोदया, हमारी आदरणीय और सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने यह जो बजट रखा है, यह एक पालिसी डाक्यूमेंट है, पांच साल का यह विजन डाक्यूमेंट है और बजट को देखने से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि जो आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया का विजन 2020 है, वह इस बजट में, पहले बजट में ही परिलक्षित होता दिख रहा है और यह दिख रहा है कि आने वाले 2020 तक राजस्थान प्रदेश की क्या दिशा होगी, क्या दशा होगी। यह पांच साल का एक रोड मैप है।

सभापति महोदया, यह राजस्थान प्रदेश महाराणा प्रताप का प्रदेश है, यह राजस्थान प्रदेश मीरा बाई का प्रदेश है। यहां के लोग स्वाभिमानी हैं। यहां के लोग यहां की जनता तौल के देती है और तौल के लेती है। मेरे कुछ कांग्रेस साथियों ने कहा, इस बार के चुनाव में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जब पूरे राजस्थान प्रदेश में सुराज संकल्प यात्रा के माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री

(श्री अशोक परनामी)

महोदया राजस्थान प्रदेश के एक-एक कस्बे, एक-एक गांव में घूमीं, तो उन्होंने राजस्थान की स्थिति और परिस्थिति के बारे में जनता को बताया और सच बताया, परन्तु हमारे कांग्रेस के साथी यह कह रहे थे कि गलत जानकारी दी। मैं कांग्रेस के साथियों को यह बताना चाहता हूं कि वह गलत जानकारी नहीं दी गयी थी, वह राजस्थान में आपके द्वारा की गयी सच्ची तस्वीर जनता के सामने रखी गयी थी।

मैं कुछ आंकड़े आपके माध्यम से सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं राजस्व घाटे के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जब 2003-04 में आदरणीया मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजेजी ने कार्यभार सम्भाला था तो यह गहलोतजी की सरकार थी जो पांच वर्षों तक चली थी और जब वह सरकार छोड़कर गये थे तो 2003-04 में जो राजस्व घाटा था, वह 3,424 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा था। आदरणीया मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे की दूरदर्शी, अच्छी नीति, सुशासन की नीति और एक अच्छी सोच ने पांच वर्षों तक, 2003-04 से लेकर 2007-08 तक, राजस्थान प्रदेश का विकास भी किया; जो राजस्थान प्रदेश 'बीमारू' प्रदेश कहलाता था, उस राजस्थान प्रदेश को पूरे भारत वर्ष में एक विकसित प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा किया और उसके बाद भी, 2007-08 में सत्ता छोड़ी तो 1,653 करोड़ का राजस्व सरप्लस इस गहलोतजी की सरकार को देकर गये थे। फिर उसके बाद 2007-08 और उससे लेकर 2013-14 तक पुन: गहलोतजी की सरकार आई, कांग्रेस की सरकार आई। उनके कुवित्तीय प्रबन्धन ने, मुझे कहते हुए यह बड़ी शर्म हो रही है कि ना तो राजस्थान प्रदेश का विकास किया, वरन राजस्थान प्रदेश को पुन: 'बीमारू' प्रदेश बना दिया और इसके साथ-साथ 2,500 करोड़ का राजस्व घाटा फिर इस राजस्थान प्रदेश पर छोड़कर गये। मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि पुन: हमने सत्ता सम्भाली; भारतीय जनता पार्टी ने सत्ता सम्भाली, आदरणीया वसुन्धराजी पुन: मुख्य मंत्री बनीं और उन्होंने अपना जो पहला बजट पेश किया, 2014-15 का, उसमें पुन: राजस्थान प्रदेश के विकास को लेकर, विकास के साथ-साथ 737 करोड़ का राजस्व सरप्लस इस बजट में दिखाया।

मैं यह बताना चाहूंगा, 2003-04 से लेकर 2007-08 तक आप पूरे बजट के फिगर देख लीजिये, हमने जो-जो बजट सदन में रखा, उस बजट को अक्षरश: पूरा किया और मैं उसी दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार का

(श्री अशोक परनामी)

भी जो आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट सदन में प्रस्तुत किया है, उस बजट पर शत-प्रतिशत यह सरकार काम करेगी। सभापति महोदय, जरूरत है एक सोच की, एक दिशा की, एक कुशल वित्तीय प्रबन्धन की, जिससे राज्य का विकास हो सकता, परन्तु यह गहलोतजी की सरकार इन मापदण्डों पर पूरी नहीं उतर सकी।

एक माननीय सदस्य: यहां कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): जो बैठे हैं, वे ही सुनकर बता देंगे। एक मेम्बर भी नहीं है।

श्री कालीचरण सराफ (शिक्षा मंत्री): सभापति महोदय, प्रतिपक्ष का एक भी सदस्य नहीं है, कांग्रेस का।

श्री सभापति: कोई बात नहीं। अपनी बात रखें, कहीं न कहीं सुन रहे होंगे। इसी प्रेमिसेज में कहीं सुन रहे होंगे वे आपकी बात।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदया, मैं पेशे से व्यापारी हूं, अर्थनीति इतनी नहीं जानता परन्तु व्यापारी होने के नाते से एक व्यापक व्यापार का दृष्टिकोण मेरे बीच में है। यह सच है कि विकास करने के लिये ऋण लेना आवश्यक है। आज जितने भी बड़े उद्योग चलते हैं, सभी उद्योग ऋण लेते हैं परन्तु वे ऋण लेकर ऋण के ब्याज का भुगतान भी करते हैं और ऋण का भी भुगतान करते हैं और उसके साथ-साथ रोजगार का सृजन भी करते हैं। मुझे यह कहते हुए शर्म आती है कि पिछली सरकार ने, जब हम सरकार छोड़कर गये थे, आदरणीया वसुन्धराजी 2007-08 में जब सरकार छोड़कर गयीं तो 77,138 करोड़ का ऋण राजस्थान पर था, अभी गहलोत साहब ने जब सरकार छोड़ी 2013-14 में, तो 1 लाख 20,640 करोड़ रुपया, 53,502 करोड़ रुपये का ऋण लिया। ऋण लिया, इसका हमें कोई दु:ख नहीं है, परन्तु यदि इस ऋण का वे सदुपयोग करते, कैपिटल एक्सपेंडिचर करते तो हमें अच्छा लगता, परन्तु खाली घोषणाओं के माध्यम से, थोथी घोषणाओं के माध्यम से उन्होंने इस ऋण का इस्तेमाल किया। एक बहुत पुरानी कहावत है, सभापति महोदया, 'ऋणम कृत्वा, घृतम् पिवेत्' अर्थात् 'ऋण लो और घी पीओ' कहावत है। परन्तु यह कहावत किसके लिये है, सभापति महोदया, यह कहावत है अकर्मण्य व्यक्ति के लिये। कांग्रेस ने चरितार्थ भी यही किया, ऋण तो लिया परन्तु घी पीने के लिये ऋण लिया, राजस्थान प्रदेश को मजबूत करने के लिये वह ऋण नहीं लिया।

(श्री अशोक परनामी)

सभापति महोदया, घोषणाएं करनी थीं और उन्होंने घोषणाएं कीं परन्तु दु:ख इस बात का है कि उन्होंने राजस्व घाटे को बढ़ाने का भी काम किया। 2003-04 में साढ़े 6 प्रतिशत राजकोषीय घाटा था, जब हमने सरकार सम्भाली, आदरणीय वसुन्धराजी ने सरकार सम्भाली थी, पर उनकी कुशल नीति ने उस राजकोषीय घाटे को 2007-08 में पौने 2 प्रतिशत पर लाकर खड़ा कर दिया। पुन: गहलोतजी ने सरकार सम्भाली, पुन: जब गहलोतजी ने सरकार छोड़ी तो यह राजकोषीय घाटा वापस 3 प्रतिशत कर दिया।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि राज्य की विकास दर बढ़ाने के लिये पूंजीगत परिव्यय की नितान्त आवश्यकता होती है। ज्यों-ज्यों पूंजीगत व्यय बढ़ेगा, परिव्यय बढ़ेगा, त्यों-त्यों हमारी राजस्व आय बढ़ेगी। यह मैंने पहले भी कहा था, जब मैंने आपको व्यापार का एग्जाम्पल दिया था, वह ही उदाहरण यहां भी परिलक्षित होता है। सभापति महोदया, अभी हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने जो बजट पेश किया, हमने भी बजट में 20,185 करोड़ रुपये का लोन लेने की बात की, परन्तु इस लोन के साथ-साथ हमने पूंजीगत परिव्यय 26 हजार करोड़ रुपया बताया है, जो 129 परसेंट होता है; जो कांग्रेस के समय 42 परसेंट था, परिसम्पत्तियां बनाने का। यह है कांग्रेस की अकर्मण्यता। इसी कारण से राजस्थान प्रदेश जो पिछड़ा, उसके पिछड़ने का यह सबसे बड़ा कारण था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्री महोदया को, जो उनका वित्तीय प्रबन्धन है उस वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से 2003 से लेकर के 2008 तक भी राजस्थान प्रदेश विकास की दृष्टि से आगे बढ़ा था और पुन: 2014-15 से लेकर 2020 तक पूरा राजस्थान प्रदेश आगे बढ़ेगा।

सभापति महोदया, मैं आपको कांग्रेस की और कारस्तानी सुनाता हूं, हालांकि राव साहब ने इस बारे में बहुत कुछ कह दिया, मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और देना चाहता हूं। योजनाएं बनाना आसान है परन्तु योजनाओं को एग्जीक्यूट करना, उनको धरातल पर लाना, यह बहुत मुश्किल काम है, जो कांग्रेस की सरकार के माध्यम से राजस्थान में नहीं हो पाया। मैं यहां कुछ फिगर देना चाहूंगा प्लान एक्सपेंडिचर के। 2008-09, जिसमें 9 महीने तो भारतीय जनता पार्टी के थे, आदरणीया वसुन्धराजी का समय था और केवल मात्र तीन महीने गहलोतजी के थे, कांग्रेस की सरकार थी, उस समय 14,924 का प्रपोज्ड प्लान था और खर्चा हुआ 15,676 करोड़। जितना प्लान था, प्लान से अधिक खर्च हुआ। उसका एक ही कारण था कि 9 माह आदरणीया वसुन्धरा

(श्री अशोक परनामी)

जी उस समय मुख्य मंत्री महोदया थीं। उसके बाद का लीजिए, 2009-2010 में 18,560 करोड़ का प्रपोज्ड प्लान था परन्तु खर्च कितना हुआ, 17,448 करोड़ रुपया; 1,112 करोड़ कांग्रेस की सरकार खर्च नहीं कर पायी। 2010-11 में 23,562 करोड़ का जो प्लान था और खर्च किया 20,859 करोड़ रुपया, 2,7,003 करोड़ रुपया कम खर्च किया। 2011-12 में 29,261 करोड़ प्लान था और 24,613 करोड़ रुपये खर्च किया गया, 4,648 करोड़ रुपया कम खर्च किया गया। यह कांग्रेस की अकुशलता थी, अकर्मण्यता थी। पूरा बजट भी कांग्रेस की सरकार खर्च नहीं कर पायी।

यह खाली राजस्थान का बजट ही नहीं, सभापति महोदया, जो हमें केन्द्र से पैसा मिलता है, वह पैसा भी राजस्थान सरकार पूरा खर्च नहीं कर पायी और राजस्थान प्रदेश की जनता को विकास से महरूम रखा। मैं यहां बताना चाहूंगा, 2010-2011 में 491 करोड़ रुपये का था और खर्च किया 407 करोड़ रुपया; 2011-12 में 722 करोड़ था और खर्च किया 480 करोड़ रुपया; 2012-13 में 634 करोड़ था और खर्च किया 554 करोड़ रुपया। इस प्रकार, 500 करोड़ रुपया जो दिल्ली से आया था, खाली हमको खर्च कर के हिसाब देना था, यह कांग्रेस की सरकार ने 500 करोड़ रुपये का राजस्थान की जनता का नुकसान किया।

सभापति महोदया, बिजली का ले लीजिए, हमने जब 2007-08 में सरकार छोड़ी तो 15 हजार करोड़ का बिजली की कम्पनियों पर बोझा था, ऋण था, परन्तु इन पांच वर्षों में कांग्रेस की अकर्मण्यता ने, कांग्रेस के गलत प्रबन्धन ने इस घाटे को 75 हजार करोड़ रुपये पहुंचा दिया। पांच वर्षों में 60 हजार करोड़ का घाटा इन बिजली कम्पनियों में बढ़ा दिया। यह कांग्रेस की देन थी राजस्थान प्रदेश को।

इसके साथ-साथ कांग्रेस की सरकार ने 2009 में घोषणा की थी, हमने कुल चार हजार मेगावाट के तीन सुपर-क्रिटिकल ताप बिजलीघरों की स्थापना का निर्णय लिया था, मैं कांग्रेस की सरकार से पूछना चाहता हूं, कोई नहीं बैठा, फिर भी पूछना चाहता हूं, क्या पांच वर्षों में इन परियोजनाओं को धरातल पर लाया गया? धरातल पर ही नहीं, सभापति महोदया, कागजों में भी लेकर के नहीं आयी। दूसरी तरफ, जब हमारी सरकार थी, 2003 और 2004 में 4,984 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता हमें मिली थी और हमने उसको बढ़ा कर

(श्री अशोक परनामी)

के 6,395 मेगावाट कर दिया और यहां तक ही नहीं, 2008-09 के अंत तक 2,019 मेगावाट क्षमता की वृद्धि होनी तय थी परन्तु किसी कारण से जो 'भेल' कम्पनी है, उसने हमें पूरा कोयला नहीं दिया जिसके कारण उत्पादन नहीं कर पाये, परन्तु हमने यह उत्पादन क्षमता हमारे कार्यकाल में बढ़ा दी थी।

इसके साथ-साथ, किस प्रकार से छीजत को कम किया जाए, उस छीजत को कम करने के लिए, किसान को घरेलू बिजली का कनेक्शन अलग देने के लिए हमने श्यामा प्रसाद मुखर्जी विजय ज्योति फीडर सुधार अभियान प्रारम्भ किया, जिसके तहत हमने घरेलू पूर्ति के लिए फीडर्स लगाये, 4,900 फीडर का कार्य हमने पूरा किया, 9.37 प्रतिशत छीजत की हमारे समय में कमी आयी और 34 हजार से अधिक गांवों को निकटतम शहरी क्षेत्रों के समान हमने बिजली की आपूर्ति की। यह हमारी सरकार की उपलब्धि थी ऊर्जा के क्षेत्र में।

सभापति महोदया, अभी भी हमारे ऊर्जा मंत्री महोदय ने उस दिन कहा कि अभी केवल मात्र हमें आठ माह हुए हैं, हम निश्चित रूप से 24 घण्टे बिजली देंगे और हमारा राजस्थान प्रदेश बिजली की दृष्टि से जल्दी ही आत्मनिर्भर हो जायेगा। इसके साथ ही साथ हमने सोलर ऊर्जा का 25 हजार मेगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य और रिन्यूएबल एनर्जी में चार हजार करोड़ से अधिक का व्यय कर के ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र के भी निर्माण की घोषणा अभी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदय ने की।

मुझे हमारे पूर्व प्रधान मंत्री, आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की वे पंक्तियां याद आती हैं, जब वे प्रधान मंत्री बने थे तो उन्होंने कहा था, जब तक हम देश का पूरा तंत्र मजबूत नहीं कर देंगे, जब तक हम देश में पूरा सड़कों का जाल नहीं बिछा देंगे, तब तक हमारा देश विकास की गति नहीं पकड़ पायेगा। जिस प्रकार से हमारे शरीर के अन्दर हृदय को खून पहुंचाने के लिए धमनियों का इस्तेमाल होता है, उसी प्रकार से देश को मजबूत करने के लिए, देश को एक विकसित देश बनाने के लिए सड़कों का निर्माण करेंगे और ये सड़कें धमनियों का निर्माण करेंगी जो देश को मजबूत करेंगी। उसी को दृष्टिकोण रखते हुए, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीया वसुन्धराजी ने आधारभूत ढांचे में, जो पिछले पांच वर्षों में बिगड़ा हुआ था, उसे सुधारने का काम भी हमने अपने हाथ में लिया।

(श्री अशोक परनामी)

मैं यहां यह बता देना चाहता हूं कि 2003 से लेकर के 2008 का आप आंकड़ा उठा कर के देख लें, राजस्थान प्रदेश में आदरणीया वसुन्धराजी के नेतृत्व में 2003 से लेकर 2008 तक 40 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण हुआ था और पिछले पांच वर्षों में गहलोतजी के राज में, कांग्रेस के राज में राजस्थान प्रदेश में केवल -मात्र नौ हजार किलोमीटर सड़कों का

(15.00 बजे)

निर्माण हुआ। यह कांग्रेस की देन थी राजस्थान प्रदेश की जनता को। हमारी सरकार ने 2003 से लेकर के 2008 के बीच में 10 हजार 222 गांवों को सड़कों के साथ जोड़ने का काम किया था, इस कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने केवल मात्र 1,500 गांवों को जोड़ने का काम किया।

सभापति महोदया, अभी जो आदरणीया मुख्य मंत्री, वसुंधराजी ने बजट रखा, उन्होंने सड़कों पर विशेष ध्यान दिया और 20 हजार किलोमीटर रोड बनाने का पूरा प्लान रखा। पहले हमने नार्थ-साउथ कोरिडोर पूरा किया था, अब ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर बनाने के लिए 1 हजार किलोमीटर सड़कों का और निर्माण किया जायेगा, 20 हजार किलोमीटर सड़कों के साथ-साथ।

सभापति महोदया, इसके साथ; गांवों में सड़कें बनती हैं, पानी पड़ता है, सड़कें वापस टूट जाती हैं। तो आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने सोचा कि गांवों में बार-बार सड़कें नहीं टूटें, इसलिए गांवों में आर सी सी की सड़कों के निर्माण की बजट में घोषणा की गयी। इससे निश्चित रूप से गांवों को लम्बे समय तक सड़कें मिलेंगी। इसके साथ-साथ, 530 गांव ऐसे हैं जो अभी तक सड़क से नहीं जुड़ पाये हैं, उनको भी जोड़ने का काम रखा, जिसमें 1 हजार 294 किलोमीटर सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया।

सभापति महोदया, शिक्षा को ले लीजिये, मैं आपको अपनी साक्षरता दर है, पूरे देश की, उसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य जो था, पूरे देश का, वह लक्ष्य था 79.57 साक्षरता प्रतिशत और पूरे देश में इसको जब पूरा किया तो वह किया 73 प्रतिशत और हमारे राजस्थान प्रदेश ने 73 का आंकड़ा भी पूरा नहीं किया। हमारे राजस्थान प्रदेश में 66.8 साक्षरता है। यह कांग्रेस की देन थी। उसके पीछे कारण हैं। आपको ताज्जुब होगा कि 2008 से 2013 के बीच में राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में 22वें पायदान पर आकर के खड़ा हो गया।

(श्री अशोक परनामी)

मैं यदि यहां पर आपको सरकारी विद्यालयों की जानकारी दूं तो राज्य के 900 विद्यालय तो ऐसे हैं जो बिना भवन के ही चल रहे हैं। प्रदेश के 5 हजार स्कूल बिना शिक्षक के चल रहे हैं; 2 हजार स्कूल बिना प्राध्यापक के चल रहे हैं; 7 हजार 500 स्कूल बिना प्रयोगशाला के चल रहे हैं; यह तो एक तरफ देख लीजिये और दूसरी तरफ 142 विद्यालय ऐसे हैं जहां 252 शिक्षक हैं और बच्चा एक भी नहीं है। पढ़ने वाला बच्चा एक भी नहीं है। 8 हजार 164 विद्यालय, जिनमें 14655 टीचर हैं, जहां पर विद्यालय में 1 से 15 बच्चे हैं; 19 हजार 760 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर 42 हजार 150 टीचर हैं किन्तु बच्चों की हर विद्यालय में 16 से 30 तक की संख्या है। तो कैसे साक्षरता हमारे राजस्थान प्रदेश की बढ़ेगी?

सभापति महोदया, चिकित्सा की तरफ देख लीजिये, कांग्रेस की सरकार ने बड़ी डींगे मारीं, बहुत बड़ी-बड़ी बातें कीं उन्होंने कि हम मुफ्त दवा देंगे, मुफ्त जांच करेंगे, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आज पूरे देश की जो शिशु मृत्यु दर है वह 42 प्रतिशत है, जो लक्ष्य था वह 40 प्रतिशत का था, हमारा राजस्थान प्रदेश 49 प्रतिशत पर है। हम भारत का जो आंकड़ा है 42 प्रतिशत, उस पर भी नहीं पहुंच रहे हैं। बारहवीं योजना में मातृ मृत्यु दर का लक्ष्य 200 था, भारत की औसत दर आ गयी 178, परन्तु हमारा राजस्थान प्रदेश 255 पर खड़ा है। फिर भी हमारे गांधीवादी पूर्व मुख्य मंत्री कहते हैं कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया। इन्होंने मुफ्त दवा के नाम से और मुफ्त जांच के नाम से राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया।

सभापति महोदया, पेयजल व्यवस्था ले लीजिये। मैं पेयजल व्यवस्था में भी आपको बताना चाहूंगा कि हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने 81 ऐसी योजनाओं की घोषणा की थी जिनके लिए वित्तीय प्रबंधन ही नहीं किया। मानो, घोषणा करने मात्र से जनता को पेयजल की आपूर्ति हो जायेगी। यह कांग्रेस की बात है।

मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण पेयजल योजना का रिपोर्ट में आया है, जो उन्होंने बजट दिया, उस बजट को भी पूरा खर्च नहीं किया। सभापति महोदया, 2009-10 में ग्रामीण पेयजल योजना में 2 हजार 65 करोड़ का बजट इन्होंने सैंक्शन किया और खर्च कितना किया, 1 हजार 676

(श्री अशोक परनामी)

करोड़; 2010-11 में 2 हजार 350 करोड़ स्वीकृत किया और खर्च किया 1 हजार 502 करोड़ रुपया; 2011-12 में 2 हजार 570 करोड़ रुपया स्वीकृत किया और उस पर खर्च कितना किया, 2 हजार 54 करोड़ रुपये; 2012-13 में 2 हजार 626 करोड़ रुपये सैंक्शन किये और 2 हजार 165 करोड़ रुपये खर्च किया और 2013-14 में 3 हजार 768 करोड़ रुपये स्वीकृत किये और 3 हजार 508 करोड़ रुपया खर्च किया। इन 5 वर्षों में एक भी वर्ष में पूरा बजट इस कांग्रेस की सरकार ने खर्च नहीं किया, फिर कहते हैं कि हमने राजस्थान प्रदेश का विकास किया। कहां से कर दिया?

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ आप शहरी क्षेत्र को भी ले लीजिये, ये शहरों के भी नहीं हैं और ग्रामीण के भी नहीं हैं। शहर में भी 529 करोड़ का बजट 2009-10 में स्वीकृत किया और 477 करोड़ खर्च किया; 2010-11 में 462 स्वीकृत किया और 352 करोड़ खर्च किया; 2011-12 में 518 स्वीकृत किया और 368 खर्च किया; 2012-13 में 646 करोड़ और 500 खर्च किया और 2013 में 1 हजार 017 की जगह 850 करोड़ रुपया खर्च किया गया। यह इनका पेयजल का ले लीजिये। पूर्ववर्ती सरकार पेयजल के प्रति भी गम्भीर नहीं थी।

सभापति महोदया, हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने 2003 से लेकर के 2008 तक में भी पेयजल में बहुत काम किया। अभी भी जो उन्होंने बजट दिया तो उन्होंने पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए ग्रामीण पेयजल योजना को पंचायत समितियों को सौंपने का एक अभूतपूर्व निर्णय लिया। इससे जहां पंचायती राज को पावर शेयरिंग होगी, पंचायतों की भागीदारी बढ़ेगी, पेयजल योजना की लोकल रूप से देखरेख हो सकेगी, वहीं पंचायती राज भी मजबूत होगा।

सभापति महोदया, गांव को शुद्ध पानी मिले, इसके लिए भी हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने घोषणा की कि ग्रामीण जनता को भी आर ओ तकनीक से 1 हजार हैबिटेशंस में पेयजल की आपूर्ति की जायेगी। इसके साथ-साथ, राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन का गठन भी किया गया, जिससे कि पेयजल परियोजनाओं का समुचित प्रबंधन किया जा सके।

सभापति महोदया, यह मैंने 2003 से लेकर के 2008 और 2008 से

(श्री अशोक परनामी)

लेकर 2013 तक का पूरा खाका आपके सामने रखा है। कांग्रेस के सदस्य मौजूद हैं तो ठीक है, उनका यह कहना कि आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया जब अपनी यात्रा पर निकलीं तो जनता में गलत बातों का प्रचार किया, मैं समझता हूं कि इसको सुनने के बाद आपको लगेगा कि उन्होंने जो जनता के सामने रखा, वह सच्चाई के साथ रखा और जनता ने भी उसको सच्चाई के साथ स्वीकार किया।

मैंने पहले भी कहा था कि यह मीरा का प्रदेश है, तौल के लेना और तौल के देना, यह राजस्थान प्रदेश की परिपाटी है। राजस्थान प्रदेश की जनता ने 2003 से लेकर के 2008 का वसुंधराजी का कार्यकाल देखा और 2008 से लेकर के 2013 तक का गहलोतजी का कार्यकाल देखा, और उनका तुलनात्मक विश्लेषण किया। उस तुलनात्मक विश्लेषण के माध्यम से राजस्थान प्रदेश की जनता ने इतनी ऐतिहासिक जीत वसुंधराजी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी को दिलायी है। यह ऐसी जीत है, आज तक किसी भी राजनीतिक दल ने, जब से हमारे देश में चुनाव हो रहे हैं, किसी भी राजनीतिक दल ने किसी भी प्रदेश में इतने भारी बहुमत से सरकार नहीं बनाई जितने भारी बहुमत से सरकार आदरणीया वसुन्धराजी ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनाई। यह तुलनात्मक विश्लेषण हुआ, काम को देखा गया और जनता ने यह विश्वास किया कि राजस्थान प्रदेश का यदि कोई विकास कर सकता है तो वह वसुन्धराजी कर सकती हैं। इसलिए वसुन्धराजी को इतने भारी बहुत से पुन: मुख्य मंत्री बनाया।

सभापति महोदया, मैं जयपुर से विधायक हूं और जयपुर की बात नहीं करूंगा तो बड़ी बेईमानी होगी क्योंकि जयपुर के साथ तो गहलोत साहब ने बहुत ही सौतेला व्यवहार किया। साढ़े चार साल तक सरकार सोती रही, अंत के छह महीनों में उसकी जाग खुली और राजस्थान प्रदेश की जनता की सुध लेना उन्होंने शुरू किया। छह महीने में कितनी सुध ले सकते थे, वह राजस्थान प्रदेश की जनता उसको भली-भांति जानती है। राहुल गांधीजी जयपुर में आये थे, उन्होंने जे एल एन मार्ग को देखकर यह कह दिया कि जयपुर को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहिए। मैं समझता हूं कि यदि राहुलजी शहर के अन्दर भी जाते और नागतलाई का नाला देखते, सी-स्कीम का नाला देखते, जल महल का नाला देखते, जवाहर नगर का नाला देखते, जो नाला ऐसी जगहों से

(श्री अशोक परनामी)

निकल रहा है जिसके दोनों तरफ बस्तियां बसी हुई हैं, तो राहुल गांधीजी को लगता कि वर्ल्ड क्लास सिटी तो बाद में बना लेना परन्तु पहले इन नालों की सफाई तो कर लो, इन नालों को ढकने का काम कर लो।

सभापति महोदया, आदरणीया वसुन्धराजी के समय में जब मैं महापौर था, तब जयपुर शहर के लिए एक मास्टर ड्रेनेज प्लान बनाया था, जिसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनकर तैयार हो गई थी, परन्तु इस कांग्रेस की सरकार ने आकर उसको ठण्डे बस्ते में डाल दिया। उसको एक ही रट लगी कि राहुलजी कहते हैं कि वहां वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना है और वर्ल्ड क्लास सिटी बन सकती है तो केवल मात्र जयपुर शहर में मेट्रो लेकर आ जाओ तो वर्ल्ड क्लास सिटी बन जायेगी। मेट्रो आई, हमने मैट्रो का विरोध नहीं किया, परन्तु हमने विरोध इस बात का किया कि जिस मेट्रो को 2025 में लाना चाहिए, उस मेट्रो को आप इतना जल्दी लाने में क्यों इतना उत्सुक हो रहे हों? पहले जयपुर शहर की आधारभूत व्यवस्थाओं को ठीक कर लो; जयपुर की सड़कों को ठीक कर लो; जयपुर में आर ओ बी बना दो; जयपुर में हेरिटेज जो बहुत है, मजबूत है, उसका संरक्षण कर लो; बी आर टी एस का जो काम हमने चालू किया था, उसको पूरा कर लो।

बीसलपुर की परियोजना, जयपुर शहर को बीसलपुर का पानी पिलाने वाली, जयपुर शहर में बीसलपुर का पानी लाने वाली हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीया वसुन्धराजी थीं। बीस साल से बीसलपुर की परियोजना बस्तों में बंद पड़ी थी, वे उस परियोजना को जयपुर की धरती पर लेकर आईं। जयपुर की धरती पर बीसलपुर का पानी आ गया, अस्सी परसेंट तक घरों में पानी पहुंच गया, 2003 से लेकर 2008 तक, पर मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि पिछले पांच वर्षों में इस कांग्रेस की सरकार ने एक भी घर में बीसलपुर का पानी और नहीं पहुंचाया। जहां पर बीसलपुर की परियोजना आदरणीया वसुन्धराजी छोड़ कर गई थीं, आज भी वहीं की वहीं पड़ी है। मैं आपके माध्यम से आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि यह आपकी स्कीम थी, यह आपकी धरोहर थी, जो बीस परसेंट जयपुर बच गया है, उसको भी बीसलपुर का पानी आप जल्दी पहुंचाएं। इस बात की मैं आदरणीया मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी से आशा करता हूं।

सभापति महोदया, इसके साथ-साथ आदरणीया वसुन्धराजी ने जयपुर शहर की जितनी भी ओवरहैड लाइन्स थीं, आर एस ई बी की, उनको

(श्री अशोक परनामी)

अण्डरग्राउण्ड करवाने का काम किया था, करीबन 25 परसेंट काम पूरा हो गया था, बाकी काम को कांग्रेस की सरकार को पूरा करना था, परन्तु जैसे पहले भी सदन में लोग कहते रहते हैं, सदन में मेरे माननीय सदस्य कहते रहते हैं कि गहलोतजी तो जो भी परियोजना आती है, जोधपुर ले जाते हैं; मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि गहलोतजी उस जयपुर की परियोजना को जोधपुर लेकर गये और जोधपुर में अण्डरग्राउण्ड करना शुरू कर दिया और जयपुर का काम वहीं का वहीं रोक दिया। मैं आदरणीया माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा उस परियोजना को भी आप पूरा करें।

सभापति महोदया, अब मैं थोड़ा सा समअप करता हूं, दस मिनट में।

श्री सभापति: आप, आलरैडी अभी तक 40 मिनट हो गये हैं। (व्यवधान) ठीक है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): दस मिनट। कांग्रेस की सरकार ने, गहलोतजी ने अंत के छह महीने में पेंशन की योजना चालू की; फूड सेफ्टी बिल आया, उसको भी आनन-फानन में लागू किया। (व्यवधान) मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पेंशन का ऐसा हाल था, क्योंकि मैं भी कैम्पों में गया था, छह-छह महीनों तक कैम्प चले, पेंशन बांटो। पेंशन के नाम पर सरकारी अधिकारियों ने पी पी ओ तो बांट दिये लेकिन लोगों के घर पर पेंशन नहीं पहुंची। वह गरीब आदमी पी पी ओ लेकर कभी हमारे पास आता है, कभी डाक घर जाता है कि मेरी पेंशन आ गई क्या? उसको वहां से निराशा हाथ लगती है। यह पेंशन का हाल था।

फूड सिक्योरिटी बिल आनन-फानन में लागू कर दिया गया। राशन कार्ड पर ठप्पे लगा दिये गये। जब गरीब आदमी राशन की दुकान पर जाता था राशन कार्ड लेकर और कहता था कि फूड सेफ्टी बिल के अन्तर्गत जो गेहूं मिलना चाहिए, मुझे वह गेहूं दीजिये, तो राशन की दुकान वाला कहता था कि मेरे पास आपका नाम नहीं आया। निगम में जानकारी करते तो वह कहते कि लिस्टें अभी बन रही हैं।

तो यह पेंशन के नाम पर, फूड सेफ्टी बिल के नाम पर, इस कांग्रेस की सरकार ने राजस्थान प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया, उनको परेशान किया था। आज यदि कांग्रेस की सरकार भामाशाह की योजना बंद नहीं करती, जो आदरणीय वसुन्धराजी ने चालू की थी, तो इतनी तकलीफ नहीं होती पेंशन देने में। घर बैठे हर किसी को पेंशन मिलती। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं

(श्री अशोक परनामी)

आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को जिन्होंने भामाशाह योजना पुन: चालू की और चालू ही नहीं की, 1,500 रुपये की जगह 2,000 रुपये की। घोषणा की इसके लिए आज मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया का धन्यवाद करना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, वह उनका लुक-आउट है। आप बैठें, आप माननीय सदस्य का भाषण सुनें। बहुत अच्छा भाषण हो रहा है।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): सभापति महोदया, माननीया यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी के नेतृत्व में, उनके राज में जयपुर शहर विश्व के नौ सुन्दर शहरों में शुमार हो गया था और इस कांग्रेस की सरकार में विश्व तो बहुत दूर है, देश के 254वें पायदान पर जयपुर आकर खड़ा हो गया है। यह कांग्रेस की देन है।

सभापति महोदया, कांग्रेस के लोग कहते हैं कि किसान विरोधी हैं, ग्रामीण विरोधी हैं, मैं एक छोटी-सी बात बता दूं आपके सामने, गहलोत सरकार के पिछले बजट में कुल बजट का कृषि पर, किसानों के लिए 5.9 प्रतिशत बजट उन्होंने सैंक्शन किया था, जबकि अभी आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने कुल बजट का 6.7 प्रतिशत कृषि के लिए दिया है। इससे यह दिखता है कि हम किसान-विरोधी नहीं हैं, किसान-विरोधी कांग्रेस के लोग थे। इसी प्रकार से, ग्रामीण विकास में कुल बजट का गहलोत सरकार ने 9.07 परसेंट सैंक्शन किया था और हमारी आदरणीया मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने 17.32 प्रतिशत ग्रामीण विकास पर खर्च किया है। इसी प्रकार, जो सामाजिक सेवाएं हैं, जिनकी कांग्रेस दुहाई देती थी, कांग्रेस की सरकार ने, गहलोतजी की सरकार ने सामाजिक सेवाओं पर 37.43 प्रतिशत खर्च किया था कुल बजट का और इस बार आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने 40.70 प्रतिशत दिया है। इसलिए हम ग्रामीण के पक्ष में हैं, आम आदमी के पक्ष में हैं।

सभापति महोदया, मैं आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस वर्ष 2014-15 का जो वार्षिक बजट प्रस्तुत किया है, वह 69,820 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तुत की है, जो पिछले बजट से 72 प्रतिशत अधिक है। इससे निश्चित रूप से राजस्थान प्रदेश का विकास होगा।

(श्री अशोक परनामी)

मैं, अंत में, इतना ही कहूंगा कि यह बजट आर्थिक क्रान्ति का रोडमैप देता है। यह बजट 3 क्रांतियों को एक साथ ला रहा है, एक क्रांति इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, जहां 20 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण होगा, जिसके कारण कई लाख रोजगार बढ़ेंगे; दूसरी क्रांति मैन्यूफेक्चरिंग के क्षेत्र में हुई है जिसमें इलेक्ट्रोनिक्स, टैक्सटाइल्स और सिरेमिक हब बनाने की बात की गई है; तीसरी क्रांति स्किल डवलपमेंट में है जिसमें स्किल डवलपमेंट यूनिवर्सिटी, आई टी, इण्डस्ट्रियल पार्क व स्किल डवलपमेंट हब डवलप करने की बात की गयी है। मैं समझता हूं, आदरणीया वसुन्धराजी ने जो सुराज संकल्प यात्रा के दौरान एक सुराज देने का राजस्थान प्रदेश में वादा किया था, एक विकसित राजस्थान प्रदेश देने का वादा किया था, मैं समझता हूं, इस बजट के माध्यम से वह पूरा परिलक्षित होता है। मैं इस बजट की मन से प्रशंसा करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: मेरा माननीय सदस्यों से निवेदन है कि आज की जो बोलने वालों की सूची है, वह 40 और की शेष है। समय आप सबके सामने है। इसलिए इसमें अपनी बात को आप कहें, निश्चित रूप से इस वाद-विवाद में अपना हिस्सा लें, लेकिन थोड़ा संक्षेप में अपनी बात को कहेंगे तो ज्यादा उत्तम होगा और वह संक्षिप्त 5 से 7 मिनट अगर हुआ, तो भी जाकर हम रात के 10 बजे तक भी इसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा नम्र निवेदन है हमारे सभी माननीय सदस्यों को।

अगले सदस्य हैं, श्री शंकर सिंहजी राजपुरोहित।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): मेरा आधा समय दे दिया, आधा बोलूं?

श्री सभापति: आधा, यानी 5 मिनट केवल।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): दो मिनट में कह दूंगा। सभापति महोदया, वसुन्धराजी के प्रदेश के डाइनेमिक विजन के पक्ष में मैं अपने विचार बिलकुल संक्षेप में, खाली दो-चार बिन्दु रखूंगा।

श्री सभापति: आप जल्दी बोलिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदया, किसी काम को करने के लिए एक मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो निश्चित रूप से काम अच्छा होगा। अधिकारी वही होते हैं, प्रदेश वही है, काम करने का तरीका, काम का मैनेजमेंट, काम की मानिटरिंग, जिस प्रकार से पिछली सरकार में जो

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

घटना हुई है, किसी प्रकार से मैनेजमेंट नाम का कोई काम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मौनी बाबा की सरकार चल रही है। माननीय सभापति महोदया, कई बार ऐसा लगता था कि ये सरकार चला रहे हैं या मजाक कर रहे हैं।

ऐसी जो दो-चार योजनाएं चलीं, जिन पर कम से कम ध्यान सबने लिया है, एक-दो बिन्दु ले लूंगा। अब भ्रष्टाचार में डूबी सरकार, अपने आप में चार वर्षों तक राजस्थान की जनता के साथ घिनौना अपराध किया, राजस्थान की जनता को अनदेखा किया। चार वर्षों तक इनको कुछ सूझा नहीं और अंतिम वर्ष में जब इनकी खुफिया एजेंसी ने कहा कि अब आपकी सरकार नहीं आ रही है, अब आपके घर जाने वाले हों, तो आनन-फानन में दुनिया भर की योजनाएं ले आयें, जिन योजनाओं का कोई ढांचा नहीं बनाया।

अब यह मुफ्त की दवा, अभी मुझसे पूर्व में माननीय सदस्यों ने सारा डिटेल में बता दिया, मुफ्त दवा की इतनी मजाक बनी, फफूंद लगी हुई ग्लूकोज की बोतलें जोधपुर में, पूर्व मुख्य मंत्री के गृह क्षेत्र में बांटी गयीं। लोगों की मौतें हुईं, लोग बेहोश हुए! यह मुफ्त दवा योजना की मजाक हुई। कितना भ्रष्टाचार हुआ।

माननीय सभापति महोदया, ये योजनाएं इसलिए बनायीं कि इनके सबके रिश्तेदारों से, दवा कम्पनियों से दवाई खरीदकर, जिनके मानदण्ड से मरीज ठीक होता ही नहीं था। डाक्टर भी परेशान कि लिखकर दें तो मरीज ठीक नहीं होता है। मरीज कहता था कि मुझे हास्पिटल की दवा नहीं चाहिए। यह कैसा मजाक बन गया सरकार के साथ। यदि सरकार की मंशा पहले अच्छी होती तो ये योजनाएं व्यवस्थित तरीके से लाते। (व्यवधान)

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी मुख्य मंत्री महोदया को, जिस प्रकार से, जिस चुनौती भरे हुए वातावरण के अन्दर चुनौती भरा बजट दिया, समस्याओं का अम्बार लगा हुआ है और उन समस्याओं के इस जाल के अन्दर एक चुनौती भरा बजट हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस की सरकार ने जनता पर 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ रुपये का कर्जा छोड़ा और उस कर्जे से किस तरह से राजस्थान की जनता के साथ एक अन्याय किया। ऐसी चुनौती भरी स्थिति के अन्दर मुख्य मंत्रीजी ने बजट दिया है। विद्युत कम्पनियों पर 75 हजार करोड़ का घाटा दिया है, हर तरीके का लीकेज है, इसके लिए जितना कहना चाहें, कम है और वैसी स्थिति में एक

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

बढ़िया विजन मुख्य मंत्री महोदया ने दिया है। चाहे वह पब्लिक-प्राइवेट-पार्टनरशिप के माध्यम से हो, हर योजना को कहीं न कहीं, किसी न किसी तरीके से ठीक करना है और हम करेंगे। सारे आंकड़े दिये हैं, सब दिये जाएंगे, एक-एक योजना का आकार अच्छा देंगे।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्री महोदया को, जैसा अभी बताया माननीय अध्यक्षजी ने कि 20 हजार किलोमीटर सड़क का मैप बनाया, ऐसी परिस्थिति में जब खजाना खाली कर दिया है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने ही कहा था कि मैं दो ही मिनट बोलूंगा, लेकिन 8 मिनट हो चुके हैं।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): ऐसा क्यों? सभापति महोदया, आप कुर्सी पर बैठी हैं और आप अगर अन्याय करें तो यह तो ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप संक्षिप्त कर लीजिए। जो अंतिम लाइन आपको बोलनी है, वह बोल दीजिए।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): बोल देता हूं। माननीय सभापति महोदया, बिलकुल संक्षिप्त कर देता हूं।

आज हिन्दुस्तान की जनता ने ऐसे नेता को केन्द्र में शासन दिया है जो इस देश की मूल धारा से जुड़ा हुआ एक सन्यासी है, वैसे व्यक्ति को इस देश को शासन दिया है। नदियों को नदियों से जोड़ने का विजन अटल बिहारीजी वाजपेयीजी ने लिया था, उसी विजन को आगे बढ़ाते हुए नरेन्द्र भाई मोदी आगे लाये हैं और उसी बात को वसुन्धराजी ने, इसको पूरा करने की जो सौगात हमने ली है और नदियों से नदियों को जोड़ना, यह हमारी जीवन रेखा है।

माननीय सभापति महोदया, पुराने जमाने की बात करें तो नदियों और तालाबों के किनारे गांव बसते थे। हमने नदियों के ऊपर बांध बना दिये, गांवों को सुखा दिया, डार्क जोन में नदियां आ गयीं। अब नदियों से नदियां जोड़ना जरूरी है। एक जीवन रेखा, एक जीवन्त नदियां जुड़ेंगी।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री महोदया को इतना ही निवेदन करूंगा कि माही बजाज का पानी, जो 1966 में गुजरात सरकार और राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता हुआ था, उस समझौते में यह कहा गया था कि माही का पानी जो गुजरात में जा रहा है, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा का पानी

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

आने के बाद, वह 44 टी एम सी पानी जालौर, सिरोही, बाड़मेर और पाली जिलों को मिलेगा। बड़े दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि 2008 में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में नर्मदा का पानी तो पहुंच गया, 2008 के बाद, जो पूर्ववर्ती सरकार है वह एक सिंगल पत्र भी राजस्थान की पश्चिमी जनता के लिए नहीं लिख पाई। यह दुर्भाग्य का विषय है।

मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्री, वसुंधराजी को निवेदन करूंगा कि आप, अपने घोषणा पत्र में जो कहा था कि माही बजाज का पानी कैसे आये, और इतना पानी है कि पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, चारों जिलों को 365 दिन और 24 घण्टे नहरों से सिंचित किया जा सकता है; माननीय सभापति महोदया, अगर पानी मिला तो वहां की धरती केसर उगलेगी, केसर वहां पर उगेगी, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है कि इस माही बजाज पर विशेष ध्यान दें। माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से मैं मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करूंगा कि कम से कम सर्वे के लिए तो एक बजट सैंक्शन करें जिससे हमारी जनता को राहत मिले।

श्री सभापति: अगले सदस्य।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): एक मिनट। मैं मेरे एरिया की बात कह रहा हूं, एक धन्यवाद देना चाहूंगा। बजट के अन्दर 303 करोड़ रुपया नर्मदा के लिए, एफ.आर. प्रोजेक्ट के लिए जो जालौर और आहौर के लिए दिया है, उसके लिए मैं मुख्य मंत्री महोदया का मेरी ओर से और मेरी जनता की ओर से धन्यवाद करता हूं। माननीय सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से, जवाई नदी में पानी छोड़ना है, लेकिन जब नदियां जुडेंगी, जवाई बांध में पानी माही बजाज का आयेगा, तो निश्चित रूप से सारे नौनिहाल हो जाएंगे।

अब मैं आपके माध्यम से, मेरे आहौर में जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहां पर राजकीय महाविद्यालय के लिए मैंने निवेदन किया हुआ है, वह ले लें। एक भाद्राजून में सी.एच.सी. के लिए मेरा निवेदन है। सियाणा में उप-तहसील बनाई जाए, यह भी मेरा एक निवेदन है। आहौर में कोर्ट नहीं है, उस कोर्ट के लिए मेरा निवेदन है।

सारी माइंस आहौर में हैं और वहां पर एक भी इण्डस्ट्री नहीं है। 80 प्रतिशत इलाका खाली बरसाती मौसम पर है, न कोई उद्योग-धंधे हैं। इसलिए वहां पर रीको डवलप किया जाए। यह मेरा निवेदन है।

(श्री शंकरसिंह राजपुरोहित)

सबसे अंत में, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि हिन्दुस्तान में एक पहला इतिहास बनेगा जिसमें गोपालन मंत्रालय हमारी सरकार बनाने जा रही है। आज की स्थिति में यह आ गया है कि आज गौशालाओं में चारा नहीं है। तो अब किसी न किसी माध्यम से गौशालाओं को अनुदान के लिए मेरा करबद्ध निवेदन है।

माननीय सभापति महोदया, आपने जल्दबाजी में जो भी हमें समय दिया, कोई बात नहीं, हमारे प्रदेश अध्यक्षजी थे, इसलिए हमने हमारा समय उनको दे दिया था, लेकिन आपने जो मुझे बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अब यह राजस्थान की जनता बहुत-बहुत धन्यवाद देगी कि डायनेमिक मुख्य मंत्री, डायनेमिक विजन और डायनेमिक राजस्थान हिन्दुस्तान की धरती पर बनेगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डा. मंजू बाघमार। समय का ध्यान रखें, मुझे बार-बार बीच में बोलना न पड़े।

डा. मंजू बाघमार (जायल): माननीय सभापति महोदया, सबसे पहले मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुंधरा राजेजी को धन्यवाद देती हूं कि निश्चित रूप से यह बजट सुराज स्थापित करने में और आने वाले कल के सशक्त और सुनहरे राजस्थान की नई इबारत लिखेगा। बजट केवल आय-व्यय की अभिव्यक्ति का, कागज का पुर्जा मात्र नहीं है, वरन् यह करोड़ों मतदाताओं और राजस्थानवासियों, जिनके समर्थन से भाजपा को 163 सीटें प्राप्त हुई हैं, उनकी उम्मीदों और विश्वास को जगाने वाला और उन्हें सम्बल प्रदान करने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है।

विगत कांग्रेस शासन ने ऐसे दिशाहीन बजट प्रस्तुत किए जिनमें न तो उनका वित्तीय अनुशासन था और न ही रोजगार सृजन की सम्भावनाएं थीं। कांग्रेस सरकार की आर्थिक नीतियों और दिशाहीन बजट, दिशाहीन विकास के दौर में राजस्थान को विकास के अंतिम पायदान पर लाकर खड़ा कर दिया।

यह बजट अनगिनत गरीब और वंचित लोगों की उदासीन जिन्दगी में खुशियों की सौगात प्रदान करने वाला है और उन्हें समाज की मुख्य धारा में शामिल करने का कार्य करेगा। वर्तमान में मुख्य मंत्री महोदया द्वारा राज्य की अर्थव्यवस्था को एक सार्थक और सकारात्मक कदम, सकारात्मक दिशा देने का प्रयास किया गया है जो राज्य के आर्थिक विकास को अग्रसर करेगा।

(डा. मंजू बाघमार)

माननीय सभापति महोदया, वार्षिक योजना का आकार 46,990 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 69,820 करोड़ करना, मुख्य मंत्री महोदया की राज्य के समग्र विकास की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और निश्चित रूप से राज्य इसमें विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ेगा।

मुख्य मंत्री महोदया ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से शक्ति और शिक्षा, दोनों को महत्व देकर अपनी संवेदनशीलता का परिचय दिया है जिसके कुछ उदाहरण, महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए सेल्फ-डिफेंस ट्रेनिंग प्रदान करना है; राज्य के 100 चयनित आंगनबाड़ी केन्द्रों को शिशुपालना गृह के रूप में विकसित करने हेतु 2014-15 में दो करोड़ रुपये का व्यय किया जाना है। महिला बी पी एल परिवारों को दो हजार रुपये, विधवाओं को पारिवारिक पेंशन, आंगनबाड़ी कर्मियों को यशोदा अवार्ड, एस सी, एस टी और बी पी एल महिलाओं के पक्ष में विक्रय पत्रों पर स्टाम्प ड्यूटी चार प्रतिशत से घटाकर तीन प्रतिशत करना, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 में प्रवेश करने वाली समस्त बालिकाओं को साइकिल प्रदान करना, इत्यादि सराहनीय कदम हैं।

माननीय सभापति महोदया, राज्य की 186 शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई पंचायत समितियों में अंग्रेजी माध्यम के माडल स्कूल खोले जाना ग्रामीण विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा का सामना करने में सहायक सिद्ध होंगे।

साथ ही, राज्य सरकार ने इस बजट में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में संचालित आई आई एम, आई आई टी, एन आई टी एवं अन्य राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं में चयनित होने वाले राज्य के विद्यार्थियों को स्कालरशिप प्रदान करने से राज्य के विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ेगा। इसके अलावा, 7 नये मेडिकल महाविद्यालय खोलना और तीन नये अभियांत्रिकी महाविद्यालय खोलना, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षणिक वातावरण के एक नये युग की शुरुआत होगी।

इस बजट में पहली बार परम्परागत शिक्षा से हटकर, स्किल डवलपमेंट के लिए एक स्किल यूनिवर्सिटी की स्थापना करना, निश्चित रूप से भारत में एक अनूठा प्रयास है, जो राज्य के विकास में एक इंजन साबित होगा।

माननीय सभापति महोदया, मुख्य मंत्री महोदया द्वारा तकनीकी विकास पर भी जोर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार तकनीक का प्रभावी प्रयोग करने हेतु 2014-15 में 9,177 ग्राम पंचायतों तथा समस्त जिला स्तरीय

(डा. मंजू बाघमार)

कार्यालयों में आई.पी. फोन के प्रस्ताव हैं। कम्प्यूटराइज्ड बार्डर चैकपोस्ट की स्थापना करना, इससे न केवल राज्य के विकास में गतिशीलता होगी, बल्कि पारदर्शिता भी बढ़ेगी और भ्रष्टाचार भी समाप्त होगा।

राजस्थान के इतिहास में पहली बार बजट में हमने पी.पी.पी. मोड को स्वीकार किया है और इन्फ्रास्ट्रक्चर, बिजली और हायर एजुकेशन में इसको स्वीकार किया है। इसे इतना वाइड कवरेज दिया गया है जिससे निश्चित रूप से राज्य जो आर्थिक संकट से जूझ रहा है, उसे दूर करने में सहायता मिलेगी।

यह देश का पहला ऐसा बजट है जिसमें 67 प्रतिशत जनता को, ¾ जनरेशन को हैल्थ इंश्योरेंस से कवर किया गया है। यह अपने आप में एक महत्वाकांक्षी कदम है।

राज्य के आधारभूत संरचना विकास के साथ आर्थिक विकास दर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष के उच्च स्तर पर ले जाने तथा प्रति वर्ष तीन लाख से अधिक नये रोजगार उपलब्ध कराने के प्रस्ताव भी सराहनीय हैं।

राज्य में अलग से अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा बोर्ड का गठन किये जाने का निर्णय भी सराहनीय है।

बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए RMOL और RSLDC के द्वारा ढाई लाख परिवारों को स्वरोजगार से जोड़ा जायेगा, उन्हें टूल किट्स उपलब्ध कराये जाएंगे, जो निश्चित रूप से बेरोजगारों को आजीविका में सम्बल प्रदान करेगा।

यदि हम सड़कों की बात करें तो 20 हजार किलोमीटर लम्बाई की सड़कों का विकास करना, पहली बार राज्य के विकास में इतना बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट हमने रखा है। सड़कों के रखरखाव हेतु 100 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। इससे न केवल आधारभूत ढांचे का विकास होगा, बल्कि रोजगार का भी सृजन होगा और राजस्थान राज्य भारत के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा।

भामाशाह योजना, गुरु गोलवलकर योजना के माध्यम से जनसहभागिता से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय विकास को बढ़ावा मिलेगा। आम आदमी जो पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहा है, इस दिशा में गांव-ढाणियों में शुद्ध पेयजल, गुणवत्तायुक्त पानी उपलब्ध कराने के लिए 2014-15 में 1,000 आर.ओ. संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव भी स्वागत-योग्य है।

(डा. मंजू बाघमार)

पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ करने एवं ग्रामीण जलप्रदाय योजनाओं को प्रभावी रूप से उत्तरदायी बनाने के उद्देश्य से पंचायतों के पास उपलब्ध टी एफ सी और एस एफ सी, अनुदान का एक निश्चित अंश पेयजल आपूर्ति के लिए किया जाना अनिवार्य करने से पेयजल समस्या से निजात मिलेगी और 2014-2015 में 3,173 ग्राम ढाणियों में पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जायेगी।

माननीय सभापति महोदया, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इस बजट में राज्य के पेयजल संकट को देखते हुए पेयजल परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 2,171 करोड़ रुपये का अंतरिम बजट में प्रावधान तथा 289 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। उसमें मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध करना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल के अन्दर पेयजल की गम्भीर समस्या है। इसमें वर्तमान में मातासुख परियोजना वहां पर संचालित है लेकिन वहां पर पेयजल के लिए जो पानी उपलब्ध कराया जा रहा है, वह न केवल मनुष्यों के लिए, बल्कि पशुओं के पीने लायक भी नहीं है। विभाग द्वारा सरकार को बार-बार गुमराह किया जा रहा है। मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदया से अनुरोध रहेगा कि जायल क्षेत्र की पेयजल की गम्भीर समस्या को दूर करने के लिए बजट में कुछ करोड़ रुपये का ही प्रावधान करने की आवश्यकता होगी। जो नहर का पानी नागौर में पहुंच चुका है, नागौर से फर्लोड तक, मेरे विधान सभा क्षेत्र के गांव फर्लोड तक, जहां पर पानी का स्टोरेज बनाया गया है और पूरे जायल क्षेत्र के अन्दर पानी की पाइपलाइनें बिछी हुई हैं, यदि 35 किलोमीटर की लम्बी पाइपलाइन वहां से जोड़ दी जाये तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया का पूरे नागौर जिले को नहर के मीठे पानी पिलाने का जो सपना था, वह सपना भी साकार होगा। जायल की जनता को आशा ही नहीं, बल्कि पूर्ण विश्वास है कि हमारे इस अनुरोध को स्वीकार किया जायेगा।

अंत में, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को पुन: धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने योजनाओं को संतुलित आकार दिया है और राजकोष का सदुपयोग-उपयोग करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है और ''आओ साथ चलें'' के नारे के साथ सभी वर्गों को साथ में लेकर, राजस्थान के विकास को बुलंदियों पर छूने की एक परिकल्पना पेश की है। धन्यवाद। आपने मुझे मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डा. बालूरामजी चौधरी।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): माननीय सभापति महोदया, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने 14 तारीख को यहां जो बजट पेश किया था, वह अपने आप में अनूठा, बहुत सक्षम, राजस्थान को विकसित करने वाला, आत्मनिर्भर बनाने वाला और राज्य को विकास के पथ पर ले जाने वाला बजट है। महोदयाजी, आपके माध्यम से मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन्होंने राज्य को 2020 तक विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति, दूरगामी सोच और एक विजन के साथ बजट प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से राजस्थान, हिन्दुस्तान के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आयेगा।

सुराज संकल्प यात्रा के दौरान माननीया वसुन्धराजी गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, गरीबों, किसानों, हर क्षेत्र में, हर जगह जाकर सबसे रूबरू हुई हैं और उनकी समस्याओं को अपनी आंखों से देखकर सारी चीजों को इस बजट में डाला है। उस बजट में डालकर, उनकी समस्याओं को देख-देखकर बजट बनाया है, वह बहुत ही अच्छा बजट है। इसकी जितनी तारीफ की जाये, उतनी ही कम है।

पिछली सरकार ने, जिन आर्थिक हालात में सरकार मिली है, वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब है, कर्जा बहुत बढ़ा हुआ है, राजस्व घाटा है। जब वसुन्धराजी ने अशोकजी को सरकार सौंपी थी, उस समय वसुन्धराजी ने 1,653 करोड़ रुपये का सरप्लस फण्ड इनको राजस्व में दिया था। गहलोत साहब ने उसको वापस घाटे पर लाकर, 2,500 करोड़ राजस्व घाटा कर दिया, 2014 तक। यही नहीं, 2008 में जो कर्ज था, वह 77,138 करोड़ था, जो 2014 में वह पहुंच कर 1,30,640 करोड़ रुपये हो गया। यही नहीं, वसुन्धराजी ने जो 850 करोड़ रुपये विकास एवं गरीबी उन्मूलन निधि के नाम से बचाकर रखे थे, उस पैसे को भी इन्होंने उड़ा दिया।

इस तरह से पूरे राज्य का वित्तीय प्रबन्धन इतना खराब रहा। जिस रूप में अभी वसुन्धराजी ने चार्ज लिया है, ऐसा खराब वित्तीय प्रबन्धन होने के बावजूद भी, ऐसी विकट आर्थिक परिस्थिति होने के बावजूद भी माननीया वसुन्धराजी ने जिस तरह का बजट दिया है, जिस तरह का विजन दिया है, वे बहुत-बहुत बधाई की पात्र हैं। इससे परिलक्षित होता है कि उनका वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा है। जब-जब वे शासन में रही हैं, वित्तीय प्रबन्धन बहुत अच्छा करके, राज्य को बहुत आगे ले गयी हैं।

(श्री बालू राम चौधरी)

माननीय सभापति महोदया, समय की कमी की वजह से मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन मुख्य-मुख्य बातें आपके ध्यान में लाना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 15 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है; प्रति वर्ष तीन लाख युवाओं को रोजगार देकर आने वाले पांच सालों में 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जायेगा और उसके लिए 70,000 करोड़ रुपये का बजट रखा है। यह बहुत बड़ी सोच है और युवाओं के लिए बहुत बड़ी सौगात है।

यही नहीं, राज्य के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर डवलपमेंट बहुत जरूरी होता है। उसके लिए, सड़कों के निर्माण के लिए, 20,000 किलोमीटर सड़कों का निर्माण किया जायेगा, जिससे गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जुड़ जायेंगे।

पहले मैडम ने नोर्थ-साउथ कोरिडोर बनाया था, इस बार ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर का निर्माण किया जायेगा।

यही नहीं, राजस्थान स्टेट हाइवे अथोरिटी का गठन किया जायेगा जिससे रोड्स में गुणवत्ता रहे और राजस्थान को बहुत अच्छी रोड्स की सौगात मिले। इन रोड्स की मेंटीनेंस के लिए ओ पी आर सी पद्धति के माध्यम से आने वाले आठ साल तक इनको बहुत अच्छा मेनटेन किया जायेगा ताकि जनता को कोई तकलीफ नहीं हो।

''ग्रामीण गौरव पथ'' योजना के माध्यम से 9,000 से अधिक पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जायेगा; 250 से 500 की जो आबादी है, ऐसे 530 गांवों को सड़कों से जोड़ा जायेगा। इस तरह से, पूरे राजस्थान में सड़कों का एक तरह से जाल बिछ जायेगा। जब सड़कें अच्छी होंगी, राज्य का विकास होगा।

सड़कों पर परिवहन के लिए, यात्रा के लिए जिस तरह का अभी सिस्टम चल रहा था, उससे जनता बहुत परेशान थी। आदरणीया मुख्य मंत्रीजी ने सारे नेशनलाइज्ड रोड्स को डि-नेशनलाइज कर दिया है। इन रोड्स पर प्रतिस्पर्द्धा भी बढ़ेगी, निजी क्षेत्र की गाड़ियां भी इस पर आयेंगी। यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी, बहुत जल्दी सुविधा मिलेगी।

दूसरा, रोडवेज बस अड्डों में इनकी गुणवत्ता सुधारने के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए, आधारभूत सुविधा डवलप करने के लिए राजस्थान स्टेट बस कारपोरेशन का गठन किया गया है। इसके लिए 360 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।

(श्री बालू राम चौधरी)

राज्य की सीमाओं पर चैक पोस्टों को कम्प्यूटराइज करके और वहां ओवर-लोडेड वाहनों की जो प्रोब्लम थी, वहां सारे वे-ब्रिज स्थापित किये जा रहे हैं। उससे जो भी वाहन ओवर-लोड होगा, उनका वहीं चालान होकर, उनसे वहीं पेनल्टी वसूल की जायेगी। इस रूप से, स्टेट के सारे चैक पोस्टों पर बहुत अच्छा कार्य होगा।

ऊर्जा के क्षेत्र में पिछले पांच सालों से जनता में बहुत त्राहि-त्राहि है। माननीया मुख्य मंत्रीजी का जो लक्ष्य है, 24x7, 24 घंटे बिजली उपलब्ध होनी चाहिए, इसी लक्ष्य के साथ वे काम कर रही हैं। बहुत ही शोर्ट स्पान में, पिछले सात महीने में इस सरकार ने 900 मेगावाट बिजली का अतिरिक्त उत्पादन किया है। उसमें 600 मेगावाट कालीसिंध से, छबड़ा में 250 और रामगढ़ में 500 मेगावाट बिजली पैदा की। इसी वित्तीय वर्ष में 850 मेगावाट और बिजली उत्पादन करने का लक्ष्य है और आने वाले पांच वर्षों में 6,500 मेगावाट का लक्ष्य है। इसलिए अल्टिमेटली यह टारगेट है कि जनता को सुचारु रूप से रेगुलर थ्री फेज और वन फेज, दोनों तरह की बिजली लगातार उपलब्ध रहे और इस टारगेट तक पहुंचना है कि बिजली सरप्लस हो और अपन दूसरों को दे सकें।

कृषि कनेक्शन के मामले में किसान बहुत परेशान थे, 3.11 लाख कनेक्शन की अभी वेटिंग लिस्ट बनी हुई है। वसुंधरा राजे जी की सरकार आने के बाद इस वित्तीय वर्ष 2014-15 में 40 हजार कृषि कनेक्शन का टारगेट रखा गया है। जो ड्रिप इर्रिगेशन के माध्यम से अगर सिंचाई करना चाहते हैं, उनको आन-डिमाण्ड कनेक्शन दिए जाएंगे। सुदूर पूर्व इलाके, जहां बिजली नहीं पहुंचाई जा सकती है, ऐसे रिमोट एरियाज हैं वहां लोकल सोलर ड्रिप एण्ड स्टैण्ड अलोन सोलर सिस्टम डवलप करके 10 हजार गांवों को बिजली उपलब्ध कराई जाएगी।

पेयजल के मामले में, पंचायतों के पास जो भी पेयजल योजनाएं हैं। उनको पी एच ई डी के माध्यम से सही करवाकर के वापस पंचायतों को सुपुर्द किया जाएगा और पंचायत के पास टी एफ सी और एस एफ सी का जो फण्ड होता है, उसमें एक निश्चित अंशदान पेयजल के लिए हमेशा रखा जाएगा, जिससे सुचारु रूप से गांव में पेयजल उपलब्ध रहे। 2014-15 में 3,173 नये गांवों को पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा और पेंडिंग पड़ी जो 12 वृहद्

(श्री बालू राम चौधरी)

परियोजना थीं, उनको इसी वर्ष पूरा किया जाएगा। उसके लिए 2 हजार 171 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बहुत अच्छी बात है। ये बहुत बड़ी-बड़ी परियोजनाएं हैं, ये इसी वर्ष पूरी हो जाएंगी।

जल संसाधन के मामले में नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम है, उसमें राजस्थान रिवर बेसिन अथोरिटी का गठन किया गया है, जिससे जल का संचय हो, जल वेस्ट न हो और जहां अतिवृष्टि होती है वहां का पानी जहां कम वृष्टि है या कम पानी होता है, वहां डाइवर्ट किया जा सके।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षिप्त करें।

श्री बालू राम चौधरी (सहाड़ा): शहरों के विकास के लिए राजस्थान अरबन ड्रिंकिंग वाटर, सीवरेज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन का गठन किया गया है; राजस्थान अरबन लैंड बिल भी लाया गया है। शेष शहरों में जहां मास्टर प्लान नहीं बने हैं, उन शहरों के इसी वर्ष मास्टर प्लान बन जाएंगे। गाँवों में 'श्री योजना' के माध्यम से ग्राम स्वच्छता, चिकित्सा, सड़क, शिक्षा एवं विद्युत योजनाओं का पूरा कवरेज किया गया है। पिछड़े एरिये के लिए विशेष पैकेज दिये गये हैं जिनमें मेवाड़ क्षेत्रीय विकास बोर्ड, मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड, डांग क्षेत्रीय विकास बोर्ड, देवनारायण बोर्ड, इन सारों हेतु 300-300 करोड़ का बजट पास किया गया है। 55 नई शहरी लैबोरेटरीज का गठन किया गया है।

मैं आदरणीया मुख्य मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इस वर्ष उन्होंने पूरे राजस्थान में सात नये मेडिकल कालेज खोलने की घोषणा की है। पिछले 65 वर्षों में पूरे राजस्थान में सरकार के माध्यम से केवल छह ही मेडिकल कालेज थे और एक ही वर्ष सात मेडिकल कालेज लाना, एक अपने आप में आठवां आश्चर्य है। 700 नये मेडिकल स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। धीरे-धीरे करके अपने राजस्थान में चिकित्सकों की जो कमी है, इतने चिकित्सक निकलेंगे कि आने वाले चार साल, पांच साल बाद अपने चिकित्सकों की जो मैनपावर की कमी है, उसकी भरपाई होगी, और उस क्षेत्र में जहां-जहां मेडिकल कालेज खुल रहे हैं, वहां के क्षेत्र की जनता को चिकित्सा का बड़ा लाभ मिलेगा।

मेडिकल की सेवा में कैंसर एक महामारी रूप में आ रही है, इतने ज्यादा बीमार पूरे राजस्थान में हैं। उसके लिए झालावाड़ और बीकानेर में टरशरी कैंसर सेंटर खोला है और सारे जो दूसरे मेडिकल कालेज हैं, उनमें भी कैंसर चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र खोले हैं।

(श्री बालू राम चौधरी)

सुपर स्पेशलिटी के मामले में राजस्थान बहुत पीछे था। इस बजट में बीकानेर, उदयपुर और कोटा, तीन मेडिकल कालेजों में 150-150 करोड़ का प्रावधान रखकर के सुपर-स्पेशलिटी का डवलपमेंट किया गया है।

स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्दर जो कवरेज आता है, उन सारे आदमियों को रूटिन इलाज के लिए तीस हजार का और गम्भीर बीमारियों के लिए तीन लाख के बीमे का प्रावधान है जिसमें उनको सारी चीजें ये उपलब्ध होंगी और उनको जो ओ पी डी में फ्री मेडिसिन और फ्री जांच की सुविधा है, वह भी उपलब्ध रहेगी। इंस्टिट्यूट आफ ट्रोमोलोजी और आर्थोपेडिक्स के लिए जयपुर में बहुत बड़ा सेंटर बना है। उनके लिए बनकर तैयार हो गया है; 15 करोड़ का और प्रावधान किया है। वह बहुत जल्दी चालू हो जाएगा। उससे रोड एक्सिडेंट में ट्रोमा के जितने केस आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी, गुणवत्ता वाली सर्विसेज मिलेंगी। जनता को इससे बहुत फायदा होगा। इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं।

कोई भी बजट हंड्रेड परसेंट नहीं होता है, हमेशा उसमें सुधार की सम्भावनाएं रहती हैं। मैं मेडिकल फील्ड के बारे में थोड़ा सा निवेदन करना चाहूंगा। गांवों में ए एन एम, नर्सिंग स्टाफ, डाक्टर्स के आलमोस्ट आधे पद रिक्त हैं। मेरा सुझाव है कि जो अवेलेबल मैनपावर है, उसके बारे में कोई ऐसी योजना बनाई जाए जैसा कि स्कूलों के एकीकरण के बारे में किया गया है। जो-जो मैनपावर, जो कहीं ए पी ओ हैं, कहीं बैठे हैं, कहीं काम नहीं है तो भी ऐसा है, तो उनको एग्रीगेट करके, एक ऐसी कमेटी बनाकर के, उनके डैटा इकट्ठे करके, उनकी मैक्सिमम प्रोडक्विटविटी का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उस बारे में थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है और हम सबको भी विचार करने की जरूरत है।

मेरे क्षेत्र की एक मुख्य समस्या के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। अपन सारी योजनाएं बना रहे हैं, किसानों के लिए पानी उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों के लिए बिजली उपलब्ध करा रहे हैं, किसानों के लिए अपन खाद दे रहे हैं, किसानों को बिजली दे रहे हैं ताकि किसान की फसल बहुत अच्छी हो। जब किसान की फसल बहुत अच्छी हो जाती है, एक दिन ऐसा आता है कि रात में सारे रोजड़े, जिसको नील गाय कहते हैं, यह समस्या हमारे क्षेत्र में,

(श्री बालू राम चौधरी)

विशेषकर रात को आते हैं और पूरी फसल साफ करके चले जाते हैं। किसान अपने आपको बिलकुल असहाय और ठगा सा महसूस करता है। उसके पास करने को कुछ नहीं रहता है। सुराज संकल्प यात्रा के दौरान इस बारे में विचार माननीया मुख्य मंत्रीजी के ध्यान में लाया गया था और उन्होंने इस बारे में विचार करने का आश्वासन भी दिया था कि किसानों को अपने खेतों में तारबंदी करने के लिए एक विशेष बजट दिया जाएगा और उसमें सब्सिडी का प्रावधान किया जाएगा, ताकि किसान अपनी फसल की रक्षा कर सकें, ताकि उनको ये सारे जो लोसेज हो रहे हैं, वे नहीं हों। यह बहुत बड़ी गम्भीर समस्या है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं इस बारे में सबका ध्यान आकर्षित करता हूं।

एक बार पुन: मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इतना अच्छा और इतना बढ़िया बजट पेश किया है और माननीया सभापतिजी का भी बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे बोलने का समय दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री विट्ठल शंकरजी अवस्थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): आदरणीय सभापति महोदया, इस सदन के हालात देखते हुए मुझे माननीय नरेन्द्र मोदीजी का वह जुमला याद आता है कि इस देश को कांग्रेस-मुक्त बनाना है और मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि यह राजस्थान का सदन कांग्रेस-मुक्त है और कांग्रेस अल्पसंख्यक-मुक्त है और एस सी-मुक्त है। पहली बार राजस्थान के इतिहास में ऐसा विपक्ष आया है जो बिलकुल नाकारा है।

जो बजट प्रस्तुत हुआ है, पहले भारत का बजट प्रस्तुत हुआ, उसके बाद राजस्थान का हुआ और मैं दावे के साथ कहता हूं कि बजट पर जो प्रतिक्रियाएं आई हैं, वे इतनी शानदार हैं कि ऐसा बजट राजस्थान के इतिहास में पहले कभी पेश नहीं किया गया। किसी भी क्षेत्र में लीजिए आप, चाहे शिक्षा, चाहे चिकित्सा, चाहे सड़क, चाहे बिजली, चाहे महिला, चाहे कानून-व्यवस्था, इस बजट में हर पहलू को छुआ गया है, हर वर्ग को छुआ गया है।

जो हालत राजस्थान में शिक्षा की इस कांग्रेस की सरकार की थी, उसका परिणाम इस वर्ष आया है और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो नौवीं क्लास, आठवीं क्लास के जो रिजल्ट हैं और नौवीं क्लास में जो बच्चे इस वर्ष

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

पढ़े हैं, जिस संख्या में वे फेल हुए हैं, वह एक इतिहास है। इस पूरी शिक्षा पद्धति का भट्ठा बैठा कर कांग्रेस ने जो इस पीढ़ी के साथ पाप किया है, आने वाले पीढ़िया भविष्य में इस कांग्रेस को माफ नहीं करेंगी।

सभापति महोदया, हमारे शास्त्र और बुजुर्ग कह गये हैं कि विद्या ही सबसे बड़ा धर्म है।

न चोरहार्य न च राजहार्य न भ्रातृभाज्यं न च भारकारी । व्यये कृते वर्धते एव नित्यं विद्याधनं सर्वधन प्रधानम् ॥

अगर इस शास्त्रोक्त वाक्य पर कांग्रेस सरकार का ध्यान होता तो ना तो इतने बेरोजगार पैदा होते, न शिक्षा की यह दुर्गति होती। आज पहली से

(16.00 बजे)

आठवीं तक जो इन्होंने बिना पास किये नवीं में बैठाने का निर्णय लिया था, वह इस ग्रामीण पीढ़ी के लिए विनाशकारी सिद्ध हुआ है और यह पूरी एक पीढ़ी को खराब करने का कार्य किया गया है। इस पाप से यह कांग्रेस कभी मुक्त नहीं हो सकती। शिक्षा मंत्रीजी यहां विराजमान हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आने वाले समय में शिक्षा को वापस पटरी पर लाने के लिए और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए वापस व्यवस्थाएं सुधारें। यह आपसे निवेदन है।

इस बजट में भीलवाड़ा को जो मेडिकल कालेज दिया गया है, मुख्य मंत्रीजी को मैं अपनी तरफ से और मेरी जनता की तरफ से बहुत-बहुत साधुवाद देता हूं और यह विश्वास दिलाता हूं कि जो आपने यह उपकार भीलवाड़ा पर किया है, उसका कई वर्षों तक आपको प्रतिफल मिलेगा। यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूं।

आज भीलवाड़ा टैक्सटाइल इण्डस्ट्री में एशिया का मैनचेस्टर कहलाता है और लगभग 80-85 करोड़ मीटर कपड़ा प्रति वर्ष वहां भीलवाड़ा में बनता है। पिछली सरकार ने जो दुर्गति इस वस्त्र उद्योग की की थी, उस दुर्गति से कई उद्योग-धंधे बंद हुए थे और कई राज्य से बाहर पलायन किये, महाराष्ट्र गये, गुजरात गये, एम पी गये। आज आपने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर राजस्थान में जो नयी टैक्सटाइल पालिसी की घोषणा की है और एक माह के भीतर-भीतर इसको लागू करने का एलान किया है, मैं इसके लिए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजे को बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित

(श्री विट्ठल शंकर अवस्थी)

करता हूं और विश्वास करता हूं कि इस नीति को सम्पूर्णता से लागू किया जाएगा।

राजस्थान में वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा क्षेत्र है और इसके माध्यम से लाखों व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। भीलवाड़ा अकेले में 80 करोड़ मीटर कपड़ा प्रतिवर्ष बनना अपने आप में एक रिकार्ड है। आप सब लोगों से यह प्रार्थना है कि इस बजट को दूरगामी दृष्टि से देखते हुए और इस बजट के जो रिजल्ट आएंगे, वे एक-दो दिन में नहीं, आने वाले ये पांच-दस सालों में इस बजट के रिजल्ट मिलने वाले हैं। इस राजस्थान को जो एक नयी दिशा मिलेगी, एक गति प्रदान होगी, उससे इस राजस्थान को देश के नक्शे में अपना स्थान सुरक्षित करने में मदद मिलेगी।

पेयजल के क्षेत्र में चम्बल परियोजना की घोषणा इस कांग्रेस सरकार ने पहले बजट में की थी। पांच वर्ष में पूरे जिले के प्रत्येक गांव को पानी देने का इन्होंने पहले बजट में वादा किया था और पांच वर्ष में एक गांव को पानी नहीं पिला सके ये। हमारे माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने पांच वर्ष में स्वर्णिम चतुर्भुज बना कर पूरे देश को सड़कों से जोड़ दिया था, लेकिन पांच वर्ष में ये चम्बल का पानी भीलवाड़ा तक नहीं ला सके और पांच साल हर बजट में चम्बल का नाम लेकर चले गये। अब मैं इस सरकार से आशा करता हूं कि इसी वर्ष हमको चम्बल का पानी मिलेगा और भीलवाड़ा जिले की पूरी जनता आप सबको बहुत-बहुत आशीर्वाद देगी।

इस बजट के माध्यम से मैं इस सरकार का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और आशा करता हूं कि आने वाले पांच साल के बजट ऐसे होंगे जिनसे राजस्थान सौ वर्षों तक पिछड़ा प्रदेश नहीं कहलायेगा, ऐसा मेरा विश्वास है।

आपने मुझे बोलने के लिए जो समय दिया, उसमें एक निवेदन और करता हूं कि मेरे पुर कस्बे में, चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजमान नहीं हैं, 70 हजार की आबादी है उस कस्बे में, पी एच सी चालीस वर्षों से है, उसको क्रमोन्नत करने के लिए वहां की जनता बार-बार आग्रह कर रही है। उनसे तो हमने पांच साल तक भीख मांगी थी, एक तरह से हाथ जोड़-जोड़ कर थक गये थे लेकिन नहीं सुना गया। इस सरकार में निश्चित सुनवाई होगी, ऐसा विश्वास है।

आप सबने मुझे सुना और, सभापति महोदया, आपने बोलने का समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ने मात्र सात मिनट में अपनी पूरी बात कही, बिना किसी भूमिका के, और इतने अच्छी तरीके से बात कही। एक बार और उनके लिए हम लोगों को ताली बजानी चाहिए।

अगले सदस्य, माननीय डा. फूलचन्दजी भिण्डा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): माननीय सभापतिजी, सामने की बेंचेज खाली हैं। मैं उनसे पहला आग्रह तो यह करना चाहता हूं कि यह बजट, अर्थसंकल्प नाम की जो पुस्तिका है, उसको दो-दो बार पढ़ें। इसमें कुछ ऐसे शब्द हैं जो आज तक कांग्रेस के किसी भी वित्त मंत्री ने नहीं रखें। उन शब्दों को समझाया ही नहीं केवल, उनके कार्यक्रम भी दिये हैं, उनके कदम उठाने की घोषणा भी की है और व्यवस्था भी की है। इस कारण से मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कांग्रेस के माननीय विधायकों से कि इस पुस्तक को आराम से पढ़ें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदया, सदन तो छोड़ दिया, अब पार्टी छोड़ने के लिए विचार कर रहे हैं।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बजट में दो शब्दों का उपयोग किया है हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने समृद्ध और विकसित राजस्थान। जब वसुन्धराजी ने सत्ता गहलोत साहब को सौंपी थी, 2003 के दिसम्बर में, तब विकास दर दस प्रतिशत के लगभग थी और जब आपसे हमने, हमने नहीं, जनता ने आपको भगा करके हमें स्वागत-योग्य सत्ता सम्भलवायी है, ऐतिहासिक रूप से समर्थन दिया है, उस समय विकास दर 4.7 है। अभी कुछ सदस्यों ने दो दिन के भाषणों में कहा कि ये 12 प्रतिशत कैसे होगी, यह मैं समझाना चाहता हूं। जब 46,990 करोड़ की वार्षिक योजना थी, तब 7.7 परसेंट वादा था, अब उसको हमने 69,820 करोड़ रुपये किया है। इस कारण से, क्योंकि यह समझने की आवश्यकता है कि केवल बजट में प्रावधान करने से नहीं होता, एक कैपिटल आउटपुट रेशो भी होता है, एक लेबर-कैपिटल आउटपुट रेशो भी होता है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदया, गुरुजी की काफी कुछ सुनाने की इच्छा थी, इनका मन भी था। कृपया करके विपक्ष के एक माननीय सदस्य को तो बुला दो ताकि वे तो सुनें, एक भी नहीं है।

श्री सभपति: ठीक है। माननीय सदस्य, आप पाइंट पर आ जाइये और जल्दी अपनी बात को कहें।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): इस कारण से, यह केवल 12

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

परसेंट वसुन्धरा जी ने ऐसे ही नहीं दी। वे इकोनोमिक्स की आनर्स स्टूडेंट रही हैं। इस कारण से मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि कांग्रेस के बंधुओं की दो घंटे की इकोनोमिक्स की दृष्टि से क्लास लें जिससे इनके बजट समझ में आ जाए।

इसमें यह भी कहा गया है, सब जन विकास और सब जन उत्थान। यह ऐसे ही नहीं कहा इसके बारे में। बहुत-सी व्यवस्थाएं की गई हैं, बिजली क्षेत्र के लिए बिजली ग्रिड, पानी ग्रिड, शिक्षा आयोग, मेडिकल कालेज, कौशल विश्वविद्यालय, सड़क निर्माण अभिकरण, नदियों को जोड़ने वाली व्यवस्था, सभी पंचायतों में माध्यमिक विद्यालय। ये इस प्रकार के उदाहरण कुछ दे रहा हूं जो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि हम सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी राजस्थान को विकसित करना चाहते हैं।

ये 4,900 सीनियर हायर सेकण्डरी स्कूल; एक-एक स्कूल के लिए पहले पूर्व विधायक, यहां अब तो इस सदन में नहीं आ पायें, वे झुंझुनूं जिले से आते थे, एक-एक स्कूल मांगते थे वे सदन में, अब तो 4,900 स्कूलें। कल बानसूर से आने वाली बहन कह रही थीं कि मुझे भी स्कूल देना। ये 4,900 स्कूलें, दो सौ के दो सौ विधान सभा क्षेत्र हैं, उनके प्रत्येक पंचायत हैडक्वार्टर की स्कूल इसमें शामिल हैं। ऐसा कांग्रेस ने कभी नहीं किया और यह बी जे पी की सरकार ने पांचवीं बार किया है।

पहली बार जब माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत मुख्य मंत्री थे, तब उन्होंने एक आदेश जारी किया था 1978 में कि प्रत्येक तीन हजार की आबादी के गांव में सेकण्डरी स्कूल होगा। जब गुलाब चन्दजी कटारिया शिक्षा मंत्री थी और माननीय भैरोंसिंहजी दुबारा मुख्य मंत्री थे, तब एक आदेश में लिखा था कि प्रत्येक पंचायत में मिडल स्कूल होगा। उस वक्त के उच्च शिक्षा मंत्री थे, माननीय ललित किशोरजी चतुर्वेदी, उन्होंने कहा कि प्रत्येक जिले में एक लड़कियों का कालेज होगा। चौथी बार वसुन्धराजी ने पिछली बार शासन में कहा था कि प्रत्येक पंचायत पर सेकण्डरी स्कूल खोलूंगी और उन्होंने 3,108 स्कूलें एक साथ खोली थीं। यह पांचवां उदाहरण है सर्वस्पर्शी विकास का कि उन्होंने घोषणा की है कि प्रत्येक पंचायत पर सीनियर हायर सेकण्डरी बनाऊंगी। 1 से 12 तक की शिक्षा प्रत्येक बच्चे को मिलेगी। राजस्थान का यह दुर्भाग्य है कि 47 साल तक कांग्रेस ने शासन किया, इस कारण से शिक्षा में

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

पिछड़ते रहे और जब-जब बी जे पी का शासन रहा, तब-तब शिक्षा की विकास दर बढ़ी है। आप आंकड़े उठाकर देखना, जब भैरोसिंहजी ने लगातार साढ़े आठ वर्ष तक शासन किया था, उस समय 21 परसेंट विकास दर शिक्षा की दर्ज हुई है, इंडिया में कहीं नहीं हुई और अब उसको आप 5 परसेंट पर ले आयें।

मैं आपके माध्यम से इनको बताना चाहता हूं कि पिछला बजट था, उसमें यह कह रहे थे हम इस प्रकार से करेंगे मेरे सामने एक पन्ना है, इसमें आठ तो नाबार्ड के लोन हैं, जिनमें यह स्पष्ट किया गया था कि एस टी, एस सी की बस्तियों के लिए लोन लिया जा रहा है, सड़कों के लिए, और उसका परिणाम है, सभी आंकड़े जीरो हैं। एक भी किलोमीटर, एक भी पैसा उनकी बस्ती में 2013-14 में नहीं लगाया गया। यह रिकार्ड पर जो दस्तावेज आपको दिया गया है, एक भी नहीं है।

इसी प्रकार से, वसुन्धराजी ने काफी कुछ यह प्रमाणित किया है कि हमारी सरकार में और आपकी सरकार में क्या अन्तर है, कांग्रेस सरकार में क्या अन्तर है। यह जी एस डी पी का एक शब्द आया है, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जब वसुन्धराजी मुख्य मंत्री थीं, तब कर्ज 42 परसेंट केवल कैपिटल व्यय होता था और जब आईं, उसको 109 परसेंट तक; कर्जा 100 रुपये का और इन्कम, उत्पादन 109 रुपये का, ऐसा प्रमाणित का करके गई थीं। इस कारण से, राजस्थान पिछड़े राज्य से ऊपर आया था। लेकिन वापस गहलोत साहब ने इसको कहां पहुंचा दिया, उसकी वापस 47 परसेंट पर पहुंचा दिया। 100 रुपये का कर्जा लिया है, उसकी टोटल कैपिटल जो एसेस्ट्स हैं, वे केवल 42 परसेंट हैं, 47 रुपये आपने पैदा किये हैं। यह भी इस प्रदेश का दुर्भाग्य है। इसी प्रकार से, डैट इक्विटी रेशो, यह समझना आपके लिए आवश्यक है, जो ऋण लेते हैं और जो हमारे पास पूंजी होती है, उसका कोई न कोई तालमेल होना चाहिए। जब आप थे, तब ढाई रुपये मिले, एक रुपया पैदा किया आपने; वसुन्धराजी ने जब सत्ता छोड़ी, उसमें एक रुपये में एक रुपये नौ पैसे पैदा किये। यह रिकार्ड पर है। आप इसको पढ़ लेना, इस दस्तावेज को।

इस कारण से मैं आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि यह बजट इस राज्य के लिए दिशा देने वाला बजट है; अगले बीस वर्ष तक इस प्रांत को एक नम्बर पर ले जाने के रास्ते को प्रमाणित करने वाला बजट है।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

इस कारण, इसको राजनीति से ऊपर उठकर कांग्रेस के बंधु भी, विपक्ष के बंधु हैं, उनको निश्चित तौर पर इसका स्वागत करना चाहिए और उसको समझना चाहिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संक्षिप्त करिएगा।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री सभापति: नहीं, शुरू नहीं किया है। हो गया, काफी टाइम हो गया। (व्यवधान) आप बीच में ना बोलें, आप इनकी सिफारिश न करें। आपको जब बोलने का समय होगा तो आप दो मिनट ही बोलना।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): कभी भी कांग्रेस ने जितने साधन प्राप्त हुए, उनको पूरा खर्च नहीं किया। नवीं योजना आपके टाइम में थी, उसमें आपने 20 परसेंट पैसा खर्च नहीं किया। जब-जब हम सत्ता में आएं, जितना बजट था, जितना प्लान बजट था, उससे ज्यादा हमने खर्च किया और ज्यादा विकास दर प्राप्त की। अभी केन्द्र सरकार से मिलने वाली, शत-प्रतिशत वित्त-पोषित योजना है नरेगा। नरेगा की दुर्गति देखिये, वसुन्धराजी जब मुख्य मंत्री थीं, तब 6,075 करोड़ रुपये हमने खर्च किये और गहलोत साहब जब सत्ता छोड़ रहे हैं, उस समय उनका एक्सपेंडिचर 2,606 है। इतना ही नहीं, जो परिवार कांग्रेस से रोजगार मांगते थे, उनमें एस सी के परिवारों को, केवल 19 परसेंट को आपने रोजगार दिया; एस टी के 24 परसेंट परिवारों को रोजगार दिया। जब मैं जिलों की बात करूंगा तो ऐसी स्थिति बनती है कि जो रोजगार मांगते थे, जिनको 100 दिन का रोजगार मिला अलवर जिले में, केवल 2.60 परसेंट; पूरे तीन भी नहीं। भरतपुर में तो और ज्यादा दुर्गति हुई, 1.6 । दो आदमियों को भी नहीं दिया आपने, 1.6 को ही आपने रोजगार दिया। इस प्रकार से ऐसे जिले हैं, टोंक का तो और भी ज्यादा है, 1.1 परसेंट ही। यह स्थिति इस प्रकार की है जो यह प्रमाणित करती है कि कांग्रेस आर्थिक क्षेत्र में असफल हो गई, उनका आई क्यू खतम हो गया और उनका सोच ही खतम हो गया। अगर सोच होता तो इस प्रकार की स्थिति नहीं होती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): जल्दी कर रहा हूं।

श्री सभापति: सिर्फ दो मिनट।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): 2013-14 में आपने आधुनिकीकरण

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

के लिए, सड़कों के आधुनिकीकरण के लिए 982 करोड़ का हमसे बजट पास करवाया था, 2,521 किलोमीटर बननी थीं, 31 दिसम्बर तक एक भी इंच सड़क नहीं बनी। यह इनकी एफिशिएंसी और कार्यकुशलता की मैं यहां प्रशंसा कर रहा हूं।

विकास दर का जहां तक सवाल है, 2005-06 में 12.38 परसेंट थी प्रति व्यक्ति आय वृद्धि दर; 2006-07 में 15 थी; 2007-08 में 14.8 थी; 2008-09 में चूंकि चार महीने हमको नहीं मिले, दो चुनाव के चले गये, तो 6 महीने नहीं मिले, फिर भी 13.82 थी। उसके बाद जब इन्होंने सत्ता सम्भाली तो 13.42 से 16.80; उनके कारण से नहीं, एकदम एग्रीकल्चर ग्रोथ से 36 परसेंट चली गई, इस कारण से; उसके बाद 9 परसेंट, 6 परसेंट।

किसानों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी एस सी, एस टी का उदाहरण दिया, इनको एक भी एस सी, एस टी की सीट इसलिए नहीं मिली कि इन्होंने कुछ भी नहीं किया। सभापतिजी, अब एग्रीकल्चर ग्रोथ, मैं आपके सामने निवेदन कर रहा हूं, 2011-12 में एक परसेंट भी नहीं है ग्रोथ किसानों की, 0.25; उससे ज्यादा और कमी हो गई, 12-13 में तो 0.11 ही रह गई और 13-14 में 0.22 ही रह गई। इस प्रकार की स्थिति किसानों की हो गई।

मैं कुछ निवेदन उदाहरण के तौर पर करना चाहता हूं, कुछ सुझाव हैं। पहला मेरा सुझाव है कि किसानों का ऋण भार ब्याज पर डिपेंड करता है और चार परसेंट की घोषणा इस बजट में की गई है। मेरा निवेदन है कि बी जे पी की मध्य प्रदेश में सरकार है, वह जीरो परसेंट ब्याज पर, और हमारे घोषणा पत्र में एक परसेंट ब्याज की बात है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि यहां का किसान गरीब है, क्योंकि मैंने आपको विकास दर बता दी, और गरीब होता चला गया, इस कारण से उसको जीरो परसेंट किया जाए।

डार्क जोन में किसानों को कृषि कनेक्शन के लिए खुद को पैसा देना पड़ेगा। उसको सामान्य कनेक्शन की भांति शामिल किया जाए, सामान्य योजना के अनुरूप बनाया जाए।

इसी प्रकार से, प्रशासनिक संरचना के बारे में पहली बार वसुन्धराजी ने निर्णय किया है और कुछ कदम भी उठाये हैं। मैं एक निवेदन करूंगा कि जो भी कर्मचारी-अधिकारी होते हैं, उनके जीवन में बीच में जो थोड़ा-बहुत संचार

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

होता है, वह होता है पदोन्नति से, डी पी सी से। इस कारण से, समय पर डी पी सी हो। क्योंकि ऐसे उदाहरण हैं राजस्थान में, जो टाप लेवल के अधिकारी हैं, जिनको आई ए एस कहते हैं, उनके सात पदोन्नतियां होती हैं और राजस्थान में चपरासी की एक भी पदोन्नति नहीं होती। 24 साल तक कभी कोई पदोन्नति चपरासियों की नहीं हुई। इस कारण डी पी सी समय पर हों, एक मेरी यह प्रार्थना है।

इसी प्रकार से, आर्थिक कार्यकुशलता बढ़ाने की आवश्यकता है। क्योंकि कैपिटल आउटपुट रेशो या इन्पुट-आउटपुट रेशो महत्वपूर्ण बिन्दु हैं। इस कारण से आर्थिक एफिशिएंसी में जब तक जवाबदेही नहीं होगी, तब तक यह कार्यकुशलता नहीं बढ़ेगी। इस कारण से आर्थिक जवाबदेही की जाए।

इसी प्रकार से, सौर ऊर्जा में किसानों को, पहले 56 परसेंट अनुदान मिलता था, अब उसको घटाकर 30 परसेंट किया गया है। मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि इसको वापस 56 परसेंट किया जाए।

केन्द्र से मिलने वाले जो संसाधन हैं, उनका पूरा उपयोग होना चाहिए, पूरा विदोहन होना चाहिए। एक उदाहरण दूंगा। हमारे प्रदेश में मगरे खूब हैं, ढाणियां खूब हैं लेकिन राजस्व गांव नहीं हैं और केन्द्र की जो ग्रामीण सड़क योजना है, राजस्व गांव के हिसाब से सड़कें बनाते हैं, 250 की आबादी, 500 की आबादी। अगर दो, तीन या चार ढाणियों को मिला दिया जाए तो 500 से ज्यादा की आबादी बनती है और उसका शत-प्रतिशत पैसा केन्द्र से मिलेगा। इस कारण से, केन्द्रीय शत-प्रतिशत योजनावाइज जो वित्तपोषित योजना है, उसका उपयोग करने के लिए अभियान चलाकर छोटी ढाणियों को गांव बनाया जाए। एक मेरा यह निवेदन है।

श्री सभापति: संक्षिप्त करें। अब हो गई आपकी बात।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): दो ही मिनट और।

श्री सभापति: अब क्या, दो क्या?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): दो ही शब्द और हैं।

श्री सभापति: दो पाइंट और हैं?

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): दो पाइंट और हैं। एक पी पी पी माडल का काफी वर्णन इसमें आया है, कई जगह चालू भी हैं। 1954 में कांग्रेस ने यह तय किया कि समाजवादी समाज की स्थापना करेंगे और बाद में उसको

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

बदला किसमें, राष्ट्रीयकरण में। 92 तक राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण, राष्ट्रीयकरण करते चले गये और जब देश का भट्टा बैठ गया, अन्दर से खोखला हुआ, तो नेहरूजी के उत्तराधिकारी नरसिंम्हा रावजी ने डि-राष्ट्रीयकरण किया। इस कारण से पी पी पी माडल में भी खतरे हैं।

मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर अध्ययन करना हो तो पी पी पी माडल पर जितने बने हैं, सारे सड़कों के, वहां लूट हो रही है, जनता ठगी जा रही है। इस कारण से, यह अच्छी स्कीम हो सकती है, इसकी मानिटरिंग अच्छी हो। अगर घोड़ा नियंत्रण में रहे तो अच्छी राइडिंग हो सकती है, वरना इसमें खतरे ही खतरे हैं। लूट का आधार है, एक। आज जो निर्णय करने वाला टाप लेवल का व्यक्ति है, उसको परचेज कर लेती हैं कम्पनियां और उसके बाद में जनता को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप पाइंट्स पर आ जाइए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): हां, यह लास्ट पाइंट है। इसी प्रकार से, मैं मेरी बात कहूंगा कि मैं जहां से विधायक हूं ...(व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदया, यहां पर कांग्रेस का एक भी सदस्य नहीं है। यह किन को कह रहे हो? आप यह तो बताओ।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): सुन रहे हैं। रिकार्ड पर आ रहा है, रिकार्ड पर। रिकार्ड पढ़ लेंगे वे।

श्री सभापति: रिकार्ड पर आ जाएगा। आप बैठें। कृपया आप बैठ जाएं, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): आपको झेल रहे हैं हम, यहां पर बैठे-बैठे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपको अगर इतनी ही, आप बैठे हैं...। माननीय सदस्य, अब मैं यह कहूंगी कि आप तुरन्त समाप्त कर दीजिए।

डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर): बस एक ही पाइंट है। एक ही पाइंट है। विराट नगर पौराणिक, ऐतिहासिक, बौद्ध-कालीन, महाभारत-कालीन और मुगल -कालीन अवशेषों का केन्द्र है। वहां पर बटोड़ का भैरूं भी है, पांडु के टाइम के गणेशजी भी हैं, बौद्ध-कालीन बुद्ध-स्तूप भी हैं, अशोक के शिलालेख भी हैं, महावीर -कालीन जैन नसियां भी हैं। इस कारण से मेरा यह निवेदन है कि जयपुर और

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

अलवर दोनों का पर्यटक सर्किट बनाया गया है, उसके मध्य में विराट नगर आता है, इस कारण से उसको शामिल किया जाए, ऐसी प्रार्थना मैं करता हूं और विराट नगर में जो पिछले पांच साल में कोशिश करके कुछ योजनाएं मैंने मंजूर करवाई थीं, वे पूर्ण नहीं हुईं, उनको पूर्ण किया जाए।

किसानों के जो जिंस हैं, उनके भावों में जो उतार-चढ़ाव आता है, जैसे टमाटर अबकी बार सड़कों पर पड़ा, इसको रोकने के लिए कोई कोष स्थापित किया जाए।

इस श्रेष्ठ बजट को, सर्वव्यापी बजट को, सार्वभौम बजट का मैं समर्थन करता हूं और आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

श्री सभापति: वरिष्ठ सदस्य, माननीय श्री मानिक चन्दजी सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदया, वर्तमान बजट 2014-15, जिस पर इस सदन में चर्चा हो रही है, काफी माननीय सदस्यों ने इस पर प्रकाश डाला है, काफी विश्लेषण हुआ है और निस्संदेह रूप से इस बजट के डाक्यूमेंट को एक साथ पढ़ने की आवश्यकता है जिससे कि यह पता चले कि इसका स्वीप कितना बड़ा है, कौनसा क्षेत्र है जो इसमें समाया हुआ नहीं है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को राजस्थान में पहली बार एक लाख करोड़ के बजट को लाने के लिए बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज तक जो बजट आये, माननीय सदस्यगण, वह 77 हजार करोड़ का आखिरी बजट था 2013-14 का और 77 हजार करोड़ से हमारी राजस्व आय, निश्चित रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी के नेतृत्व में ही एक लाख छह हजार करोड़ होने का अनुमान है और एक लाख छह हजार करोड़ जो होने का अनुमान है, उसमें, माननीय सभापति महोदया, भारत सरकार जो अब तक सिर्फ 10 हजार करोड़ रुपये की सहायता, अनुदान देती थी, उन्होंने अपने सहायता अनुदान को 27 हजार करोड़ तक बढ़ाया है और एक ही मद में 17 हजार करोड़ रुपए बढ़ने से, हमारी खुद की कर आय 77 से 79 हो गई और 27 हजार उनका आया और हमारी आय एक लाख छह हजार करोड़ हो गई। एक लाख छह हजार करोड़ के माइलस्टोन को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो सरपास किया है, उसी के लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 17 हजार करोड़ की हमारी राजस्व आमदनी बढ़ गई और 17 हजार करोड़ रुपए ही इस साल शुद्ध उधार है,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पूंजीगत प्राप्तियों में शुद्ध उधार 17 हजार करोड़ हैं, 34 हजार करोड़ का इजाफा बजट में हुआ लेकिन, जब मैंने बजट के आंकड़े को देखा तो हमारे पूंजीगत खर्च में मात्र साढ़े पांच हजार करोड़ की ही बढ़ोतरी है। गत सरकार ने 20 हजार करोड़ रुपये का विनियोजन किया था पूंजीगत खर्च में और हमारी सरकार 26 हजार कुछ पांच सौ करोड़ का विनियोजन कर रही है।

माननीय सभापति महोदया, मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि हम फिस्कल डेफिसिट के आंकड़े को, इसमें 20 हजार करोड़ का है, यदि हमारी राजस्व आमदनी बढ़ जाए 17 हजार करोड़, शुद्ध उधार भी आ जाए 17 हजार करोड़, शुद्ध उधार ले लें हम, तो आपकी जो राजस्व आमदनी बढ़ी है, आप उसको राजस्व में खर्च करिये, योजना में खर्च करिये, पर यह 17 हजार जो शुद्ध उधार है, माननीय सभापति महोदया, यह तो कम से कम पूंजी निर्माण में खर्च होना चाहिए। हम इंफ्रास्ट्रक्चर को, आधारभूत ढांचे को, चाहे वह बिजली का हो, चाहे सड़क का हो, चाहे जल संसाधन हो, सिंचाई का हो और चाहे वह अन्य किसी मद में हो, निश्चित रूप से झोटवाड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने पूंजी निर्माण पर बहुत अधिक महत्व अपने भाषण में दिया था, तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पूंजी निर्माण तो अभी 17 हजार करोड़ का होता और 17 हजार करोड़ का हमने शुद्ध उधार जो लिया है, उसका हम विनियोजन करते तो हम कह सकते थे कि हमने एक-एक पाई का उपयोग पूंजी निर्माण में, आधारभूत ढांचे में किया है।

मुझे दु:ख है कि राजकोषीय घाटा हमारा आज भी 20 हजार करोड़ है और राजकोषीय घाटा जब 20 हजार करोड़ है तो, माननीय सभापति महोदया, एक लाख 31 हजार करोड़ तो पहले से है ही उधार और यह 20 हजार करोड़ में शुद्ध उधार 17 ही समझिये, तो अगले साल तो हमको ब्याज एक लाख 48 हजार करोड़ पर देना है। अभी भी ब्याज का आंकड़ा दस हजार करोड़ का है। मुझे और किसी को कोट करने की जरूरत नहीं है, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हम बिजली के 75 हजार करोड़ रुपये के उधार पर 10 हजार करोड़ का ब्याज दे रहे हैं, तो ब्याज की राशि तो हम पर 20 हजार करोड़ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी की अगुआई में राज्य को कुछ ऐसा करना चाहिए कि आगे आने वाले दस सालों में, पन्द्रह सालों में हम ऐसी प्रक्रिया शुरू करें कि हर साल कम से कम पांच हजार करोड़ रुपये जो

(श्री मानिक चन्द सुराना)

राजकोषीय घाटा है, वह हर साल पांच हजार करोड़ रुपये कम हो। आखिर तो राजकोषीय घाटे को अपन ढोएं क्यों? यह 20 हजार करोड़ रुपया जो हम ब्याज में दे रहे हैं, यह राजस्थान की जनता के काम में नहीं आ रहा है। यह तो जिन्होंने हमको रुपया उधार दिया है, उनके खाते में जा रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस पर निश्चित रूप से चिंतन, मनन होना चाहिए।

आपने चलते-चलते, इस कांग्रेस सरकार ने तीन हजार करोड़ रुपए खर्च कर दिए मेट्रो में। मुझे बहुत नम्रता के साथ निवेदन करना है कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जितनी उसकी तीखी, कड़ी आलोचना की है, अपने फरवरी के भाषण में और इस भाषण में, उसको पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी स्वयं, यह चांदपोल से बड़ी चौपड़ का रेलवे का प्रोजेक्ट जो पूरे जयपुर शहर को खोद देगा, चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक और सवाई जयसिंह ने जो जयपुर बसाया, उसके स्ट्रक्चर में, मूलभूत स्थापत्य कला में उसका परिवर्तन होगा। ऐसा काम, माननीया मुख्य मंत्रीजी क्यों इजाजत दे रही हैं? उनके सामने कोई मजबूरी नहीं है, जनता का भयंकर विशाल मैनडेट उनको प्राप्त है और जब वे खुद यह कह रही हैं कि यह निर्णय अच्छा नहीं था, तीन हजार करोड़ के व्यय का, तो आप एक हजार करोड़ क्यों कर रही हैं? वह 979, जो भी है, 969, मैं कह रहा हूं कि मोटे तौर पर वे एक हजार करोड़ क्यों खर्च कर रही हैं? इस जयपुर की स्थापत्य कला को भूमिगत रेलवे बनाकर, कुल मिलाकर बरबाद करने का काम होगा। उस काम को रोकना चाहिए।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, जो जयपुर से ही आते हैं, मैं अर्ज करता हूं कि आपने 9.2 किलोमीटर जो रेल बनाई, मेट्रो रेल, मानसरोवर से चांदपोल, इसमें, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, 2,024 करोड़ रुपये खर्च हुए और इस 2,024 करोड़ को आप 9.2 किलोमीटर, 9.7 किलोमीटर से डिवाइड करेंगे तो 200 करोड़ रुपया, 208 करोड़ रुपया उसकी इंवेस्टमेंट की कीमत आएगी और इस चांदपोल से बड़ी चौपड़, यह 488 करोड़ पर-किलोमीटर की कोस्ट है। यह खर्चा हमें क्यों करना चाहिए? आखिर जयपुर के विधायक तो बहुत शक्तिशाली हैं, मैं निवेदन करूंगा राजस्थान के विधायकों से कि जो कुछ माननीया मुख्य मंत्रीजी का वक्तव्य है, उसके आधार पर ही यह मेट्रो रेल चांदपोल पर जहां पर है, उसको वहीं पर रोकना चाहिए। इसके आगे की आवश्यकता नहीं है। यह तो एक कांग्रेस का बोझ है जो हम पर लाद दिया

(श्री मानिक चन्द सुराना)

गया, जिसको हम ढो रहे हैं और मजबूरी, जैसा माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा कि अब जो बन गया है, उसको तो समेटना ही पड़ेगा, तो उस तक तो हम रेल चलायें लेकिन इसको आगे बढ़ाने का जो काम है, जो गलत निर्णय है, हम उन पर तीखी टिप्पणी करके भी फिर उस निर्णय को आगे बढ़ायें, यह मुझे उचित नहीं लगता है।

सदन से मेरा नम्र निवेदन है कि मेट्रो रेल द्रोपदी का चीर है। आपने यदि इसको चांदपोल से बड़ी चौपड़ जाने दिया तो रामगंज वाले कहेंगे, हमने क्या पाप किया है, एक किलोमीटर हमारे यहां भी बढ़ा दो। और फिर यह तो बढ़ता ही रहेगा।

दिल्ली में रुकता नहीं है। दिल्ली में तो भारत सरकार है जिसने लाख करोड़ खर्च करके दिल्ली की मेट्रो रेल बढ़ाई। क्योंकि उसकी आबादी करोड़ से ऊपर है और उस करोड़ की भीड़-भाड़ में वह मेट्रो रेल भरी हुई चलती है और आपकी मेट्रो रेल, मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैंने खूब पढ़ी है, 2 लाख यात्री आपने सोचे हैं मानसरोवर से चांदपोल के बीच में, आपको यात्री मिलेंगे नहीं 25 हजार भी। 2 लाख यात्री मिलें ना, तब वह वाएबल कही जा सकेगी और दिल्ली मेट्रो रेल ने इसीलिए 2 लाख का आंकड़ा बना दिया। क्योंकि उनको तो इन अशोक गहलोतजी ने कहा कि हर हालत में रेल बनानी है, आंकड़े आप चाहे जो उसमें डाल दो, और उन्होंने 2 लाख का आंकड़ा डाल दिया।

उधर दुर्गापुरा से अम्बा बाड़ी तक जो रेल बन रही है, उसमें 4 लाख का आंकड़ा है कि 4 लाख यात्री ट्रैवल करेंगे। मैं अर्ज करता हूं, उसमें 40 हजार यात्री भी ट्रैवल नहीं करेंगे। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट जो बसें चलाती हैं, लेलैण्ड वाली बड़ी बस चलती है, इनकी यात्री संख्याओं को आप देखें कि ये जो बसें चलती हैं, इनकी यात्री संख्याएं क्या हैं? इनकी यात्री संख्याएं मैंने ली हैं आर.टी.आई. में, वह यात्री संख्याएं पिछले साल तक 18-20 हजार के बीच में थीं और आपकी 10 प्रतिशत बढ़ भी गयीं तो 25-30 हजार को क्रोस नहीं करेंगी। कहां 2 लाख का आंकड़ा उन्होंने डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डाल रखा है।

मैं निवेदन करता हूं कि मेट्रो रेल को जहां है, वहीं रोकिये और यह रुपया राजस्थान के पीने के पानी की समस्या में लगाइये। एशियन डवलपमेंट बैंक ने ऋण दिया है, तो उसका सार्थक उपयोग हो और पीने के पानी से ज्यादा

(श्री मानिक चन्द सुराना)

महत्वपूर्ण कोई और प्रोजेक्ट नहीं हो सकता। आप पीने के पानी में लगायें, चाहे बिजली में लगायें, लेकिन इस रुपये का मेट्रो रेल बनाकर अपव्यय न करें। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बजट में कोई क्षेत्र अछूता नहीं है। यातायात में बड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये हैं। जो 13 हजार से ऊपर सड़कें राजस्थान की राष्ट्रीयकृत कर दी गयी थीं हमारे रोडवेज के लिए, माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बहुत दूरदर्शिता से उनको डि-नेशनलाइज किया है, वह राष्ट्रीयकरण की प्रक्रिया समाप्त की है ताकि रोडवेज में और प्राइवेट एंटरप्रिन्योर्स में, हमारे जो बस अड्डे हैं, उनके आधुनिकीकरण की बात कही गयी है, ताकि उन बस अड्डों पर प्राइवेट बस भी चलें; समय से चलें और हमारी बसें भी समय पर चलें ताकि उनको भी लाभ हो और राज्य की रोडवेज को भी लाभ हो। जो डि-नेशनलाइज किया गया है, मैं उसका बहुत स्वागत करता हूं, वह बहुत दूरगामी कदम है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने साफ कहा है कि आज मोनोपोली का टाइम नहीं है कि हम कोई स्टेट मोनोपोली ग्रहण करें, ऐसा समय नहीं है, इसलिए अब इसको डि-नेशनलाइज किया जाता है।

माननीय शिक्षा मंत्रीजी, अभी तो आप हमारे बीकानेर में 12 दिन का प्रवास करके आये हैं, 19 से 30 तक। बहुत उम्मीदें थीं और बहुत उम्मीदें सार्थक भी सिद्ध हुई हैं। संभाग के दौरे में आप जहां गये, चाहे हनुमानगढ़ गये, गंगानगर गये, जितनी हमारे नहरें हैं, बीकानेर संभाग की महत्वपूर्ण नहरें, उन सभी के पुनरुत्थान की बात माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने भाषण में कही है। इंदिरा गांधी नहर को 50 साल हो गये, मुख्य मंत्रीजी ने लिखा है और उसके लिए रिनोवेशन का प्रोग्राम उन्होंने बिना किसी बड़ी मांग के, जनता की, वह रिनोवेशन का प्रोग्राम भी एक दूरदर्शिता का परिणाम है और उन्होंने समय से पहले ही, समय के अनुसार ही उस काम को किया है।

मैं निवेदन करता हूं, तकनीकी विश्वविद्यालय की मांग, जो बीकानेर शहर में है, आपके समक्ष आई है और अभी आपने फरमाया भी है कि कैबिनेट कमेटी इसको देख रही है। मुझे खुशी है कि राजस्थान सरकार सकारात्मक दृष्टिकोण से, संवेदनशील दृष्टिकोण से उसको एग्जामिन कर रही है। मैं शिक्षा मंत्रीजी के ध्यान में एक बात लाना चाहता हूं कि हमारे यहां दो इंजीनियरिंग कालेज हैं, बीकानेर में, और दोनों में आप ही के बोर्ड आफ गवर्नर्स हैं, एक का

(श्री मानिक चन्द सुराना)

नाम बीकानेर इंजीनियरिंग कालेज है, दूसरे का नाम कालेज आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी है। 1999 में पहला इंजीनियरिंग कालेज आ गया और दूसरा भी 5-6 साल बाद आ गया। हमारे विद्यार्थियों की संख्या 6 हजार है। 300 बीघा जमीन आपने दे रखी है उस अभियांत्रिकी महाविद्यालय को और वह जो परिसर है, जो ताम-झाम वहां हैं और जो इन्फ्रास्ट्रक्चर वहां है, वह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के लिये पर्याप्त है। मैं निवेदन करूंगा कि यदि आप दोनों कालेजेज को संघटक कालेज घोषित कर देते हैं, कोटा बहुत दूर है, माननीय मंत्रीजी ध्यान रखें, 600-700-800 किलोमीटर बीकानेर संभाग से कोटा है और 600-700-800 किलोमीटर दूर एक गरीब किसान अपने बेटे को नहीं भेज सकता तकनीकी विश्वविद्यालय में। आप किसान का ध्यान रखें, आप ग्रामीण का ध्यान रखें, शहर के लोगों का भी ध्यान रखें और यह बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, मैं अर्ज करता हूं, पूरे पश्चिमी राजस्थान की दृष्टि से बीकानेर में सारा इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। आप यदि वहां के प्रोफेसर और लेक्चरर, जो विधिवत नियुक्त हैं, उनको यदि यूनिवर्सिटी में समायोजित करते हैं तो यूनिवर्सिटी को 10 साल का फायदा होगा; 500 करोड़ का तो आपको इन्फ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और 10 साल का समय मिलेगा और तकनीकी विश्वविद्यालय, पहले वर्ष से ही 20 करोड़ रुपये भारत सरकार से उसको एड मिलना तय है।

पशुपालन विश्वविद्यालय 2010-11 में बना है, माननीय मंत्रीजी, और पशुपालन विश्वविद्यालय में पहले साल राज का 10 करोड़ खर्चा हुआ और हमारा तकनीकी विश्वविद्यालय भी आप बनायें तो आपका खर्चा तो महत्वपूर्ण 10 करोड़ का ही होगा, कि हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय की बिल्डिंग बन जाये। तकनीकी विश्वविद्यालय में फीस से आज भी 30 करोड़ रुपये आ रहे हैं, 25 करोड़ का बिल है, राज्य सरकार को उसको फीड नहीं करना पड़ता है। ठीक है, राज्य सरकार यदा-कदा हर साल 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ अनेक कामों के लिये, उसमें सुधार के लिये, उसके बेसिक इन्फ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिये देती है और वह भी शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा मंत्री होने के नाते आप जो उसमें दे रहे हैं, वह भी बहुत प्रशंसनीय काम है।

मैं निवेदन यह करूंगा कि जब एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार है तो यह कांग्रेस सरकार ने पिछले साल घोषणा कर दी बजट में, इनकी नीयत तो ठीक थी ही नहीं, इन्होंने तो 22 अक्टूबर को घोषणा की है, ताकि वे ना इधर के रहें,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ना उधर के रहें। मार्च में वह आर्डिनेंस लैप्स हो गया। माननीय सभापतिजी, उसके लैप्स होने के बाद कोई तकनीकी विश्वविद्यालय अस्तित्व में नहीं है। आज तकनीकी विश्वविद्यालय बनायेगा तो यह सदन बनायेगा, यह सरकार बनायेगी और उस पर कोई कांग्रेस की छाप नहीं लगने वाली है, माननीय मंत्रीजी।

यदि यह विश्वविद्यालय सिर्फ इस आधार पर न बने कि सन 2008 में माननीया वसुन्धराजी ने 4 विश्वविद्यालय घोषित किये थे और इस अदूरदर्शी कांग्रेस सरकार ने वे चारों विश्वविद्यालय नहीं बनायें 2008 से 13 में, उसका दण्ड बीकानेर की जनता को, बीकानेर के युवकों को और तकनीकी शिक्षा के प्रसार के लिए उस बात को न रोकिये। इतना बड़ा मेन्डेट है जनता का वसुन्धराजी को कि आपको 163 दिये, फिर लोक सभा में तो सारे अवरोध तोड़कर 25 की 25 सीटें दे दीं। इतने बड़े मेन्डेट को और उस जनता की जो भावनाएं हैं कि हमको हमारा न्यायसंगत अधिकार मिलेगा, मैं शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि हमारा न्यायसंगत अधिकार है कि आप हमको तकनीकी विश्वविद्यालय इसी साल प्रदान करें।

मुझे मालूम है कि आवश्यक नहीं है कि आप बजट में घोषणा करें, बजट में तो घोषणा कल होगी, आपके पास सप्लीमेंट्री ग्रांट्स लाने का अधिकार है। सब अधिकार है राज के पास में। आपकी कैबिनेट कमेटी की मीटिंग में आप सब पक्षों पर विचार करिये, हम भी ज्ञापन देंगे, हमारे बीकानेर संभाग के सारे विधायक भी आपको ज्ञापन दे देंगे, हमारे चारों एम.पी. भी आपको ज्ञापन दे देंगे, आप विचार करें और संवेदनशीलता के साथ आप इस तकनीकी विश्वविद्यालय का हमारा जो नम्र निवेदन है, उसको आप स्वीकार करने की कृपा करें, यह सरकार उसको स्वीकार करे। यह मेरा निवेदन है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा सम-अप, प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ समय, पांच-सात मिनट लूंगा।

श्री सभापति: 20 मिनट हो चुके हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो सोलर पालिसी घोषित की है, 25 हजार मेगावाट सोलर पावर बनायेंगे, इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो नहीं सकती

(श्री मानिक चन्द सुराना)

लेकिन मैं जानता हूं कि एक मेगावाट में दस करोड़ का खर्चा है। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने कहा है कि हजार मेगावाट जो लगायेगा, उसको 26 परसेंट की इक्विटी देंगे। माननीया मुख्य मंत्रीजी, आप उन 25 आदमियों की खोज क्यों कर रही हैं जो हजार मेगावाट लगाने की स्थिति में हों, आठ-दस हजार करोड़ खर्च करने की स्थिति में हों? आप तो यह 26 परसेंट इक्विटी 50 मेगावाट पावर पर दे दीजिए। 50 मेगावाट पावर वाला तो 400 करोड़ में बनायेगा, 500 करोड़ में बनायेगा। उसको दे दीजिए 26 परसेंट इक्विटी। राजस्थान का प्रवासी वर्ग और राजस्थान का खुद का उद्योगपति इतना सक्षम है कि 400-500 करोड़ के आपको 500 आदमी सोलर पावर में मिलेंगे; सोलर पावर में मिलेंगे, तो जो मुख्य मंत्रीजी का सपना है 25 हजार मेगावाट का, सवा लाख करोड़ के निवेश का, मेरा निवेदन है कि वह निवेश बिलकुल सार्थक हो जायेगा, फलीभूत हो जायेगी लेकिन इस हजार मेगावाट पर ही 26 परसेंट इक्विटी देने का मानस बदल लें और 50 मेगावाट बनाने वाले महानुभाव को, उद्योगपति को भी आप 26 परसेंट नहीं, 20 परसेंट इक्विटी दें, लेकिन 20 परसेंट इक्विटी देंगे तो भी वह राज़ी-खुशी आयेगा और नियोजन करेगा और राजस्थान की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति करेगा। विद्युत मंत्रीजी सदन में नहीं हैं ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपसे मेरा यह नम्र निवेदन है ...

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): मैं कोई इर्रेलेवेंट बात कहूं तो आप टोक देना। कोई दिक्कत नहीं है मुझे।

श्री सभापति: नहीं, नहीं, इर्रेलेवेंट बात नहीं, आपकी बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात है लेकिन आज जो बोलने वाले माननीय सदस्य हैं, वे 43 हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पांच-सात मिनट मुझे देने की कृपा करें। मैं सदन का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करता हूं ...

एक माननीय सदस्य: अच्छा बोल रहे हैं।

श्री सभापति: अच्छा बोल रहे हैं लेकिन सारे सदस्यों को भी बोलना है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): माननीय कालू लालजी, आप मेरी मदद करें। आप बीस मिनट दें, मुझे दस-बीस मिनट।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): माननीय सदस्य, आपको पता

(श्री कालू लाल गुर्जर)

है, 42 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं, नये-नये। वे सीखेंगे। आपने खूब बोल दिया, आपने तो जिंदगी भर बोला है। यह तो कई लोग तो पहली बार ही बोलने आये हैं, साहब, उन पर तो दया करो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप कंटिन्यू करें। बस पांच मिनट में सम-अप करें।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): पांच मिनट में ही खतम करता हूं।

एक माननीय सदस्य: बुजुर्ग आदमी हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): बुजुर्ग की बात नहीं है। मैं सन् 1962 का विधायक हूं, जब कई पैदा भी नहीं हुए होंगे, जो अभी विराजे हैं। मैं 50 साल से पार्लियामेंट्री पोलिटिक्स में हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप तो बोलिये। बोलिये।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): नहीं, नहीं, मैं वह नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं मैं वरिष्ठतम विधायक हूं, यह ध्यान करें।

श्री सभापति: बिलकुल।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर): 68 के विधायक हैं, बाकी मैं 1962 का एक ही हूं। ध्यान करें।

मैं निवेदन करता हूं कि उत्पादन निगम में इस कांग्रेस सरकार ने क्या कबाड़ा किया है, उसकी तरफ मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं। 2011-12 में उत्पादन निगम का जो उत्पादन था, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, वह उत्पादन 26,550 मिलियन यूनिट था; मिलियन यूनिट, दस लाख का एक यूनिट मानते हैं वहां; फिर वह घट कर, साढ़े ग्यारह सौ मिलियन यूनिट घट कर 12-13 में आ गया 25,366 पर और अब वह 33,065 मिलियन यूनिट घट कर 13-14 में आ गया। अब हमारी क्षमता सिर्फ 87 परसेंट पावर उत्पादन की रह गयी, 11-12 में।

मैं अर्ज करता हूं कि यह हो क्या रहा है? हमारा विनियोजन बढ़ रहा है तापीय बिजली घरों में और उत्पादन घट रहा है। उत्पादन निगम के बड़े-बड़े अफसर हैं, बड़े-बड़े चेयरमैन हैं, जनता की नींद आज हराम है क्योंकि बिजली नहीं मिल रही चार घंटे, बिजली नहीं मिल रही छह घंटे, पांच घंटे और नहीं मिल रही। मैं कोई कपोल कल्पना नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरे

(श्री मानिक चन्द सुराना)

पास आंकड़े हैं और उन आंकड़ों के आधार पर मैं आपसे अर्ज करता हूं। जब तक बीकानेर में राज था, माननीय शिक्षा मंत्रीजी थे और मुख्य मंत्रीजी थीं, तब तक आर्डर था कि बिजली कटौती नहीं होगी। मई में हुई, जून में हुई। चलो बारह दिन नहीं हुई। फिर जुलाई में जो हाल है, जुलाई में एक जुलाई को 40 मिनट की कटौती, फिर पांच जुलाई को तीन बार दो घंटे की कटौती। और यह कटौतियां ग्रामीण ग्रिड्स पर और जिसमें कस्बे में वहां ड्रम्स हैं, उन पर भी हुई है। सात जुलाई को एक घंटे 37 मिनट की कटौती और आठ जुलाई को लूणकरणसर क्षेत्र के सभी ग्रामीण ग्रिड व लूणकरणसर के कस्बाई ग्रिडों पर एक घंटा 30 मिनट की कटौती और, माननीय, 15 जुलाई, दो दिन पहले, छह घंटे 38 मिनट जयपुर के एल.डी. संदेश के फलस्वरूप कटौती हुई हैं। यह एल.डी. संदेश राजस्थान के हर हिस्से में जाते हैं और हर हिस्से में आम जनता को जो बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है, उसका दुष्परिणाम यह है कि पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जब बिजली भी नहीं मिलेगी और पीने का पानी भी नहीं मिलेगा तो वह व्यक्ति जिसने आपको विधान सभा में वोट दिया है, लोक सभा में वोट दिया है, वह इतना तो पूछने का अधिकारी है कि, भाई साहब, यह हो क्या रहा है? हमको भी लोग पूछते हैं, आप विधायक हो गये, यह बिजली कटौती कैसे हो रही है? आप तो हमको नहीं मानते बी.जे.पी. का लेकिन हमारी जनता मानती है कि हम ही वहां पर बी.जे.पी. हैं और इसीलिए हम यहां आये हैं। इसीलिए आये हैं।

इसलिए मैं अर्ज करना चाहता हूं कि हमारी जनता की नींद हराम है, बिजली, पानी न मिलने से, लेकिन आपके चेयरमैन उत्पादन निगम के जो भी हैं, एन.एम. माथुर, उनकी नींद हराम नहीं है। आपके बिजली अधिकारियों की नींद हराम नहीं है। क्यों नहीं है? हमारी नींद हराम है, हमारी जनता की नींद हराम है तो आपकी नींद भी हराम होनी चाहिए और आपको तब तक नींद नहीं आनी चाहिए जब तक आप हमको बिजली और पानी पर्याप्त तरीके से न दिलाएं।

यह बिजली कटौती का युग नहीं है। मैडम ने कहा है 24x7, सात दिन में 24 घंटे बिजली चाहिए। तो मैडम ने जो कहा है, जो एल.डी. मेसेज है जयपुर का, वह मैडम के निर्देशों के और मैडम के उद्देश्यों के बिलकुल विपरीत है। इस एल.डी. मेसेज को, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, आप अभी सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप माननीया मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करें कि

(श्री मानिक चन्द सुराना)

आपकी इच्छाओं के विपरीत, आपके उद्देश्यों के विपरीत जो एल.डी. मेसेज होता है और जिसके लिए ट्रांसमिशन निगम के अध्यक्ष श्री आलोक हैं, बड़े आई.ए.एस. अफसर, दिल्ली रहे हैं और दिल्ली से उनकी दोस्ती है, जो भी मेसेज आता है, उन्होंने कभी प्रोटेस्ट नहीं किया कि मैं छह घंटे कटौती क्यों करूं? क्या पूरे नोर्दर्न ग्रिड में छह घंटे कटौती हो रही है? राजस्थान के साथ नोर्दर्न ग्रिड भेदभाव कर रहा है और उस भेदभाव का विरोध आपके आई.ए.एस. अफसर नहीं कर रहे हैं। यह लाबी, यदि यही प्रभावी रही तो राजस्थान की जनता ने जो विशाल मेन्डेट आपको दिया है, उस पर प्रश्नचिह्न अपने आप लगेगा। मैं चाहता हूं कि प्रश्नचिह्न लगे, वर्षा भी जल्दी हो, ताकि यह विद्युत का संकट जल्दी से समाप्त हो और जनता को 24 घंटे में कम से कम 22 घंटे तो बिजली मिले। यह मेरा आपसे निवेदन है।

मैं माननीय सभापतिजी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय तीन घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय तीन घंटे बढ़ाया जाए? आप सब सहमत हैं?

(स्वीकृत)

इसलिए तीन घंटे सदन का समय बढ़ाया जाता है।

हमारी आदरणीय माननीय सदस्या, श्रीमती सूर्यकान्ताजी व्यास।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदया, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी ने जो बजट 2014-15 का प्रस्तुत किया है, एक ऐतिहासिक बजट है और इससे बढ़ कर कोई बात हो नहीं सकती। इतना जबरदस्त बजट दिया है। ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए भी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

उन्होंने समर्पित बजट दिया है। इस बजट से, नागरिकों को दया का पात्र बनाने की पूर्ववर्ती सरकार की नीति को बदल कर, 'सबका साथ सब का विकास' करने की क्षमता रखने वाली राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने अपना बजट दिया है।

कांग्रेस के माननीय सदस्य कोई हैं नहीं, मैं कांग्रेस के सदस्यों को कहना चाहती थी कि आपने किस तरीके से सरकार को लूटा है, लेकिन वह सामने सारी टेबलें खाली पड़ी हैं। जोधपुर विकास प्राधिकरण का अगर हवाला दूं, जोधपुर विश्वविद्यालय का हवाला दूं, मैं किस-किस का हवाला दूं, जहां पर देखो वहां भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार था।

हमारे जोधपुर के अन्दर, जिस तरीके से माननीय सदस्य कह रहे थे कि राजस्थान के पूर्व मुख्य मंत्री सारी चीजें जोधपुर ले गये, लेकिन वे ले क्या गये थे, सिर्फ कागजों में ले गये थे। कागजों में थीं उनकी योजनाएं, यह बात सही है मगर उन्होंने वहां किया कुछ भी नहीं। जो कुछ भी उन्होंने किया है तो उन्होंने सरदारपुरा में किया है, बाकी ना तो शहर में किया, ना सूरसागर में किया। राजस्थान का मुख्य मंत्री पूरे राजस्थान का होता है, उनको सब पर नजर रखनी चाहिए, मगर उन्होंने सिर्फ सरदारपुरा का सोचा, बाकी किसी का नहीं सोचा।

सभापति महोदया, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जयपुर से दूसरा नम्बर जोधपुर है, मगर जोधपुर के अन्दर आज अगर आप जाकर देखें तो सड़कों की क्या हालत है! पानी की क्या हालत है! एक समय था, जब वसुंधराजी मुख्य मंत्री बनीं थी तो पहले यह कहा था कि पहले पानी की व्यवस्था हो, सड़कों की व्यवस्था हो और बिजली की व्यवस्था हो। आज भी अगर वहां सड़क जाकर देखें जोधपुर में, तो जालौरी गेट से फतेह पोल तक की सड़क, अगर करौंथी से काटें तब वह सड़क कटती है, और एक इस पूर्व सरकार की सड़कें जाकर देखो, तो उनमें खड्डे पड़े हैं। क्योंकि वह भ्रष्टाचार में लिप्त थी और सड़कें अच्छी नहीं बनीं। मैं यह कहना चाहती हूं कि कांग्रेस सरकार की यह स्थिति थी। सामने बैठने तक की स्थिति में वे नहीं हैं।

सभापति महोदया, जयनारायण विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के अन्दर जो घोटाला हुआ है, माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं चाहूंगी कि उसकी अगर आप इन्क्वायरी करायेंगे तो पता चलेगा और उसमें दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। आप देखेंगे कि उसमें कितना भ्रष्टाचार हुआ है और किस तरीके से हुआ है।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभापति महोदया, थोड़ा मेरे नजर का है तो मैं थोड़ा ऐसे देख सकती हूं। हमारी नेता और उनके आर्थिक सलाहकारों की अपार मेहनत स्पष्ट झलकती है और यही कारण है कि बिना विकास को रोके, अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं के लिए राशि उपलब्ध करायी है।

सभापति महोदया, माननीय अटल बिहारीजी वाजपेयी ने प्रधान मंत्री बनने पर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना में सड़क निर्माण के नये कीर्तिमान स्थापित किये थे। माननीय नरेन्द्र भाई मोदी के केन्द्रीय बजट के बाद इस परम्परा को प्रदेश के बजट में माननीया वसुंधराजी ने आगे बढ़ाया है। राज्य उच्चमार्ग से लेकर मिसिंग लिंक से सीधा जोड़ा है और ग्राम, ढाणी की मुख्य सड़कों से जोड़ने के लिए बजट में बड़ी राशि प्रदान की है।

सभापति महोदया सड़क के साथ हवाई परिवहन के लिए प्रदेश के शहरों को आपस में हवाई सेवा से जोड़ने का नवीन संकल्प प्रस्तुत हुआ, जिसका लाभ उद्योग और पर्यटन जगत को मिलेगा।

सभापति महोदया, पिछली कांग्रेस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में स्वयं द्वारा एक भी विद्युत उत्पादन केन्द्र विकसित नहीं कर पाने की विरासत हमें सौंपी। परन्तु हमारा लक्ष्य है राज्य के प्रत्येक नागरिक को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराना, आन-डिमांड कृषि कनेक्शन, आम किसान तक गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना। यह हमारी पाजिटिव सोच रही है।

सभापति महोदया, हमारे प्रदेश पर सूर्य भगवान की अपार कृपा है। अब तक इनकी कृपा किरणों से गर्मी हमारे लिए पहुंचाई जाती है लेकिन हमारी सरकार ने 5 साल में 25 हजार मेगावाट क्षमता के सोलर पावर प्लांट की स्थापना का लक्ष्य रखा है। इससे ऊर्जा उत्पादन हमारी प्राथमिकता है। इससे व्यवस्था में खर्च हो रहे करोड़ों रुपयों की धनराशि की बचत प्राप्त हो रही है।

सभापति महोदया, मैं थोड़ा समय का भी ध्यान रखूंगी लेकिन मेरे सूरसागर क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, उनको मैं कहना चाहूंगी। जोधपुर में सूरसागर शहर पिछड़ा हुआ है। आज यह स्थिति है कि स्कूलें देखें तो वहां भवन नहीं हैं। माननीय शिक्षा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं मुख्य मंत्रीजी से और शिक्षा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे सूरसागर क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय खोला जाये जिससे कि बालिकाओं को पढ़ने के लिए अच्छी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सुविधा मिलेगी। ढाई लाख की आबादी वाले इस क्षेत्र के अन्दर इससे एक अच्छी व्यवस्था होगी।

सभापति महोदया, शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों का भी समुचित विकास होगा। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने पर्यटन के बारे में बहुत कुछ कहा है, मैं यह चाहूंगी कि जोधपुर में पर्यटन संख्या और ठहराव बढ़ाने की अपार सम्भावनाएं हैं लेकिन इस दृष्टि से सोचा ही नहीं जा रहा है। मेरा निवेदन है कि जोधपुर में चौपासनी मंदिर; श्रीनाथजी महादेव मंदिर, जिसे श्रीनाथजी के तर्ज पर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाये; कायलाना अपने आप में शाम बिताने लायक स्थान है; वीर दुर्गादास स्मारक स्थान; सम्राट अशोक उद्यान; सुंदर बालाजी; गंगलाव तालाब; ये बड़े पर्यटन केन्द्र बन सकते हैं। इसमें मेरा निवेदन है कि इस पर्यटन विकास में सूरसागर महल का भी अपने आप में बहुत नाम है। उस महल को भी पर्यटन की दृष्टि से देखा जाये।

सभापति महोदया, राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी ने यह कहा है कि हम जितनी पुरानी इमारतें हैं, मंदिर हैं, उनको पर्यटन की दृष्टि से विकसित करेंगे। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी को यह कहना चाहूंगी कि सूरसागर महल का अपने आप में नाम है लेकिन उसके अन्दर इतना कचरा भरा हुआ है और वह ऐसे ही पड़ा हुआ है। मैं जब उसको देखने गयी और एक टीले के ऊपर मेरा हाथ चला गया, तो मैं समझती हूं कि आज अगर हम करोड़ों रुपये खर्च करें तो भी ऐसा प्लास्टर नहीं हो सकता, हाथ लगाते ही उसमें मुंह दिखना शुरू हो गया। वह ऐसा महल है। वह स्टेट के टाइम का बनाया हुआ है।

सभापति महोदया, नहरों के बारे में और नदियों के बारे में भी मुख्य मंत्रीजी की सोच है। मैं कहना चाहूंगी कि सूरसागर के अन्दर और जोधपुर के अन्दर नाले नहीं हैं, वे नहरें हैं स्टेट के टाइम की, जो कि जनता को पानी पिलाने के लिए थी। आज वे सारी नहरें कचरे से भरी पड़ी हैं। आज उनकी स्थिति बड़ी ही चिंताजनक है। मैं यह चाहूंगी कि उन नहरों को साफ करायें। नहरों में कचरा भरा हुआ है, किसी ने अतिक्रमण कर लिया है, इस तरीके के हालात हैं उन नहरों के। मैं यह चाहूंगी कि उनका भी काम हो।

सभापति महोदया, गंगलाव तालाब और बाईजी का तालाब, ये स्टेट के टाइम के बने हुए हैं। स्टेट के टाइम में, उनका जनता के प्रति यह सोच रहता

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

था कि जनता प्यासी नहीं रहे। वह पानी कैसे पियेंगे अगर बरसात नहीं हुई तो? उन्होंने इसलिए तालाब, बांध बनाये थे। लेकिन आज उनकी स्थिति बड़ी खराब है। कचरे से वे भरे पड़े हैं। सभापति महोदया, मैं बैठने ही वाली हूं, आप चिंता नहीं करें। मैं दो मिनट में ही अपनी बात समाप्त करूंगी। मैं यह चाहूंगी कि इन नहरों की भी अच्छी व्यवस्था हो।

सभापति महोदया, जोधपुर का यातायात प्रबंध भारी समस्या बन चुका है। कम से कम 3 फ्लाईओवर का प्रावधान बजट में किया जाये।

घरेलू उद्योगों में संलग्न कारीगरों के लिए दीनदयाल उपाध्याय पार्क की चारदीवारी के बाहर हाट बाजार का निर्माण किया जाये।

सभापति महोदया, मैं जल्दी ही खतम कर दूंगी, आप घंटी मत बजाना, नहीं तो मैं मेरी बात भूल जाऊंगी। हैल्थ मिनिस्टर हैं नहीं, फिर भी आप मेरी बात वहां तक पहुंचायें, महात्मा गांधी अस्पताल में एक एम आर आई और सीटी स्कैन सुविधा पी पी पी मोड पर आरम्भ की जाये। एक नया

(17.00 बजे)

एस टी पी और एक एस टी पी तक सीवरेज जल पहुंचाने के तंत्र के विकास के लिए भी समुचित राशि प्रदान की जाये।

माननीय सभापति महोदया, मेरा आपसे निवेदन है कि आपने जोधपुर के हैण्डीक्राफ्ट एवं एग्रो फूड अंतरराष्ट्रीय मार्केट में प्रसिद्ध करने के लिए पहले जोधपुर ब्रह्मगुप्त अनुसंधान केन्द्र का शिलान्यास किया था परन्तु सरकार बदलने के बाद वह बंद कर दिया गया था। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस महत्वाकांक्षी योजना को वापस शुरू करें। हालांकि कहावत तो यह है और इतिहास यह कहता है कि हाकिम बदले, हुक्म नहीं बदले, लेकिन सरकार बदली और अशोकजी ने इस बात को बदल दिया।

मेरा आपसे एक और निवेदन है कि जोधपुर के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो टैक्स लगाया हैण्डीक्राफ्ट के ऊपर और मसालों के ऊपर, मैं आपके माध्यम से यह चाहूंगी कि इस हैण्डीक्राफ्ट और मसालों के ऊपर जो टैक्स लगाया, उसको वापस लिया जाये ताकि जोधपुर के लोगों को राहत मिल सके।

आपने मुझे समय दिया, बोलने का मौका दिया, मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

सभापतिजी, मैं मुख्य मंत्रीजी के इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करती हूं कि उन्होने ऐसा बजट दिया और दो घण्टे तक जिस तरीके से उन्होंने अपना भाषण दिया, पानी तक भी नहीं पिया। मेरे ख्याल से ऐसा, न भूतो न भविष्यति; ऐसा कोई भी बजट पेश करना बहुत मुश्किल है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को बहुत-बहुत साधुवाद और धन्यवाद दे रही हूं।

माननीय सभापति महोदया, एक मेरी बात और ध्यान में आई हुई रह गई है। जोधपुर शहर के अन्दर जे डी ए के ऐसे लक्ष्य हैं कि कोई भी काम कराने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत कर्जा हुआ है। मैं यह चाहूंगी, जोधपुर की हालत को देखकर राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से मांग करूंगी कि कोई स्पेशल पैकेज दें ताकि जोधपुर शहर में ज्यादा से ज्यादा काम हो सकें, यह भावना लेकर चल रहे हैं।

आपको बहुत-बहुत साधुवाद दे रही हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री अशोकजी डोगरा।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): माननीय सभापति महोदया, जो 14 तारीख को राजस्थान की यशस्वी और लोकप्रिय मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धराजी ने 2014-15 का बजट पेश किया है, वह किन परिस्थितियों में किया है, जब राजस्थान का राजस्व घाटा 2,500 करोड़ का, राज्य पर कर्जा 1,30,640 करोड़ का, बिजली कम्पनियों का कर्जा 75 हजार करोड़ का। उसके बावजूद एक ऐसा लोक-लुभावन बजट जो पेश किया है, उसकी पूरे राजस्थान की जनता, खाली इधर के दस-बीस लोगों को छोड़कर, सारे टी वी चैनल्स, सारे अखबार, सारे राजस्थान की जनता इसकी प्रशंसा कर रही है। इस बजट के माध्यम से माननीया वसुन्धराजी ने जो विजन दिखाया है, आर्थिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने का प्रयास किया है, यह बजट राजस्थान के विकास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसमें अंतिम लाइन में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति को भी टच करने का प्रयास किया गया है।

कांग्रेस वाले इसको पचा नहीं पा रहे, इतने अच्छे बजट को, क्योंकि पूरी दुनिया इसकी तारीफ कर रही है। कुछ तो जनता ने भगा दिया और आज शायद खुद ही यहां से भाग गये। इनके राज में क्या-क्या हुआ। मैंने इनके भी पांच बजट देखे हैं। इन्होंने स्कूल अपग्रेड किये तो खाली नाम ही बताया, नाम

(श्री अशोक डोगरा)

ही चेंज किया, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक। इसके अलावा, न तो वहां कोई टीचर लगाया, न वहां कोई व्यवस्था की। उसकी वजह से आज शिक्षा की व्यवस्था ही खतम हो गई। बच्चे प्राइवेट स्कूलों में जाने लग गये।

इन्होंने पांच साल तक हर बजट में एक-एक लाख हर साल नौकरियों की घोषणा की, लेकिन इनके पूरे पांच साल का इतिहास देख लो, मुश्किल से पचास हजार लोगों को भी नौकरियां नहीं मिलीं।

इन्होंने मुफ्त दवाई की घोषणा की, तो डाक्टर नहीं लगाये। डाक्टरों के अभाव में जनता को प्राइवेट हास्पिटलों में जाना पड़ा। इन्होंने मुफ्त जांच की बात की, तो वहां उपकरण नहीं खरीदे। कोई बजट की घोषणा पूरी नहीं हुई।

सभापति महोदया, मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में इन्होंने, माननीय अशोकजी गहलोत ने पहले बजट में बूंदी से भीलवाड़ा मेगा हाइवे की बात कही थी, जिस पर 111 करोड़ का प्रावधान भी दिया था, ये पांच साल का शासन करके, हार के, विपक्ष में आ गये, लेकिन वह सड़क आज तक नहीं बनी।

इससे पिछले वाले बजट में अशोक गहलोतजी ने बूंदी में एक मेडिकल कालेज की भी बात की थी, लेकिन उसके लिए न तो कोई बजट दिया, न वह बनना था और न बना।

इनकी सब बातें सिर्फ थोथी, झूठी साबित हुईं। इन्होंने कोई काम नहीं किया पांच साल तक, बल्कि साढ़े चार साल तक यह सरकार सोयी रही। जब माननीया वसुन्धराजी की सुराज संकल्प यात्रा निकली और उसमें जो भीड़ उमड़ने लगी, उससे घबराकर फिर इनको जनता की याद आई, तब इनको याद आई कि जनता को, बी पी एल को साड़ी भी चाहिए, कम्बल भी चाहिए; तब इनको ध्यान आया कि विधवा को पेंशन, विकलांग को पेंशन, वृद्ध को पेंशन। उन्होंने सारे उस समय नियम-कायदे ताक पर रखकर ऐसे रेवड़ियां बांटने की कोशिश की कि जैसे उन रेवड़ियों से ये सरकार में वापस आ जायेंगे। पांच साल तक इन्होंने बिजली नहीं दी, फिर दो-दो सी एफ एल देकर लोगों से वोट मांगने की बात की। इनके मंत्री और विधायक, भ्रष्टाचार और व्यभिचार में लिप्त रहे। इससे ज्यादा शर्मनाक बात राजस्थान के लिए और क्या होगी, जिस सरकार के कितने मंत्री और कितने विधायक व्यभिचार के मामलों में जेलों में गये और आज भी जेलों में पड़े हैं?

(श्री अशोक डोगरा)

अब माननीया वसुन्धराजी ने इस परिवर्तित बजट में सात नये मेडिकल कालेजों की घोषणा की है, जो बहुत स्वागत योग्य है; तीन नये इंजीनियरिंग कालेजों की भी बात की; केन्द्रीय विद्यालय की तर्ज पर इंग्लिश मीडियम के 66 माडल स्कूलों की बात की ताकि गांव का बच्चा भी इंग्लिश सीख सके; हर पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय का प्रयास किया; हर पंचायत समिति में आई टी आई होगी; बच्चियां जब नाइन्थ क्लास में प्रवेश करेंगी तो उनको साइकिलें मिलेंगी ताकि उसके पीछे वे अपने छोटे भाई-बहन को भी बैठा कर स्कूल ला सकें।

माननीय सभापतिजी, सबसे बड़ी बात है, गौरव पथ के लिए आज तक किसी ने नहीं सोचा था, इन्होंने गौरव पथ के लिए भी, गांव में आधे किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर तक सी सी रोड और नाली का प्रावधान किया है जिसे पूरे गांव की जनता ने सराहा है और बहुत स्वागत किया है।

चालीस हजार नये कृषि कनेक्शन देने की भी बात कही है। अपने राजस्थान की 67 प्रतिशत आबादी को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने का प्रयास किया। जनता जल योजना में पी एच ई डी का नियंत्रण सीधे पंचायतों को सुपुर्द किया और एक निश्चित फण्ड देकर पंचायत समितियों में टेक्निकल आदमी लगाकर, उस पर नियंत्रण उनका रहेगा। भामाशाह योजना जो पिछली सरकार ने बंद कर दी थी, उसको पुन: चालू किया। थर्ड ग्रेड टीचर्स जो कई तरह की परीक्षा दे रहे थे, उनको मात्र एक ही परीक्षा देकर आना है। रोडवेज के बस स्टैण्डों पर शापिंग के लिए और वेटिंग के लिए उनको मोडिफाई करने की बात की। 20 हजार किलोमीटर सड़कों की भी बात की, जो बहुत ही सराहनीय है। पूरी दुनिया इसके लिए उनकी वाह-वाह कर रही है।

सबसे बड़ी बात यह है कि पांच वर्षों में 15 लाख लोगों के रोजगार के अवसर प्रदान किये जायेंगे। पिछली सरकार ने हमारे युवाओं के लिए, रोजगार के लिए बिलकुल ध्यान नहीं दिया था। माननीया वसुन्धराजी ने 15 लाख लोगों को रोजगार की बात की है।

इस बजट में माननीया वसुन्धराजी ने मेरे विधान सभा क्षेत्र बूंदी को भी जैत सागर, नवल सागर, सुख महल और रामेश्वर महादेव के विकास के लिए 4 करोड़ 93 लाख रुपये दिये हैं। मैं मेरी तरफ से और बूंदी की जनता की तरफ से मैडम को बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं।

(श्री अशोक डोगरा)

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बूंदी की कुछ समस्याएं हैं, मेरे विधान सभा क्षेत्र की, उनके लिए भी सरकार को कहना चाहता हूं। मेरे बूंदी शहर में 60 परसेंट आबादी फोरेस्ट में आ गई है। पूरा आबादी क्षेत्र है। 2003 का नोटिफिकेशन है, अब उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है कांग्रेस के राज में, जिसकी वजह से लोग अपनी प्रोपर्टी नहीं बेच सकते, कोई निर्माण नहीं करवा सकते। माननीया वसुन्धराजी जब सुराज संकल्प यात्रा में बूंदी आई थीं, तब भी लोगों ने इनको बताया था और इन्होंने एक साल में इसको फोरेस्ट से निकालने का कहा था। तो मैं माननीया वसुन्धराजी से निवेदन कर रहा हूं कि बूंदी की आबादी में से 60 परसेंट आबादी फोरेस्ट के क्षेत्र में आ रही है, इसको किसी तरह निकलवाया जाये।

मेरे एक गरड़दा बांध है जिसके निर्माण में 150 करोड़ रुपये से ऊपर लग गये थे, 15 अगस्त, 2010 को वह बांध जब पहली बार 25 परसेंट भरा और 25 परसेंट भर कर वह बांध टूट गया। उस पर 150 करोड़ रुपये बह गये पानी में। पुरानी अशोक गहलोतजी की सरकार उस बांध को ही भूल गई और बांधों की लिस्ट में से उसका नाम ही हटा दिया। मैडम की 60 दिन की कार्ययोजना में उसमें 56 करोड़ रुपये मिले, लेकिन उसके टेण्डर नहीं हो पा रहे। तो मेरा इस सरकार से यही निवेदन है कि इस बांध को जल्दी से जल्दी बना दिया जाये।

लाखेरी से बिजौलिया मेगा हाइवे बने। पर्यटन की दृष्टि से बूंदी बहुत महत्वपूर्ण है। यह मेगा हाइवे नहीं होने की वजह से, सवाई माधोपुर से लोग आते हैं, वे सीधे कोटा होते हुए चित्तौड़ और उदयपुर निकल जाते हैं, बूंदी छोड़ जाते हैं।

मेरा माननीय बिजली मंत्रीजी से निवेदन है कि मेरे एरिये में डाबी ऐसा एरिया है जिसमें 15 पंचायतें हैं, वह बूंदी से थोड़ा अलग-थलग पड़ता है, वहां एक 32 के वी का सब स्टेशन चाहिए।

पिछली सरकार ने बूंदी के 13 गांव मेरे विधान सभा क्षेत्र के कोटा यू आई टी में बिना बूंदी की पब्लिक से पूछे मिला दिये। किसी जन-प्रतिनिधि से नहीं पूछा, वहां के कलक्टर से नहीं पूछा। पहली बार राजस्थान में ऐसा हुआ कि एक जिले के एक गांव को दूसरे जिले की यू आई टी में मिला दिया। इससे भी जनता में आक्रोश है। यह आर्डर निरस्त कराकर, इनको वापस बूंदी में लगाया जाय।

(श्री अशोक डोगरा)

बूंदी में सीवरेज का काम चला था 34 करोड़ का, उसमें 10 प्रतिशत भी पैसा खर्च नहीं हुआ और वह ठेकेदार काम छोड़कर भाग गया। उसके वापस टेण्डर नहीं हो पा रहे हैं। आर यू आई डी पी के तहत काम था। इस काम को भी जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय।

मेरा दूसरा निवेदन था कि खटकड़ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बहुत आवश्यक है, वहां 17-18 पंचायतें पड़ती हैं। उसके लिए भी, माननीय चिकित्सा मंत्रीजी यहां विराजे हैं, इनसे निवेदन कर रहा हूं। पिछले 5 साल में मैंने कई बार पिछली सरकार में यह मामला उठाया, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया।

दूसरा एक यह निवेदन था कि कुरैल नदी है, उसमें हनुतिया और जैथल के बीच एक पुल बन जाय तो नेशनल हाइवे 12 मेगा हाईवे से मिल जाएगा; बूंदी और केशोरायपाटन विधान सभा क्षेत्र आपस में जुड़ जाएगा। उस एरिये के करीब 40 गांव हैं जो एक पुलिया नहीं होने की वजह से सीधे कोटा मण्डी में चले जाते हैं और बूंदी मण्डी का नुकसान होता है। वे बूंदी मण्डी में आने लगेंगे।

एक लास्ट निवेदन और है। जो केन्द्र सरकार ने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी राजस्थान को दी है, इसको हाड़ौती में कहीं न कहीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनायी जाय। पहले भी हाड़ौती की आई आई टी पुराने मुख्य मंत्री, अशोक गहलोतजी जोधपुर ले गये। इसलिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी केन्द्र की बनेगी, उसको कोटा, बूंदी में कहीं भी, हाड़ौती में बनाया जाय।

आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्या श्री शंकर सिंहजी रावत।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदया, आपने बजट पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, धन्यवाद।

बजट के ऊपर मैं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री और राजस्थान की आम जनता की आशा की किरण, सम्माननीया वसुन्धराजी का बहुत-बहुत आभार और साधुवाद देता हूं कि उन्होंने राजस्थान की जनता को, 36 जातों को एकछत्र में बांधकर, सबको एक नजर से देखते हुए, सभी राजनैतिक बातों को भूलते हुए, उन्होंने अपने परिवार के रूप में जो बजट पेश किया है, उसके लिए बजट का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और उनको बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री शंकर सिंह)

जिस प्रकार, शासन कांग्रेस के राज में भी चला था, जब हमारी मुख्य मंत्री वसुन्धराजी थीं, 2003 से 2008 तक, उनको बजट की प्राप्तियां हुईं 1,62,669.43 करोड़ रुपये, बजट खर्च किया 1,63,292.25 करोड़। उस बजट के अन्दर जो सड़कें बनी हैं, राजस्थान का विकास हुआ है, वह किसी से छिपा हुआ नहीं है। इतना अच्छा राजस्थान का विकास हुआ, इसमें 24,220 किलोमीटर सड़कें बनायीं। कांग्रेस का पिछले 5 साल का शासन काल, 2009 से 2013 तक का, उसमें 2,93,091.19 करोड़ रुपये की आवक हुई और 2,92,222.37 करोड़ खर्च किये गये और सड़कें बनायीं मात्र 4,888 किलोमीटर, जबकि हमारे 5 साल के शासन काल में 24,220 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, और राजस्थान का जो विकास हुआ है उसको भी आप देख लीजिए।

अब उस शासन के अन्दर हमारी मुख्य मंत्रीजी ने 10 लाख लोगों को नौकरी दी। कांग्रेस के शासन काल में कितने लोगों को नौकरी दी? सिर्फ तड़फाने के अलावा कुछ नहीं किया। गायें मर रही थीं, उनको चारा कहीं नहीं मिला। राजस्थान में देवी के रूप में शासन चलाने के लिए शासन की लगाम राजस्थान की जनता ने दी है। मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं कि इन तड़फती हुई गायों की तरफ नजर पड़ी और उन्होंने गौशाला आयोग का गठन किया। मैं आग्रह करूंगा कि उनके लिए चारे की भी ऐसी कोई व्यवस्था करें, आदमियों की जैसी व्यवस्था की है वैसी उन गायों के लिए भी कोई न कोई व्यवस्था करें।

जिस प्रकार पिछली सरकार के अन्दर बजट पेश किये गये थे, कांग्रेस से जीतकर आने वाले सदस्य मुझे यहां नजर नहीं आ रहे हैं, बड़े जोर-शोर से सत्ता पक्ष में बैठकर बोलते थे, हमारा विकास का राज चलाने वाले मुखिया हैं, ये राजस्थान के गांधी हैं। मैंने कहा कि गांधीजी तो ऊपर बैठे हुए हैं, उनकी फोटो लगी हुई है, उनको बदनाम मत करो। लेकिन गांधी के रूप में उनको पेश किया गया, परन्तु कार्य कैसे हुए? राजस्थान की जनता की आम बहनें अगर कोई मंत्री के घर पर मिलने गई हैं, वे आज तक वापस नहीं लौटीं। पता नहीं, कहां गयीं। ऐसे शासन नहीं चलता है। शासन चलाना इस देवी से सीखें।

इसलिए मेरा उनसे निवेदन है, आज शासन चलाने का, कांग्रेस के सदस्य बोलते हैं छाती ठोंककर कि हमारे राज में ऐसा हुआ है, आप कह रहे हों, चार दिन के बाद में अच्छे दिन आने वाले थे, क्या हुआ? मैं उनको कहना

(श्री शंकर सिंह)

चाहता हूं, सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। ऐसे शासन नहीं होता है। कांग्रेस के अन्दर आपने शासन चलाने का जो काम किया था, आपने शिक्षा का मंदिर है, स्कूल है, उन स्कूलों का नाम भी आपने राजीव गांधी के नाम से कर दिया। अभी पिछले कार्यकाल में जो ग्राम पंचायत मुख्यालय पर आई टी सेंटर खोले गये हैं, ये गवर्नमेंट के थे, कांग्रेस के नहीं, लेकिन उनका नाम भी राजीव गांधी निर्माण आई टी सेंटर। मैं उनको कहना चाहता हूं, आप राजस्थान के अन्दर आम आदमी के नाम पर टोपी बनाकर राजीव गांधी या कांग्रेस का नाम लिखा देंगे, तो भी राजस्थान की जनता समझ चुकी है, आपकी बातों में आने वाली नहीं है। उन्होंने राजस्थान के अन्दर ही नहीं, हिन्दुस्तान के अन्दर भी इस कांग्रेसमुक्त भारत बनाने का सोच बना लिया है।

मेरा तो आपसे निवेदन है, माननीय सभापति महोदया, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, अभी माननीय विद्युत मंत्रीजी विराजमान हैं, उनसे भी आग्रह है, बिजली के कनेक्शन के लिए, आपने राजस्थान की जनता को जो थ्री फेज बिजली, सिंगल फेज बिजली 22 घण्टे देने के लिए बात चल रही है, उसके लिए मैं माननीय विद्युत मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने बिजली में बहुत सुधार किया। आपने शासन में आते ही, जिस प्रकार कांग्रेस के शासन में 5-5, 6-6 घण्टे सिंगल फेज बिजली मिल रही थी, आपने चुनाव जीतने के बाद तुरन्त कहा, 22 घण्टे बिजली देने की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की थी, उसके अनुरूप आप बिजली दे रहे हैं, हम आपका बहुत-बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। मेरा इसमें निवेदन है, मंत्री महोदय, एक सुधार और करें कि बिजली के लिए काश्तकारों की जो मांग है, उसमें थोड़ा और सुधार करें। सिंगल फेज के जो कनेक्शन हैं, वे काश्तकारों को देने के लिए आप कोई न कोई संशोधन करें। सिंगल फेज के कनेक्शन काश्तकारों को मिल जाएंगे तो निश्चित वे आपको बहुत-बहुत याद रखेंगे, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। जानवरों के पीने के पानी के लिए वे खेली भी भरते हैं, पीने का पानी भी वे सिंगल फेज से भरेंगे।

कांग्रेस के शासन में शिक्षा का ढर्रा बिगड़ा है। उसको सुधारने के लिए माननीय शिक्षा मंत्रीजी से आग्रह है कि आज प्राइवेट स्कूलों की तरफ बच्चे जा रहे हैं, भीड़ लगी रहती है और हर व्यक्ति प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाने जाएंगे। उन अध्यापकों की तनख्वाह, जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी तनख्वाह 5 हजार से, 10 हजार से ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छी शिक्षा मिलने

(श्री शंकर सिंह)

के कारण वहां बच्चों की संख्या ज्यादा बढ़ जाती है। हमारे सरकारी स्कूलों के अन्दर 30-40 हजार तनख्वाह दे रहे हैं, उसके बावजूद शिक्षा का सुधार नहीं हो रहा है और हमारे बच्चों की संख्या वहां कम होती जा रही है। कांग्रेस के कर्मों का फल हम भुगत रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय से मेरा आग्रह है कि आप निश्चित तौर पर इसमें ऐसा कोई सुधार लायें कि पहली क्लास से उस बच्चे को इंग्लिश में, के.जी., एल.के.जी. से स्कूल शुरू हों और निश्चित रूप से उनमें अच्छी पढ़ाई मिले। उसमें ऐसा कम्पल्सरी किया जाए कि पहली क्लास से ही इसमें सुधार हो, ताकि पांचवीं क्लास, आठवीं क्लास के बच्चे अपने आप अपना भविष्य आगे तय करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इस कांग्रेस के शासन में जो ग्रामीण क्षेत्र में, सभी में पहली क्लास से आठवीं क्लास तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से पास करने का किया है, यह किसी पेड़-पौधे की जड़ों में तेजाब डालने का काम किया है। ऐसा काम हमें नहीं करना है। हमें पूरे राजस्थान में अच्छा काम करने के लिए, सुधार करने के लिए, आपने अच्छा सुधार किया भी है, फिर भी आप थोड़ा और सुधार करने के लिए ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पर राजस्थान की जनता और ग्रामीण क्षेत्र की जनता आपको कभी नहीं भूलेगी।

साथ में, मेरा ब्यावर क्षेत्र के लिए निवेदन है कि ब्यावर से जयपुर के रास्ते पर जिस प्रकार हाइवे के ऊपर होटलों का संचालन हो रहा है, माननीय सभापति महोदया, उन होटलों के अन्दर एक जाति विशेष के लोगों के द्वारा उन पर कब्जा किया जा रहा है। आने वाले टाइम में निश्चित तौर पर वे आतंकवादियों के अड्डे के रूप में आपको मिलेंगे। इसलिए उसमें सुधार होना चाहिए। उन होटलों के अन्दर, अभी भी अपन देखें तो जितने भी अपराध के कार्य हैं, अपराधी के रूप में जो आते हैं, वे वहीं शरण लेकर रहते हैं। इसलिए उनकी हमेशा जांच होनी चाहिए, उसमें सुधार होना चाहिए। काश्तकारों से, भोले-भाले लोगों से कम पैसों में जमीन खरीदकर हाइवे पर होटल बनाये जा रहे हैं। उनके लिए मेरा सुझाव है कि उसमें सुधार किया जाए।

ब्यावर से जो रेल की मांग की है...(व्यवधान) सब्र तो करो थोड़ा। यह कोई कांग्रेस का शासन नहीं है जो जिला नहीं बनेगा। ब्यावर जिला बनेगा। हमारी मुख्य मंत्रीजी बनायेंगी। ऐसी बात नहीं है। आप सब्र करें और तसल्ली रखें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन को सम्बोधित करें और जल्दी अपनी बात को समाप्त करें। माननीय सदस्य, आप अपनी बात को अब सम-अप करें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदया, ब्यावर से उदयपुर वाया टाटगढ़, राजसमन्द होते हुए रेल लाइन के निर्माण हेतु मेरा सुझाव है कि हमारे शासन में इस बात की भी आगे बढ़ोतरी करें।

ब्यावर के अन्दर सम्राट पृथ्वीराज चौहान खेल स्टेडियम का निर्माण हो रखा है, वह अपूर्ण पड़ा हुआ है। उसके ऊपर भी बजट के लिए, कुछ न कुछ आगे बढ़ें, ताकि वह स्टेडियम पूरा बने।

ब्यावर के अन्दर यू.आई.टी. की मांग बहुत वर्षों से चली आ रही थी। अभी छह महीने पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, उस समय, उसके बाद में जैसे ही चुनाव हुआ तो उसका सर्वे किया गया और सर्वे में यू.आई.टी. की श्रेणी में ब्यावर आया है। इसलिए मेरा आग्रह है कि ब्यावर में शीघ्र यू.आई.टी. चालू की जाए।

ब्यावर में संख्या की दृष्टि से पुलिस थाने कम हैं। इसलिए साकेत नगर पुलिस चौकी को ब्यावर में नये थाने के रूप में चालू किया जाए।

ब्यावर में मेडिकल कालेज हो। आज अमृत कौर अस्पताल और सभी अस्पतालों में डाक्टरों की संख्या बहुत कम है। माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजमान हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि डाक्टरों की संख्या और बढ़ायी जाए। जिस प्रकार अमृत कौर अस्पताल एक 'अ' श्रेणी के अस्पताल के रूप में राजस्थान में था, उसकी इस कांग्रेस शासन में बहुत बुरी दुर्दशा हो गई है। वहां पर आज 20-20 डाक्टर्स की पोस्टें खाली हैं, अन्य स्टाफ की पोस्टें भी खाली हैं। इसलिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी विराजमान हैं, निश्चित रूप से डाक्टरों के सम्बन्ध में भी वहां पर सुधार करने के लिए कुछ न कुछ करेंगे। उन्होंने 'हां' में 'हां' मिलाई है, मेरा उनसे आग्रह है कि उसमें सुधार हो।

पीने के पानी के लिए घूमद और कड़िया बांध से जो देवाता फीडर का निर्माण हो रखा है, मेरा सरकार से आग्रह है कि वहां के काश्तकारों के लिए, निश्चित रूप से उस काम को करने के लिए, देवाता फीडर का निर्माण हो जाएगा तो वहां पर पीने के पानी और खेती के लिए हमेशा के लिए सुविधा मिलेगी।

बीसलपुर के पानी को 199 गांवों में पहुंचाने के लिए 250 करोड़ की

(श्री शंकर सिंह)

योजना का कार्य चालू है। उस कार्य को एक वर्ष हो गया है पर वह कार्य किन ठेकेदारों के हाथ में है, न तो ठेकेदारों का पता है, न कार्य करने वालों का पता है और अभी तक खाली पाइप लाकर डाले गये हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि उस कार्य को अंजाम देने के लिए समय सीमा तय की जाए ताकि वह कार्य हो और जनता को पानी पहुंच सके।

दूसरा, ब्यावर से देवाता चौराहे तक जो सड़क है, उसकी तीन मीटर से सात मीटर की चौड़ाइकरण करने के लिए, उस सड़क को सात मीटर चौड़ी बनाया जाए। जस्सा खेड़ा से सारण तक मेगा हाइवे बनाया जाए।

नरेगा कार्य में जिस प्रकार आज काम बहुत कम हो रहा है, उसमें मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर गंगा और यमुना के पानी को लाने के लिए हमारी मुख्य मंत्री महोदया खुद प्रयासरत हैं और निश्चित ही वह पानी जिस दिन राजस्थान में आ जाएगा, हम तो कह रहे हैं, हमारा आग्रह है कि नरेगा के अन्दर जो बजट खर्च हो रहा है, उस बजट को वहां खर्च किया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब सम-अप करें आप। माननीय सदस्य, आपके क्षेत्र की सारी समस्याएं आ गईं, अब आप सम-अप कर दें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय सभापति महोदया, मुझे दो मिनट दें। जवाजा को तहसील बनाया जाए।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): 16-17 मिनट हो गये। (व्यवधान) 18 मिनट हो गये हैं। 5-5 मिनट में खतम करो, नहीं तो बोलना ही नहीं होगा फिर। नम्बर ही नहीं आयेगा फिर तो। हो गये एक मिनट करते-करते तो पांच मिनट।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शंकर सिंहजी, इसको जल्दी से सम-अप करें। आपकी बात हो गई।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ब्यावर को जिला बनाने के लिए निवेदन है। इसमें सबकी सहमति मिल रही है। लास्ट में, मेरा ब्यावर जिले के लिए आग्रह है। निश्चित रूप से आप मेरी बात को महारानीजी तक पहुंचायेंगे।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद और बजट के लिए मैं बहुत-बहुत स्वागत करता हूं कि बहुत अच्छा बजट पेश किया। महारानीजी को इसके लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, डा. किरोड़ी लालजी मीणा। (व्यवधान)

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): आप तो कल बोल लेते न। किरोड़ी लालजी, कल बोलते न। आज तो इधर ही बोलने दो न।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेरे इधर मित्र बहुत बैठे हैं, टोका-टाकी करेंगे। इसलिए ज्यादा लम्बा नहीं बोलूंगा।

श्री सभापति: आप तो संक्षिप्त में जितना अच्छे से अच्छा बोल सकें...

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मैं संक्षेप में ही बोलूंगा, लम्बा नहीं बोलूंगा। (व्यवधान) अंग्रेजी में बोलें? (व्यवधान) अंग्रेजी से क्या लेना देना?

श्री जोगाराम पटेल (लूणी): डाक्टर साहब, आज आपने काला क्यों पहना है? आप नहीं पहनते, कभी नहीं पहनते।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मुझे आज नन्दलालजी को फेस करना था, इसलिए काला पहना है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे साथ चलेंगे आदिवासी इलाके में। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बजट पर चर्चा शुरू करें।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): सभापति महोदया, बजट भाषण बड़ा लम्बा था और शायद राजस्थान की विधान सभा का ऐतिहासिक लम्बा भाषण छक्का मार था। झालावाड़-झालावाड़ ज्यादा इस बजट में आ रहा था। जो कुछ दिया, वह झालावाड़ को दिया।

यह बजट भाषण का 42 नम्बर का पेज है, उसमें वन एवं पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण में केवल इतना सा लिखा है- 'चूरू जिले में 1 करोड़ 73 लाख रुपये की लागत से नेचर पार्क की स्थापना की घोषणा करती हूं।' बस। राठौड़ साहब, आप चूरू के लिए पैसा ले गये। इतना सा ही वन एवं पर्यावरण मंत्रालय है क्या? सभापति महोदया, 33 प्रतिशत मरु भूमि वन से आच्छादित होनी चाहिए। वन बढ़ने चाहिए, पौधे बढ़ने चाहिए, पर्यावरण की रक्षा होनी चाहिए। इस दृष्टि से मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि आखिर जिसने बजट बनाया है तो कुछ तो इसमें आपको डालना चाहिए था। आज पर्यावरण में जो ओजोन परत के लिए खतरा पैदा हो रहा है, जिसकी चिंता पूरा विश्व कर रहा है और उसमें एक लाइन, डेढ़ लाइन में लिखकर, वन एवं पर्यावरण के बजट के बारे में जो माननीया मुख्य मंत्रीजी बोली हैं, उसमें मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है। माननीय राठौड़ साहब, आप थोड़ी सलाह देते तो यह और भी अच्छा रहता।

(डा. किरोड़ी लाल)

कृषि में क्या है? कृषि में खरीफ और रबी के मौसम में हमारे किसान भाइयों को कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध हो सकें, इसके लिए 28.50 करोड़ रुपये दिये हैं। कृषि सम्बन्धी टेक्नोलोजी के लिए 50 करोड़ रुपये। बस, इतने में किसान का बजट खतम हो गया।

मैं इसलिए, सभापतिजी, कहना चाहता हूं कि यह जो बजट है, यह किसान विरोधी है, यह बजट मजदूर विरोधी है, यह बजट बेरोजगारी को बढ़ाने वाला है, दलित विरोधी है। इस बजट में ऐसी कोई दिशा नहीं दी गई कि भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा। राठौड़ साहब, कोई दिशा नहीं दी गई।

पटवारी जो नीचे के लेवल पर नामान्तकरण में पैसे लेता है, भ्रष्टाचार फैलाता है, या ग्राम पंचायत स्तर पर सेक्रेटरी लेता है, वह कैसे रुकेगा? जब तक आपके नीचे का कर्मचारी सही नहीं होगा, तब तक जनता को रिलीफ मिलने वाली नहीं है। रजिस्ट्री में जो परसेंटेज किसानों से लेते हैं खातेदारी जमीन खरीदते समय, वह कैसे रुकेगा? ट्रांसफार्मर पर जे ईएन स्तर, ए ईएन स्तर पर पैसा लिया जाता है, उस पर अंकुश कैसे लगायेंगे? डोमेस्टिक कनेक्शन हो, चाहे एग्रीकल्चर कनेक्शन हो, ट्रांसफार्मर बिक रहे हैं, सभापति महोदया। पैसा दो और ट्रांसफार्मर लो। बी पी एल धारी तक से रिश्वत ली जा रही है। आशा यह की जाती थी कि 163 का प्रचण्ड बहुमत है, ये एक प्रभावी कार्यवाही भ्रष्टाचार पर करेंगे, लेकिन कोई ऐसा विजन इसमें दिया नहीं गया।

पी डी एस का गेहूं डकार रहे हैं बुरी तरह से। गरीब के पेट तक अन्न कैसे पहुंचे, बी पी एल का गेहूं या पी डी एस का गेहूं गरीब के पेट तक कैसे पहुंचे, यह सुनिश्चित करने की कोई रणनीति बजट में नहीं बताई गई है। सामाजिक क्षेत्र की जितनी भी योजनाएं हैं, उनमें भारी भ्रष्टाचार है।

इसलिए, सभापति महोदया, मैं कंडेम करना चाहता हूं इस बजट को, इस दृष्टि से कि आखिर में भ्रष्टाचार पर अंकुश कैसे लगेगा? देश के प्रधान मंत्रीजी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार-मुक्त भारत हो और जब इतना प्रचण्ड बहुमत आपको दिया है तो यह मंशा सरकार की मेरे को ठीक नहीं लगी, कि क्या सरकार भ्रष्टाचार पर कोई अंकुश लगायेगी?

जहां तक महंगाई का मामला है, सभापति महोदया, आपकी जानकारी में है कि मनमोहन सिंह सरकार ने महंगाई को नियंत्रित करने के लिए एक कमेटी बनाई थी, मोदी कमेटी के नाम से वह कमेटी प्रसिद्ध हुई थी, जिसमें

(डा. किरोड़ी लाल)

पृथ्वीराज चौहान, किरण कुमार रेड्डी और करुणानिधि, ये तीन मेम्बर और थे। इस मोदी कमेटी ने रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में छह सिफारिशें मोदी कमेटी ने की थीं। मैं इसलिए महंगाई की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि महंगाई की दृष्टि से भी बजट में कोई विजन सरकार का दिखाई नहीं दिया। ये छह शर्तें थी, छह कंडिशन जो डाली थीं, जमाखोरी गैर-जमानती जुर्म होगा; बिचौलिया-मुक्त कृषि मार्केट होगा; बजट में कोई ऐसी चीज आई नहीं। स्टोरेज, इन्फ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा; कीमतें स्थिर रखने के लिए एक फण्ड तय करना होगा; आपने ऐसी कोई घोषणा बजट में उपभोक्ता फण्ड के लिए नहीं की। दो चीजें जो इनसे बाहर हैं कि कर्ज का दायरा बढ़े और यह कारोबार पर रोक लगे, यह भारत सरकार का मामला है, लेकिन चार बिन्दु आपसे सम्बन्धित हैं।

इसमें जो महंगाई को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए था या बजट में कोई चीज आनी चाहिए थी, जैसे जमाखोरी एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए जेटलीजी ने कहा, भारत सरकार के वित्त मंत्रीजी ने कहा कि सख्त कदम उठायें; राज्य स्टाक सीमा तय करें; और विशेष अदालत बनायी जायें, स्पेशल कोर्टस, जमाखोरों पर सख्ती करने के लिए, मुनाफाखोरों को और बिचौलियों को खतम करने के लिए, लेकिन कोई ऐसी चीज बजट भाषण में दिखाई नहीं दी। कोई स्पेशल कोर्ट बनाने की घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की हो, या राज्य में कोई स्टाक सीमा तय करने जा रहे हों, या जमाखोरों के खिलाफ हम क्या कार्यवाही करेंगे, ऐसा मन्तव्य इन्होंने कोई जाहिर नहीं किया। मैं कहना चाहूंगा कि महंगाई को नियंत्रित करना, इस सरकार की चिंता होनी चाहिए। इसलिए ऐसे में, माननीय सभापतिजी, महंगाई को रोकने के लिए मूल्य निगरानी और नियंत्रण आयोग सरकार को बनाना चाहिए, उपभोक्ता मामलों का विभाग मजबूत किया जाना चाहिए, इस बजट में ऐसी कोई चीज आई नहीं।

(17.35 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

मूलभूत सुविधाओं के लिए जरूरी वस्तुओं पर कर कम किया जाये, वह भी नहीं किया गया; उपभोक्ता नीति कोई विशेष बननी चाहिए महंगाई पर नियंत्रण करने के लिए, न वह आई; और उपभोक्ता कल्याण कोष सुदृढ़ होना

(डा. किरोड़ी लाल)

चाहिए, इस प्रकार का भी कोई विजन सरकार का नहीं दिखाई दिया। पेट्रोल-डीजल पर वैट तो आप कम कर सकते थे, वैट कम करके महंगाई पर कुछ न कुछ अंकुश लगा सकते थे, लेकिन यह भी करने में विफल रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये सरकार को कहना चाहूंगा, आखिर क्या वजह है, कंज़्यूमर ड्यूरेबल्स यानी मोबाइल, टीवी जैसी वस्तुएं लगातार सस्ती होती जा रही हैं लेकिन रोटी, चावल, दाल की कीमतें आसमान छूती जा रही हैं। हर रोज बाजार में उतर रही नई-नई तकनीकी के कारण मोबाइल, टीवी सस्ते होते जा रहे हैं लेकिन किसान के लिए नई तकनीकी इजहार करने का मन सरकार का कोई है नहीं। नई से नई तकनीकी किसान को दी जाये, जिससे किसान भी समृद्ध हों और यह जो महंगाई आसमान छू रही है, इस महंगाई पर भी नियंत्रण हो। इस ढंग का किसानों के प्रति इस सरकार की तरफ से कोई किसान-हितैषी कहा जा सके, ऐसा मुझे लगता नहीं है।

क्या दिया कृषि के क्षेत्र को? कृषि के क्षेत्र को क्या दिया, कुछ नहीं दिया। मैंने बताया, केवल मात्र 70-80 करोड़ रुपये सरकार ने दिये हैं। मानसून अलग रूठ गया है। सरकार रूठ गई, भगवान रूठ गया। मैं कहना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, किसानों ने बड़े महंगे भावों का बीज अपने घर में डाल लिया, बोने के लिए; थोड़ी बरसात हुई कुछ दिन पहले, वह बो दिया; फसल नष्ट हो गई, फर्टिलाइजर नष्ट हो गया। मैं सरकार से मांग करना चाहूंगा कि जब मौसम ऐसा आ रहा है, सही बरसात हुई नहीं, किसान का महंगा बीज नष्ट हो गया, किसान के लिए फर्टिलाइजर नहीं मिल रहा, मैं सरकार से मांग करूंगा कि ऐसी परिस्थितियों में, जहां अकाल की स्थिति बनने वाली है और सोइंग समय पर नहीं हुई, क्या सरकार, किसानों का बीज है, अब आगे किसान बुवाई करेगा तो क्या किसानों को मुफ्त बीज सरकार देगी? क्या फर्टिलाइजर देगी? क्या के सी सी के लोन माफ करेगी? जो महंगी बिजली दी जा रही है, उसको कुछ सस्ता करेंगे? आपदा कोष की राशि को बढ़ाकर क्या किसानों को कोई विशेष सहायता देंगे?

राठौड़ साहब, आप तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में मेडिकल कालेज ले आये, काफी पैसा ले आये। मैं प्रभूजी से भी कहना चाहूंगा, प्रभूजी, आप भी जायें, किसानों के लिए कुछ स्पेशल असिस्टेंस केन्द्र सरकार से लेकर आयें! किसानों की यह माली हालत होती जा रही है, सभापति महोदय, किसानों की आत्महत्या का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। वे आत्महत्या को मजबूर होते जा रहे

(डा. किरोड़ी लाल)

हैं और पलायन की स्थिति राजस्थान के कई गांवों में पैदा हो गई है। अकाल की भयावह स्थिति आने वाली है। सरकार में... (व्यवधान) आज बरसात हुई है, वह भी जयपुर में हुई है; मेरे उधर तो हुई नहीं है, मैंने पूछ लिया। (व्यवधान) आज सब जगह हो गई, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन बुवाई पहले कर दी, जिनका बीज चला गया, उनको तो कुछ पैसा दे दो। माना, एक बरसात से काम चलने वाला नहीं है, सभापतिजी, जैसा कृषि मंत्रीजी कह रहे हैं। (व्यवधान) वे भविष्यवक्ता हैं, चार महीने होगी बरसात। लेकिन इसमें यह है कि भीषण अकाल पड़ गया, सभी जिलों में बरसात नहीं हुई, तो अकाल की दृष्टि से बजट में जो प्रावधान होने चाहिए थे, चारा डिपो कितने खुलेंगे, चारे की व्यवस्था कैसे होगी, पेयजल का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, पानी कैसे उपलब्ध कराया जायेगा, पशुओं को मरने से कैसे रोका जायेगा, किसी प्रकार का कोई नया आइडिया सरकार की तरफ से बजट में नहीं रखा गया है।

सभापति महोदय, पिछली सरकार ने भी और जब मैं सरकार में मंत्री था, हमारी पूर्ववर्ती सरकार में मैं मंत्री था, तब भी सरकार ने कहा था कि हम एस टी, एस सी, ओ बी सी, एस बी सी के भले के लिए, विशेषकर एस टी, एस सी के लिए जो बैकलाग है, कम से कम 70,000 पोस्ट हैं, उनको हम भरेंगे। बड़ी ताज्जुब की बात है, सभापति महोदय, इस बजट में एस सी, एस टी का बैकलाग भरने का जिक्र तक नहीं है। मैं आपके द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप अगर एस टी, एस सी के हितैषी हों...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): डाक्टर साहब, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, जब आप मंत्री थे तो आप याद करो, एक बार पूरा बैकलाग खतम किया था वसुंधराजी ने और आप ही ने सबसे पहले साधुवाद दिया था कि पहली बार बैकलाग खतम हुआ है। 22 हजार से ज्यादा पद थे बैकलाग के उस समय।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उदयपुर सम्भाग में जितनी भर्तियां वसुंधराजी की सरकार में हुई, उतनी कभी नहीं हुई। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): बहुत अच्छी बात है। मैं तो खुद ही इस बात को कह रहा हूं। लेकिन अब आखिर में आपने जो 15 लाख नियुक्ति दी हैं, आजीविका मिशन एक कागजी घोड़ा है और यह कहा है कि 15 लाख, 3 लाख प्रतिवर्ष के हिसाब से नियुक्ति देंगे, मेरे को यह बता दो, सरकार का कोई मंत्री खड़ा होकर के, कि सरकारी नौकरी कितनी दोगे? बता दो। एक भी नहीं, सरकारी नौकरी। 15 लाख सरकारी नौकरी दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): हम राजस्थान को स्वावलम्बन की तरफ लेकर जाएंगे। राजस्थान का नौजवान सरकार की तरफ नहीं देखेगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा। इस प्रकार का विजन दिया है हमारी मुख्य मंत्रीजी ने।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): मेनिफेस्टो में, घोषणा पत्र में चुनाव से पहले कह दिया कि हम 15 लाख सरकारी नौकरी देंगे और अब राठौड़ साहब कह रहे हैं, अपने पैरों पर खड़े रहने वाली नौकरी हम देंगे। क्या आप मुकर गए? आप बेरोज़गारों को रोजगार देने से मुकर गए? आप दलित और एस सी, एस टी का जो बैकलाग, उसको भरने की बात से मुकर गए?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): माननीय मीणा साहब, मैं निवेदन करूं कि आप भी सरकार के पार्ट रहे हुए हैं और 15 लाख सरकारी और अर्द्ध-सरकारी नौकरियां देने की घोषणा की है तो इन पांच सालों में हम देंगे।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): 15 लाख सरकारी नौकरियां?

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण): सरकारी और अर्द्ध-सरकारी।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): राठौड़ साहब, सम्भाल लो, वे मंत्री बनने वाले हैं। (व्यवधान) सभापति महोदय, दोनों ही सरकार, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बी जे पी की सरकार हो, भाई नंदलालजी चले गये दिखते हैं, साढ़े 8 परसेंट महाराष्ट्र पैटर्न पर ट्राइबल एरिया को बजट देंगे, क्या साढ़े 8 परसेंट बजट ट्राइबल एरिया को मिल रहा है? टोटल बजट का साढ़े 8 परसेंट बजट ट्राइबल एरिया को मिले, यह घोषणा सरकार की है, घोषणा पत्र में है और साढ़े 8 रुपये का भी बजट इस ट्राइबल एरिया के लिए नहीं दिया गया। बेवकूफ बनाना, गुमराह करना और यह इस ढंग से मैं कह सकता हूं कि हमारा तो एरिया छोड़ दिया, पूरा एरिया छोड़ दिया पूर्वी राजस्थान का लेकिन दक्षिण राजस्थान का जो भूख के कगार पर खड़ा आदिवासी है, उसके लिए आपने क्या दिया? आपने साढ़े 8 परसेंट महाराष्ट्र पैटर्न का यहां पर पारित कर लिया और कह दिया हम महाराष्ट्र पैटर्न पर बजट देंगे, लेकिन उसके लिए एक पाई नहीं।

श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सदस्य, आपके बीच में मैं बोलना नहीं चाहूंगा, आपने भूख के नाम पर पूरे उदयपुर सम्भाग में इतना गुमराह करने का प्रयास किया और आपने इतने हेलिकाप्टर उड़ाएं, लेकिन शायद एक भी जन-प्रतिनिधि आपके साथ में नहीं जुड़ पाया। माननीय, आप बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता हूं। धन्यवाद।

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): अगर मैं हेलिकाप्टर नहीं उड़ाता तो आप जीत कर के नहीं आते।

इसी हिसाब से, सभापतिजी, टाडा और माडा के बजट में भी किसी प्रकार की कोई बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की है। बल्कि पूर्ववर्ती सरकार ने, मैं ज्यादा बड़ाई तो नहीं करना चाहूंगा, पूर्ववर्ती सरकार ने जितनी नौकरियां घोषित की थीं, वे सारी की सारी लटका दीं, समीक्षा के नाम पर। अब यह समीक्षा कब तक करेंगे? विद्यार्थी मित्र तो सड़कों पर रो ही रहे हैं। हर डिपार्टमेंट में जितनी भी रिक्तियां पूर्ववर्ती सरकार में जारी की थीं, मैं, राठौड़ साहब, आपसे पूछना चाहूंगा, आप ही बैठे हो आगे तो, और कोई मंत्री हैं नहीं, प्रभूजी हैं वे तो चर्चा में मशगूल हैं, इनको कब तक नौकरी दे दोगे?

सभापति महोदय, एक पूर्व सरकार ने प्रावधान किया था, मेरे आदिवासी इलाके के विधायक इस पर गम्भीरता से विचार करेंगे कि वहां हण्ड्रेड परसेंट आरक्षण कर दिया? कर दिया ना? आरक्षण पापुलेशन के आधार पर है ना? आपके इलाके में 90 परसेंट एस टी हैं, आपको 50 परसेंट आरक्षण मिलेगा। बाकी का 50 कौन खाएगा? राठौड़ साहब, यह प्रावधान कितना इल्लीगल है, इतना असंवैधानिक है। इसलिए मैं, सभापतिजी, आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार का मंतव्य केवल कोरे ढोल पीट कर एस सी/एस टी हितैषी बनना है और वास्तव में एस सी/एस टी की हितैषी यह सरकार है नहीं।

जहां तक शिक्षा का मामला है, शिक्षा का मामला, समानीकरण और यह पहले चलते आये हैं, पहले भी सरकार में हुए हैं लेकिन, सभापति महोदय, मैं तो मेरे दौसा जिले की बात कह सकता हूं, टीचरों की अधिकतर स्कूल में, राठौड़ साहब, वैकेंसी बहुत है। इसको मजाक का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। जो बच्चा गणित ले रखा है, जिसने फिजिक्स ले रखी है, जिसने केमिस्ट्री ले रखी है, उसको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। यह तो उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसलिए, सभापति महोदय, आपके जरिये सरकार से आग्रह करना चाहूंगा, बल्कि दुराग्रह करना चाहूंगा कि जितने भी स्कूलों में वैकेंसीज हैं चाहे सेकण्डरी हों, चाहे सीनियर सेकण्डरी हों, चाहे यू पी एस हैं, आप उनको तुरन्त भरें। इसमें बजट में इस ढंग का कोई इंडिकेशन मुख्य मंत्रीजी की तरफ से नहीं दिया गया।

पढ़ाई का स्तर तो बहुत बिगड़ा हुआ है। आप कोई गांव में, किसी स्कूल में जाकर के पूछें कि प्रदेश के राज्यपाल कौन हैं, तो उसका नहीं बता सकते। जी.के. तो कमजोर है ही, पर पढ़ाई वहां के गांव के बच्चे के साथ जिस

(डा. किरोड़ी लाल)

ढंग का घात, दगा, धोखा सरकार की एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है, यह सहन, बरदाश्त करने लायक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपके जरिये सरकार से आग्रह करूंगा कि शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार तो आपने दे दिया, आठवीं तक किसी को फेल नहीं करेंगे, चाहे वह कापी को खाली छोड़ दें, चाहे वह एक दिन पढ़ने नहीं आये। हमारे गांव के बच्चों की नींव कमजोर करने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। इसलिए मैं आपके जरिये सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी नींव, गांव के बच्चों की, मजबूत हो, उसके प्रयास किये जाने चाहिए और शिक्षा का स्तर बढ़ाना चाहिए।

जहां तक बिजली कम्पनियों का मामला है, बिजली कम्पनी, रोडवेज का निजीकरण होने जा रहा है। प्रदेश की बिजली वितरण कम्पनियों के निजीकरण के विरोध में सारे इंजीनियर्स, मिनिस्ट्रीयल स्टाफ प्रदर्शन करने जा रहे हैं, 31 तारीख को, जो मेरे को पता है, और इसी ढंग से रोडवेज में है। रोडवेज में जितने स्वयंसेवी संगठन हैं, वे सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हैं, किसलिए, कि कान्ट्रेक्ट लैबर एक्ट, फैक्टरीज एक्ट और कम्पनीज एक्ट में जो प्रावधान बजट में डाले गये हैं, वे पूरी तरह से, मंत्रीजी, श्रमिक विरोधी हैं। किसानों को तो खा ही गये ये, मजदूरों को और निकलना चाहते हैं यह एक्ट लाकर के। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो बजट है, वह पूरी तरह से मजदूर विरोधी है।

अब पी पी पी मोड, आप पी पी पी माडल पर सड़क बनाओगे और आपने कोई सड़क ऐसी बना दी जहां आवाजाही लोगों की कम है, तो क्या कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगाने वाला आदमी आ जाएगा आपके पास में? मेरे को लगता नहीं है, कोई आ जाए। अगर आ भी गया तो कब बना पाएगा, और बना पाएगा तो रिकवरी कैसे होगी? मेरे को जो पता लग रहा है, ऐसे पी पी पी माडल पर सड़क बनाकर के करीबन 1 हजार टोल राजस्थान में लगाएंगे। एक हजार टोल! अभी 10-15 टोलों ने ही राजस्थान की जनता को लूट खाया है, एक हजार टोल लगाकर राजस्थान की जनता को लुटवाने का काम इस बजट में मुख्य मंत्रीजी ने किया है। मैं इसका जबरदस्त विरोध करता हूं। आप हर सड़क पी पी पी मोड पर दोगे तो हर गांव, छोटी ढाणी का आदमी भी, पहले उसकी जेब को खाली करवाएगा टोल टैक्स वाला, जब वहां से निकलेगा। आखिर सरकार क्या कर रही है? सरकार क्यों राजस्थान की जनता को लुटवाने पर आतुर है?

(डा. किरोड़ी लाल)

रोजगार, रोजगार का मैंने बता ही दिया। एक तो मंत्री बनने वाले हैं, वे यह कह रहे हैं कि हम 15 लाख सरकारी नौकरी दे देंगे, पर लगता नहीं है कि पचास हजार भी सरकारी रोजगार दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय, हमारा इलाका, विशेषकर पूर्वी राजस्थान के हमारे जसवंत सिंहजी भी वहीं से हैं, अलवर, धौलपुर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, पीने के पानी की भीषण समस्या है। सिंचाई की तो फिर है ही। लेकिन मैं सरकार से, वसुंधराजी ने जो अपना बजट भाषण दिया है, उसमें कई जगह अच्छे सिंचाई के प्रोजेक्ट दिये हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि हमारी चंबल नदी बारह माह बहने वाली एक नदी है, कोटा की डाउनस्ट्रीम से लेकर धौलपुर तक जिसका पानी बह कर बेकार चला जाता है, करीबन डेढ़ सौ-दो सौ किलोमीटर, और बरसात में तो बेजा पानी जाता है; मैं सरकार से मांग करता हूं कि जैसे आप और जगह नदियों को जोड़ रहे हैं, जैसे आप बीसलपुर में पानी ला रहे हैं ब्रह्माणी नदी का, क्या चम्बल के पानी को लिफ्ट करके...?

सभापति महोदय, एक ईसरदा का डैम बना था, आपकी जानकारी में होगा, ईसरदा का डैम इसलिए बना था कि यहां जयपुर में पीने के पानी का क्राइसिस हो गया था, तो जयपुर में पानी कहां से लाया जाए, तो बनास नदी पर एक ईसरदा का डैम बनाया जाए और वहां से उस पानी को लाया जाए, यह विचार बना लेकिन बीसलपुर की क्षमता बढ़ा कर बीसलपुर से जयपुर को पानी ले आये। अब वह कोफर डैम ज्यों का त्यों बना हुआ है। हमारे माननीय सदस्य इधर बैठे हुए हैं दौसा वाले भी हैं, महुआ वाले भी हैं, हम सब बराबर मांग करते आये हैं कि कोफर डैम जो ईसरदा का बना हुआ है, उसका पानी दौसा को दे दो, सवाई माधोपुर को दे दो, पर्याप्त पानी है और पानी कम पड़ता है तो आप जो मेज नदी है, मेज नदी के पानी को उसमें डाल दो, जो बूंदी के पास है। पर्याप्त पानी वहां तक ही नहीं, उस पानी को आप दौसा में भी दे सकते हैं, सवाई माधोपुर में भी दे सकते हैं, आगे करौली भी ले जा सकते हैं।

हमने तो एक बार पढ़ा था, पिछली सरकार के बजट भाषण में यह घोषणा की गयी थी कि पांच सौ करोड़ रुपये इस बात के दिये गये हैं कि मेज नदी का पानी रामगढ़ बन्धे में लाकर डालेंगे; जो बरसाती पानी बह कर बेकार

(डा. किरोड़ी लाल)

चला जाता है, उस जमुआरामगढ़ बन्धे को, रिजरवायर को पूरा भरेंगे। अगर ऐसा हो जाए तो भरतपुर तक को, अलवर तक को पानी दिया जा सकता है। रामगढ़ बन्धे का पानी बिलकुल जो बाणगंगा जा रही है, वहां तक पानी को डाला जाए, ढूंढ नदी में डाला जाए, ढूंढ से मोरल में डाला जाए, मोरल से बनास में डाला जाए, बनास से चम्बल को लिंक करके, इन चारों-पांचों जिलों को, जो पानी के लिए मोहताज हैं, इन पांचों-चारों जिलों को पानी दिया जा सकता है, लेकिन, सभापति महोदय, किसी प्रकार से पूर्वी राजस्थान की चिन्ता सरकार ने की नहीं।

श्री बाबूलाल वर्मा (केशोरायपाटन): बूंदी जिले को खाली रखोगे क्या? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल (लालसोट): आपने ध्यान से नहीं सुना होगा, बाबूलालजी, मैंने यह नहीं कहा, मैंने यह कहा कि बरसाती पानी, जो बह कर एक्स्ट्रा, बेकार चला जाता है, उसको रिजरवायर में। आप यह वसुन्धरा जी को कह देना, ताकि मंत्री बन जाओगे। मैं मेरे इलाके की समस्या उठा रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि जो पानी बरसात का बह कर बेकार जा रहा है, कोफर डैम आपका बना पड़ा है, तो क्या कोफर डैम से सरकार बजट भाषण, में आपके जरिये मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि बजट भाषण में कम से कम मुख्य मंत्रीजी इस बात की चर्चा जरूर करें कि कोफर डैम, जो ईसरदा का, करोड़ों रुपये खर्च करके बनाया गया है, सभापति महोदय, उसका पानी कम से कम सवाई माधोपुर और दौसा जिले को दिया जाना टैक्निकली फीजिबल है। उसमें कुछ प्रावधान एप्रोप्रिएशन बिल में आप, राठौड़ साहब, करायें जिससे दौसा को भी पानी मिल जाए और महुआ को भी मिल जाए; अलवर के राजगढ़ तक चला जाए और धौलपुर तक चला जाए, करौली तक चला जाए। मैं ऐसी प्रार्थना आपको यहां करना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मेरे को पता है ...(व्यवधान) नहीं, मैं तो दूसरी बात, इसमें एक बात और आगे बढ़ाना चाहता हूं, सिंघल साहब। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि अगर सरकार चाहे तो क्या सम्भव नहीं है। अगर विल-पावर हो और सरकार चाहे तो यमुना का पानी, जो हर बार यमुना में बाढ़ आती है, दिल्ली में; दिल्ली बहा, दिल्ली में पानी आ गया; उस यमुना के पानी को, धारूहेड़ा तक तो डैम है ही, धारूहेड़ा तक उस पानी को लाया जाए और

(डा. किरोड़ी लाल)

धारूहेड़ा से उस पानी को लाकर अगर जमुआरामगढ़ बन्धे में डाला जाए, जो सम्भव है, बरसात का पानी, अगर जमुआरामगढ़ बन्धे में डाला जाए, तो सभापति महोदय, आपका इलाका शाहपुरा भी, कोटपूतली भी और वहां सोनी नदी, रूपारेल नदी तक इस पानी का जगह-जगह एनिकट बना कर डाल दिया जाए, तो आपका इलाका जयपुर ग्रामीण उससे सिंचित भी हो सकता है। पीने का पानी ही नहीं, सिंचित भी हो सकता है।

इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि यमुना को लिंक करें जमुआरामगढ़ बन्धे से, मेज नदी को लिंक करें अपने जमुआरामगढ़ बन्धे से और मेज नदी का पानी, जमुआरामगढ़ बन्धे का पानी पहले जाया करता था भरतपुर तक। बीच में पड़ने वाले जयपुर ग्रामीण का इलाका, बीच में पड़ने वाले दौसा का इलाका, बीच में पड़ने वाले अलवर और भरतपुर के इलाके में भी इससे पीने के पानी की समस्या का ही समाधान नहीं होगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा और अगर यमुना का पानी ले आएं तो आपका जयपुर ग्रामीण, झुंझुनूं, चूरू तक की समस्या का समाधान इसमें हो सकेगा।

मैं, सभापति महोदय, इतनी ही बात कह कर आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। आपका हाथ घंटी की तरफ जा रहा है, घंटी से पहले ही मैं बैठना चाहता हूं और आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे को बोलने का मौका दिया। राठौड़ साहब से मैं यह प्रार्थना करूंगा कि हमारे कम से कम ईसरदा डैम का पानी तो दौसा जिले को, बजट में जरूर वसुन्धराजी से घोषित करा देंगे तो हम सारे जन-प्रतिनिधि आपका बड़ा धन्यवाद देंगे और बड़ी सभा आपकी दौसा में करायेंगे। धन्यवाद। राम-राम सा।

श्री सभापति: श्री बंशीधरजी खंडेला।

श्री बंशीधर (खण्डेला): आदरणीय सभापति महोदय, राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी द्वारा परिवर्तित बजट 2014-15 14 जुलाई को प्रस्तुत किया गया, उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा।

इस बजट से और पिछली सरकार के कार्यकाल के कार्यक्रमों से, कार्यकलापों से साफ दिखता है कि अच्छा प्रबन्धक और कुप्रबन्धक, दोनों ही इसमें झलकते हैं। जो प्रदेश में संसाधन हैं, वे पहले भी थे, आज भी हैं, आगे भी रहेंगे, कुछ कम-ज्यादा हो सकते हैं लेकिन नीति निर्धारण के कारण कुछ होते हुए भी अपन कुछ नहीं कर सकते और अच्छी नीति निर्धारण होने के

(श्री बंशीधर)

कारण अच्छा प्रशासक होने के कारण, अपन सब कुछ कर सकते हैं। पहले की सरकार में कुप्रबंधक के कारण आज यह स्थिति दिख रही है कि जो कुछ चुन कर आये हुए हैं, वे भी इस हिम्मत में नहीं हैं कि हम बजट पर बहस सत्ता पक्ष की सुन सकें। नहीं सुन सकेंगे। इसका मतलब, जो चुन कर आयें, उनमें भी एकता नहीं है; जो उनके लीडर हैं उनमें यह क्षमता नहीं है कि अपने सारे एम एल एज को बैठायें यहां पर।

मैं इस सम्बन्ध में आगे कहना चाहूंगा कि 2003-04 में, जब कांग्रेस सरकार गई थी, उस टाइम अतिरिक्त कर्ज पर केवल 42 प्रतिशत पूंजीगत व्यय था, जिसको बढ़ा कर, 2007-08 तक हमारी सरकार ने बढ़ाया और 109 प्रतिशत बढ़ाया। इसी को तो एक अच्छा प्रबंधक कहते हैं। जो जी एस डी पी दर हमारी सरकार 3.4 प्रतिशत छोड़ कर गयी थी, वह कांग्रेस सरकार के पिछले टाइम पर अब 2.95 प्रतिशत रह गयी है। ये सारी चीजें एक प्रबंधक के काम में आती हैं।

पिछली सरकार के टाइम में सड़क के बारे में बात करना चाहूंगा। हमारी जो सरकार थी, 2008 में, तब सड़कों की तुलना गुजरात से हुआ करती थी, लेकिन अब पिछली सरकार के समय मध्य प्रदेश की खराब सड़कों से राजस्थान की तुलना होने लगी और मध्य प्रदेश ने भी पिछले समय में यहां तक कह दिया था कि मैं राजस्थान में रोडवेज नहीं भेजूंगा क्योंकि वहां रखरखाव का खर्चा ज्यादा आता है। यानी कि मध्य प्रदेश से भी बहुत ज्यादा खराब सड़कें हमारी रह गई थीं। यह एक प्रबंधक की ही देन है कि वह कैसा सही काम करता है, कैसा गलत काम करता है।

इस साल इस बजट में पांच हजार किलोमीटर ओ डी आर, धार्मिक सड़कों, बीस हजार किलोमीटर तक पी पी पी मोड पर बनाने का जो फैसला किया है, वह हर जनता को, हर राहगीर को एक अच्छा रास्ता देने की एक अच्छी शुरुआत की गई है। सात हजार किलोमीटर, जो डी पी आर बनाया जा रहा है, जो बनेंगी आने वाले समय में, पन्द्रह किलोमीटर प्रति दिन प्रदेश में सड़कें बनेंगी। वह एक अच्छी शुरुआत है। 9,000, यानी, हर ग्राम पंचायत में एक अच्छे विजन के कारण, आदरणीया वसुन्धराजी का अच्छा विजन रहा कि शहर की तरह गांवों में भी अच्छा विकास हो और गांवों के अन्दर आधा किलोमीटर से लेकर दो किलोमीटर तक आर सी सी सड़कें बनायी जाएं और

(श्री बंशीधर)

उनके साथ-साथ नालियां भी बनाई जाएं जिससे कि गांव एक शहर की दृष्टि से दिखे और पलायन रुक सके। यह ऐसा आने वाले समय में, पांच साल में करने का हमारी सरकार का यह विजन है। पी एम जी एस वाई रोड, साठ साल से कांग्रेस ने बहुत सारा राज किया, आदरणीय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, अटलबिहारी वाजपेयीजी की एक छोटी सी सोच के कारण आज गांव-गांव, ढाणी -ढाणी और पहाड़ों में, जंगल में सड़कें बनी हुई हैं। वह सोच थी केवल पेट्रोल, डीजल पर छोटा सा सैस लगाया था। आज वह सैस इतना बड़ा हो गया है कि आज हर ढाणी-ढाणी पी एम जी एस वाई सड़क बन रही है। एक सोच का फर्क है। पहले कांग्रेस के पास यह सोच नहीं थी। इसी को तो एक अच्छा प्रबंधक कहते हैं।

(18.00 बजे)

मैं इस बारे में एक बात और कहना चाहूंगा। रोडवेज के अन्दर, घाटे में चल रही है, फिर भी बस में बैठने वाले ज्यादातर अपने ही यात्री, अपने ही प्रदेश के आदमी हैं। उनको बस का इंतजार करने के लिए बस स्टैण्ड अच्छा होना चाहिए, उसके लिए आदरणीया वसुन्धराजी ने 80 नये बस स्टैण्ड बनाए जाने की घोषणा की है। उनके अन्दर अच्छे रेस्टोरेंट होंगे, अच्छे विश्राम गृह होंगे और अच्छी सुविधाओं वाले काम्प्लेक्स होंगे, जिससे आने वाले आदमी देखेंगे तो राजस्थान एक अलग तरह से दिखेगा।

राजस्थान में राजस्थान स्टेट बस पोर्ट सर्विसेज कारपोरेशन (आर एस बी एस सी) का गठन किया गया है। यह एक पहली अनूठी शुरुआत है। इससे प्राइवेट बसें और रोडवेज की बसें एक जगह संचालित होंगी। दूरदराज नहीं जाने के, इस गठन के लिए 360 करोड़ का जो प्रावधान किया है, वह एक सराहनीय प्रावधान है।

इसी परिवहन के ऊपर, आदरणीया वसुन्धराजी ने प्रदेश को हवाई जहाज की सेवाएं देने के लिए 16 नई पटिट्यां बनाने की घोषणा की है। उसके पीछे एक लोजिक है कि हमारा राजस्थान पर्यटक से जुड़ा हुआ है। पर्यटक एक ऐसी पूंजी है जिससे प्रदेश में हर आदमी को, हर दुकानदार को, ट्रांसपोर्टर को इन्कम होती है। उसे बढ़ावा मिलेगा तो देश में और प्रदेश में संसाधनों से आय होगी। दुनियां में कई देश तो ऐसे हैं जिनकी आर्थिक हालात केवल उसी से चलती है कि वहां अच्छे पर्यटक स्थल हैं। उनको अच्छी तरह विकसित करते

(श्री बंशीधर)

हैं, वहां पर्यटक जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं। उसी तर्ज पर यहां राजस्थान में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए 16 हवाई पट्टी बनाने की घोषणा की है। एक एम ओ यू भी बनाया जा रहा है, जिसके अन्दर धार्मिक स्थान या बड़े-बड़े, जैसलमेर जाने के लिए कोई पर्यटक आता है तो वहां कोई हवाई अड्डा नहीं है, वहां जाने के लिए जोधपुर जाना पड़ता है, वह बहुत खर्चीला पड़ता है। यह सोचकर आदरणीया वसुन्धराजी ने किया है।

हमारे बिजली तंत्र पर मैं बात करना चाहूंगा। हमारी सरकार छोड़कर गई थी, तब मात्र 15 हजार करोड़ का घाटा था। पिछले कई सालों से, जब से बिजली बोर्ड का गठन हुआ, तब से लेकर 15 हजार करोड़ का घाटा था। 5 साल में कांग्रेस सरकार के कुप्रबंधन के कारण 15 हजार करोड़ रुपये से चार गुणा, यानी 60 हजार करोड़ रुपये अतिरिक्त खर्च हो गया। आज 75 हजार करोड़ रुपये का घाटा विद्युत बोर्ड पर है। इसी के कारण, आज हमें प्रति वर्ष 10 हजार करोड़ रुपये ब्याज के देने पड़ते हैं। जो बिजली खपत होती है, उसकी प्रति यूनिट के हिसाब से देखें तो 1.80 पैसा पर-यूनिट हमारा खर्चा आ रहा है।

बिजली के बारे में, कृषि कनेक्शन के ऊपर हम बात करें, 2012-13 तक 3 लाख 11 हजार कृषि कनेक्शन बाकी थे। बहुत लम्बे समय से काश्तकार यह सोचता आ रहा है कि मेरे कब कृषि कनेक्शन होगा, लेकिन अब इसी साल में 40 हजार कनेक्शन सरकार किसानों को देगी। यह एक अच्छी शुरुआत है। जिस किसान को ज्यादा जल्दी है, बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति से भी काम करना चाहेगा, कनेक्शन लेना चाहेगा, उसको आन-डिमाण्ड कनेक्शन मिलेगा।

वर्ष 2014-15 के इस बजट में जो घोषणा हुई है, 400 के वी के 3 स्टेशन, 220 के 9 स्टेशन तथा 132 के वी के 11 नये ग्रिड सब-स्टेशन बनाये जा रहे हैं। वह एक अच्छी शुरुआत है। 33 के वी के 220 सब-स्टेशन बनाये जाएंगे। इससे बिजली की गुणवत्ता बढ़ेगी, अच्छी रहेगी; बिजली का पूरा वोल्टेज आएगा, छीजत में कमी आएगी। यह बिजली के लिए बहुत अच्छी शुरुआत है।

मैं सोलर ऊर्जा के हिसाब से बात करना चाहूंगा, 25 हजार मेगावाट क्षमता का 5 वर्षों में सोलर ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। यह एक ग्रीन ऊर्जा मिलेगी। इससे कोई पोल्यूशन नहीं होगा। एक बार खर्चा होने के बाद, हमेशा कोई खर्चा नहीं लगेगा। एक अच्छी शुरुआत है। सोलर ऊर्जा प्लांट संयुक्त क्षेत्र में स्थापित किये जाएंगे। संयुक्त क्षेत्र के अन्दर 26 प्रतिशत

(श्री बंशीधर)

सरकार भूमि देगी और 26 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होगा। यह बहुत अच्छी शुरुआत है। गांव और ढाणियों में जहां बिजली के पाइंट पहुंचने का कोई सपना नहीं है क्योंकि वहां बिजली भेजने के लिए प्रसारण तंत्र में बहुत ज्यादा खर्चा आता है, उस खर्चे को ध्यान में रखते हुए, खर्चा नहीं करना पड़े और गांव व ढाणियों में बिजली पहुंच जाए, इसके लिए सोलर ग्रिड बनाया जा रहा है। उसके अन्दर जगह-जगह सोलर पार्क बनाकर, जहां दूरदराज बिजली नहीं पहुंच सकती, वहां उनको बिजली देने के लिए अच्छी शुरुआत की जा रही है। इसके लिए 100 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह बहुत ही अच्छी बात है।

गांव और ढाणी के हिसाब से मैं एक बात और कहना चाहूंगा। पंचायतों को पानी की व्यवस्था के लिए जो उनके पास संसाधन हैं, वे संसाधन बहुत कम हैं। उन संसाधनों को ठीक करके वापस पंचायतों के सुपुर्द किया जाएगा। इससे आने वाले समय में, सही संसाधन होने के बाद में, जो पंचायतों को टी एफ सी और एस एफ सी का अनुदान मिलता है, उसमें निश्चित प्रतिशत पेयजल के लिए किया जाएगा जिससे वे संसाधन आराम से चलते रहेंगे, गांवों को अच्छा पानी मिलेगा।

गांव में शुद्ध पानी मिलने के लिए आर ओ स्थापित किये जाएंगे। गांवों में आजकल फ्लोराइड बहुत ज्यादा है और फ्लोराइडयुक्त पानी पीने से आदमी ठीक नहीं रहता। फ्लोराइड को निकालकर अच्छा पानी देना हमारी सरकार का कर्तव्य है। इसलिए एक हजार आर ओ योजना, आने वाले पांच वर्षों में है, यह बहुत अच्छी योजना है। आर ओ का पानी, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी शुद्ध पानी पहुंचेगा तो शहर की तरफ पलायन की कोई सोचेगा भी नहीं।

राजस्थान में ड्रिंकिंग वाटर ग्रिड स्थापित करने के लिए एक अनूठी योजना चालू की गई है। यह पहली योजना है, यह बहुत अच्छी है। गुजरात की तर्ज पर नदियों को जोड़ने के लिए, पीने के पानी के लिए और कृषि कार्य के लिए जो योजना चालू की जा रही है, वह राजस्थान के लिए अच्छी शुरुआत है। इससे जहां–जहां डैम बनेंगे, वहां-वहां पानी का रिचार्ज भी हो जाएगा। आसपास के गांवों और ढाणियों के पीने के लिए और कृषि के लिए अच्छा रहेगा।

राजस्थान में लघु सिंचाई के लिए बहुत अच्छी परियोजना बनाई जा रही है। इस परियोजना में 2015 में 33 हजार हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई क्षेत्र का लाभ मिलेगा। इससे किसानों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। आई जी एन पी, इंदिरा गांधी नहर, द्वितीय चरण में 6 लिफ्ट परियोजनाओं को लगाकर 3 लाख

(श्री बंशीधर)

हैक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई के लिए पानी दिया जाएगा। पानी की बचत के लिए फव्वारा और ड्रिप पद्धति से प्राथमिकता दी जाएगी। इससे पानी भी बचेगा और किसानों की अच्छी फसल भी पैदा होगी।

आई जी एन पी के साथ- साथ 476 किलोमीटर की जो सड़कें बनी हुई है और आज नकारा घोषित हुई हैं काम में नहीं आ रही हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए और नहर के लिए ये सड़कें की जाएंगी। यह चरणबद्ध सड़कें पी डब्ल्यू डी को देकर, सही करके, गांव-वासियों को, वहां आसपास रहने वालों के लिए बहुत अच्छी शुरुआत की जा रही है।

जयपुर में मेट्रो की कोई जरूरत नहीं थी, पहले सर्वे कराया गया था तो जयपुर में मेट्रो 2025 में सक्सेज होती लेकिन बड़े शर्म की बात है, कुप्रबंधन के कारण जो रेल, जो डिब्बे 2019 तक काम आएंगे, वे आज ही परचेज कर लिये गये। तो इसमें तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा घपला हुआ है परचेजिंग में। तब यह इतना जल्दी किया गया है। वह भी लोन लेकर काम किया है। सोचने की शक्ति कांग्रेस के जो मुखिया थे, उनमें खतम हो गई थी। तभी तो आज से पांच साल बाद काम आनी चीज आज ही खरीद कर रख लेते हैं। तो यह तो बहुत ही घटिया किस्म की सोच है।

कृषि क्षेत्र में किसानों को सोलर ऊर्जा के लिए सोलर सेट दिये जा रहे हैं। मैं सरकार से एक बात जरूर कहूंगा कि इसके अन्दर 30 प्रतिशत केन्द्र सरकार देती है और पहले राज्य सरकार इनको 56 प्रतिशत देती थी, उसको घटाकर 30 प्रतिशत किया। यह किसानों के विरुद्ध काम हुआ है। मैं आदरणीया वसुंधराजी से सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, इसको 56 रखा जाए। इससे बिजली की बचत होगी, काश्तकार को सुविधा भी होगी।

राजस्थान में राज्य भण्डारण निगम द्वारा 3 लाख 10 हजार मैट्रिक टन भण्डारण की क्षमता के गोदामों के लिए 150 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। यह बहुत अच्छा है। जो काश्तकार पैदा करता है, पसीने से अपना धन पैदा करता है, अनाज पैदा करता है वह बरसात में भीग कर सड़ जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

दो मिनट और लूंगा, साहब। बारिश में यह सबके लिए दु:खदायी चीज है, जो देश का नुकसान होता है।

(श्री बंशीधर)

चिकित्सा के लिए डाक्टर्स की बहुत कमी है। पांच मेडिकल कालेज खोले गये हैं, सात मेडिकल कालेज खोले गये हैं, इनमें 700 सीट्स आएंगी। केन्द्र सरकार राजस्थान को एक मेडिकल कालेज और दे रहा है। मैं आदरणीया वसुन्धराजी से, सरकार से यह निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर के अन्दर एक इतनी बड़ी जमीन हमारी टी.बी. हास्पिटल के नाम से फेमस है, सौ बीघा जमीन सीकर में है और उसमें 40 कमरे बने हुए हैं। इन संसाधनों को देखते हुए, सरकार का पैसा कम लगेगा, वह मेडिकल कालेज हमारे सीकर को दें। यह सौगात मिलेगी हमें, मैं ऐसी आशा करता हूं।

एक अनूठा काम और हुआ है। जिप्सम की खुदाई आज तक सरकारी उपक्रम ही करते थे लेकिन आदरणीया वसुन्धराजी ने काश्तकारों को ध्यान में रखते हुए, जिप्सम की खुदाई के लिए, काश्तकार स्वयं खोद सकता है। यह एक अच्छी शुरुआत की है जिससे काश्तकारों को बहुत अच्छा फायदा होगा।

कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, बंजर भूमि के लिए, आज प्रदेश के अन्दर 180 लाख हैक्टेयर बंजर भूमि है और 2014-15 में जलग्रहण संग्रह कार्यक्रम करके इसको 3 लाख 69 हजार हैक्टेयर भूमि में, इस 180 लाख हैक्टेयर में से 3 लाख 69 हजार हैक्टेयर एक वर्ष के अन्दर कृषि योग्य बनाई जाएगी और इसमें जल संग्रहण भी काम आयेगा। यह एक अच्छी शुरुआत है।

100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भण्डारण के लिए 10 लाख रुपये प्रति समिति के लिए 10 करोड़ का जो प्रावधान किया है, गांव के किसान के लिए एक बहुत ही अच्छा किया है। गांव के किसान के पास अपनी उपज को रखने के लिए जगह नहीं होती है, उसके कारण से उसे बाजार में माल बेचना पड़ता है, मजबूरी में। उस भंडारण गृह में रखकर वह पैसा उधार ले सकता है जी.एस.एस. से। यह एक अच्छी शुरुआत की गई है। इसके लिए मैं आदरणीया वसुन्धराजी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

जयपुर में रवीन्द्र मंच के लिए 3 करोड़ 75 लाख रुपये जो सैंक्शन किये हैं...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट, सर। लास्ट वन मिनट, सर। चलो, लास्ट में, अपनी एक बात बता देता हूं, ज्यादा आपको नहीं करना पड़ेगा।

जो शिक्षकों के लिए टैट खतम करके आर.ई.ई.टी. की घोषणा की है, बहुत अच्छी शुरुआत है।

(श्री बंशीधर)

मैं इस सरकार द्वारा पांच वर्षों में जो काम किया गया है, ...(व्यवधान) वह अच्छे प्रबंध के लिए यह सरकार, हर मुख को खाना, हर हाथ को काम मिलेगा और सबकी खुशहाली होगी। यह बजट बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही अच्छा है। इसकी मैं बहुत-बहुत प्रशंसा करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: डा. जसवन्त यादव।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, जो सरकार ने, माननीया यशस्वी मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धराजी ने बजट पेश किया है, इसके लिए मैं ही नहीं, सभी ने तारीफ की है। सब जगह, पूरे क्षेत्र में भी तारीफ हो रही है। हर वर्ग, हर कौम, चाहे वह किसी से भी जुड़ा हुआ हो, सब तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि उम्मीद यह थी।

राजस्थान की जिस तरह से खस्ता हालत पिछली सरकार ने कर रखी थी, उसका परिणाम था कि हर आदमी त्रस्त था। तभी हम लोग 163 जीत कर आये, तभी उनका सफाया हुआ। जब जनता ही पूरी तरह से त्रस्त थी, खजाना पूरा खाली हो चुका था। जहां सरकार पर एक लाख 30 हजार 640 करोड़ का कर्ज हो, बिजली विभाग पर 70 हजार का कर्ज हो, स्कूलों में शिक्षक नहीं, अस्पतालों में डाक्टर नहीं, रोडवेज के अन्दर बसों की खस्ता हालत। मतलब, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जिसके अन्दर हर आदमी त्रस्त नहीं था और उस त्रस्त होने का परिणाम यह हुआ कि कांग्रेस का जनता ने गुस्से में बिलकुल सफाया कर दिया कि यह अगर रह गये तो शायद पता नहीं, कितनी अराजकता फैल जाएगी। इंसान जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता है। ऐसे हालात में सरकार का प्रथम बजट जो आया, हम लोगों को खुद को भी डर था कि सरकार बजट पेश करने जा रही है, कैसे जनता को फेस करेंगे, पता नहीं, कितने टैक्स लगेंगे, किस तरह से सारे मंत्री अपने मंत्रालयों को सम्भालेंगे। अब डाक्टर किरोड़ीलालजी कह रहे थे, बैठे हुए हैं, अभी तो प्रथम बजट है, खस्ता हालत के अन्दर यह बजट पेश किया गया है। खजाना पूरा खाली है और फिर इस तरह का बजट पेश करना, चाहे हम कितने भी विरोध में हों, इस साहसिक कदम के लिए तो आपको भी, सबको माननीया मुख्य मंत्रीजी की, सरकार की भूरि-भूरि प्रशंसा करनी चाहिए।

आज हम पहले ही बजट में, सात महीने हुए नहीं हैं सरकार को और आज उम्मीद करें और आज हम यह कहें कि ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ;

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

यह तो मुख्य मंत्रीजी का अपना कौशल है, अपनी योग्यता है कि इन्होंने हर क्षेत्र के अन्दर ध्यान दिया। मैं बहुत ज्यादा, निश्चित रूप से जिस तरह से बजट आया है, उससे राजस्थान का सर्वांगीण विकास होगा। औद्योगिक क्षेत्र में विकास होगा; रोजगार बढ़ेंगे; शिक्षा में विकास होगा; सड़क में विकास होगा; विद्युत में बढ़ोतरी होगी। जब मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि 24 घंटा, आज तक तो पहले किसी ने नहीं की थी, सिंगल फेज लाइट सात घंटा किसान को और बिजली में भी काफी सुधार हुआ है। हर चीज के अन्दर जिस गति से काम चल रहा है, निश्चित रूप से जो हमने नारा दिया था कि 'अच्छे दिन आएंगे', वह बहुत जल्दी, डाक्टर साहब, अच्छे दिन आएंगे। रोजगार भी मिलेगा और राजस्थान का विकास भी होगा।

अब मेरा तो, देखिए, बोलने वाले बहुत हैं, माननीया मुख्य मंत्रीजी की जितनी तारीफ कर सकते हैं, उतना ही कम है, पर मेरे कुछ सुझाव हैं जो माननीया मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इन सुझावों के अन्दर थोड़ा-सा और ध्यान दें, बजट अच्छा है। उद्योगों के अन्दर, मेरा क्षेत्र तो औद्योगिक क्षेत्र है, जापानी हों और बहुत बड़े-बड़े उद्योग आ रहे हैं लेकिन जो उद्योग लग रहे हैं, हम निश्चित रूप से कल्पना में तो कह सकते हैं कि उन उद्योगों में रोजगार मिलेगा, रोजगार बढ़ेगा लेकिन हमारी कोई सही और ठोस उद्योग नीति नहीं है। कोई इस तरह का कानून नहीं है कि हम उद्योगपतियों को बाध्य कर सकें कि स्थानीय नौ-जवानों को नौकरी मिल सकें। तो माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि जो हमारे यहां पर जिस तरह के उद्योग लगे हैं, इससे बड़े उद्योग तो और कोई लग नहीं सकते, जो प्रोग्रेस रही है उद्योगों के अन्दर, पर उनमें सारे लोग बाहर के हैं। स्थानीय बच्चों को वहां पर नौकरी नाम मात्र की भी नहीं देते हैं। केवल कानून में कमी के कारण उसका फायदा उठाते हैं कि हमारी उद्योग नीति स्पष्ट नहीं है।

तो इसमें अभी जो माननीया मुख्य मंत्रीजी जवाब दें, तो मेरा तो आग्रह है कि वहां के नौ-जवानों को यह बहुत बड़ी उम्मीद है कि मुख्य मंत्रीजी ऐसा कोई कानून बनाएंगी। जिस तरह से गुजरात में है, क्योंकि गुजरात पैटर्न पर ही सारा काम चल रहा है कि स्थानीय नौ-जवानों को रोजगार सुनिश्चित किया जाए। उसमें परसेंटेज है कि इतना तो मिलना ही मिलना है, नहीं तो उद्योगों के लाइसेंस रद्द कर दिये जाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो हम उद्योग बढ़ाना चाहते हैं, हम निवेश करवाना चाहते हैं, उद्योगपतियों को लाना

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

चाहते हैं, उसमें अराजकता का माहौल हो जाएगा और हमारे सारे प्रयास विफल हो जाएंगे। न उद्योगपति आएंगे और न उद्योग बढ़ेंगे। बहुत ज्यादा आक्रोश है नौ-जवानों में। मैं इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी से, सरकार से निवेदन करना चाहता हूं।

इसी तरह से, जो किसानों के लिए है कि अभावग्रस्त, उसमें चाहे वह ओला हो, शीत हो, पाला-वृष्टि हो, कोई प्राकृतिक आपदा हो, इसके अन्दर जो भारत सरकार इन-पुट सब्सिडी देती है; आज के हालात को देखते हुए, जो किसानों की हालत बिगड़ती जा रही है, जो किसान दिनोंदिन गरीब होते जा रहे हैं, उनके जीवन के लिए कोई साधन नहीं बचा है। ऐसे में हकीकत है कि वह तो सब कुछ बरबाद हो जाता है, जब ओला पड़ जाता है, या अतिवृष्टि हो जाती है, या कम वृष्टि होती है, या पाला पड़ जाता है। तो इसमें इन-पुट सब्सिडी के स्थान पर राजस्थान सरकार को अपनी तरफ से मुआवजा देना चाहिए। हम इसको जनरल मुआवजा कहते हैं, पर हकीकत यह है कि यह मुआवजा नहीं है। इसको मुआवजे में राजस्थान सरकार अपनी तरफ से किसानों को दे जिससे वे बच सकें, अपने बच्चों का पालन-पोषण कर सकें।

इसी तरह से, जो अब नई योजना चली कि डार्क जोन जगह-जगह पर घोषित हो रहे हैं; हम प्रोत्साहन भी दे रहे हैं, एक तरफ तो हम यह कह रहे हैं कि ड्रिप सिस्टम लाओ, फव्वारा लाओ, यह लाओ; तो मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब चीजों के अन्दर प्रोत्साहित कर रहे हैं तो किसान को इसमें जो पहले 75 परसेंट था, उससे ज्यादा नहीं बढ़ाया तो कोई बात नहीं पर उसको 60 प्रतिशत तो मत करो, वरना किसान तो इस युग में मर जायेगा और आपका किसान को आगे बढ़ाने का सपना भी पूरा हो जायेगा।

इसी तरह से, सौर ऊर्जा के अन्दर जो आजकल शुरू हुआ था, किसानों के पम्प सेट लगाना, यह सब, उसमें सब्सिडी 86 प्रतिशत से घटाकर 60 प्रतिशत कर रहे हैं। इसके अन्दर भी थोड़ा-सा मैं, माननीय कटारियाजी बैठे हुए हैं, मैं सरकार से निवेदन करता हूं, इस वक्त इस पर जोर देने की जरूरत है। जब इतना अच्छा बजट दिया, हर तरफ ध्यान दिया तो इससे किसान को बहुत बड़ी परेशानी हो जायेगी, इस महंगाई के अन्दर। इस पर भी आपको ध्यान देने की जरूरत है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इसी तरह, सुराज संकल्प यात्रा में जगह-जगह घोषणाएं हुई थीं। मेरे क्षेत्र में भी तीन-चार गौशालाएं हैं। आप क्या करें, क्या नहीं करें, पर वे गौशाला वाले कह रहे हैं कि हमने राज बनाने में मदद की है। तो माननीया मुख्य मंत्रीजी से, सरकार से निवेदन करता हूं, उनको अनुदान तुरन्त प्रभाव से 12 महीने चालू कर देना चाहिये। यह भी मेरा आपसे एक आग्रह है।

इसी तरह से, आपसे उम्मीद ही नहीं थी कि खस्ता हाल, गहलोतजी बरबाद कर गये, कांग्रेस सरकार सब कुछ नष्ट कर गयी; किसी को उम्मीद नहीं थी कि आप सीनियर सेकण्डरी, माध्यमिक विद्यालय हर पंचायत हैडक्वार्टर पर खोलो और ना कोई इतनी इमरजेंसी भी है, फिर भी आपने ऐतिहासिक फैसला लिया, इस शिक्षा के लिए इस बजट को समर्पित किया। तो गांव के अन्दर जो लोग हैं, पंचायत हैडक्वार्टर पर स्कूल खोलोगे, उसमें इस विज्ञान के युग को देखते हुए विज्ञान संकाय भी तो खोलो। आप विज्ञान संकाय नहीं खोलेंगे, तो न तो फिर उनको नौकरी मिलेगी, न वे किसी अच्छे क्षेत्र में जा सकते हैं। आप इस साल की जगह, चाहें दो साल बाद खोल देना, आपको इसके लिए मेरा आग्रह है सरकार से, कि निश्चित रूप से गांवों में जो स्कूल खोलने जा रहे हों, चाहे कितना भी एक्सपेंडिचर बढ़ा हो, चाहे किसी और में कटौती करो, पर निश्चित रूप से आपको विज्ञान संकाय खोलने चाहिये जिससे गांवों के बच्चों को आगे बढ़ावा मिल सके।

अब गांव और ढाणियों के लिए घोषणा की है कि अब थ्री फेज, अच्छा पानी मिले, इसके लिए एक हजार आर.ओ. लगाने की भी घोषणा की। इससे बढ़िया कोई घोषणा हो नहीं सकती। सिंगल फेज बोरिंग की घोषणा की, हैण्ड पम्प की घोषणा की लेकिन आपने उसमें लिमिट कर रखी है। एक तरफ हमारा इलाका ज्यादातर, मेरा अपना इलाका भी डार्क जोन घोषित हो गया। डार्क जोन तभी तो घोषित हुआ है, जब उसका वाटर लेवल नीचे चला गया। अब 150 मीटर पर तो क्या, 300 मीटर तक तो पानी है ही नहीं। हमारे लिए तो सिंगल फेज लगावें या नहीं लगावें, वे कामयाब नहीं हो सकते। थ्री फेज 200 मीटर से कामयाब नहीं हो सकता, क्योंकि वहां सब कुछ ड्राई होता जा रहा है, पूरे के पूरे ब्लाक पानी से खाली हो रहे हैं। तभी डार्क जोन में आये। इसके अन्दर गांव वालों को पानी मिल सके।

पीने का पानी, पहले, तो यह कि इसमें जब तक पानी नहीं आये, इस

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

150 मीटर और 250 मीटर का मापदण्ड खतम करके, इसके अन्दर यह संशोधन करना चाहिये। अभी तुरन्त प्रभाव से जरूरत है कि इसमें जितना गहराई तक हम ले जा सकते हैं, जहां पानी लग जाये, हैण्डपम्प में पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाये, बोरिंग चल जाये, उतनी गहराई तक करें। इसकी लिमिट नहीं होनी चाहिये। तब तो गांवों को फायदा है। वरना तो बोरिंग लगाकर खड़ा कर आओ, दूसरे दिन उसमें पानी नहीं आयेगा। वह पैसा भी बेकार गया, न गांव वालों को सुविधा मिली।

अब डार्क जोन एरिया के अन्दर आप यह कह रहे हैं, आपने यह घोषणा की, अब तक तो कांग्रेस सरकार में तो इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया पर आपने ध्यान दिया, इसके लिये तो हम आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं, पर आपने आन-डिमाण्ड जो बिजली कनेक्शन देने की घोषणा की है, यह व्यावहारिक नहीं है। मेरे जैसे किसान ने तो आज से 20 साल पहले कनेक्शन ले लिया था, मुझे तो जरूरत नहीं है, आप चाहे जितना रेट बढ़ा दो, चाहे जितना घटा दो; अब जो छोटे लघु किसान हैं, जिसके पास में दो बीघा, चार बीघा, पांच बीघा है, उनको आज के दिन, वे बहुत बाद में चेते हैं, उनको आज के दिन कनेक्शन की जरूरत है और आन-डिमाण्ड कनेक्शन का मतलब ढाई लाख रुपये। तो ना उनकी जिन्दगी में ढाई लाख रुपये होंगे, न वे कनेक्शन ले सकते हैं। तो इसको व्यावहारिक बनाना चाहिये, इस तरफ ध्यान देना चाहिये, क्योंकि शुद्ध रूप से जो भी डार्क जोन इलाके हैं, उनमें छोटे किसानों को ही जरूरत है, बड़े किसानों के पास तो सबके पास अपने बोरिंग हैं।

इसमें मेरा सरकार से आग्रह है, प्रार्थना है कि उन लोगों की कठिनाई को देखते हुए, उनकी हकीकत को देखते हुए, वे अपने बच्चों का पेट पाल सकें, इसको थोड़ा व्यावहारिक बनाना चाहिये। इसमें थोड़ा संशोधन करने की जरूरत है।

डार्क जोन एरिये के लिये आज बोरिंग खोल दिये। इससे बड़ी बात तो कोई हो नहीं सकती, यह तो हिस्टोरिकल फैसला है पर आज दो साल बाद वे बोरिंग भी फ्लाप हो जायेंगे, वे भी ड्राई हो जायेंगे। तो उसके लिये हकीकत है कि आपको कोई न कोई ऐसी योजना बनानी चाहिये जिससे भविष्य के अन्दर उन इलाकों को बचाया जा सके। जैसे हमारे चम्बल का है, 10 साल से तो हम भी सुनते आ रहे हैं, पिछली बार गहलोतजी ने तो सारी घोषणाएं ही झूठी की

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

हैं, थोथी की हैं और पत्थर भी लगायें और यह भी घोषणा कर दी कि 1,200 करोड़ रुपये घोषित कर दिये, अलवर जिले को चम्बल का पानी मिलेगा, लेकिन कोई लेना नहीं, देना नहीं। इसके लिये भी निश्चित रूप से अलवर को, इधर कोई और फीजिबल है नहीं, किसी भी तरह, चाहे लिफ्ट करके लाया जाये, निश्चित रूप से चम्बल के पानी की अभी से योजना बनायें, नहीं तो वहां के लोग तो अपने आप में पीने के पानी को ही तरस जायेंगे, सिंचाई की बात तो दूर रहेगी।

मेरा आग्रह है कि सरकार ने जो बजट पेश किया है, हकीकत में ऐसी कठिन परिस्थिति में, इतनी खस्ता हालत में राजस्थान को कांग्रेस छोड़कर गयी है, उन हालात में इस तरह का बजट पेश करना, यह तारीफ के काबिल है। सरकार की, माननीया मुख्य मंत्रीजी की जितनी तारीफ की जाये, उतनी कम है। इस तरफ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। जो मेरे सुझाव हैं, उनके लिये मैं आग्रहपूर्वक निवेदन करता हूं मुख्य मंत्रीजी से, सरकार से, कि उन पर ध्यान दें। जिससे और इस बजट में चार चांद लग सकें। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री जीतमल खांट।

श्री जीतमल खांट (गढ़ी): सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान की सरकार, हम सबकी, जन-जन की प्रिय मुख्य मंत्री महोदया ने राजस्थान का परिवर्तित बजट 2014-15 को जो पेश किया है, मैं आज इस मौके पर उनको साधुवाद देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा।

इस सदन में सभी माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव, तर्क-वितर्क और अपने यहां पर पक्ष और विपक्ष के माध्यम से समालोचना की गयी है। अपने विचारों में मैं अपनी बात को जोड़ता हुआ सदन में कहना चाहूंगा कि यह सारा का सारा, पूरे राजस्थान के सारे वर्गों को अपने साथ में जोड़ने का जो प्रयास किया गया है, सबकी तकलीफों को उन्होंने महसूस किया है और इन तकलीफों का निराकरण, समस्या का समाधान करने के पीछे सबसे बड़ा जो कारण रहा है, सुराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने पूरे राजस्थान भर में 14 हजार किलोमीटर की जो यात्रा की, उस यात्रा के दौरान इन्होंने पूरे राजस्थान के गांव, ढाणी, मजरों में लोगों के विचारों को, वहां की परिस्थितियों को, रहने के रंग और ढंग को और समस्याओं से रूबरू होने का जो उन्होंने 14 हजार किलोमीटर की यात्रा पूरी करके, पूरे राजस्थान को समझने

(श्री जीतमल खांट)

का प्रयास किया और उसी का परिणाम है, आज इतना बेहतर यहां पर जो बजट पेश किया गया है, उसी का परिणाम मैं मानता हूं।

सम्पूर्ण राजस्थान की जनता ने शायद 1998 के अन्दर जब अशोक गहलोतजी की सरकार बनी थी, उस दरम्यान में 156 सीटें आई थीं और कांग्रेस के माननीय सदस्य सभी, जब उस पीरियड में बैठा करते थे, सुनते थे, भूरि-भूरि प्रशंसा करते थे कि राजस्थान के इतिहास में इतना प्रचण्ड बहुमत आया और अशोक गहलोतजी के कार्यकाल को महान कार्यकाल बताया। लेकिन समय ने अपनी धीरे-धीरे करवट बदली। मुझे याद है कि आज इस पूरे सदन में माननीय सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त कीं, कई समस्याएं अपने-अपने क्षेत्र की यहां पर सदन में रखी हैं। वसुन्धराजी राजे सिंधिया का यह जो कार्यकाल है और राजस्थान की जनता ने जिस भावना को समझ कर के जो प्रचण्ड बहुमत दिया है, उसी का यह परिणाम है कि आने वाले समय में राजस्थान के इतिहास में 163 का आंकड़ा कोई दूसरी पार्टी क्रास नहीं कर पायेगी और हमेशा राजस्थान के इतिहास में यह कार्यकाल स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायेगा। ऐसा मेरा मानना है।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के नौजवान, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, मध्यम वर्ग का व्यक्ति हो, हर व्यक्ति ने यह महसूस किया कि 2003 से लगाकर 2008 तक राजस्थान की मुखिया के रूप में वसुन्धराजी ने जो कार्यकाल और विजन दिया, जो उस समय का उनका कार्यकाल रहा, बेहतर ढंग से राजस्थान में एक अच्छा सुशासन चलाने का काम किया। अच्छा वित्तीय प्रबन्धन था, अच्छे ढंग से राजस्थान का ढांचा चलाया।

अभी हमारे बीच में डाक्टर साहब नहीं हैं, डाक्टर साहब उस समय सत्ता के साथ में थे, राजस्थान के उस दक्षिणी राजस्थान के प्रति कभी चिंता नहीं की, आज अपनी चिंता जाहिर कर रहे हैं, ठीक बात है लेकिन उस पीरियड में राजस्थान का दक्षिणी भाग, जिसमें पूरा टी.एस.पी. क्षेत्र आता है, उस टी.एस.पी. क्षेत्र में जितने अध्यापक वसुन्धराजी के कार्यकाल में लगें, पिछला जो गहलोतजी का कार्यकाल निकला, इस बार के कार्यकाल में एक भी स्टेज तक हमारे कोई इतनी बड़ी संख्या में अध्यापक नहीं बनें। इसीलिए दक्षिणी राजस्थान की आम जनता ने, पिछली बार चार या पांच सदस्य आये थे और

(श्री जीतमल खांट)

इस बार हमारे उदयपुर सम्भाग में सबसे ज्यादा, अप्रत्याशित, सिर्फ एक सीट को छोड़ कर के, सारे के सारे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माननीय सदस्य जीत कर के आये हैं।

मैं सबसे पहले माननीया मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए भी साधुवाद देना चाहूंगा कि उदयपुर डिविजन को उन्होंने सर्विस कैडर के रूप में पहला कानून पास कर के पूरे उदयपुर डिविजन के सामान्य और जनजाति वर्गों में एक बहुत बड़ा, अच्छा संदेश देने का काम किया है। इस सर्विस कैडर के माध्यम से, हमारे उदयपुर डिविजन में 67 साल की आजादी में आज अगर हम प्रशासनिक और इन सेवाओं में आंकड़ा उठा कर देखें तो आई.ए.एस. और आई.पी.एस. का आज दिन तक 0.1 परसेंट देखने को मिलता है, आज निश्चित रूप से इस सर्विस कैडर के बनने के बाद में जितनी छोटी-छोटी नौकरियां हैं, चाहे सामान्य वर्ग हो, चाहे एस.टी. हो, चाहे एस.सी. हो, इन लोगों के जीवन में भी यह कानून वरदान बन कर आगे आयेगा।

मैं आपके माध्यम से, माननीय सभापति महोदय, कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने हमारे दक्षिणी राजस्थान के लिए बहुत कुछ, सड़क, बिजली, चिकित्सा, कृषि, सभी के बारे में आपने दरियादिली दिखाने का प्रयास किया है। लेकिन मैं सदन का ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा कि जिस इलाके में हम लोग रहते हैं, उस इलाके में 67 साल की आजादी में कई ढाणी और मजरे राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं हैं। राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने की वजह से 250 की आबादी का जो लाभ हमको मिलना चाहिए, 300 की आबादी का जो लाभ मिलना चाहिए, हम आज भी उन ढाणी और मजरों को जब तक राजस्व रिकार्ड में नहीं जोड़ेंगे, राजस्व का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक हमें सड़क का, बिजली का, पानी का लाभ नहीं मिल सकता है। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि सरकार को हमारा यह सुझाव जाए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आगे एक बात और कहना चाहूंगा। बी.पी.एल. योजना के अन्तर्गत उदयपुर संभाग के अन्दर, पूरे राजस्थान में 38 लाख बी.पी.एल. परिवार हैं। आप अनुमान लगाइये कि पूरे राजस्थान में सात करोड़ की जनंसख्या है, जो यह सर्वे हुआ है, पिछली कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, 2001 या 2002 के आसपास यह सर्वे हुआ था, आज दिन तक उस आंकड़े को

(श्री जीतमल खांट)

ज्यों का त्यों उसी रूप में पेश किया जा रहा है। इतने लम्बे अन्तराल के बाद में काफी कुछ परिवर्तन आया है। मैं चाहूंगा कि उदयपुर डिविजन में, पूरे राजस्थान की बात तो माननीय सदस्य अपने-अपने क्षेत्र की करेंगे, लेकिन उदयपुर डिविजन में बी.पी.एल. का सर्वे पुन: होना चाहिए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

कई सरकारी, गैर-सरकारी आंकड़ों में क्या स्थिति बनी है, मैं इस बारे में नहीं जाना चाहूंगा; पिछली सरकार ने क्या किया, वह भी नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन निश्चित रूप से हमारे साथ में भेदभाव हुआ है। मैं आसन से चाहूंगा कि कोई ऐसी व्यवस्था दें और आने वाले समय में अगर हमें बी.पी.एल. का लाभ मिलेगा तो निश्चित रूप से इसमें गैर-जनजाति भी हैं, जनजाति भी हैं, एस.सी. के लोग हैं। आज ऐसे-ऐसे लोगों का नाम बी.पी.एल. में है जिनके दो-दो ट्रैक्टर खड़े हैं, मोटर साइकिलें खड़ी हैं; जिनके घर में कुआं है, बिजली है, जिनके घर में हर तरीके की सुविधा से सम्पन्न व्यक्ति हैं, वे बी.पी.एल. में हैं और जिनका धरती और आसमान के बीच में कोई धणी-धोरी नहीं है, ऐसे व्यक्ति का नाम ए.पी.एल. में चल रहा है। तो, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि जब भी इस तरीके की योजना बने, निश्चित रूप से एक बड़े पैमाने पर उदयपुर संभाग में सर्वे का कार्य करवाया जाए।

तीसरा, मैं आपके सामने एक बिन्दु रखना चाहूंगा कि हमारी माही परियोजना, जो कहना चाहिए, हमारी जीवन रेखा है, लाइफलाइन है और इस माही परियोजना के लिए बजट में यहां पर मात्र बीस करोड़ का प्रावधान रखा है। मैं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आने वाले समय में बांसवाड़ा जिले के अन्दर हमारा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, खनिज सम्बन्धी और हमारी कई ऐसी योजनाएं भारत सरकार के माध्यम से भी आने वाली हैं, प्रस्तावित हैं, काम धीरे-धीरे उस स्थिति पर चल रहा है, लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र के अन्दर, बांसवाड़ा जिला, डूंगरपुर जिले के अन्दर जो भी हमारा माही परियोजना का काम है, बीस करोड़ से तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ वहां की सैलेरी है, वहां के स्थानीय लोगों की...

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं चाहूंगा कि इस माही परियोजना का काम बड़े पैमाने पर हो। उसको हाई लेवल कैनाल बना कर के हमारा जितना भी असिंचित क्षेत्र है...

(श्री जीतमल खांट)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट में पूरा कर देता हूं। हमारी माही परियोजना का जो काम है, अभी हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि जालौर और पाली ले जाए, बांसवाड़ा के उस डैम के अन्दर 77 टी.एम.सी. पानी की भराव क्षमता है। यानी कि 77 टी.एम.सी. भराव क्षमता का पानी होना, यानी कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर को पूरी तरह से सरसब्ज कर सकता है, इतनी बड़ी क्षमता वाला यह डैम है। मैं चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि कडाणा और माही डैम के किनारे बसे हुए जो गांव हैं, जो पानी के लिए तरसते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी कोई इस तरह की लिफ्ट की योजना बनायी जाए और बड़े पैमाने पर, जिस तरह से गंग नहर के लिए जो पैसा देना प्रस्तावित हुआ है, उसी ढंग से माही परियोजना को भी जीवित करने का काम करें। हमारे एस.ई., एक्स.ईएन., चीफ इंजीनियर की जो पोस्टें टूट गयी हैं, उनको भी वापस बहाल करने का प्रयास करें।

मैं अपनी ज्यादा कुछ बात नहीं कहना चाहूंगा लेकिन मेरे क्षेत्र की एक-दो मांगें हैं, उनको आपके बीच में कह देना चाहूंगा। बिना भूमिका के मैंने अपनी बात रखी है।

मेरे उपखण्ड कार्यालय, गढ़ी क्षेत्र के अन्दर राजकीय महाविद्यालय नहीं है, राजकीय महाविद्यालय खोला जाए। साथ-साथ में, वहां पर जो हमारा डी वाई.एस.पी. का कार्यालय है, वहां पर डीवाई.एस.पी. के पद को सृजित किया जाए। वहां पर यह सभी लोगों की एक मांग है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय कटारिया साहब यहां पर बैठे हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी इच्छा व्यक्त की है, ग्राम पंचायतों के अन्दर पुनर्गठन में जो अपनी इच्छाशक्ति जताई है, निश्चित रूप से इस राजस्थान सरकार का यह स्वागत-योग्य कदम है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जय हिन्द। जय भारत। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2014-15 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: एक मिनट, माननीय सदस्या।

मुख्य सचेतक महोदय, समय को देखते हुए मैं, आसन आपसे अनुमति चाहता है कि दो महिला सदस्य और हैं, निरन्तर उन दोनों को बुला दिया जाए जिससे कि उनको कम से कम समय पर बोलने का मौका मिल जाए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): हमारी लोकप्रिय नेता और राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने बजट 2014-15 पेश किया। वह आज दिन तक का सबसे बेहतरीन बजट है। आज जनता की आवाज, महिलाओं, युवाओं, छात्र-छात्राओं, किसानों व निम्न जीवन यापन करने वाले गरीब तबके के परिवारों को ध्यान में रखते हुए, राजस्थान की जनता के दु:ख-दर्द और समस्याओं को सुराज संकल्प यात्रा के दौरान राज्य भर में 14 हजार किलोमीटर का सफर तय कर गांव-गांव और ढाणी-ढाणी जाकर स्वयं ने सुना और जनता ने जिस उम्मीद, विश्वास और भरोसे के साथ में भारी बहुमत और जनादेश दिया, उन जनता की उम्मीदों को ध्यान में रखते हुए यह बजट पेश किया गया है।

सभापति महोदय, मैं जिस अनुसूचित जाति सीट से जीतकर आती हूं, उन अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के वोटों पर यह कांग्रेस सरकार अपनी हुकूमत समझती है। यह हमारा सौभाग्य है कि राजस्थान के इतिहास में ऐसा उदाहरण देखने का मौका मिला कि पूरे प्रदेश में एक भी अनुसूचित जाति का विधायक कांग्रेस का जीतकर नहीं आया। क्योंकि कांग्रेस सरकार ने वोटों के बाद हमेशा इन लोगों के साथ में सौतेला व्यवहार किया था। मैं समाज की बहुत-बहुत आभारी हूं और बड़ी उम्मीद के साथ धन्यवाद देती हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश भर में हमारी लोकप्रिय नेता और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी के ऊपर भरोसा किया और उनको भारी समर्थन दिया।

सभापति महोदय, मैं पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारीजी वाजपेयी और हमारी लोकप्रिय नेता, वसुंधरा राजे सिंधियाजी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने पिछले 5 वर्षों में, राज्य की सड़कों की जो व्यवस्था अभी देखने को मिल रही है, हमारे प्रधान मंत्रीजी के समय में पूरे देश भर में सड़कों का जो जाल बिछा था, आज भी गांव की जनता उन सड़कों के जाल को याद कर रही है। यह पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार, जो पिछले 5 सालों में सड़कें बनी थीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में, उन सड़कों पर डामर भी नहीं लगा सकी। यह हमारे लिए दुर्भाग्य की बात है। पिछले 5 वर्षों में पूरे राजस्थान के गांव-गांव और ढाणी-ढाणी के अन्दर जिस तरह से सड़कों की जो व्यवस्था चरमरा गयी है,

(श्रीमती संजना आगरी)

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के शासन में, विपक्ष में बैठे हमारे सारे विधायकों ने पूरे प्रदेश भर से अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को यहां पर समय-समय पर रखा, सड़कों की अव्यवस्थाओं से अवगत कराया कि सड़कें टूटी-फूटी हैं, आये दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं लेकिन इस कांग्रेस सरकार ने हां-हां करते हुए पूरे 5 साल निकाल दिये, जिससे दुर्घटनाओं का ग्राफ बढ़ा है। यह वाकई में हमारे लिए चिंता का विषय है।

सभापति महोदय, जो सड़कें इन्होंने बनाईं, वहां ठेकेदारों की मिलीभगत से कालिख पोतकर रख दी। 5 साल पूरे नहीं हुए, उससे पहले उन सड़कों की हालत यह है कि बारिश से पहले ही वे सड़कें आज की तारीख में टूट चुकी हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको सोजत विधान सभा क्षेत्र की स्थिति के बारे में अवगत कराना चाहूंगी कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 2 स्टेट हाइवे स्वीकृत हुए थे, एक तो सोजत शहर, रूपावास ग्राम पंचायत से जाते हुए, राजोला से लेकर जोधपुर तक है और दूसरा जोधपुर, सरदारसमंद, जाडौन होते हुए गौमती चौराहे तक जाता है, दोनों स्टेट हाइवे की यह हालत है कि पिछले 5 सालों के अन्दर उन सड़कों के पास में आधे-आधे फिट के खड्डे करके रख दिये हैं। 50 से ज्यादा दुर्घटनाएं मैंने वहां अपनी आंखों से देखी होंगी। यह मेरा और मेरी जनता का भी दुर्भाग्य है। मैं हमारी लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्य मंत्री जी से निवेदन करना चाहती हूं कि सोजत विधान सभा क्षेत्र के स्टेट हाइवे जो अब जीर्ण-शीर्ण अवस्था में पड़े हैं, क्यों नहीं, इस बजट संशोधन के अन्दर उन्हें भी पैकेज में लेकर वहां की जनता को आप राहत प्रदान करायें?

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि बजट 2014-15 में हमारी लोकप्रिय नेता और यशस्वी मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि राजस्थान में उपलब्ध 16 हवाई पट्टियों में सुधार किया जायेगा। मैं आपको बताना चाहूंगी कि पूरे पाली जिले के अन्दर सोजत नगरपालिका शहर में मात्र एक एयर स्ट्रिप बनी हुई है, जहां पर वायुयान का आना-जाना सुनिश्चित है। लेकिन उसका सुदृढ़ीकरण नहीं होने के कारण एयर स्ट्रिप के सीमांकन के अन्दर बहुत से लोगों ने अवैध कब्जे कर लिये हैं। मेरा मुख्य मंत्रीजी से निवेदन है कि बजट संशोधन में सोजत एयर स्ट्रिप का सुदृढ़ीकरण करवाकर अवैध कब्जेधारियों को वहां से तुरन्त हटाया जाये तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत अच्छा काम होगा।

(श्रीमती संजना आगरी)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारी लोकप्रिय नेता और मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे सोजत विधान सभा क्षेत्र के अन्दर आज भी 6 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां पर 30 से 35 गांव ऐसे हैं जो मगरा क्षेत्र के अन्दर आते हैं। मैं हमारी यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने 2003 से 2008 में, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, तो मगरा विकास बोर्ड बनाया था और पूरे अजमेर और ब्यावर की सरहद के मगरा क्षेत्रवासी उस में आ गये थे। लेकिन यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि सोजत विधान सभा क्षेत्र की 6 पंचायतों के मगरा क्षेत्रवासी आज भी मगरा विकास बोर्ड से वंचित हैं। वहां उनके बच्चों के पढ़ने के लिए उचित शिक्षा व्यवस्था नहीं है। महिलाओं को प्रेग्नेंसी के समय में 4-4 किलोमीटर दूर झोली में डालकर अस्पताल ले जाया जाता है। उनके रहने के लिए ना मकान हैं और ना उनके लिए रोजगार के साधन हैं। बारिश के दिनों में उनकी झोंपड़ियों से पानी टपकता है। हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहती हूं कि मगरा विकास बोर्ड के लिए आपने 300 करोड़ रुपये के बजट के प्रावधान रखे हैं, क्यों नहीं सोजत विधान सभा क्षेत्र के इन वंचित मगरा क्षेत्रवासियों को बजट में लेकर उनके विकास के लिए आप जरूर कुछ न कुछ करें?

सभापति महोदय, मैं आपको वहां की पेयजल स्थिति के बारे में भी अवगत कराना चाहूंगी। हमारी सरकार की यह मंशा है कि गांव की गरीब जनता को पेयजल की समस्या का सामना नहीं करना पड़े। अभी गर्मी का समय निकला है, इसके लिए हमारी सरकार पूर्ण रूप से संकल्पबद्ध है। हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि गर्मी का समय निकला, लेकिन पूरे प्रदेश के अन्दर इस बार पेयजल व्यवस्था बहुत ही व्यवस्थित तरीके से रही, जिसके लिए मैं बहुत-बहुत आभारी हूं।

सभापति महोदय, इसके साथ ही मैं आपको निवेदन करना चाहती हूं कि मैं जिस सोजत विधान सभा क्षेत्र से आती हूं, वहां पर 28 सौ से 32 सौ टी डी एस का फ्लोराइडयुक्त पानी वहां की जनता पी रही थी। वहां पर हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने जवाई पाइपलाइन परियोजना का जो पैकेज बनाया था, 2003-08 की सरकार में, उसका पानी चौथे पैकेज के अन्दर हम सोजत लेकर गये। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार जो कांग्रेस की थी, उन्होंने हमारे वहां जो वाटर फिल्टर स्टोरेज बनाये थे, वे वहां पर नहीं बनकर कहीं और जगह पर पानी लेकर चले गये हैं। आज की तारीख में जवाई बांध का मीठा पानी सोजत

(श्रीमती संजना आगरी)

क्षेत्र की जनता को मिल रहा है, लेकिन ओनली 40 लाख लीटर रा वाटर मिल रहा है, जबकि हमारे सोजत शहर की जो आबादी है वह 40 हजार है और मात्र 4 एम एल डी का वाटर स्टोरेज हमारे पास उपलब्ध है। मैं हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि महिलाओं की इस भारी ज्वलंत समस्या को देखते हुए, आप इस 4 एम एल डी की जगह 12 एम एल डी का एक वाटर स्टोरेज शीघ्र उपलब्ध करवायेंगे तो हमारे जो पानी की आपूर्ति आज की तारीख में 7 से 9 दिनों से हो रही है, उससे हमारी जनता को राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि हमारा राजकीय चिकित्सालय, सोजत, जो नेशनल हाइवे 14 पर है और वहां 4 लाइन का काम पिंडवाड़ा से लेकर ब्यावर तक चल रहा है, वहां पर आये-दिन एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं होती हैं। मैं माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि वह नेशनल हाइवे 14 पर स्थित जो हमारा अस्पताल है, वहां पर हमारे पास आर्थोपेडिक डाक्टर की कमी है और उसके साथ गायनिक और 2 एम ओ डाक्टर की आप इमिजिएटली व्यवस्था करायेंगे तो हमारी जनता को बहुत बड़ी राहत मिलेगी।

सभापति महोदय, हमारी गुड गवर्नेंस और मुख्य मंत्रीजी की यह मंशा है कि सरकारी योजनाओं का लाभ आम व्यक्तियों को मिले, गरीब और निम्न जीवनयापन करने वाले समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को मिले। हमारी मुख्य मंत्रीजी की मंशा है कि यह गर्त में डूबा राजस्थान पुन: विकसित और विकासशीलता की ओर अग्रसर हो। इसके लिए 'सरकार-आपके- द्वार' आपने जो मिशन और कार्यक्रम तैयार किया है, निश्चित रूप से मिशन 2020 नये आयामों को छूएगा। इसके लिए मैं पुन: हमारी सरकार और हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी का हृदय की गहराई से बहुत-बहुत हार्दिक अभिनन्दन और धन्यवाद देती हूं।

श्री सभापति: श्रीमती कमसा मेघवाल।

श्रीमती कमसा (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट सत्र में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपकी बहुत-बहुत आभारी हूं।

बजट 2014-15 हमारी मुख्य मंत्रीजी ने जो पेश किया, आज तीन

(श्रीमती कमसा)

दिन से इस पर वाद-विवाद चल रहा है और विधान सभा में आये हुए मेम्बर ही नहीं, बाहर भी, किसान, महिला, हर वर्ग इस बजट की प्रशंसा करना चाहता है और मैं भी बहुत गहरे दिल से इस बजट की और जो बजट पेश किया है, उसकी बहुत-बहुत प्रशंसा करती हूं।

राजस्थान के अन्दर पहली बार वसुन्धराजी ने आम ग्रामीण तक, ठेठ गांव की ढाणियों तक सुराज संकल्प यात्रा निकाल कर गांव की गहराइयों के अन्दर जो गांव की समस्याएं होती हैं, उनको जाना है कि गांव के अन्दर किस तरह की समस्याएं होती हैं। आजादी के 60 साल बाद भी, हर बार बजट आता है, हर सरकार आती है और बजट पेश करती है, लेकिन पांच साल तक वसुन्धराजी ने राज किया था, उन्होंने गांव के अन्दर विकास किया था। उसी के आधार पर, दूसरी बार जो कांग्रेस की सरकार बनी, उन्होंने गांव की जो समस्याएं थीं, उनकी उन्होंने निगरानी नहीं रखी। वसुन्धराजी ने गांवों में जाकर, सुराज संकल्प यात्रा निकाल कर, गांव की जो समस्याएं देखीं, उन्हीं के आधार पर राजस्थान की जनता ने इनको 163 सीटें देकर भारतीय जनता पार्टी का राज बनाया है और अब राजस्थान की जनता को पूरी-पूरी उम्मीद है और मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहती हूं कि मां, मां होती है, और मां के दिल में जो गहराई होती है, जो दर्द होता है, वह कोई और नहीं समझ सकता है। यह मां ही है, बच्चों को स्कूलों के अन्दर जो साइकिलें दी हैं, यह मां का दिल ही है और मां ही समझ सकती है कि बच्चियां कैसे पढ़-लिख कर आगे बढ़ सकती हैं।

आज जो गांव की समस्याएं हैं, हम शिक्षा के स्तर को ऊंचा ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर सत्र के अन्दर यही आवाज उठती है कि स्कूलों के अन्दर टायलेट बनने चाहिए। आज के दिन स्कूलों के अन्दर टायलेटों की सुविधा नहीं है तो गांव की बच्चियां पढ़ कर कैसे ऊंचे स्तर तक पहुंचेंगी? तो मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि हर ग्राम पंचायत के अन्दर, हर पंचायत समिति के अन्दर, हर जो स्कूल है, वहां स्कूल के अन्दर टायलेट भी बनाया जाये और एक महिला टीचर अवश्य लगी होनी चाहिए। क्योंकि गांव की बच्चियां अच्छी तरह से पढ़-लिख कर, जो बारहवीं तक अगर बच्ची अच्छी तरह पढ़ जायेगी तो फिर बारहवीं के बाद तो प्राइवेट पढ़ कर भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन सीनियर तक उसको सब सुविधा मिलनी चाहिए। हर स्कूल के अन्दर एक महिला टीचर जरूर होनी चाहिए।

(श्रीमती कमसा)

मानलीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि गांव के अन्दर कर्मचारी नहीं लगते हैं, गांव के अन्दर डाक्टर की भी कमी होती है, एक भी लेडी डाक्टर कोई गांव के अन्दर नहीं मिलती है। आपको यह भी पता होगा कि गांव की महिला है तो गांव की महिला, आज से पहले जो महिलाएं थीं, जो 60 साल की, 70 साल की, जो 40 साल की उम्र की महिलाएं हैं, वे कम पढ़ी-लिखी होने के कारण अपनी समस्या होती है तो वे उसको पुरुष डाक्टर को नहीं बता सकती हैं। तो इसके ऊपर मुख्य मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि हर पंचायत समिति के अन्दर एक गायनिकोलोजी डाक्टर जरूर होनी चाहिए जिससे उस महिला को किसी तरह की बीमारी हो तो अच्छी तरह से उस महिला डाक्टर को बता सके।

मेरा यह भी निवेदन है कि गांवों के अन्दर कर्मचारी नहीं लगते हैं, इसका एक बहुत बड़ा कारण है। शहरों के अन्दर शहरी भत्ता मिलता है। शहरी मकान किराया भत्ता मिलता है, उसको पैसे ज्यादा मिलते हैं और गांवों के अन्दर जो कर्मचारी लगते हैं, उनको पेमेंट कम मिलता है। तो यह असमानता है, इसको दूर किया जाये। गांवों के अन्दर भी हाउस रेंट है, बढ़ाया जाये। शहरों में जो हाउस रेंट मिलता है, मैं यह नहीं कहती कि उनका बंद किया जाये लेकिन गांवों के अन्दर भी जो गांव का भत्ता है, उसको ज्यादा मिलना चाहिये। ज्यादा मिलेगा तभी गांवों में कर्मचारी लगेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है कि भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो तिवरी-मथानिया पानी वाली योजना थी, 5 साल अशोक गहलोतजी का राज रहा और हमारा दुर्भाग्य रहा, जोधपुर क्षेत्र से होते हुए भी उन्होंने भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र को पानी नहीं पिलाया। अब आपके माध्यम से मेरा निवेदन है कि तिवरी-मथानिया वाली योजना, पेयजल योजना भोपालगढ़ के लिए चल रही है, वह जल्दी से जल्दी इस बजट के अन्दर, पैसों की कमी तो है नहीं, क्योंकि मां का दिल होता है तो पैसे इन्द्र देवता और भगवान की कृपा से सब कुछ मिल जाता है; भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जल्दी से जल्दी पानी मिल सके, मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है।

मैं यह भी कहना चाहती हूं कि भोपालगढ़ क्षेत्र के अन्दर, ग्रामीण क्षेत्र के अन्दर सड़कों की अव्यवस्था है। पी डब्ल्यू डी मिनिस्टर यहां बैठे हैं, इनसे

(श्रीमती कमसा)

भी मेरा निवेदन है कि जिन सड़कों से वसुन्धराजी मैडम गुजरी थीं, उन्होंने गांव वालों से वादा किया था कि ये गहरे-गहरे खड्डे हैं जो भरवाना चाहते हो क्या? तो गांव वालों ने 'हां' भरी थी कि मैडम, हम आपको वोट देकर जितायेंगे, राजस्थान की सी एम बनायेंगे। तो ये खड्डे आप भरें।

मेरा आपसे निवेदन है कि भोपालगढ़ विधान सभा क्षेत्र की सड़कों की जो भी समस्या है, जो मैं आपको लिखकर दे दूं, वे सारी की सारी होनी चाहिए। खेड़ागढ़ से भोपालगढ़ तक और भोपालगढ़ से जोधपुर तक जो भी सारी सड़कें हैं, उन सारी सड़कों का पुन: निर्माण होना चाहिए। क्योंकि हर गांव के अन्दर, शहरों के अन्दर यह जो बन रही है, मेट्रो ट्रेन हो, चाहे मेगा हाइवे हो, लेकिन गांव का आदमी, वह अपनी जिन्दगी में न तो कभी टवेरा खरीद सकता है, न बोलेरो खरीद सकता है, वह ट्रैक्टर से ही उन्हीं सड़कों पर घूमता है। तो कम से कम किसान के लिए, जो अपनी फसल कटती है, वह जो कृषि मण्डी तक लेकर जाता है, तो उसको तो वही सड़क काम आयेगी। वह अपने जीवन में मेट्रो सिर्फ टीवी पर देख सकता है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा मंत्रीजी अभी सदन में नहीं हैं, उनसे भी मेरा निवेदन है कि यह मेट्रो के अन्दर, शहरों के अन्दर जो बिजली की बड़ी-बड़ी लाइटें लगती हैं, वे किसान के काम नहीं आती हैं। किसान के तो, आज किसान का बेटा गांव की ढाणी में एक बल्ब के लिए तरस रहा है। अगर गांव की ढाणी में कनेक्शन नहीं होगा, मैं आपको यह भी बताना चाहती हूं, माननीय सभापति महोदय, 2003 का सर्वे है, जो पेयजल योजना के तहत सर्वे हुआ था, आज के दिन कहीं भी चले जाएं तो सीधे डिपार्टमेंट की तरफ से कहा जाता है कि 2003 की जो ढाणियों का सर्वे हुआ था, उसमें आपकी ढाणी आ रही है, या नहीं आ रही है। यह पुराना सर्वे है। (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, मैं आपको यह निवेदन करना चाहती हूं कि वह सर्वे पुन: करवाकर, गांव का जो किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, वह एक बल्ब के लिए तरस रहा है। तो ढाणियों के अन्दर, पांच-पांच के ग्रुप के अन्दर जो ढाणियां हैं, उनको तुरन्त एप्लाई करते ही कनेक्शन मिलना चाहिए। क्योंकि ये बड़ी-बड़ी लाइटें जो शहरों में लगती हैं, वे उनके काम आने वाली नहीं हैं। वह पांचवीं तक, दसवीं तक अगर बच्चा पढ़ता है, उसको लाइट नहीं मिलेगी तो वह बच्चा कैसे पढ़ेगा, माननीय सभापति महोदय?

(श्रीमती कमसा)

अपन चाहते हैं कि विकास हो, राजस्थान का विकास हो, हिन्दुस्तान का विकास हो। मोदीजी ने भी जगह-जगह भाषण दिया था, हमारी ग्राम पंचायत रतकुड़िया में भी वे आये थे, उन्होंने देखा था, गांव की भौगोलिक स्थिति कैसी है। लेकिन जब तक जमीनी स्तर का विकास नहीं होगा, तब तक प्रदेश और हिन्दुस्तान का विकास नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि गांव को क्या चाहिए? बिजली, सड़क, पानी और शिक्षा, चार चीजें चाहिए। न तो उनको हवाई अड्डा चाहिये, न ही उनको मेट्रो चाहिये और न ही उनको कोई मेगा हाइवे चाहिये। ये चार मूलभूत सुविधाएं हैं। इनके ऊपर विशेष ध्यान देकर गांव को ऊपर उठाने के लिए, महिलाओं को ऊपर उठाने के लिए, मैं वसुन्धराजी को यह भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि मैडम ने ही पंचायती राज में 50 परसेंट महिलाओं को आरक्षण दिया था और उस आरक्षण की वजह से ही आज महिलाएं आगे बढ़-चढ़कर आ रही हैं। उनको इस बात का भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि जो भामाशाह योजना थी, पिछली बार मां नहीं बनी, इसलिए भामाशाह योजना बंद हो गई, तो अबकी बार सभी महिलाओं का परसेंट भी ज्यादा था, महिलाओं ने इसी आधार पर वोट दिये और वसुन्धराजी ने भामाशाह योजना भी वापस चालू कर दी है। इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं और आभार प्रकट करती हूं।

आप अब घण्टी बजाने वाले हों, तो मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि गांव की, ढाणियों की महिलाओं का आप विशेष तौर से ध्यान रखें।

मैं यह भी कहना चाहती हूं, जब भी न्यूज आती है अखबारों में, हम गांवों में खूब अच्छे-अच्छे काम करते हैं लेकिन यहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। दूसरे दिन आते हैं सदन के सितारे, तो वे भी हाई-फाई लोग ही आते हैं। तो मैं समझती हूं कि ये बड़े-बड़े जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और एक बात यह भी कहना चाहूंगी कि जो भी पोस्टें होती हैं, एस पी है, कलेक्टर है, गांव के नहीं, जैसे मेरा विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ है तो वहां के जो पद हैं, वे शहर तक ही सीमित हैं। तो वह जो सिटी के अन्दर लगे हुए होते हैं उनके दिमाग में एक ही भूत रहता है कि शहर वाले विधायक ही विधायक हैं, गांव वाले विधायक, विधायक ही नहीं हैं। तो उनकी पोस्टें अलग करके विधान सभावाइज की जाये तो बिलकुल काम होगा और समस्या का समाधान होगा। हम गांव के

(श्रीमती कमसा)

अन्दर रहते हैं, हमेशा शहर के अन्दर जाना ही नहीं चाहते, न हमें शहर पसन्द है। इसलिए मैं चाहती हूं कि जो क्षेत्र गांवों के अन्दर है, वहां जो पोस्टें हैं, एक्स ईएन है, ए ईएन है, वे पोस्टें गांवों के अन्दर होनी चाहिए।

गुलाबजी भाई साहब यहां नहीं हैं, पंचायती राज मंत्री महोदय, उनसे भी मेरा निवेदन है कि पंचायत समिति की मीटिंग होती है तीन महीने में एक बार, तो आप ताज्जुब करोगे, क्योंकि मैं भी प्रधान रही हूं और हर पंचायत समिति की मीटिंग के अन्दर जाती हूं, ए ईएन के अलावा कोई कर्मचारी नहीं आता है। जब तक पंचायत समिति की मीटिंग और पंचायतें सक्षम नहीं होंगी, तब तक कोई ढांचा, मूलभूत, आगे नहीं बढ़ सकता है। मेरा आपके माध्यम से यह भी निवेदन है सभापति महोदय, हर मीटिंग के अन्दर जो कर्मचारी नहीं आयें, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करके पंचायतों को सशक्त बनाया जाये। धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत। जय जय राजस्थान।

(19.00 बजे)

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, 2014-15 का परिवर्तित बजट हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री सम्माननीया वसुन्धरा राजेजी सिंधिया ने यहां पर रखा। इससे पूर्व भी लगातार 5 वर्ष के बजट हम लोगों ने देखे। सबसे बड़ी खासियत इस बजट की जो रही, वह खासियत आर्थिक विकास और इस राजस्थान के विकास की तो है ही, लेकिन जो हमने देखा, देखकर बड़ा अच्छा लगा और एक महिला होने के नाते बड़ी खुशी हुई कि यह राजस्थान वीरों का प्रदेश है, वीरांगनाओं का प्रदेश है। जब पूरे बजट को माननीय सी एम महोदया ने पढ़ा और पूरे बजट में एक बार भी, एक बूंद, पानी का एक घूंट भी उन्होंने नहीं लिया तो बड़ी खुशी हुई, क्योंकि हमने देखा था, पूर्व सी एम साहब ने जब बजट भाषण दिया तो एक वर्ष तो लगातार, 17 बार लगातार पानी का घूंट पीया, 17 बार पानी उन्होंने पिया। इससे यह साबित होता है कि वास्तव में हमारी सी एम साहिबा का कितने जज्बे से इस राजस्थान का विकास करने में, इस राजस्थान को आगे बढ़ाने में उनका योगदान रहेगा।

मैं तो कहना चाहूंगी कि जब उन्होंने चारभुजानाथ से, उदयपुर सम्भाग से 14 हजार किलोमीटर की यात्रा करके, सुराज संकल्प यात्रा उन्होंने शुरू की

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

और उन्होंने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंचकर इस राजस्थान की गरीब जनता की, किसान की, बेरोजगार भाइयों की, महिलाओं की, सबकी समस्याएं उन्होंने देखीं। वास्तव में उनके मन में पीड़ा थी और कुछ कर गुजरने के लिए, इस राजस्थान की जनता के लिए, उनके मन में एक दर्द था और उस दर्द को उन्होंने देखा। तो वास्तव में उसी का प्रतिफल है कि इस राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इतना बड़ा समर्थन और आशीर्वाद दिया है।

मैं तो कहना चाहूंगी कि उन्होंने जो बजट रखा, उस बजट में महिलाओं का ध्यान भी उन्होंने रखा, किसानों का ध्यान भी रखा, बेरोजगार भाइयों का भी रखा। सबका ध्यान रखते हुए, हर गरीब का ध्यान रखते हुए, इस बजट को उन्होंने प्रस्तुत किया। मुझे मालूम है कि विपक्ष का काम मात्र उसकी आलोचना करना है, लेकिन मैं निवेदन करना चाहती हूं कि यह बजट राजस्थान सरकार का है, उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि हम बुराई तो करें, लेकिन इस तरह की शुरुआत माननीया वसुन्धराजी ने की है और यह हमारा ट्रेलर है तो आगे हमारी पिक्चर क्या होगी, यह उनके मन में सवाल आना चाहिए।

मैं तो कहना चाहूंगी, बहुत-बहुत धन्यवाद माननीया वसुन्धराजी को देना चाहूंगी, हमारी सी एम साहिबा को देना चाहूंगी कि उन्होंने चम्बल नहर परियोजना की जो दायीं मुख्य नहर हमारे कोटा में है, उसके जीर्णोद्धार के लिए, उसके सुदृढ़ीकरण के लिए 75 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में रखा। इस बात के लिए तहेदिल से और मन से उनको धन्यवाद देती हूं।

सबसे बड़ा धन्यवाद उनको देना चाहूंगी, गोपालन बोर्ड जो उन्होंने गठित किया और गौसंवर्धन के लिए हमारी सरकार की जो प्राथमिकता उन्होंने रखी है, इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं। क्योंकि हम सबको मालूम है कि जब भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया, अपने हाथ पर उठाया और उनकी आंखों से जब आंसू आये तो द्वारपालों ने उनसे यह भी पूछा कि हे भगवान, हमें यह बताइए कि आपकी आंखों में आंसू क्यों आये? तो स्वाभाविक ही उनके मुख से निकल पड़ा कि मुझे इस बात का दुःख है कि आने वाले समय में इस गौसंवर्धन के लिए कौन क्या करेगा, इस गौमाता का क्या होगा? मुझे लगता है कि इस राजस्थान सरकार ने यह जो निर्णय लिया है इससे कहीं न कहीं गौरक्षा के लिए तो मन में एक संकल्प यह जनता लेगी। लेकिन जितनी भी हमारी गौशालाएं हैं, जो वास्तव में आर्थिक दृष्टि से जूझ

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

रही हैं, जिन गायों को चारा नहीं मिल पाता, यह सारी व्यवस्था इस गोपालन के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से होगी। मैं इस बात के लिए भी उनको धन्यवाद देना चाहती हूं।

मैं इस बात के लिए भी धन्यवाद देना चाहती हूं कि कोटा मेडिकल कालेज से सम्बद्ध अस्पतालों के लिए जो सुपर-स्पेशलटी विंग स्थापित करने की उन्होंने इस प्रस्ताव में घोषणा की है, इसके निमित्त 150 करोड़ रुपये उन्होंने प्रस्तावित रखे हैं। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद देंगे, क्योंकि मुझे मालूम है कि कोटा जिले के ही नहीं, बल्कि झालावाड़ जिला, बारां जिला, बूंदी जिला, इन आसपास के जिलों से वहां की गरीब जनता वहां इलाज के लिए आती है। हम यह भी सोच सकते हैं कि हमारा जो एम डी एस हास्पिटल है, वह बीच में बना हुआ है, वहां तक पहुंचने में ज्यादा समय लगता है और यहां पर पहुंचने में इतना आसान रास्ता, बिलकुल ओपन रास्ता है। इस बात के लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं कहना चाहूंगी कि इसके निमित्त हमें बहुत सारे विभाग इस मेडिकल कालेज में मिलेंगे। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

दूसरा धन्यवाद देना चाहूंगी कि झालावाड़ और कोटा जिला हाड़ौती का क्षेत्र रहा है, यह वास्तव में ऐसा क्षेत्र रहा है जिसने अनेक परेशानियों का सामना भी किया है, उनसे जूझना भी इनको पड़ा है, लेकिन इसके निमित्त हाड़ौती की जनता ने इतना जबर्दस्त आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को दिया है, तो उसके निमित्त अगर माननीया वसुन्धरा राजेजी, मुख्य मंत्री महोदया ने झालावाड़ को कुछ दे दिया, बारां को कुछ दे दिया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वहां की जनता ने जबरदस्त आशीर्वाद दिया है। उन्होंने ए डी जे कैम्प कोर्ट संचालित है, उसको नियमित कोर्ट की घोषणा की है और जिला न्यायालय परिसर में पुस्तकालय की स्थापना की घोषणा की है, इस बात के लिए उनको धन्यवाद देना चाहूंगी। कैंसर वार्ड का सेंटर झालावाड़ के अन्दर बनेगा। इससे बहुत ज्यादा लाभ मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की जनता को मिलेगा, क्योंकि खनन क्षेत्र है और सारे श्रमिक, मजदूर वहां निवास करते हैं।

मैं कहना चाहूंगी कि लगातार 5 वर्ष तक हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जनता बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा के लिए जूझती रही। हम लोग भी लगातार इस राजस्थान के सर्वोच्च सदन में इस बात को उठाते रहे, लेकिन न जाने, कितनी बार इस विधान सभा में किसी भी बात को उठाने

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

के बाद भी यदि किसी समस्या का समाधान न हो तो मन को बड़ा दुःख होता है, बड़ी ठेस पहुंचती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि कोटा से झालावाड़ तक जो नेशनल हाइवे है, उस रोड की जो दुर्दशा है, उसको देखकर मन को बड़ी पीड़ा होती है। मैं निवेदन करना चाहूंगी कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी, उसने सरकार बनते ही उस रोड की जो दुर्दशा थी, हम चार-चार, पांच-पांच घंटे में कोटा से रामगंजमण्डी, 70-75 किलोमीटर की दूरी को तय कर पाते थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उन्होंने इसको रिपेयर किया। लेकिन, माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि 60 किलोमीटर का टुकड़ा जो वन विभाग के अन्तर्गत आता है, उस टुकड़े की जो दुर्दशा आज बनी हुई है, 16-16 घण्टे तक जाम रहता है। कोटा स्टोन के व्यापारी, झालावाड़ तक के सारे भारी वाहन वहां से गुजरते हैं और 16-16, 17-17 घण्टे तक जाम लगता है। मुझे लगता है, किसी को बोल दिया जाय कि आपको यहां से झालावाड़ जाना है, कोटा से रामगंजमण्डी जाना है, तो पहले ही अपने पैर पीछे खींच लेगा। मेरा आप लोगों से इस सदन के माध्यम से निवेदन है, सरकार से निवेदन है कि पिछले एक वर्ष में इस 60 किलोमीटर टुकड़े में 58 मौतें हो चुकी हैं, इतने एक्सीडेंटल केस वहां पर होते हैं, मेरा सदन से करबद्ध निवेदन है कि तुरन्त प्रभाव से, इसका जो भी पेचवर्क हो, वैसे तो रोड बचा ही नहीं, लेकिन इसका दुरुस्तीकरण हो जाए तो जनता हमें दुआएं देगी।

मैं और निवेदन करना चाहूंगी कि कृषि के क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छे कदम उठाये हैं और उन्होंने यह भी कहा है कि डार्क जोन में कोई किसान तुरन्त प्रभाव से कनेक्शन लेना चाहे तो उसे कनेक्शन दिये जाएंगे। लेकिन जिस तरह की राशि उससे जमा करवायी जाएगी, मुझे लगता है, हमारा किसान वैसे भी पिछड़ा हुआ है और सारी आपदा जो भी आती है वह किसान पर आती है, यह किसान के हित में नहीं है। इस पर हमें विचार करना चाहिए।

जो घोषणा माननीय सी एम महोदया ने की, उन्होंने कहा कि हम 31 दिसम्बर, 2013 तक जो कृषि कनेक्शन लम्बित हैं 3 लाख 11 हजार, उन्होंने टारगेट रखा है 2014-15 तक 40 हजार देने का, और 31 दिसम्बर, 2013 तक जो 3 लाख 11 हजार लम्बित हैं, उन्हें भी दिये जाएंगे। यह बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है और इस बात के लिए भी मैं उनको साधुवाद देना चाहती हूं।

एक और निवेदन करना चाहूंगी कि रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

डार्क जोन क्षेत्र में आता है और वहां किसान किस तरह से खेती करता है। पिछली बार जब वहां पर सोयाबीन की फसल नष्ट हुई, उसका जो मुआवजा किसानों को मिला, उसमें इस तरह के प्रावधान अधिकारियों और सरकार द्वारा जोड़ दिये गये कि जो कुएं से खेती करता है उसे हम सिंचित नहीं मानेंगे और जहां नहरी क्षेत्र है उसे ही सिंचित माना जाएगा। यानी कि रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र के किसानों का यह कहकर नुकसान कर दिया गया कि वह असिंचित क्षेत्र है। मेरा इस सदन के माध्यम से, सभापति महोदय के माध्यम से कृषि मंत्रीजी से निवेदन है कि इसमें भी कुछ इस तरह का परिवर्तन किया जाए। दो मिनट मैं और लूंगी।

एक निवेदन और मैं करना चाहूंगी। वैसे तो बिजली के क्षेत्र में कितनी ही विकट परिस्थिति से हम लोग जूझ रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी जो सुधार सरकार बनने के बाद हुआ है, उसके लिए धन्यवाद देना चाहूंगी, लेकिन फिर भी हमें बहुत कुछ सुधार करने की आवश्यकता है, यह मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है। क्योंकि लगातार ट्रिपिंग होना और यह सारी परेशानी आ रही है, तो जनता बड़ी दु:खी है। गांवों में यह स्थिति है कि अगर तीन दिन भी थ्री फेज बिजली उनको नहीं मिलती है तो गांवों से 20 किलोमीटर दूर चलकर आटा पिसवाने के लिए लाना पड़ता है। यह स्थिति बनी हुई है। इसलिए इसमें भी हम लोग कुछ सुधार करें।

दूसरा निवेदन करना चाहूंगी कि जो पिछली सरकार ने जो बजट में घोषणाएं की थीं, वे भी आपने देखी थीं। माननीय सभापति महोदय, सरकार ने आनन-फानन में घोषणाएं तो कर दीं लेकिन घोषणा करने के बाद यदि उन पर अमल नहीं होता तो जनता को कितना बुरा लगता है। इसका एक जीता-जागता उदाहरण बताना चाहूंगी कि अण्डरपास के लिए जो हमारी रामगंजमण्डी नगरपालिका है, वहां पर अण्डरपास के लिए उन्होंने स्वीकृति दी और उसके बाद खुद माननीय सी.एम. साहब जाकर उस अण्डरपास का शिलान्यास करके आते हैं, लेकिन उसका कोई बजट सरकार ने नहीं दिया। तो मैं वर्तमान सरकार से निवेदन करती हूं कि रामगंजमण्डी ऐसी जगह बसी हुई है कि चारों तरफ से उसके रास्ते कट जाते हैं। जो हमारी रामगंजमण्डी नगरपालिका में रेलवे लाइन निकली हुई है, उसके नीचे रेलवे का नाला है, उस नाले के नीचे से सारी जनता को गुजरना पड़ता है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इसके बजट की भी सरकार तुरन्त व्यवस्था करे।

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

माननीय सभापति महोदय, रामगंजमण्डी में पीने का पानी नहीं है। दो मिनट। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बहुत अच्छी योजना बनाई। मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि जब पिछली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो उन्होंने पचपाड़ पेयजल योजना, चम्बल का पानी रामगंजमण्डी की धरती पर लाने का प्रयास किया और उस योजना को पूरा किया। लगभग 195 करोड़ रुपये की वह हमारी योजना थी। लेकिन पिछली सरकार ने और कर्मचारियों, अधिकारियों ने उसकी सार-सम्भाल के अभाव में उस योजना की यह स्थिति कर दी कि गांवों की जनता एक बूंद पानी के लिए तरसती है। इसलिए मेरा इस सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन है कि हमारी जो साथलखेड़ी, क्योंकि आहू नदी, इतनी बड़ी नदी हमारे सुकेत के अन्दर, रामगंजमण्डी के अन्दर बहती है, अगर वहां से कोई योजना बने तो मुझे लगता है कि रामगंजमण्डी, साथलखेड़ी, सुकेत और मोड़क, पूरा विधान सभा क्षेत्र उससे पानी पी सकता है। 16 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी वहां के कर्मचारियों ने भिजवाया है, उसे भी स्वीकृत करें।

आपने समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री विद्याशंकर नन्दवाना।

श्री विद्याशंकर नन्दवाना (पीपल्दा): माननीय सभापति महोदय, 14 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा इस सदन में वर्ष 2014-15 का बजट रखा गया। 15, 16 और 17 तारीख को पक्ष और विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने तरीके से इस प्रस्ताव के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रकट किये गये। मैं यह कहना चाहूंगा कि पहली बार राजस्थान सरकार का एक ऐसा बजट आया है जिसे सभी समाचार पत्रों ने सराहा है, सभी इलेक्ट्रोनिक मीडिया के लोगों ने भी इसकी प्रशंसा की है। समाज के सभी तरफ से, इस बजट के सभी पहलुओं पर लोगों ने अपनी अच्छी प्रतिक्रियाएं दी हैं।

माननीय सभापति महोदय, यह हमारा, मैं कहूंगा कि दुर्भाग्य ही है कि आजादी के 66 साल बाद, जहां एक राजनैतिक दल के रूप में 50 साल तक जिस दल ने इस प्रदेश की शासन व्यवस्था संभाली और उस 50 साल के प्रभाव के बाद, पिछले 5 वर्ष तक भी जब उसी दल की सरकार रही, लेकिन राजस्थान की स्थिति इस प्रकार की बनी रही कि जहां स्कूल थे वहां अध्यापक नहीं थे, जहां डाक्टर थे वहां दवाइयां नहीं थीं। सरकार द्वारा लगातार औषधालय,

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

चिकित्सालय खोले गये पर स्टाफ के अभाव में जो व्यवस्थाएं मिलनी चाहिए थीं वे व्यवस्थाएं नहीं मिल पाईं। आधारभूत आवश्यकताओं के नाम पर जहां हम बिजली की बात करें, पानी की बात करें, प्रदेश की सड़कों की बात करें, शिक्षा की बात करें, शिक्षा का तो यह स्तर रहा कि राजस्थान में जहां राइट-टू-एजुकेशन के नाम पर कक्षा 1 से 8 तक बिना परीक्षा लिये पास करने की परम्परा बनी और उसी का परिणाम रहा कि धीरे-धीरे विद्यालयों से बालकों की संख्या कम होती चली गई। अभिभावकों की सरकारी विद्यालयों के प्रति लगातार रुचि घटती जा रही है और इस वर्ष हमारा जो सेकण्डरी का परिणाम आया, वह बड़ा ही चिंताजनक है।

माननीय सभापति महोदय, मैं यहां कहना चाहूंगा कि जहां सार्वजनिक सड़कों की बात इस सदन में माननीय सदस्यों के माध्यम से कई बार निकल कर आई कि जब केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधान मंत्री थे, तब माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के विकास का एक सपना देखा और उस सपने के तहत देश के उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम को जोड़ने के लिए एक स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का प्लान हिन्दुस्तान की जनता के सामने रखा। बी.ओ.टी. में उस सड़क की योजना पर जब विचार हुआ तो कांग्रेस के कई माननीय सदस्यों द्वारा लोक सभा में टोल लगने पर काफी गम्भीरता से उसका विरोध किया गया। लेकिन आज हिन्दुस्तान की जनता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी को उनके देश में किये गये योगदान के लिए और प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क रोजगार योजना के तहत देश के प्रत्येक गांव, ढाणी को जोड़ने के लिए, जो उन्होंने 2013 तक देश के सभी गांव और ढाणियों को जोड़ने की योजना बनाई, वह अपने आप में एक कीर्तिमान रहा। यह हमारा दुर्भाग्य है कि यू.पी.ए. सरकार ने उस विषय पर आगे चिंता नहीं की और आज जिस प्रकार से रोड जुड़ने चाहिए थे, वे रोड जुड़ नहीं पाये।

मैं यहां कहना चाहूंगा कि माननीय वसुंधरा राजेजी ने राजस्थान के सभी जिलों की सारी सड़कों की व्यवस्था को सुराज संकल्प यात्रा के दौरान अपनी आंखों से देखा और उनके मन में एक पीड़ा थी कि इस राजस्थान को अगर विकास के लिए और आगे बढ़ाना है तो सबसे पहले इस प्रदेश की रोड अच्छी हों, गांवों की कनेक्टिविटी बढ़े, लोगों को यातायात की उपलब्धता मिले और उसी को लेकर माननीय मुख्य मंत्री द्वारा राजस्थान में राज्य के सभी

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

स्टेट हाइवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड और 5,000 किलोमीटर की ODRs और टूरिस्ट तथा धार्मिक महत्व की सड़कों को शामिल करते हुए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में 20 हजार किलोमीटर की सड़कें बनाने का कार्यक्रम अपने हाथ में लिया। इसके अतिरिक्त, राज्य में 6 प्रमुख मार्गों पर एक हजार किलोमीटर से अधिक लम्बाई की सड़कें ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर के रूप में विकसित की जाने की योजना बनाई। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्री द्वारा, केवल यह सपना सपना ही नहीं रहे, इसके लिए प्रयास भी मन में बनाकर राज्य सरकार द्वारा 7 हजार किलोमीटर सड़कों के डी पी आर बनाने का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और 2017 तक प्रदेश में 20 हजार किलोमीटर की सड़कों का निर्माण कराना और इस कार्यक्रम के निमित्त रोजाना 15 किलोमीटर लम्बाई की सड़कें बनें, इस योजना के रूप में कार्य करना निश्चित किया। राज्य के 9 हजार से अधिक ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर 0.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर लम्बी सड़क का चयन कर आगामी तीन वर्षों में आर सी सी सड़कों तथा नालियों का निर्माण कर ग्रामीण गौरव पथ के रूप में विकसित किया जाना, ग्रामीण विकास के लिए एक सपने से अधिक है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में 250 से 499 की आबादी को सड़कों से जोड़ने की बात और इसके लिए 509 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान रखना, यह भी इस कार्य के लिए अपना योगदान है।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा 3,173 नये गांव एवं ढाणियों को 2014 तक शुद्ध पेयजल पिलाने की व्यवस्था कराने का सपना, इस राजस्थान के लिए अपने आप में एक कीर्तिमान है। जहां हम देखते हैं कि लगातार हैण्डपम्प के बाद हैण्डपम्प खोदे जा रहे हैं और हमने यह सपना नहीं बनाया, हमने कोई कार्ययोजना नहीं बनाई कि हम इस राजस्थान को हैण्डपम्पों से मुक्ति दिलायेंगे, लेकिन यह पहली बार इस प्रकार की कार्ययोजना हाथ में लेकर माननीया मुख्य मंत्री द्वारा एक इतिहास कायम किया गया है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में जहां चारों तरफ नदियां बहती हैं और बड़ी संख्या में गांव फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिए विवश होते हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदया द्वारा फ्लोराइड-ग्रसित गांवों को मुक्ति दिलाने की योजना एवं शुद्ध पेयजल पिलाने की योजना अपने हाथ में ली गयी। यह भी एक महत्वपूर्ण कार्य किया है।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

प्रदेश में सिंचाई के संसाधनों को बढ़ावा देना, लघु और वृहद सिंचाई परियोजनाओं पर एक साथ काफी बड़े स्तर पर काम करना, यह एक महत्वपूर्ण काम है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में इसका बहुत बड़ा कमाण्ड एरिया है जहां चम्बल की मुख्य वितरिकाएं बहती हैं, लेकिन पिछले 50 वर्षों में उनके सुदृढ़ीकरण के लिए जो कार्य होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया, जिसके अभाव में 30 से 40 प्रतिशत पानी वेस्टेज बहकर नदी-नालों में निकल जाता है। माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने 75 करोड़ रुपये का प्रावधान इस ओर दिया है। यह भी एक साहसिक कार्य है।

प्रदेश के शिक्षा स्तर को बढ़ाने के लिए समग्र प्रयास किये गये हैं, राज्य में 15 नये महाविद्यालय खोलने की बात की गई है, मैं यहां अनुरोध करूंगा कि कोटा जिले के सभी ब्लाक्स में महाविद्यालय हैं, मेरे निर्वाचन क्षेत्र के दो ब्लाक, सुल्तानपुर और इटावा, इससे वंचित हैं। मैं यहां यह कहना चाहूंगा कि इटावा एक ऐसा ब्लाक है जो मध्य प्रदेश की सीमाओं से जुड़ता है और जहां पूरे जिले का सर्वाधिक शिक्षा का स्तर है। यदि यहां राजकीय महाविद्यालय खोला जाता है तो अति उत्तम होगा।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का अधिकांश भाग कृषि आधारित है। यहां कृषि को बढ़ावा देने के लिए, इस वित्तीय वर्ष में 3,089 हेक्टेयर क्षेत्रफल में जलग्रहण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित करने के लिए 1,392 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा जाना, यह अपने आप में सराहनीय कदम है।

माननीय सभापति महोदय, जहां चिकित्सा क्षेत्र की हम बात करें तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र सभी परिवारों हेतु स्वास्थ्य बीमा की योजना लागू करना, जिसका लाभ राजस्थान के लगभग 67 प्रतिशत परिवारों को हो सकेगा, यह एक अभूतपूर्व कार्य है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य की 248 पंचायत समितियों में से 186 पंचायत समिति शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई हैं। राज्य सरकार द्वारा सभी पंचायत समितियों में अंग्रेजी माध्यम से माडल स्कूल खोलना व वर्तमान में जहां 3,439 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय हैं, सरकार द्वारा शेष बचे हुए सभी पंचायत मुख्यालयों पर चरणबद्ध माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने की योजना, अपने आप में एक कीर्तिमान है।

(श्री विद्याशंकर नन्दवाना)

माननीय सभापति महोदय, आज समाचार पत्रों में एक समाचार प्रकाशित हुआ, दुनिया भर के देशों में सबसे ज्यादा गरीब आबादी, यह बात संयुक्त राष्ट्र संघ की एक नई रिपोर्ट में कही गई है, शताब्दी विकास लक्ष्य रिपोर्ट 2014 के मुताबिक दुनिया के समस्त निर्धनतम लोगों का 32.9 प्रतिशत हिस्सा भारत में रहता है। यह रिपोर्ट अपने आप में देश और प्रदेश की दुर्दशा की ओर ध्यान आकर्षित करती है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार यदि बी पी एल परिवारों का पुन: सर्वे करे तो प्रदेश में आज भी दो से तीन गुणा बी पी एल परिवारों की संख्या बढ़ सकती है। यदि सरकार आज भी पुन: वृद्धावस्था या अन्य पेंशन योजना के लिए शिविर लगाये तो यह संख्या भी आज लाखों में बढ़ सकती है। यह बात मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि हमें आज प्रदेश में पुरुषार्थ को बढ़ावा देने के लिए अन्य योजनाओं पर भी काम करने की आवश्यकता है। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि आपके द्वारा गुरु गोलवलकर योजना में 50 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया है, इसे बढ़ाकर 200 करोड़ रुपया किया जाये। चूंकि जब तक हम सहभागिता के क्षेत्र में काम नहीं करेंगे, तब तक इस प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं मिलेगा।

मैं, माननीय सभापति महोदय, एक बात और निवेदन करना चाहूंगा कि मेरा विधान सभा क्षेत्र मध्य प्रदेश की सीमा से लगता है और कोटा से मध्य प्रदेश की सीमा तक बी ओ टी में रोड बना है। उसके आगे पार्वती नदी बीच में दोनों प्रदेशों की सीमा को जोड़ती है। उसके बाद, श्योपुर के लिए भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मेगा हाइवे का निर्माण किया गया है। वर्षा ऋतु में लगातार चार माह तक आवागमन के साधन बाधित होते हैं। चूंकि बीच में नदी पर जो पुलिया बनी हुई है, वह काफी नीची और पुरानी पुलिया है, इसे ऊंची बनाने के लिए भी कार्य किया जाये।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में काफी बड़ा क्षेत्र जंगल से जुड़ा हुआ है। इसलिए उसमें बार-बार कंटीले तारों की योजना पर भी...। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री पूरणमल सैनी।

श्री पूरणमल सैनी (खेतड़ी): सर्वप्रथम माननीय सभापतिजी का इस आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2014-15 पर वाद विवाद के लिए समय देने के लिए आभार व्यक्त करते हुए, मैं संस्कृत के एक श्लोक के माध्यम से कहना

(श्री पूरणमल सैनी)

चाहूंगा कि ''शैले शैले न माणिक्य, मोतीकम् न गजे गजे; साधु नहीं सर्वत्र, चन्दन न वने वने।'' अर्थात्, उस मोती रखने वाले पर्वत के समान कठोर हृदय वाली, उस मणिधारी सर्प की तरह रोशनी देने वाली, उस 60,000 हाथियों की ताकत रखने वाली की तरह 163 सहयोगी साथियों की ताकत रखने वाली, वह उस चन्दन की लकड़ी देने वाले वन की तरह दयालु स्वभाव वाली, सदन की नेता एवं इस प्रदेश की मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धरा राजे को साधुवाद व धन्यवाद देते हुए, इसके लिए मेरा कोई पक्ष और विपक्ष नहीं, बहुजन समाज पार्टी में काम करते हैं। पिछले दस वर्ष से लगातार कांग्रेस के राज को भी देखते रहे और बी जे पी के राज को भी देखते रहे हैं। इस सदन में पक्ष और विपक्ष की एक परम्परा रहती है कि जब सत्ता पक्ष कोई करता है तो प्रतिपक्ष के नेता और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य उनकी बुराई करने में अपना विश्वास रखते हैं। लेकिन हम बहुजन समाज पार्टी के लोग काम में विश्वास रखते हैं। हम कहना चाहेंगे कि इस सदन की नेता, प्रदेश की मुख्य मंत्री महोदया ने आय व्ययक के, बजट-2014 के बिन्दु संख्या-4 में कहा है और उससे महसूस होता है, हम सब लोगों को पार्टनर के रूप संज्ञा देते हुए कहा है कि हम सब 200 के 200 लोगों की जिम्मेदारी बनती है इस प्रदेश के विकास की। इसलिए उनका आभार व्यक्त करते हुए और उनको साधुवाद देते हुए हम हमारी बात रखना चाहेंगे और कुछ सलाह भी देना चाहेंगे।

हमारी बात में यह है कि माननीया वसुंधराजी ने इस प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए अपना बजट तैयार किया, इस प्रदेश को चलाने के लिए। उसमें माननीया मुख्य मंत्री ने बिन्दु संख्या-2 में कहा है, स्वयं ने माना है कि ''आजादी के 65 साल बाद जब हम पोस्ट कार्ड से ई-मेल तक, ट्रंक काल से विडियो काल तक और बैलगाड़ी से मेट्रो तक का फासला तय कर चुके हैं, आम आदमी बिजली, पानी, सड़क, डाक्टर और शिक्षकों की बुनियादी समस्याओं से आज भी जूझ रहा है।'' यह माननीया सदन की नेता ने माना है। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस 67 वर्ष की आजादी के बाद राज तो किसी न किसी पार्टी के लोगों ने किया ही है। इन बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति जब हम या हमारे दूसरे दलों के नेतागण आज तक नहीं कर पाये हैं, इसका कोई न कोई कारण तो रहा ही है। मेरी तरफ से अपील करना चाहूंगा और इन्होंने कोशिश भी की है बजट में कि बुनियादी ढांचे को तैयार किया जाए, और बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं आवश्यक समझता हूं, 1,500 या 2,000

(श्री पूरणमल सैनी)

रुपये उन गरीब महिलाओं के खाते में भिजवाने से उनका भला नहीं हो सकता, चाहे वह कांग्रेस की सरकार ने 500 भेजे या 1,500 भेजे और चाहे यह सरकार 2,000 भिजवाये, इस प्रदेश की जनता का भला, उस गरीब का भला तब हो सकता है जबकि उस गरीब के पढ़े-लिखे परिवार के एक सदस्य को, हर हाथ को रोजगार देने की बात, अगर एक बार में नहीं कर सकते तो उस जैसे चयनित परिवारों को चिह्नित करके भी लगाया जाएं, उस गरीब परिवार के बेटे-बेटी को नौकरी दी जाएगी तो निश्चित रूप से अपने सभी तरह के काम वह उसके माध्यम से कर लेगा। इन्होंने प्रयास भी किया है, स्किल यूनिवर्सिटी खोलकर के लोगों को उसके लिए तैयार करने के लिए। लेकिन मैं चाहूंगा कि और भी जितना ज्यादा इसमें समायोजन किया जाए और कमाने की ताकत पैदा की जाए, उसके लिए काम किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, एक मेरा यह निवेदन है कि प्रदेश के 52 प्रतिशत से अधिक निवासी अभी भी कृषि पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर हैं। यह बात सदन की नेता, मुख्य मंत्री महोदया ने अपने बजट भाषण में बिन्दु संख्या-3 पृष्ठ संख्या-2 पर कही है और माना भी है। इसके बावजूद भी, कृषि से जीवनयापन करने वाले उन 52 प्रतिशत लोगों के लिए बजट में खेती सम्बन्धी कोई प्रावधान नहीं रखा है। जबकि सदन के सभी माननीय सदस्यों सहित पूरे प्रदेश की जनता को पता है कि प्रदेश में पूर्ण रूप से सूखा चल रहा है। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से अपील करना चाहूंगा कि इस बजट में सूखे से लड़ने के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बिन्दु संख्या-99 में नई खनन नीति शीघ्र ही घोषित करने की बात माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने कही है तथा प्रदूषण को समाप्त करने के लिए जीरो वेस्ट खनन को बढ़ावा देने की बात कही है। यह सराहनीय है। किन्तु क्या सरकार अवैध खनन को रोकने के लिए प्रतिबद्ध है, यह उसमें नहीं कहा गया है।

साथ ही, माननीया सदन की नेता ने खनिजकर्मियों के अन्य अधिकारों को भी सुनिश्चित करने की बात कही है; जबकि माननीय सदन की नेता ने उस गरीब किसान का इसमें कोई उल्लेख नहीं किया है। जिस क्षेत्र में खनन कार्य को बढ़ावा दिया जाएगा और उन गरीब लोगों को, क्योंकि बिना पट्टे के

(श्री पूरणमल सैनी)

कम से कम 40 प्रतिशत लोग गांवों में गैर-आबादी क्षेत्रों में बसे हैं और बिना पट्टे के बसे हैं। सरकार की नीति में यह बात है कि किसी भी गैर-आबादी क्षेत्र का कोई घर भी है तो उससे केवल 45 मीटर दूर खनन का कार्य करने के लिए खनिजकर्मियों को अनुमति दी जाती है, जो उस गरीब के घर के लिए बिलकुल ही खतरे का सूचक है। क्योंकि वह जुताई के लिए खेत वहीं होते हैं, उसके पशु वहीं चरते हैं और उसका घर वहीं होता है, तो उनको पट्टियां टूटने का भी भय होता है। तो मैं माननीया सदन की नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि खनिज की नई नीति में वहां के स्थानीय लोगों के लिए कोई न कोई प्रावधान इसमें रखा जाए, उनके अवस्थान के लिए कोई आर्थिक दृष्टि से उनको संवर्द्धन दिया जाए।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस खनिज नीति के द्वारा, खनिज कार्य के द्वारा राज्य सरकार को जो राजस्व की वसूली होती है, उसमें से सन् 2011 से पंचायतों को केवल एक प्रतिशत राशि दी जाती है, जो मैं कहता हूं कि ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। क्योंकि जब खनन कार्य वहां किया जाता है तो उस पंचायत क्षेत्र की, उस स्थानीय निकाय क्षेत्र की सड़कें टूटती हैं, वहां के जल का दोहन होता है और वहां के मकानों का खण्डहर रूप बन जाता है। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि स्थानीय क्षेत्र के विकास के लिए, खनिज नीति को अगर बढ़ावा दिया जाता है, तो कम से कम राजस्व वसूली का एक प्रतिशत से बढ़ाकर के पचास प्रतिशत स्थानीय निकायों के लिए किया जाना चाहिए, जो बजट में डालने के लिए निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने बजट भाषण में जनजातिय क्षेत्र में निवेश और उस क्षेत्र के विकास के संकेत दिये हैं, किन्तु आदिवासियों का विकास कैसे सम्भव होगा? खनन क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों की गरीबी, लाचारी, विस्थापन, आदि की समस्या को भी बजट में डाला जाए।

साथ ही, खनिज की बात कर रहा हूं और सरकार को सुझाव देना चाहूंगा कि हम विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी से आये हैं, तो विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में आखावाली खानों को भी, निश्चित रूप से किसी न किसी लीज के माध्यम से उनको फरमाया जाए।

माननीया सदन की नेता ने पी पी पी मोड के माध्यम से पिछली सरकार की तरह और उसी तर्ज पर यूनिवर्सिटी के लिए जो बात कही थी, मैं तो पीड़ित रहा हूं, मेरे क्षेत्र खेतड़ी की जनता पीड़ित रही है, पिछली बार बी ओ

(श्री पूरणमल सैनी)

टी में, 2010 में टूटी एक सड़क को उन्होंने बी ओ टी में डाल कर और आम पब्लिक को स्वीकृति की कापी दिखा-दिखा कर और हर चुनाव में काम लेते रहे, चाहे वह नगरपालिका का चुनाव आया, चाहे पंचायत समिति और पंचायतों का चुनाव आया; जब-जब वोट की जरूरत पड़ी, उपयोग किया; वैसे ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पी पी पी मोड में भी वह सरकार नहीं कर पाई तो क्या इस सरकार से हम अपेक्षा नहीं करें? दो राज्यों को जोड़ने वाली वह राजा-महाराजाओं के समय की सड़क 2010 से टूट कर और उस तरह से विभाजन किये हुए हैं दो राज्यों का जैसे दो देशों के बीच होता है। दो मिनट मात्र और।

माननीय सभापति महोदय, समय के अभाव में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कह कर, मेरे क्षेत्र की दो-चार चीजों की मांग करना चाहूंगा। सड़क के लिए, जैसे मैंने कह दिया। विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी में एक मात्र नगरपालिका है, उस नगरपालिका में पेयजल की इतनी विकट समस्या है। मैं वैसे भी सदन में महसूस करता हूं कि इस प्रदेश में पांच वर्ष तक उस क्षेत्र के विधायक पानी और बिजली के मंत्री रहे, उसके बावजूद भी दस-दस दिन से विधान सभा क्षेत्र खेतड़ी की नगरपालिका में आज की तारीख में पानी की सप्लाई की जा रही है। तो मैं अपील करना चाहूंगा, बजट में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है, सुनते हैं और लोग बताते हैं कि कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना के माध्यम से खेतड़ी को पानी पिलाया जा रहा है, तो मैं निवेदन करना चाहूंगा पी एच ई डी मंत्रीजी से यथाशीघ्र उस कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना को हमारे यहां खेतड़ी में भिजवा कर पेयजल समस्या का निवारण किया जाए।

मुझे बोलने का अवसर दिया, अंत में मैं एक दोहे के माध्यम से दुबारा कहना चाहूंगा कि 'आ जा सहेली, तासु रि पुता जननी भरतार, ताके सुत के मित्र को भजिये बारम्बार।' हम निवेदन और अपील करना चाहेंगे, सदन की नेता अकेली के लिए नहीं, आप सबकी सरकार के लिए, आप सब 163 के लिए, लेकिन उस सरकार से अलग व्यवहार करते हुए और इसकी अभ्युक्ति यह थी कि बकरी की मित्र भेड़ का शत्रु भरभूट होता है और भरभूट को जन्म देने वाली पृथ्वी होती है और पृथ्वी का पति इन्द्र भगवान को माना गया, और इन्द्र भगवान का पुत्र अर्जुन को माना गया, अर्जुन का मित्र श्रीकृष्ण को माना गया, उसको बार-बार भजिये। वैसे ही आप 163 के 163 को हम बार-बार भजें, लेकिन हमारी अपीलों को भी उस पूर्व सरकार की तरह नहीं टालें, हमारी अपीलों को सुनते रहें। जय भीम। जय भारत।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय एक घंटे के लिए और बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घंटे के लिए बढ़ाया गया।

श्री गोपाल कृष्ण।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गोपाल कृष्ण (बीकानेर पश्चिम): सभापति महोदय, बहुत धन्यवाद। मैं आपकी अनुमति से 2014-15 के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान को सपोर्ट करने के लिए खड़ा हुआ हूं। सुराज संकल्प यात्रा से लेकर के, संभागीय काबिना कार्यक्रम, जो बीकानेर में सम्भागीय सम्मेलन हुआ था, वहां तक, जितने लोगों की सलाह लेकर के, और लोगों की सलाह लेकर के, बुद्धिजीवियों की सलाह लेकर के, यह एक बहुत ही वेल्यूएबल डाक्यूमेंट तैयार किया गया है एक विजन को लेकर के और उसी को हमारी लोकप्रिय नेता, श्रीमती वसुन्धराजी ने प्रस्तुत किया। उसका हम सपोर्ट और अनुमोदन करते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा भूभाग वाला प्रदेश, दुनिया के कई देशों से बड़ा प्रदेश होते हुए, 'मैक्सिमम गवर्नेंस एंड मिनिमम गवर्नमेंट' से विकसित प्रदेश बनाने का सार्थक प्रयत्न है।

इसमें कई चीजों का उल्लेख हो चुका, बार-बार रिपीटिशन हो रहा है। लोगों ने, शुरुआत में राजपाल सिंहजी ने, और भी कई लोगों ने और माननीय श्री राव राजेन्द्र सिंहजी ने भी अपनी तरफ से, मतलब जो बातें कही हैं, उनका रिपीटिशन मैं नहीं करना चाहता, सिवाय कुछ बात कहने के, कि यह सबसे बड़ा बजट 1 लाख 6 हजार 125 करोड़ 67 लाख का, एज कंपेयर्ड टू पिछला जो बजट कांग्रेस का था, जो 77 हजार 220 करोड़ 60 लाख का था, उससे बहुत बड़ा बजट इन्होंने रखा है। निश्चित रूप से यह एक ऐसा पता लगता है कि इसमें विकास की बहुत बड़ी सम्भावनाएं हैं। थोड़ा सा जरूर इसमें टैक्स

(श्री गोपाल कृष्ण)

लगाया है लेकिन बड़ा इन्सिग्निफिकेंट टैक्स लगाया है। 350 करोड़ रुपये का टैक्स कोई बहुत बड़ा टैक्स कभी नहीं होता, उसमें भी 150 करोड़ की राहत भी दी गई है। बहुत अच्छा बजट है। इससे अच्छा बजट शायद ही कोई हो।

आपने तो बताया कि यह इस ढंग से, यह जो आपने यों उठा करके बताया न कि ये जैसे, मैं तो यह समझ रहा था कि यह बजट की कोई बाइबल है, या गीता है। मतलब इससे अच्छा बजट कोई हो ही नहीं सकता। यह बात सभी लोग कह रहे हैं, मैं भी कहता हूं। मैंने इसको पढ़ा है, अच्छे ढंग से पढ़ा है, सबने पढ़ा है, और इसलिए मैं सारी बातें तो नहीं कहता।

अभी बी एस पी के माननीय सदस्य ने कहा कि अच्छा बजट होते हुए भी, जो विपक्ष के लोग हैं उनका रवैया जरा दूसरा होता है। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही रवैया दूसरा हो, हमारी जो नेता हैं, उनकी कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, कुशलता और क़ाबिलियत में, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता।

मैं इसमें यह कहता हूं, जैसे उन्होंने कई चीजें बहुत अच्छी की हैं; सड़क के बिना, मैं यह समझता हूं कि जैसे उन्होंने बीच में कहा, कैनेडी की एक बात कही कि अमेरिका सड़कों के लिए जाना जाता है, न कि सड़कें अमेरिका के लिए जानी जाती हैं। बहुत वर्ष पहले एक जापानी शिष्टमंडल भी आया था, उन्होंने भी यही कहा कि अगर सड़कों का जाल नहीं बिछाया गया, तो किसी भी देश की विकास की सम्भावनाएं बहुत ही कम हो जाएंगी। इसलिए मैं यह समझता हूं कि सड़कें, हवाई परिवहन, हवाई रास्ते खोलना, और वैसे मैं कहता हूं कि विपक्ष के माननीय सदस्यों का कहना है कि इसके अन्दर घोषणा ही घोषणा है, घोषणा के अलावा कुछ भी नहीं है, लेकिन घोषणा के अलावा बहुत कुछ है, घोषणा ही नहीं है।

मैं तो इतना ही कहूंगा कि जैसे बीकानेर में संभागीय सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जगह-जगह से वसुन्धराजी ने ऐसा किया कि अपने जितने भी कैबिनेट के मंत्री थे, उन सबको गांव में, उस भरी गर्मी में, इतनी भयंकर गर्मी थी, उसके बावजूद भी ये हर पंचायत और ब्लाक के अन्दर गये और वहां जाकर के बड़ी-बड़ी समस्याओं का अध्ययन किया, मंथन किया, लोगों का उसी जगह पर निपटारा भी किया और जिनका निपटारा नहीं हो सका, उसके लिए

(श्री गोपाल कृष्ण)

आगे के लिए कार्यवाही करने की योजना बनाई। तो इसलिए यह मैं नहीं कह सकता। विशेष तौर से, बीकानेर के लिए ये कहते हैं कि जो वहां घोषणाएं हुईं; उनको बजट में लिया गया है। यह नहीं है कि सिर्फ घोषणा हो गई और बजट में नहीं लिया गया। यह बात भी कही गई है।

इसमें खास तौर से जलापूर्ति की योजना कोलायत के लिए; हनुमानगढ़ की सेम की समस्या का लिया है; बीकानेर में मेडिकल कालेज के लिए, चिकित्सा मंत्रीजी खुद वहां पर गये हैं और सब तरह की, वहां देखिये, दो सौ, कम से कम, ट्रक कचरे के वहां के पी बी एम हास्पिटल से निकाले हैं। बीकानेर में एक सिरेमिक्स हब बनाने की घोषणा की गई है। वह सब यहां पर हुआ है, यहां इस बजट के अन्दर शामिल किया है। हनुमानगढ़ में शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र का निर्माण किया है; चूरू जिले में एक करोड़ तिहेत्तर लाख लगाकर एक नेचर पार्क की घोषणा की गई है; बीकानेर को मेगा डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट बनाने की बात कही है; रविन्द्र मंच जो बहुत वर्षों से नहीं चल रहा था, 10-15 साल से ऐसे ही पड़ा था, उसको बनाने के लिए, निर्माण के लिए योजना बनाई है। गोगामेडी, लक्ष्मीनाथजी का मंदिर, नारायणजी का मंदिर इन सब चीजों को दुबारा बनाने का; करणीसिंह स्टेडियम का; वेलोड्रोम का, स्पोर्टस काम्प्लेक्स; सार्दुल स्पोर्टस को करने का; बीकानेर में क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला; इस तरह से कई चीजें, वहां पर निर्णय हुआ और उन सबको इस डाक्यूमेंट के अन्दर, जो डाक्यूमेंट थे, बहुत ही वेल्यूएबल डाक्यूमेंट है, प्रिशिअस डाक्यूमेंट है, इसके जरिये राजस्थान का विकास होने वाला है, ऐसा विकास जो लोगों ने कभी नहीं देखा है।

इसके साथ-साथ एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर के अन्दर एक तकनीकी विश्वविद्यालय 23 सितम्बर, 2013 को स्थापित किया गया था और उसको समाप्त कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से, शिक्षा मंत्रीजी से, वे तो हैं नहीं अभी, तो जो भी मंत्रीजी हैं, उनसे निवेदन करूंगा, जो मेरे पास ही बैठे हैं, कि कम से कम इस बात को उन तक पहुंचा दें। सभापति महोदय के माध्यम से आपसे कह रहा हूं, उनके माध्यम से आपसे निवेदन है और यहां जितने भी मंत्रीगण बैठे हैं, उनसे भी निवेदन है कि मेरी इस बात को पहुंचाएं कि आलरैडी वहां पर वी सी लग गया,

(श्री गोपाल कृष्ण)

मोटरगाड़ी दे दी, स्टाफ दे दिया और कृषि विश्वविद्यालय के अन्दर उसको जगह मिल गई, आफिस वगैरह की, उसको कह दिया कि he does not exist now. बड़ी अजीब सी बात है। बीकानेर के साथ सौतेला व्यवहार किया, इसलिए हो रहा है? पहले भी एक व्यास कमेटी बनी थी और उस व्यास कमेटी ने नेशनल यूनिवर्सिटी के लिए बीकानेर को रिकमंड किया और वह भी अजमेर भेज दी गई; रिकमंड करने के बाद भी भेज दी गई। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरी यह रिक्वेस्ट वहां तक पहुंचा दें।

यह बजट केवल घोषणाओं का बजट नहीं है, यह एक वर्किंग डाक्यूमेंट है, अगले दस वर्षों में विकसित राज्य बनाने के लिए इसका एक विजन है, वह करेंगे, लेकिन एक अलग सोच है, इनका अपना है । क्योंकि कई लोगों का यह है, स्वदोष: भवति: संकितो मनुष्य:, अपने ही दोषों के कारण मनुष्य दूसरों पर भी शंका करता है। अब ये हैं नहीं यहां, सब चले गए। अब क्या कहें? चले गए, हो सकता है, अन्दर बैठे हों; तो टीवी में देख भी लें। लेकिन घोषणा करना केवल, हमारा काम नहीं है, यह काम कांग्रेस का है। वही घोषणा करते हैं, या अपने नाम का भाटा लगा देते हैं कि हमने यह कर दिया, और करते कुछ भी नहीं हैं। सूरसागर का, सात करोड़ लगाकर वसुंधराजी ने इसको साफ-सुथरा कराया और फिर थोड़ा-सा उसको तोड़-फोड कर वापस रिपेयर करके अपना नाम लगा दिया; कई मंत्रियों ने, कांग्रेस के नेताओं ने एक भाटा अपना भी लगा दिया। जगह-जगह भाटा लगा दिया। यहां पिछले साल जो बजट पास हुआ, उसके अन्दर बजट को पास नहीं करके, बजट घोषणा करके, पहले जाकर भाटा लगाया और उसके बाद बजट पास कराया। इस ढंग की प्रवृति सिर्फ कांग्रेस में हो सकती है, यह हमारे अन्दर नहीं हो सकती।

यह भी आपने सुना होगा कि आपको घमण्ड बहुत आ गया क्योंकि 163 आदमी जीत गए; आपको घमण्ड नहीं करना चाहिए। घमण्ड किसको हो गया? हमको हो गया, या आपको हो गया? आपको यह घमण्ड हो गया था इसीलिए आपकी सरकार चली गई। पिछली सरकार इस घमण्ड के कारण से ही गई है, हमारी सरकार नहीं गई है। हमारी सरकार को घमण्ड नहीं है। काम करने का शौक है, काम करने का जज्बा है जो आप लोगों के सामने है। अहंकार किसने किया? हमने नहीं। आपको मालूम होगा कि किस तरह से पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने राजेन्द्रजी को कैसी-कैसी बातें सुनाई थीं, मैं कह नहीं सकता।

(श्री गोपाल कृष्ण)

सात पीढ़ियों तक भी वे उनकी खबर लेते रहेंगे, ऐसी बात भी कोई कही जाती है? लेकिन यह घमण्ड की बात थी और जिसने घमण्ड किया, वह कभी रहे नहीं।

(17.54 बजे)

(श्रीमती किरण माहेश्वरी, सभापति, पदासीन)

चलते गये। वह चलते गए, साहब, और अपने को कहते हैं कि घमण्ड मत कीजिए, अहंकार मत कीजिए! जबकि अपने प्रधान मंत्रीजी कहते हैं कि कांग्रेस का अहंकार सातवें आसमान पर चढ़ा हुआ है। हमारा सातवें आसमान पर नहीं, हम तो धरती पर हैं। धरती के अन्दर, धरती के लोग कभी आसमान की और अहंकार की बात नहीं करते हैं। लेकिन अब कहते यह हैं कि आपको घमण्ड हो गया। घमण्ड तो आप करते हैं और फतवा हमको देते हैं। अपने यहां फजीहत, दूसरों को नसीहत! बड़ी अजीब बात है! उलटी-उलटी बात करने की एक आदत है।

मैं आपको एक कोटेशंस बताता हूं मिल्टन का। जान मिल्टन की पैराडाइज लोस्ट में एक आलमाइटीगाड की इविल फोर्सेज से लड़ाई होती है और इविल फोर्सेज हार जाती हैं, लेकिन हारकर इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे करके क्या कहते हैं अपने सब लोगों को, सैडन नाम है उसका, सैडन सबको इकट्ठा करता है, करके कहता है, अच्छा, हार गए "What though the field is lost…." लड़ाई हार गए, मैदान हार गए तो क्या हो गया, "...All is not lost. The unconquerable will, study of revenge and immortal hate, fallen angels…" अरे हारे हुए एजेंल्स, एजेंल्स कहलाते थे, इसलिए फालेन एजेंल्स, हारे हुए दोस्तों "...to be weak is miserable…" कमजोर अपने आपको मत समझो "...doing or suffering..." कुछ भी करते हो, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हो लेकिन फिर भी ''But of this be sure..." एक बात के लिए आप निश्चित रहिये, क्या ''...to do good is not our task…" अच्छाई करना हमारा काम नहीं है" ''to do good is not our task but to do evil is our sole delight." हमारी एक मात्र खुशी बुराई करना है, क्यों, "...as the contrary to his will to whom do we resist." क्योंकि हम जिसके विपरीत है, उसके विपरीत हैं, जिससे हमारी लड़ाई है ''as the contrary to his will." उसके विल से विपरीत हैं, इसलिए हम यही काम करेंगे। ''to do good is not our task but to do evil is our sole delight, as the contrary to his will." यह बहुत पुरानी, 1600 साल के अन्दर यह कही गई बात है और आज भी सही है यह अपोजिशन के लिए। यहां के लोग ऐसा कर रहे हैं, देखने को मिल रहा है। क्या किया जाए?

(श्री गोपाल कृष्ण)

मैं तो उनको एक ही सलाह दूंगा, माननीय सदस्यों से मेरा अनुनय निवेदन है, किसी अच्छे डाक्यूमेंट के विजन को समझने का प्रयत्न कीजिए। 20 हजार किलोमीटर सड़कों का उपयोग आप भी करोगे, हम अकेले नहीं करेंगे, आप भी करोगे; ऊर्जा के उत्पादन से आपके घर भी रोशन होंगे; पेयजल योजना से जलापूर्ति आपकी तृष्णा को शांत करेगी; उन्नत, उपयोगी, अच्छी, सस्ती शिक्षा आपके बच्चों को भी शिक्षित करेगी; नये मेडिकल कालेज व चिकित्सा की सुविधा आप और आपके परिवारों को भी स्वस्थ रखेगी; स्पोर्टस, खेल मैदान, साइकिल वेलोट्रोम, आदि आपके बच्चों के शरीर को स्वस्थ, सुंदर, सुघड़, बलशाली बनाएंगे; नहरों, नदियों, नालों और वर्षा के पानी को सुनियोजित करके आपके पीने के लिए, सिंचाई की नई तकनीक से आपके खेतों को भी हरा-भरा करेंगे, प्रदेश खाद्य में आत्मनिर्भर तो है ही, निर्यात भी करेगा।

इसलिए मेरा निवेदन है कि इस महान् विजनरी डाक्यूमेंट को सहयोग देकर प्रदेश की उन्नति में भागीदार बनिये। इसमें सबका भला है।

सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिद दु:ख भागवेतु।

बहुत-बहुत धन्यवाद। भगवान सबका भला करें।

श्री सभापति: श्री ओमप्रकाश। माननीय सदस्य, श्री ओमप्रकाश।

श्री ओमप्रकाश (महुवा): बजट 2014-15 पर मुझे आपने बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही आभार व्यक्त करता हूं राजस्थान की प्रगतिशील और यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीया वसुंधरा राजेजी का, जिन्होंने मुख्य मंत्री का कार्यभार सम्भालते ही उन किसानों को, मजदूरों को जो ढाणियों में बसे हुए थे, उनको विद्युत का कनेक्शन देने की घोषणा की। उसके लिए भी राजस्थान की पूरी जनता की तरफ से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने देखा है कि कांग्रेस के लोग आम आदमी की

(20.00 बजे)

बात का राग अलापते-अलापते, करीब 65-67 साल हो गये, लेकिन इन्होंने कभी नहीं सोचा कि ढाणी में भी कोई गरीब निवास करता है, जिसके बच्चे के पढ़ने के लिए भी विद्युत की जरूरत है।

शिक्षा के क्षेत्र में भी, हर पंचायत स्तर पर, ग्राम पंचायत मुख्यालय पर

(श्री ओमप्रकाश)

जो सीनियर सेकण्डरी स्कूल खोलने की बात कही है बजट में और नये मेडिकल कालेज खोलने की जो बात कही है, एक बहुत बड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने। इससे युवाओं को रोजगार मिलेगा, मरीजों का अच्छा इलाज होगा और हमारे युवा साथियों को डाक्टर बनने का भी गौरव प्राप्त होगा।

विद्युत के क्षेत्र में जो 40 हजार नये कनेक्शन देने की जो बात इस बजट में कही गई है, वह भी तारीफ के काबिल है।

सड़क के सम्बन्ध में हम बात करें, माननीय सभापति महोदया, तो पिछले बहुत लम्बे समय तक कांग्रेस की सरकार राजस्थान में रही है, लेकिन सड़कों के निर्माण की बात तो अलग रही, पिछले पांच साल में पेच-वर्क भी पूरा नहीं कर पाई थी। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने इस बजट में 20 हजार किलोमीटर का जो एक सुनहरा संकल्प लिया है, उसके लिए भी उनका बहुत-बहुत साधुवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद। इससे राजस्थान की आवागमन की स्थिति तो सुधरेगी ही, लेकिन यहां पर भारी निवेश होने की भी पूरी सम्भावना देखी जा सकती है।

हर पंचायत समिति स्तर पर इस बजट में आई.टी.आई. खोलने का जो एक बहुत बड़ा संकल्प लिया है मुख्य मंत्री महोदया ने, उससे हमारे जो नये युवा साथी हैं उनको रोजगार मिलेगा। रोजगार के साथ-साथ, निजी रोजगार तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ-साथ में उनको सरकारी नौकरी प्राप्त करने में भी बहुत बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी।

मुख्य मंत्री महोदया ने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान एक बात कही थी और वह बात मुख्य यह थी, एक मुद्दा था कि टैट की परीक्षा को खतम कर दिया जाए। आई.ए.एस. बनने के लिए जब तीन परीक्षाएं होती हैं तो मास्टर बनने के लिए दो-दो परीक्षाएं क्यों हों? इस तरह का एक बहुत बड़ा मुद्दा आया था। आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ने यह वादा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम अध्यापक की नियुक्ति के लिए केवल एक परीक्षा लेंगे। इसके लिए भी उनका बहुत-बहुत साधुवाद कि उन्होंने अध्यापक के पद के सलेक्शन के लिए एक परीक्षा कर दी है।

यह एक ऐसा बजट प्रस्तुत किया है जिसमें युवा, मजदूर, महिला, व्यापारी, हर वर्ग के व्यक्ति के लिए फायदा दिखाई दिया है।

(श्री ओमप्रकाश)

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा, अभी खेतड़ी से आने वाले माननीय विधायक कह रहे थे कि पक्ष और विपक्ष, बजट चाहे कितना भी अच्छा हो, उसकी आलोचना, समालोचना और प्रशंसा होती रहती है, लेकिन मैंने देखा कि लालसोट से आने वाले माननीय विधायक, बजट पर उन्होंने, पूरे बजट को पढ़ने के बाद उन्होंने एक भी बात की प्रशंसा नहीं की। एक भी बिन्दु उनको पूरे इस बजट में ऐसा नहीं लगा कि जो राजस्थान की जनता के हित में हो। क्योंकि उनकी सबसे बड़ी बात यह है, उनको एक ऐसा बजट आना चाहिए था कि सड़क पर एक भैंस भी मर जाए तो सड़क जाम करने का अधिकार इस बजट में होना चाहिए था। वह अच्छा लगता उनको। राजस्थान के विकास की बात उनको अच्छी नहीं लगती। कांग्रेस के साथियों और एक नई पार्टी और बनी, एन.पी.पी., उसका फुल फार्म है, नेशनल पति-पत्नी परिवार पार्टी।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर अच्छी बातें बजट में आती हैं, इस सदन के पटल पर रखी जाती हैं, जनता के हितों की बात रखी जाती है, तो कम से कम आपको इसकी प्रशंसा करनी चाहिए। भले ही हम 163 हैं पर सबका सहयोग आदरणीय मुख्य मंत्री महोदया ...(व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): वे चले गये। यहां पर होते तो आनन्द आता। (व्यवधान)

श्री ओमप्रकाश (महुवा): बिलकुल सही बात कह रहे हैं मंत्रीजी कि लालसोट से आने वाले माननीय विधायक भी यहां पर होते तो और ज्यादा आनन्द आता। लेकिन मैं एक चीज बहुत पुरज़ोर शब्दों में कहना चाहूंगा कि बजट तो कई बार आये हैं और उम्मीद करता हूं आदरणीया वसुन्धरा राजेजी से कि 2020 का जो विजन उन्होंने दिया है, आने वाला बजट और भी अच्छा बजट होगा, लेकिन सबसे बड़ी बात, जो पूर्वी राजस्थान, चाहे भरतपुर की बात करें, चाहे धौलपुर की बात करें, चाहे करौली की बात करें, चाहे दौसा की बात करें, वहां से सुबह कोई भी व्यक्ति जब जयपुर के लिए आता था तो उसको यह पता नहीं होता था कि मैं शाम को घर वापस पहुंच पाऊंगा या नहीं। उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में कुछ जन-प्रतिनिधियों को इतनी खुली छूट दे रखी थी कि वे जब मर्जी आये, किसी का शीशा तोड़ दें; जब मर्जी आये, किसी की रोड रोक लें; जब मर्जी आयें, किसी की रेल रोक दें। कोई कण्ट्रोल नहीं था। आदरणीया वसुन्धराजी राजे मुख्य मंत्रीजी जब

(श्री ओमप्रकाश)

राजस्थान की हैं, मैं पूर्वी राजस्थान की ओर से उनका बहुत-बहुत साधुवाद, और बहुत-बहुत धन्यवाद और बहुत-बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि ऐसे जन -प्रतिनिधियों की इतनी लगाम कस दी है प्रशासन ने कि वे ऊंची गर्दन उठाकर नहीं देख सकते। इसके लिए बहुत-बहुत साधुवाद और बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय सभापति महोदया, आज आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार।

श्री सभापति: बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य, श्री मदनजी राठौड़।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): माननीय सभापति महोदया, राजस्थान की सहृदय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के नाते जो बजट प्रस्तुत किया, उसकी सर्वत्र प्रशंसा हो रही है और मुझे इस बात की खुशी है कि हिंदुस्तान की एक मात्र भारतीय जनता पार्टी की ऐसी मुख्य मंत्री होंगी जिनकी बसपा के विधायक भी सदन के अन्दर खुले मन से प्रशंसा करें। इस बात की हमें भी बहुत खुशी है।

वास्तव में जो बजट प्रस्तुत किया और उस पर आज के जो ओपनर आये, उन्होंने यह व्याख्या की कि कांग्रेस ने हम पर कितना कर्जा लाद दिया था, घाटे का बजट दिया था, फिर हमने किस प्रकार से उसको सुधारा; उसके बाद में फिर कांग्रेस ने किस प्रकार से बिगाड़ा। उन्होंने इतनी जोरदार तरीके से अपनी बात कही कि कांग्रेसी सदस्य एक-एक करके भागने लग गये और अब यह स्थिति है कि विपक्ष है ही नहीं। सदन के अन्दर एक भी कांग्रेसी नहीं है। मैं तो यह सोचता हूं कि वास्तव में मजा भी नहीं आ रहा है, जब वे सामने नहीं हों तो बोलने का आनन्द भी नहीं आता। जब कोई व्यक्ति सामने हो, तब कोई बात रखें। यहां तो जो लोग विराजमान हैं, जो माननीय सदस्य विराजमान हैं, वे सभी पारंगत हैं, विद्वान हैं और अच्छी तरह से इस बजट को पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। इसलिए मैं विशेष रूप से तो नहीं कहूंगा, कुछ बातें मैं निवेदन करना चाहूंगा।

यह बात बिलकुल सही है कि हमारी सहृदय मुख्य मंत्रीजी पर जनता का बहुत विश्वास है। उन्होंने 2003 से 2008 का जो टेन्योर निकाला था, जो कार्यकाल निकाला, उसमें जो इन्होंने वादे किए थे, जो इन्होंने घोषणाएं की थीं, वे लगभग सभी इन्होंने पूरी कीं। इस बार भी बजट में इन्होंने जो घोषणाएं की

(श्री मदन राठौड़)

हैं, निश्चित रूप से वे सब पूरी होंगी, यह जनता को पूरा विश्वास है और हम सबको भी पूरा विश्वास है।

कांग्रेस ने जो घोषणाएं की, माननीय सभापति महोदया, मैं आपको बताना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत गलत घोषणाएं कीं, उन्होंने थोथी घोषणाएं कीं। यह मेरे सामने उनके बजट हैं जो उन्होंने पूरे कार्यकाल के अन्दर बजट प्रस्तुत किये, उनमें कई ऐसी घोषणाएं हैं, जो उन्होंने 2009-2010 में जो घोषणा की, उसकी बिलकुल नकल 2010-2011 में की, वही नकल 2011-2012 में भी की। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऊर्जा के क्षेत्र में उन्होंने अपने 2009-10 के बजट घोषणा-पत्र में पैरा नम्बर-22, हूबहू उसकी नकल और उन्होंने अपना आगे का, 2010-11 का जो बजट है, उसमें भी पैरा नम्बर-14 में बाकायदा, शब्दश: शब्द, यानी, 945 मेगावाट की वृद्धि करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, यह उसमें उतारा गया है। बिलकुल नकल उतारी गई। यही नहीं, 2011-12 में भी उन्होंने इसी प्रकार की नकल की। ये लगातार इस प्रकार की नकल करते आ रहे हैं।

ऊर्जा के क्षेत्र में 2009-10 में पैरा नम्बर 23, मैंने अभी पहले पैरा नम्बर 22 का आपको बताया, पैरा नम्बर-23 में भी 1,860 मेगावाट की बढ़ोतरी करने की जो बात उन्होंने कही है कि किस-किसमें वह बढ़ोतरी करेंगे, वह की वह बात इन्होंने 2010-11 के बजट के पैरा नम्बर-15 में की है और वही 2011-12 के बजट में पैरा नम्बर-12 में की है।

तो यह बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके माध्यम से सदन को कि इन्होंने बजट बनाने में भी दिमाग नहीं लगाया। केवल नकल करते रहे और नकल करके जो इनको लाभ की बात होती थी, वह बजट में जोड़ने का इन्होंने काम किया। इस प्रकार की यह नकल करके और जनता को जो धोखा देने का प्रयास किया, वही कारण है कि आज बिलकुल विपक्ष नदारद है।

माननीय सभापति महोदया, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इन्होंने जो घोषणा की 2013 के बजट में, पैरा नम्बर-19 में, उसमें 21 सड़कें बनाने की इन्होंने घोषणा की, जिसमें 2,743 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कही है, उसमें से एक भी सड़क इन्होंने नहीं बनाई। मैं मेरे पाली जिले की बताना चाहूंगा, जो मैं कदम से कदम जानता हूं, बाली पिण्डवाड़ा, 63 किलोमीटर, 100 करोड़, लेकिन एक इंच काम इन्होंने नहीं किया, रिपेयरिंग वर्क भी इन्होंने नहीं किया।

(श्री मदन राठौड़)

मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि पैरा नम्बर 19 के अन्दर जोधपुर-सरदार समंद-मारवाड़ जंक्शन, अभी वे माननीया सदस्या यहां बोल रही थी, मैं आपको यह बताना चाहूंगा, 131 किलोमीटर, 200 करोड़ रुपया, लेकिन एक किलोमीटर क्या, एक इंच सड़क इन्होंने नहीं बनाई। यही बात सोजत सिटी से देसूरी की है। और यही नहीं, 21 की 21, मैं सोचता हूं कि इन्होंने उसमें कुछ भी नहीं किया।

सभापति महोदया, पैरा नम्बर 31 में यह घोषणा की थी कि हम बिजली 6 घंटे देंगे, जब आप 6 घंटे घोषणा की बात करो किसान के लिए, तो मैं सोचता हूं कि 4 घंटे से अधिक समय इन्होंने बिजली दी नहीं।

सभापति महोदया, मैं यह भी बताना चाहूंगा कि हमारे पाली जिले में एक झारिया बांध है, उन्होंने कहा था कि 21 करोड़ रुपये की लागत से झारिया बांध का पुनर्निर्माण करवाया जायेगा, एक कट्टा सीमेंट इन्होंने नहीं लगाया, एक कर्मचारी वहां नहीं लगाया। कुछ भी काम जो अपने घोषणा पत्र में इन्होंने किया था, उसके अनुरूप कुछ भी इन्होंने नहीं किया।

सभापति महोदया, यही नहीं, चिकित्सा के मामले में जो एम्बुलेंस लगाई, उसमें तो आपको पता है कि जो उसमें घोटाला किया, उस सम्बन्ध में मुकदमे भी दर्ज हुए। केवल मुकदमे ही दर्ज नहीं हुए, बड़े से बड़े व्यक्ति भी उसमें मुलजिम पाये गये और उनके खिलाफ में भी इस प्रकार से मुकदमे हुए।

पर्यटन की दृष्टि से इन्होंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन हमारी सरकार ने बहुत कुछ किया।

मैं आपके माध्यम से दो-तीन निवेदन करना चाहूंगा। हमारे कई माननीय सदस्य गौवंश के लिये बहुत चिन्तित रहते हैं। सभापति महोदया, गौवंश में प्रकृति समान अनुपात देती है। जिस प्रकार से नर पैदा होते हैं, लगभग उसी अनुपात में मादा भी प्रकृति देती है। प्रकृति जिस प्रकार से हमारे अनुपात में ध्यान रखती है, वैसे ही सभी पशु-पक्षियों के मामले में भी रखती है। लेकिन आज बैल का उपयोग नहीं हो रहा है। बैल का उपयोग नहीं हो रहा है, बैल अनुपयोगी हो गया है, क्योंकि ट्रैक्टर के माध्यम से लोग खेती करने लग गये हैं। बैल के माध्यम से खेती बहुत कम करने लगे हैं। लेकिन एक नया आविष्कार किया था हमारी सरकार ने पिछले टेन्योर में, बैल-ट्रैक्टर का आविष्कार किया था। मैं सोचता हूं कि इस बार हमको यह बैल-ट्रैक्टर्स पर और

(श्री मदन राठौड़)

यह निर्माण करने के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल महंगा हो रहा है। बैल-ट्रैक्टर, जैसे लीवर सिस्टम होता है, जैसे हम साइकिल चलाते हैं, साइकिल में एक पेडल मारते हैं, तो वह पहले वाला पहिया बड़ा होता है, उस पर पीछे वाला चक्का है उसका व्हील बहुत छोटा होता है। जब अगला चक्का एक पूरा करता है तो छोटा वाला चक्का दस चक्कर मार लेता है और उस पर बड़ा पहिया है, वह मैं सोचता हूं कि और कई मीटर आगे पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार से बैल ट्रैक्टर है। उसमें एक बैल चार हल वाला ट्रैक्टर चला सकता है। सभापति महोदया, यदि हमने इसका उपयोग करना शुरू कर दिया तो निश्चित रूप से वह लाभप्रद होगा और गौवंश की रक्षा करने में कामयाब हो सकेंगे।

एक निवेदन और मैं आपके माध्यम से रखना चाहूंगा। दूसरा मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हमने अपने चुनाव घोषणा पत्र में यह बात भी कही थी कि खेतों में जो सूअर और अन्य पशु घुस जाते हैं, उसके लिये हम तारबंदी की घोषणा करेंगे। मैं सोचता हूं कि यह निवेदन भी आपके माध्यम से करना चाहूंगा।

सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मैं यह भी बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में, अभी तो यह बजट की बात आई है, लेकिन बजट से पहले भी, जब-जब भी मैंने कोई भी समस्या रखी है तो मुख्य मंत्रीजी ने सदैव खुले मन से उनको स्वीकृत किया है। अभी पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर यहां नहीं हैं, पिछले विधान सभा सत्र के अन्दर, जो अपना पहला सत्र था, उसमें मैंने यह बात रखी थी कि मेरे इलाके के अन्दर फोर लेन बन रही है, उसमें जहां पुल देना चाहिये था, वहां नहीं दिया है; जो बाई-पास देना चाहिये था, वहां नहीं दिया है। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उनको, श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी ने भी उनको कहा और उन्होंने नेशनल हाइवे अथोरिटी के अधिकारी को मेरे साथ में भेजा। मेरे इलाके में जो हाइवे निकल रहा है, जहां-जहां मैंने बताया, वहां लगभग 125 करोड़ के पुल मैंने बनवा दिये हैं, वे बनकर तैयार हो गये। मैं यह बताना चाहूंगा कि कितनी संवेदनशील हमारी मुख्य मंत्रीजी हैं, और मंत्रिमण्डल के जो सदस्य हैं, वे भी कितने गम्भीर हैं और तुरन्त चिन्ता करते हैं और इस विषय में उन्होंने काम करके दिखाया।

यही नहीं, जो पानी की योजना है, पानी के लिए मैं अभी आया था दो महीने पहले। मैं आपको बताऊं कि एस एस सी के माध्यम से मेरे विधान

(श्री मदन राठौड़)

सभा क्षेत्र के अन्दर 28 करोड़ की, मणियारी, भांवरी, गोदावास, डरी और बल्लूपुरा, बांतली, आदि जगह की योजना इन्होंने 28 करोड़ की स्वीकृत कर दी और यही नहीं, उसके लिए टेण्डर्स भी शुरू हो गये। बजट तो अब आया है लेकिन खुले मन से वह संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरन्त स्वीकृतियां जारी कर दीं।

यही नहीं, मैं यह भी बताना चाहूंगा, मेरे पाली जिले में इन्होंने बहुत कुछ दिया है। पाली में टैक्सटाइल के लिए मैं यह तो निवेदन कर दूं, कम से कम मेरे इलाके की बातें मैं संक्षेप में आपके सामने रखूंगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: थोड़ा-सा फास्ट।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): टैक्सटाइल प्रमोटरी पालिसी की इन्होंने घोषणा की, उसका लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा। खनिज के क्षेत्र में सिरेमिक पालिसी जो प्रमोटरी पालिसी थी; मेगा डेजर्ट ट्यूरिज्म के अन्दर, जो अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे, मेरे जवाई बांध को भी इसमें जोड़ा, माउंट आबू को भी जोडा, पाली को भी जोड़ा। एक डेजर्ट टूरिस्ट सर्किट बनाने की इन्होंने जो घोषणा की, उसका लाभ निश्चित रूप से हमको मिलेगा।

पर्यटन की दृष्टि से जवाई बांध के अन्दर 6.43 करोड़ रुपया स्वीकृत करके जवाई बांध को सुदृढ़ करने का काम मेरे विधान सभा क्षेत्र में उन्होंने किया। मारवाड़ जंक्शन से मावली और इसमें फलाब, गौरंग घाट और गौरी धाम इस प्रकार के ऐसे हैं, मैं चाहूंगा, माननीय सदस्य भी कोई आना चाहें तो ट्रोली पर बिठाकर मैं उनको ले जाऊंगा, दिखाऊंगा, आप ट्रोली पर बैठकर के देखिये, लगभग 100-100 फीट ऊपर के पुल हैं और कई गुफाएं हैं, और बाहर झरने बहते हुए आपको दिखेंगे। वह भी आप देखें, तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से इस क्षेत्र को बहुत लाभ मिलेगा, यह क्षेत्र भी बहुत विकसित होगा।

यही नहीं, जवाई पाइपलाइन पेयजल योजना को सुदृढ़ करने के लिए इन्होंने 199 करोड़ की स्वीकृति जारी की है। इसका लाभ भी हमको मिलेगा। जवाई बांध में, वहां पर पर्यटन विकसित करने के लिए साढ़े पांच करोड़ रुपया इन्होंने स्वीकृत किया है। इसका लाभ भी हमको मिलने वाला है। पेयजल के

(श्री मदन राठौड़)

लिए, शहरी विकास के लिए पाली क्षेत्र के लिए भी इन्होंने स्वीकृतियां जारी की हैं 2,160 करोड़ की। इसका लाभ भी निश्चित रूप से मिलेगा।

यही नहीं, पाली में नवीन मेडिकल कालेज के लिए इन्होंने 189 करोड़ की जो स्वीकृति जारी की है, इसका लाभ निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। बांगड़ अस्पताल में, क्योंकि जो मेडिकल कालेज बन रहा है, उससे सम्बन्धित जो हास्पिटल है, उसमें सुपर-स्पेशलटी विंग तैयार की जायेगी। उसके लिए 150 करोड़ रुपया मिलेगा।

मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहूंगा कि गुजरात के तत्कालीन मुख्य मंत्री, जो वर्तमान में प्रधान मंत्री हैं, वे जब 2002 में हमारे क्षेत्र में आये थे, तब हमने उनसे कहा था कि आप नर्मदा का पानी हमको दीजिये। तब उन्होंने कहा कि हम पानी देना चाहते हैं, लेकिन आपकी राजस्थान की सरकार लेना नहीं चाहती और उन्होंने गहलोतजी को कहा कि आप अपने हिस्से की राशि जमा करायें तो हम आपको पानी देने के लिए तैयार हैं। श्रद्धेय मुख्य मंत्रीजी जब 2003 में मुख्य मंत्री बनीं, उन्होंने तुरन्त इस बात को महसूस किया और गुजरात के मुख्य मंत्रीजी से बात करके नर्मदा नहर का निर्माण कर दिया और सांचौर के सिल्लू पाइंट में वह पानी पहुंचा दिया।

अभी मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणा की है जवाई पुनर्भरण के लिये, उन्होंने एक टीम बना दी, एक समिति की घोषणा भी कर दी है और सिल्लू बांध से वह पानी, जो केवल 100 क्यूसेक्स लाना है, जिसमें हमारे यह आदरणीय ओटारामजी, सिरोही वाले भी और इनके सांसद भी प्रयास कर रहे हैं और मैं भी यह प्रयास कर रहा हूं कि वह पानी सिल्लू से सिरोही के माध्यम से आता हुआ हमारे सिन्धु बांध में आये, जो पश्चिमी राजस्थान की एक मात्र जीवन रेखा है जवाई बांध, उसको और सुदृढ़ किया जा सके, पूरे क्षेत्र की पेयजल योजना सफल हो सके।

मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा, अभी तात्कालिक समस्या है, अभी हमारे पाली जिले में तीन-चार दिन से पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि इन्होंने जो पाइपलाइन लगाई है, इन्होंने गलत पाइपलाइन लगा दी और उस पाइपलाइन में बहुत गोलमाल हुआ। मैं आपके माध्यम से उसमें निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पर जो लीकेज हो गया, उसके लिए बिलकुल ड्राई करना बहुत जरूरी है। अब ड्राई करेंगे तो ऊपर से पानी बंद

(श्री मदन राठौड़)

करना पड़ता है। यह बहुत बडी समस्या है। मैं सोचता हूं कि आगे के लिए इस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के अन्दर इस प्रकार के पाइप नहीं लगाये जायें, नहीं तो ड्राई करने के लिये पूरा ही बंद करना पड़ेगा, तो पूरी योजना कोलेप्स हो जायेगी। एक बहुत बड़ी समस्या हमारे लिए बन जायेगी।

सभापति महोदया, मैं आपको एक और निवेदन करना चाहूंगा।

श्री सभापति: अब समाप्त करें, माननीय सदस्य। सम-अप कर दीजिये। बहुत सारे लोगों को और बोलना है। (व्यवधान) आप अपनी बात को अब समाप्त कर दीजिये।

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर): चलो, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने जितना समय दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: डा. विश्वनाथ मेघवाल।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदया, धन्यवाद। राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, माननीया वसुन्धराजी ने जो परिवर्तित बजट 2014-15 पेश किया है, यह दूरदृष्टि का बजट है, जो राजस्थान के विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। मैं इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, शांति से सुनें। अच्छे सुझाव वे देंगे, सुनिये उनको।

श्री विश्वनाथ (खाजूवाला): राज्य की 2013-14 की जो वार्षिक योजना थी, 40,500 करोड़, इसके अनुपात में परिवर्तित अनुमान 2014-15 का आकार 69,820 करोड़ रुपये रखा गया है, जो गत योजना से 72 परसेंट अधिक है। माननीय सभापति महोदया, सभी संगठनों ने, सभी बजट एक्सपर्टस मीडिया ने इस बजट को सराहा है।

राज्य पर पिछली गवर्नमेंट ने जो कर्ज भार 1 लाख 30 हजार 640 करोड़ रुपये रखा, बिजली पर भी 75 हजार करोड़ रखा, इससे पिछली कांग्रेस सरकार ने राज्य को वापस 'बीमारू' प्रदेश की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया।

सभापति महोदया, माननीया मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी का संकल्प है कि राजस्थान राज्य शक्तिशाली, विकसित और समृद्ध राज्य बने।

मैं बात करना चाहूंगा, ऊर्जा के क्षेत्र में, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री भी

(श्री विश्वनाथ)

यहां बैठे हैं, जो अनुभवी ऊर्जा मंत्री हैं, पिछली गवर्नमेंट ने 15 हजार करोड़ से 75 हजार करोड़ का विद्युत घाटा जो दिखाया है, इतनी खस्ता हालत बिजली की इस प्रदेश में पिछली गवर्नमेंट ने की। अब मैं कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी यह चाहती हैं कि हमारे प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिले और कृषि विद्युत कनेक्शन, जो पांच साल से वेटिंग में बैठे हैं, वेटिंग लिस्ट जो हमारी है, वह क्लीयर हो; आवेदन करते ही उनको कनेक्शन दिये जाएं। 40 हजार कनेक्शन देने की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने बात की है। 900 मेगावाट विद्युत उत्पादन किया, आने वाले पांच साल में 6,500 मेगावाट का उत्पादन और होगा और 25,000 मेगावाट सोलर ऊर्जा के थ्रू उत्पादन होगा। मैं इस अच्छे निर्णय के लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं पेयजल के बारे में, सिंचाई के बारे में यह कहना चाहूंगा कि माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पेजयल के लिए जो हमारी पेयजल की स्कीम हैं, वे पी.एच.ई.डी. के माध्यम से दुरुस्त करवाकर, जो पंचायत की टी.एफ.सी., सी.एफ.सी., एस.एफ.सी. हैं, उनके माध्यम से इनको दुरुस्त करवाया जायेगा। एक हजार गांव, ढाणियों में आर.ओ. संयंत्र लगाये जायेंगे। नदियों को जोड़ने के कार्य की जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है, ये सब स्वागत-योग्य हैं। आई.जी.एन.पी. नहरों की मरम्मत, एक्सटेंशन, रिनोवेशन एण्ड माडर्नाइजेशन, इन सब चीजों के लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

मैं यह कहना चाहूंगा कि चिकित्सा के सम्बन्ध में जिस तरीके से पूरे राजस्थान में डाक्टर्स की कमी है, सात मेडिकल कालेजों का जो निर्णय लिया है और घोषणा की है, यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कार्य माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया। कैंसर चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र की स्थापना करना, मेडिकल कालेज में सुपर-स्पेशलिस्ट फैकल्टी को बढ़ावा देना, यह सब हमारे चिकित्सा क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने सुराज संकल्प यात्रा में पूरे प्रदेश में 14 हजार किलोमीटर यात्रा करके जिस तरह की सड़कों की हालत देखी, उसके बाद इस बजट में 20 हजार किलोमीटर सड़कों का विकास कार्य करने की इन्होंने जो पी.पी.पी. मोड में घोषणा की है, यह स्वागत-योग्य है। एक हजार किलोमीटर ईस्ट-वेस्ट कोरिडोर और ग्रामीण पंचायत में गौरव पथ की जो घोषणा की है, ये भी स्वागत-योग्य हैं।

(श्री विश्वनाथ)

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जो 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित करने की घोषणा की है, यह भी एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम है।

भामाशाह योजना हो, चाहे गोपालन विभाग बनाने का निर्णय हो, सभी ऐसे बहुत निर्णय जो माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किये, इनका भी मैं स्वागत करता हूं।

शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने पंचायत मुख्यालयों पर स्कूलों को क्रमोन्नत करने की जो बात की, हर पंचायत हैडक्वार्टर पर माध्यमिक से उच्च माध्यमिक में, मैं समझता हूं कि इससे जो बच्चियों का ड्राप-आउट होता है, जो बच्चियां स्कूल में पढ़ने नहीं जाती हैं, उनकी अब वृद्धि होगी। यह बहुत बड़ा, अच्छा निर्णय लिया। इसके लिए मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। सभापति महोदया, यह बहुत अच्छा, साहसिक निर्णय माननीया मुख्य मंत्रीजी ने किया है।

अंत में, मैं यह कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने भरतपुर सम्भाग का दौरा दस दिन तक किया, बीकानेर संभाग में भी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दस दिन तक अपने मंत्रिमण्डल के साथ और सभी विभागों के बड़े अधिकारियों के साथ गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर समस्याओं को सुना और उनका निस्तारण किया, यह बहुत ही सराहनीय काम किया। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को इसके लिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा।

बीकानेर के लिए इतनी बड़ी सौगातें माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दी हैं। हम पिछले पांच साल से यहां बैठे हैं, पूर्ववर्ती सरकार में भी हम यहां थे, हमने देखा कि बीकानेर का नाम पूरे पांच साल में कहीं नहीं आता था, लेकिन इस बार जिस तरीके से सौगातें दी हैं, चाहे वह बीकानेर सिरेमिक हब की बात कर लें, जिप्सम पालिसी, जिप्सम पट्टे की बात कर लें, रविन्द्र रंगमंच की बात कर लें, डेजर्ट ट्यूरिस्ट प्रोजेक्ट की बात कर लें और बीकानेर एयरपोर्ट टर्मिनल की बात कर लें और मेडिकल कालेज में टर्शरी कैंसर सेण्टर की बात कर लें, बीकानेर करणी सिंह स्टेडियम हो या बीकानेर विधिविज्ञान प्रयोगशाला की बात करें, मन्दिरों के जीर्णोद्धार की बात करें, सब क्षेत्र में जो हमें सौगातें मिली हैं, इसके लिए माननीया मुख्य मंत्रीजी का मैं हार्दिक आभार और स्वागत करना चाहूंगा।

अंत में, मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि हमारे बीकानेर को, जो

(श्री विश्वनाथ)

टेक्निकल यूनिवर्सिटी की बात आयी, उसके लिए हमारे सभी माननीय सदस्यों ने मांग रखी है; वहां पर टेक्निकल यूनिवर्सिटी चालू हो गयी थी, अब हम सुन रहे हैं, उसको वापस जिस तरीके से बंद किया जा रहा है, यह हमारे साथ अन्याय होगा। मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि वहां हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी चालू हो।

गवर्नमेंट कालेज, खाजूवाला भी है, पिछली गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था लेकिन वह भी बंद कर दिया। मैं चाहूंगा कि वह भी चालू हो।

मेगा फूड पार्क हो और हाई कोर्ट और पासपोर्ट आफिस भी वहां हों। सेण्ट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी बीकानेर में हो। ये सभी हमारी बीकानेर की तरफ से मांग हैं।

आप लोगों ने मेरे को समय दिया, इसके लिए मैं पुन: आपका आभार प्रकट करता हूं और माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरीके से एक अच्छा बजट पेश किया, इसके लिए हम माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री कैलाशजी भंसाली।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, आपने बजट घोषणाओं पर मेरी बात कहने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धराजी के नेतृत्व में भा.ज.पा. ने विधान सभा में 163 तथा लोक सभा में सभी 25 सीटें जीत कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जब मैंने 26 सितम्बर को इंडिया टीवी को एक इन्टरव्यू में कहा था कि हम 161 सीटें जीतने वाले हैं तो उन्होंने कहा, यह कैसे हो जायेगा? मैंने कहा, आप देख लेना। फिर लोक सभा चुनाव में ई टीवी के अनिल लोढ़ाजी ने कहा, इस बार क्या अनुमान है? मैंने कहा, 302 सीटें। उन्होंने कहा, सपने देख रहे हो? मैंने कहा, नहीं, धरातल की बात कर रहा हूं।

तो मैं कहता हूं कि वसुन्धराजी का जो चमत्कार मैंने देखा, जो भीड़ जुटी, सबसे पहले गोगुन्दा, उदयपुर में इतनी भयंकर भीड़, आज तक वैसी मीटिंग नहीं हुई थी। इतना जन सैलाब और महिलाओं में वह उत्साह कि वोट देंगे तो बी.जे.पी. को देंगे, नरेन्द्र मोदी को देंगे और वसुन्धराजी को देंगे। इसके लिए मैं यह कहूंगा कि उनका जो विजन है 2020, वह पूरा होगा; राजस्थान वापस विकसित प्रदेश बनेगा; 'बीमारू' से ठीक होगा।

(श्री कैलाश भंसाली)

मेरे शहर के एक विधायक, जो पूर्व मुख्य मंत्री रहे हैं, उन्होंने राजस्थान प्रदेश की जनता पर 69 हजार करोड़ का और ऋण बढ़ा दिया और हम सब को कर्जदार बना दिया। उन्होंने अपने क्षेत्र में 850 करोड़ रुपये के जे.डी.ए. के मार्फत काम करायें, जिसका भुगतान नहीं हुआ है। इसी तरह से, नगर निगम से 500 करोड़ के काम करायें, भुगतान नहीं हुआ। आज उसको हम भुगत रहे हैं, जनता भुगत रही है। सारा जोधपुर त्राहि-त्राहि कर रहा है। गटर लाइनें हैं, एक-एक फीट, छह-छह इंच की सड़कें हैं, चल नहीं सकते आदमी पैदल, और यहां तक कि डिलिवरी भी आटोरिक्शा में दो बार हो गयी है। बड़ी शर्मनाक बात है। परन्तु मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से बीस हजार किलोमीटर सड़कों के निर्माण का कहा है, उसमें जोधपुर की पी.डब्ल्यू.डी. और हाइवे की काफी सड़कें अच्छी हो जायेंगी। जोधपुर शहर की सड़कों के लिए मैं इस सदन के मार्फत मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि 500 करोड़ रुपये जे.डी.ए. को और 200 करोड़ रुपये निगम को दें तो हमारा शहर सुधर जाए।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह से अपने बजट में आधारभूत ढांचे के विकास में ऊर्जा, उद्योग, जल, रोड एवं हवाई यात्रा के लिए जो लक्ष्य रखा है, जो रोडमैप उन्होंने प्रस्तुत किया है, उसका मैं अभिनन्दन करता हूं।

महिलाओं के लिए गुरु गोलवलकर भामाशाह योजना को पुन: प्रारम्भ कर प्रत्येक महिला को 1,500 रुपये से बढ़ा कर दो हजार रुपये सीधे बैंक खाते में जमा कराने की घोषणा की। ग्रोथ रेट 8 से 9 प्रतिशत का लक्ष्य सराहनीय है। गुजरात की तरह श्रम कानूनों में आमूलचूल परिवर्तन कर, उत्पादन बढ़ाने के साथ कामदारों को सुविधा बढ़ाने की जो घोषणा की है, उसका स्वागत है।

मुख्य मंत्री ने वैट की दरों में असंतुलन दूर कर कई चीजों पर 14 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया है, उसका स्वागत है, लेकिन जोधपुर का हस्तशिल्प उद्योग, जिसका 1,500 करोड़ का निर्यात है, वह जीरो हो जायेगा। 5 प्रतिशत का वैट हम प्रतिस्पर्धा में झेल नहीं सकेंगे। हरियाणा, दिल्ली का उद्योग बढ़ जायेगा और हम पिछड़ जायेंगे। जोधपुर वैसे भी पिछड़ा हुआ पश्चिमी राजस्थान का एक शहर है।

सभापति महोदया, इसी तरह से मसालों पर जो 5 प्रतिशत वैट लगाया है, उसकी मैं निन्दा करता हूं। जोधपुर में श्रीमती विजयाराजे सिंधिया के नाम

(श्री कैलाश भंसाली)

से एक मंडी बनी है जिसमें मुख्य व्यापार जीरे का है। जीरे में अगर 5 परसेंट वैट रखा तो मंडी उजड़ जायेगी और सारा धंधा गुजरात चला जायेगा, क्योंकि गुजरात में नवम्बर, 2011 में जो वैट ढाई परसेंट था, उसको घटाकर जीरो परसेंट कर दिया। मेरा विनम्र निवेदन है मुख्य मंत्रीजी से कि इसको जीरो परसेंट कर हमको राहत दें, हमारे इस व्यापार को उजड़ने नहीं दें।

सभापति महोदया, पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार ने नई सड़कें बनाने और सीवर लाइन बनाने के जो अधूरे काम छोड़े हैं, वे जल्दी से जल्दी पूरे करवाये जायें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट। माननीय सदस्य जो वहां पर बैठे हैं, वरिष्ठ सदस्य जोधपुर से आते हैं, बहुत अच्छी अपनी राय दे रहे हैं, कृपा करके उन्हें सुनिये। पूरे सदन को डिस्टर्ब मत करिये।

श्री श्रीचन्द कृपलानी (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदया, हम तो इनको यह कह रहे थे कि डिनर की व्यवस्था करें।

श्री सभापति: ठीक है। अच्छा, आप बैठ जायें।

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): डिनर की व्यवस्था अपने घर पर ही है।

श्री सभापति: चलिये, आप सुनिये उनको और आप थोड़ा जल्दी से सम-अप करें।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): 10 मिनट तो मैं लूंगा। मेरा हक है।

श्री सभापति: नहीं, 7 मिनट हो चुके हैं।

श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर): 2 मिनट दे देंगी, आप, तो कृपा होगी।

हां, मैं निवेदन कर रहा हूं। जोधपुर की एयर कनेक्टिविटी नहीं है। बड़ा एक्सपोर्ट का मार्केट है। हमारे यहां से करीब 120 करोड़ का हर वर्ष एक्सपोर्ट होता है। जहाज आता है, सीधी दिल्ली से तो फ्लाइट है लेकिन जयपुर से या उदयपुर से नहीं है। उस कारण से बड़ी आवश्यकता है। अहमदाबाद, मुम्बई, कोच्चि, उनसे भी कनेक्टिविटी नहीं है। दक्षिण से हमारा कोई हवाई लिंक ही नहीं है। मुख्य मंत्रीजी से विशेष निवेदन करूंगा कि नागरिक उड्डयन मंत्रीजी से निवेदन कर जोधपुर में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने का प्रयास करें।

सभापति महोदया, सम्पूर्णानंद मेडिकल कालेज के तीनों हास्पिटलों में

(श्री कैलाश भंसाली)

अव्यवस्था है। फंगस से 39 मौतें आज कोई भूल नहीं रहे हैं और अब भी हर महीने 1-2 घटनाएं होती हैं। मैं धन्यवाद दूंगा राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ को कि उनके आने के बाद सफाई व्यवस्था अच्छी हुई है, अस्पतालों के रख-रखाव और डाक्टरों की उपस्थिति को ठीक किया है, लेकिन फिर भी डाक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ की तीनों अस्पतालों में कमी है। उसको जल्दी पूरा किया जाये।

सभापति महोदया, 3 बड़े काम वहां पेंडिंग हैं। महात्मा गांधी अस्पताल में आउटडोर वार्ड, उसके साथ में पार्किंग को जल्दी पूरा किया जाये; उम्मेद अस्पताल में 3 नये थियेटर और लेबर वेटिंग रूम बनायें और उनको पूरा किया जाये; इसी तरह से, मथुरादास माथुर में स्पेशयलटीज का जो वार्ड, चाइल्ड और वूमेन केयर का है, उसको जल्दी से पूरा किया जाये, जिससे राहत मिले।

उम्मेद अस्पताल में डेली 90 डिलिवरी हो रही हैं। इतना स्टाफ नहीं है, इतनी सुविधाएं नहीं हैं। लेबर रूम में, एक-एक बेड पर 3-3 महिलाएं सोती हैं, बच्चों को लेकर। बड़ी शर्मनाक बात है। लेकिन राजेन्द्र सिंहजी ने अतिरिक्त एक वार्ड को खुलवाकर उनके लिए व्यवस्था की है। उसके लिए उनको धन्यवाद।

सभापति महोदया, जोधपुर को हेरिटेज सिटी और स्मार्ट सिटी में लाया जाये। यहां के हेरिटेज से पर्यटन बढ़ेगा और जोधपुर का राजस्थान में नाम होगा। हेरिटेज के हिसाब से जोधपुर में जितने दर्शनीय स्थान हैं, सात दरवाजे हैं, उम्मेद भवन है, मेहरानगढ़ दुर्ग है, जसवंत थड़ा है, प्रताप मेमोरियल है, इन सबको विकसित किया जाये, इनका सौंदर्यीकरण किया जाये।

सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जे डी ए की विवेक विहार योजना तथा नगर निगम की गांधी नगर आवास योजना को शीघ्र पूरा किया जाये और आबंटन किया जाये।

सभापति महोदया, मेरे विधान सभा क्षेत्र के झालामंड में करीब 2 लाख लोग रहते हैं। वहां एक स्टेडियम हो, 30 बेड का सैटेलाइट अस्पताल हो मधुवन में तथा एक राजकीय सीनियर सेकण्डरी स्कूल वहां नहीं है, जो होना चाहिए। वहां प्राइवेट स्कूलों की तो भरमार है, हर गली में हैं। लेकिन सरकार का एक भी नहीं है। जो है, उसको क्रमोन्नत किया जाये।

सभापति महोदया, जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जिस तरह से

(श्री कैलाश भंसाली)

पदोन्नतियों में गड़बड़ियां हुई। यह शर्मनाक बात है। मैं सिंडिकेट का मेम्बर हूं, अभी मीटिंग इसलिए आगे लेनी पड़ी कि इसके 4 साल के अकाउंट्स प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। यह बड़ी शर्मनाक बात है। वी सी अब छुट्टियों पर चले गये हैं, यह नहीं बताया है कि वे कब तक वापस ज्वाइन करेंगे। मेरा निवेदन है कि इस अव्यवस्था को ठीक किया जाये। उनको 100 करोड़ रुपये की आवश्यकता है, जो सरकार थ्रू यू जी सी हमको दिलाये।

सभापति महोदया, दो मिनट, दो मिनट। माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में ई-गवर्नेंस और ई-गवर्नमेंट तथा सभी राजकीय विभागों में आनलाइन सिस्टम कर पारदर्शिता का जो लक्ष्य है, उसके लिए राजस्थान की जनता उनकी आभारी रहेगी।

ग्यारहवीं की बच्चियों को साइकिल देने की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं।

5 वर्षों में पशुपालन के द्वारा दूध का दुगना उत्पादन, राजस्थान में एक ऐसी क्रांति हो जायेगी जैसी अमूल डेयरी से गुजरात में हुई है और उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का बहुत-बहुत आभार।

कर प्रस्तावों में आपने सेल्स टैक्स, वैट में वार्षिक ई-रिटर्न के लिए तो 9 महीने का समय दिया है, परन्तु तिमाही के लिए समय नहीं दिया है। उसको 6 महीने किया जाये, ताकि पेनल्टी के बोझ से बहुत से व्यापारी नहीं मरें।

घटते हुए भू-जल स्तर को रोकने के लिए और पानी को सब्जियों और कृषि उपज में देने की पूर्व सरकार की जो योजना है, उसको आगे पूरा किया जाये।

झोझरी नदी में बहरे, गूंगे विद्यार्थियों के विद्यालय को समुचित स्टाफ तथा समानीकरण के कारण, इनके सारे स्टाफ का दूसरे विद्यालयों में ट्रांसफर, जहां उनकी कोई उपयोगिता नहीं है, मेरा निवेदन है कि उस स्टाफ को वापस लगाया जाये और मूक बधिर के लिए उनको दिया जाये।

सभापति महोदया, अंत में, जो हमारी मुख्य मंत्रीजी ने शानदार और विजनरी प्रोजेक्ट 2014-15 प्रस्तुत किया, उसके लिए राजस्थान की जनता की ओर से तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जनता की तरफ से बहुत-बहुत आभार। धन्यवाद।

आपने जो समय दिया, उसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय श्री बनवारीलालजी सिंघल।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदया, राजस्थान के बजट 2014 पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा राजस्थान के इतिहास में पहली बार एक अनूठी पहल की गयी, कि आम जन से बजट बनाने के बारे में प्रस्ताव मांगे गये, सुझाव मांगे गये। यह राजस्थान के लोकतंत्र के इतिहास में पहली बार हुआ। 3,256 लोगों ने आनलाइन अपने प्रस्ताव दिये और उन बजट सुझावों को शामिल करते हुए राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्री ने राजस्थान के बजट की तैयारी की। यह इस प्रकार का बजट है, जिसमें किसी भी प्रकार के अतिरिक्त करों का बोझ जनता के माथे पर डाले बिना, राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी ने लोक-इच्छानुसार जो बजट पेश किया है, निश्चित रूप से राजस्थान की जनता की इच्छा का बजट है, जिसके दूरगामी सुखद परिणाम प्राप्त होंगे।

सभापति महोदया, मैं सर्वप्रथम धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान की यशस्वी मुख्य मंत्रीजी को, पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार आये-दिन समाचार पत्रों में विज्ञप्ति निकालती थी, रिक्तियां निकालती थी और अपने ही चेले-चपाटों के माध्यम से अदालतों में कोई न कोई मुकदमा लगवाकर, उन पर स्टे प्राप्त कर, लोगों से जिस प्रकार का छल किया जाता था, राजस्थान की माननीया मुख्य मंत्रीजी की इच्छानुसार अलवर में सर्वप्रथम, जैसे ही सरकार बदली, राजस्थान में 329 सफाई-कर्मियों की भर्ती करके एक इतिहास कायम करने का और समाज के अन्दर एक ऐसा विश्वास पैदा करने का काम हुआ, जो माननीया मुख्य मंत्रीजी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है।

पूर्ववर्ती सरकार जो अब, आज तो बिलकुल ऐसे जैसे मैदान साफ हो गया। ऐसा लगता है उन लोगों ने तय कर लिया है कि पांच वर्ष तक हाउस में आने की ही आवश्यकता नहीं है। इस तरह से आज उन्होंने अपने आप को विलोपित किया है।

आये-दिन हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धराजी पर मनगढ़ंत आरोप लगाने का काम करते रहते थे। अनेक बार ऐसे अवसर आये पिछले हाउस में जब हमने प्रामाणिक तौर पर माननीय मुख्य मंत्रीजी, अनेक मंत्रियों पर, आरोप नहीं, प्रामाणिक तौर पर उनके घोटालों को उजागर किया। आज पुन: मैं एक बात कहना चाहता हूं इस बजट के माध्यम से, जो अलवर

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

का मास्टर प्लान 2031 राजस्थान की पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान की मिनिस्ट्री के साथ मिलकर तैयार किया, सारी ग्रीन बेल्ट्स, सारी ऐसी ग्रीन आचार्ड की जमीन, जिन जमीनों का कभी भी मास्टर प्लान में लैण्ड यूज चेंज नहीं हो सकता, उन सारी जमीनों को भ्रष्टाचार का ताण्डव करते हुए, जो हरित पट्टी थी, उन सब हरित पट्टियों को आवासीय और अन्य उपयोग के लिए आरक्षित करने का काम उस मास्टर प्लान में पैसे ले लेकर किया। इस बाबत समाचार पत्रों में समाचार भी आयें और मैंने भी माननीय मुख्य मंत्रीजी से शिकायत की, लेकिन चूंकि पूरी की पूरी सरकार आमूलचूल भ्रष्टाचार में आकण्ठ डूबी हुई थी, तो न कोई जांच कराई और न ही इस पर रोक लगाने का किसी भी प्रकार का उन्होंने कोई प्रयास किया। मैं आज भी आपके माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि 2013 का जो मास्टर प्लान अलवर का तैयार हुआ, उसकी अगर आज भी जांच कराई जायेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आयेगा, पूर्ववर्ती सरकार के भ्रष्टाचार की जो परतें हैं वे परत दर परत खुलेंगी और हो सकता है कि बहुत से लोगों को ऐसी जगह जाना पड़े, जहां उनके कुछेक मंत्री आराम आज भी जोधपुर और कई दूसरी जेलों में फरमा रहे हैं।

मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बिन्दु की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। पिछली सरकार में हमारे जो साथी विधायक महोदय थे, जिनकी फाइलें अब जनता के कोप से जमा हो चुकी हैं और वे लोग आज अपने-अपने घरों में आराम फरमा रहे हैं। पिछले हाउस में जब बातचीत आई थी तो बड़े आरोप लगाये गये थे माननीया वसुन्धराजी पर कि 2003 से 2008 के मध्य वसुन्धराजी ने गौ-रक्षा के नाम पर कुछ नहीं किया और राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने बहुत कुछ किया, गौ-सेवा निदेशालय बनाया और पता नहीं, किस-किस तरह के अनुदान की बात की। उस दौरान भी मैंने कहा था और आज मैं पुन: कहना चाहता हूं कि आज राजस्थान में गौ-वंश पर बहुत भारी संकट है। ऐसी स्थिति हो रही है कि रोजाना कसाइयों के हाथों हजारों-हजारों की मात्रा में गौ-वंश ले जाया जाता है। गौ-रक्षकों के द्वारा पकड़ा जाता है, राजस्थान पुलिस के द्वारा पकड़ा जाता है। इसको बचाये जाने की आवश्यकता है।

माननीय सभापति महोदया, माननीय कृषि मंत्रीजी यहां विराजमान हैं,

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने एक सर्कुलर जारी किया था 20.08.2009 को, जिसमें इन्होंने प्रति वर्ष पांच प्रतिशत मण्डी शुल्क जो प्राप्त होता है, मण्डी की प्राप्त आय में से पांच प्रतिशत प्रति वर्ष पंजीकृत गौशालाओं को देने का एक सर्कुलर जारी किया था। उसके कुछ समय बाद ही इन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, कांग्रेस की सरकार ने, 'प्रति वर्ष' शब्द को विलोपित किया जाता है, जिससे यह साबित होता था कि यह प्रति वर्ष नहीं होकर, केवल एक वर्ष के लिए रहेगा, अकाल को देखते हुए। फिर बड़ा जोरदार काम इन्होंने किया, कांग्रेस की सरकार ने एक और सर्कुलर निकाला कि पिछले दोनों सर्कुलर्स को वापस लिया जाता है। यानी, वह गौ-रक्षा के नाम पर वाहवाही लूटने वाली सरकार, उन्होंने जो भी राशि देने की घोषणा की थी, वह सारी राशि वापस लेने के तीन सर्कुलर एक साथ जारी किये।

मैं मांग करना चाहता हूं, माननीय कृषि मंत्रीजी, आपके माध्यम से सरकार से कि राजस्थान में गौ-वंश को बचाने के लिए कृषि उपज मण्डी समितियों की आय का एक निश्चित हिस्सा गौ-शालाओं को दिया जाये ताकि आज जो भीषण महंगाई है, आज इस महंगाई के समय में गौ-शालाओं के चारे का नितान्त अभाव है, जिसके कारण से गायें भूखों मरने को मजबूर हैं। बहुत सारे ऐसे पशुपालक जो अपनी गायों का सुबह-शाम दूध निकालते हैं और सड़कों पर लोगों के डण्डे खाने के लिए इधर-उधर मुंह मारने के लिए छोड़ते हैं, ऐसी गायों का भी पोषण निश्चित रूप से ऐसी गौ-शालाओं में हो सकेगा, अगर मण्डी के माध्यम से कुछ राशि गौ-शालाओं को मिलेगी।

मैं धन्यवाद करना चाहता हूं माननीया मुख्य मंत्रीजी का भी, जिन्होंने राजस्थान में गौ-वंश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उस गौ-सेवा आयोग के स्थान पर राजस्थान में गो-पालन मंत्रालय की घोषणा की है। निश्चित रूप से यह राजस्थान के गौ-वंश को बचाने के लिए मील का पत्थर साबित होगा।

एक ऐसी व्यवस्था जो यू पी ए फर्स्ट के समय की गई थी, वैट, तब तक राजस्थान में और देश के सभी प्रदेशों में सेल्स टैक्स की व्यवस्था थी और सेल्स टैक्स को सभी सरकारें अपने-अपने हिसाब से तय करती आई थीं। यू पी ए फर्स्ट के समय में केन्द्र सरकार ने यह व्यवस्था की कि सभी प्रदेशों में से सेल्स टैक्स को हटाकर, समान कर प्रणाली रहे, एक राज्य से दूसरे

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

राज्य में तस्करी नहीं हो, एक राज्य से दूसरे राज्य में किसी भी प्रकार की वस्तु पर टैक्स अलग-अलग नहीं हो, जिससे दरों में समानता रहे। इस मंशा को रखते हुए वैट की व्यवस्था की थी। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उस वैट व्यवस्था को भी आज जो वैट लागू किया गया था, अनेक सरकारों ने इसका विरोध भी किया लेकिन शनैः शनैः सभी सरकारों को इस वैट को स्वीकार करना पडा और अपने प्रदेशों में से सेल्स टैक्स को विलोपित करना पड़ा। इसका जो उद्देश्य था, सभी प्रदेशों में समान कर व्यवस्था, वह आज बिलकुल समाप्त हो गई और सभी प्रदेश उस सेल्स टैक्स की तरह से उस वैट की व्यवस्था को अपने हिसाब से चला रहे हैं और वही जो विकृत रूप था, आज भी देखने को मिलता है।

हमारे सीनियर माननीय सदस्य, राव राजेन्द्र सिंहजी ने भी इस बाबत सुबह ध्यान आकर्षण किया था, सदन का। मैं भी कहना चाहता हूं, आपने तो गंगानगर और आसपास के क्षेत्रों के लिए कहा, लेकिन हमारे बिलकुल साथ में अलवर जिले से लगता हुआ हरियाणा है, डीजल में पांच रुपये लीटर और पेट्रोल में छह रुपये लीटर का अलवर और हरियाणा में अंतर है। जिससे बहुत बड़ी तस्करी राजस्थान में होती है। राजस्थान के पेट्रोल पम्प और डीजल पम्प के डीलर्स हैं, उनको बहुत बड़ा नुकसान सेल का होता है। उधर हरियाणा की बिक्री इस कारण से बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है।

राजस्थान की कांग्रेस की सरकार ने 2008 के अपने चुनाव घोषणा पत्र में इस बाबत वादा भी किया था कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार आयेगी तो डीजल और पेट्रोल की दरों पर वैट को हरियाणा के समान करने का काम किया जायेगा, लेकिन ऐसी सरकार जिसको न तो यह ध्यान रहता था कि उन्होंने क्या घोषणा पत्र में लिखा है, न उनको यह ध्यान रहता था कि क्या अपने बजट में घोषणा की है, बस केवल एक ही काम था, जिस प्रकार से अभी हमारे माननीय सदस्य, मदनजी राठौड़ कह रहे थे, रिपीट कर-करके उन्होंने पांच वर्ष निकाले और उसका परिणाम इन्होंने भुगता। मुझे याद आती है वह बात, जब इन्हीं के एक निवर्तमान सांसद ने कहा था, जयपुर से दिल्ली जाते समय, कांग्रेस के कारनामों की वजह से कांग्रेस की वह हालत होने वाली है कि एक मिनी बस में कांग्रेस के विधायक आकर राजस्थान की विधान सभा में बैठेंगे, और वह बात पूर्णतः प्रमाणित हुई। आज राजस्थान में, देश में चलने

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

वाली मिनी बस की, सबसे छोटी जो बस होती है, उसकी संख्या 22 होती है, तो शायद उन्होंने जो भविष्यवाणी की थी, एक ड्राइवर को छोड़कर बाकी 21 ही बचे हैं। ड्राइवर की सीट उन्होंने छोड़ दी। उसको भी अगर, हो सकता है कि कंडक्टर की छोड़ते तो इनके विपक्ष का नेता भी नहीं बन पाता राजस्थान में।

राजस्थान की सरकार के पूर्व मुखिया, श्री अशोकजी गहलोत ने बहुत सपने दिखाये अफोर्डेबल हाउसिंग के, राजस्थान के हर आदमी को घर देंगे, पांच लाख मकान बनाकर देंगे, और ऐसी धराशायी योजना हुई कि लोगों के सपने चकनाचूर हुए। पचास हजार छोड़ो, पांच हजार घरों का कब्जा भी सरकार पांच वर्ष में नहीं दे पाई और मेरा मानना है कि इसी कारण से राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस की सरकार को पराजय का मुंह देखना पड़ा। मैं मांग करूंगा हमारी सरकार की मुखिया से कि इस ओर भी विशेष तौर पर ध्यान दिया जाये।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, अलवर में राजर्षि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के लिए वित्त की जो घोषणा की गई है। मैं इसमें यह भी मांग करना चाहता हूं, लम्बे समय से मैं भी और अलवर के सब लोग मांग कर रहे हैं कि इस यूनिवर्सिटी को अलवर जिले के मुख्यालय अलवर शहर में ही खोला जाये तो निश्चित रूप से आम जन के लिए उपयोगी रहेगी, आम विद्यार्थी के लिए उपयोगी रहेगी।

अलवर में जो मेडिकल कालेज की घोषणा की गई है, वह निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी हमारे बीच में यहां आसन पर विराजमान हैं, आपसे मैं प्रार्थना करना चाहता हूं, जितनी जल्दी हो सके, चूंकि अलवर बड़ा जिला है, जिसमें आधा-सा हरियाणा इलाज के लिए आता है, भरतपुर जिला आता है, आसपास के क्षेत्रों के बहुत लोग आते हैं, अलवर के सामान्य चिकित्सालय पर बहुत दबाव रहता है, अगर मेडिकल कालेज की जो घोषणा आपने की है, यह शीघ्र स्थापित होगा तो इससे अलवर के लोगों को, साथ ही बाहर से आने वाले लोगों को भी लाभ होगा।

मैं कुछ विशेष बिन्दुओं के बारे में बताना चाहता हूं। एक विशेष योजना राज्य सरकार चला रही है आर एस सी आई टी के नाम से। इस नाम से जो प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जाते हैं, इस विसंगति की ओर मैं हाउस का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, ये ऐसे केन्द्र हैं जहां आर एस सी आई टी में

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

केवल सर्टिफिकेट बांटने का काम हो रहा है। आज आर पी एम टी और आर पी एस सी की परीक्षाओं पर लगातार सदन में चिंता व्यक्त की गई है। यह जो आर एस सी आई टी का सर्टिफिकेट सरकारी कर्मचारियों को नौकरियों के लिए लिया जाना अनिवार्य किया गया है, यह केवल गोरखधंधा हो गया, पैसे लेकर आर एस सी आई टी के सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं।

आज शिक्षा मंत्रीजी भी हमारे बीच में नहीं हैं, मैं और ध्यान दिलाना चाहता हूं कि प्रदेश में निजी बी एड कालेजेज में पैसे लेकर जो बी एड कालेज के विद्यार्थी हैं, उनको साल भर का बीस हजार, पच्चीस हजार, तीस हजार रुपया लेकर हाजिरी से माफी दी जाती है। जो विद्यार्थी बी एड का पढ़ेगा नहीं, आगे आने वाले समय में यदि उसको टीचर के रूप में नौकरी मिलेगी तो क्या वह शिक्षण कराएगा? इसकी भी जांच किया जाना, आर एस सी आई टी सेंटर्स की जांच किया जाना, बी एड कालेजेज की जांच किया जाना, बहुत जरूरी है।

एक स्वास्थ्य का प्रश्न है, ओक्सीटोक्सिन इंजेक्शन जो आज बाजार में 50 पैसे, एक रुपये का मिल रहा है, भैंसों को भी लगाया जाता है, सब्जियों में भी लगाया जा रहा है। इससे युवकों में नपुंसकता और महिलाओं में बांझपन की दिक्कत आ रही है। प्रतिबंधित होने के बावजूद हर दुकान पर यह इंजेक्शन उपलब्ध है। माननीय चिकित्सा मंत्रीजी इसकी जांच करवाकर इंजेक्शन पर रोक लगाने का काम करें।

अपराध की दृष्टि से पिछले 5 वर्ष में राजस्थान की इस कांग्रेस की सरकार ने अलवर को जिस हालत में छोड़ा था, मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोगों ने, अलवर के सभी विधायकों ने, अलवर के सभी प्रत्याशियों ने 2013 के चुनावों में यह कहकर चुनाव लड़ा था, राजस्थान में भाजपा की सरकार आएगी, हम कानून-व्यवस्था का माकूल इंतजाम देंगे, कानून-व्यवस्था का राज देंगे। जिस तरह से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने अलवर में और पूरे राजस्थान में, अलवर से भिवाड़ी जाना, अलवर से तिजारा जाना, एक ऐसा चुनौतीपूर्ण काम हो गया था; हमारे साथी विधायक, श्री रामहेत यादव द्वारा 2008 से 2013 के विधान सभा काल में इस हाउस में मांग की थी कि अलवर में कानून-व्यवस्था समाप्त हो गयी है, अलवर को सेना के हवाले किया जाय, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

मुख्य मंत्री महोदया को, जिस प्रकार की कानून-व्यवस्था उन्होंने दी है उससे आज अलवर में शांति-व्यवस्था कायम हुई है।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री कालू लाल गुर्जर (मुख्य सचेतक): सभापति महोदया, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन की कार्यवाही एक घण्टे के लिए और बढ़ायी जाय।

श्री सभापति: प्रश्न यह है कि सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया जाय?

(स्वीकृत)

सदन का समय एक घण्टे के लिए बढ़ाया गया।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): सभापति महोदय, दो बिन्दु मेरे और हैं। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने...

श्री सभापति: आप अपने दो बिन्दु बिलकुल संक्षेप में कह दीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): बिलकुल संक्षेप में बोल रहा हूं, विषयवार ले रहा हूं। फ्लैट्स की रजिस्ट्री पर जो तर्कसंगत करने का काम किया है डी एल सी और स्टाम्प ड्यूटी को, मैं इस पर भी धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री महोदया का। इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क है, चूंकि इंडिपेंडेंट घर कोई बनाता है तो उसमें अपना लाभ भी बनाता है, जिसमें पानी की भी अत्यधिक खपत होती है, बिजली की भी अत्यधिक खपत होती है, लेकिन जब मल्टीस्टोरी हाउसिंग में कोई जाता है तो पानी और बिजली की बहुत बचत होती है। फ्लैट संस्कृति को बढ़ावा देने से जगह की बचत होती है। इसके लिए माननीया मुख्य मंत्री...(व्यवधान)

श्री सभापति: अच्छी बात है, आप अच्छी बात कह रहे हैं, इसीलिए वे बेंचेज बजा रहे हैं।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): हम भी बजाएंगे जब ये बोलने लगेंगे तो। हम भी ऐसे ही करेंगे, जब ये शुरू करेंगे, तब से ही शुरू करेंगे।

श्री सभापति: जल्दी, जल्दी, माननीय सदस्य।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): यह तो हमारे हाथ में भी है। टेबल हमको कौनसी बजानी नहीं आती?

चलो, मैं धन्यवाद करता हूं, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा हमारे साथियों को। यह अच्छी बात थोड़े ही है।

श्री सभापति: आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। अंतिम लाइन जो कहनी हो, वह कह दीजिए।

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): धन्यवाद, साहब, धन्यवाद। अच्छी बात है? मजाक बना रखा है, साहब, हाउस को। ऐसे थोड़े ही है। यह गलत है। (व्यवधान) लगातार डिस्टर्ब कर रहे हैं। ऐसे थोड़े ही होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री शंकर लालजी शर्मा।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): सभापति महोदया, आज मैं आपके आदेश से 2014 के इस बजट के ऊपर अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। आपने समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। हम हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री, श्रीमती वसुन्धरा राजेजी का धन्यवाद देना चाहते हैं। गत 5 वर्षों में गहलोत सरकार ने एक ऐसा वित्तीय प्रबंधन, अकुशल प्रबंधन करने के बावजूद और इससे सरकार को इतना घाटा देने के बावजूद, इतना अच्छा बजट दिया, उसके लिए मुख्य मंत्रीजी का कोटि-कोटि हृदय से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदया, इस बजट के आंकड़ों के ऊपर तो बहस हो चुकी और आंकड़ों के हिसाब से शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने बता दिया कि कांग्रेस के आंकड़े, जो गत सेशन था, उसमें अशोकजी गहलोत ने जो आंकड़े दिये थे और अभी भी आज हमारे सदस्य ने बताया कि कांग्रेस ने कितने असत्य आंकड़े देकर इस बजट का, अपने आपका प्रावधान किया। इसलिए आंकड़ों के ऊपर न जाकर, इस बजट की खासियत का कारण, हमारी मुख्य मंत्रीजी का कुशल बजट कैसे आया? क्योंकि उन्होंने सुराज संकल्प यात्रा के दौरान एक-एक गांव, एक-एक ढाणी का अवलोकन किया और उसी अवलोकन के अन्दर आम प्रजा को यह बताया गया कि हमारा 2008 का बजट कैसा था, हमने इस राजस्थान को कहां पहुंचाया था और इसके विकास में क्या गति दी, और इस कांग्रेस सरकार ने इस राज में क्या हालात कर दिये। जब उन्होंने एक-एक गांव और एक-एक ढाणी को देखा और आम जनता को यह बताया, उसका नतीजा यह निकला कि राजस्थान के अन्दर आज चारों

(श्री शंकर लाल शर्मा)

तरफ जो दिखायी दे रहा है तो केवल मात्र वसुन्धराजी की टीम दिखायी दे रही है, बाकी सारे के सारे गायब हो गये। उसी का नतीजा है, हमारा यह कुशल बजट भरतपुर, बीकानेर डिविजन की यात्राओं का नतीजा है। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी को देखकर यह बजट बना और उसी के कारण आज हम इस बजट की तारीफ राजस्थान में केवल मात्र इस सदन में ही नहीं, हर आदमी, हर वर्ग, हर जगह हो रही है।

शायद हमारे विपक्ष के भाई, अभी हमने सुना था कि वे तो केवल इसलिए चले गये कि हमारे इस इतने से छोटे बजट को क्या सुनना, यह कोई ऐसा खास बजट नहीं है जिससे राजस्थान की तरक्की हो। उसके कारण हमारे कांग्रेस भाइयों का जाना और सोचना, क्योंकि वे बाहर बैठे बातें कर रहे होंगे कि क्या राजस्थान का एक साल का इतना बजट दिया। यह बजट तो हमारे विश्व प्रसिद्ध घोटाला प्रतियोगिता के अन्दर प्रथम, द्वितीय एवं थर्ड आने वाले उनके भाई, अगर उन चार आदमियों के घोटाले का बजट आ जाता तो राजस्थान का विकास वे यों ही कर देते। इसलिए वे सोच रहे हैं कि हम उस घोटाले की रकम यहां लेकर आ जाएं तो विकास कर दें। इसलिए वे यहां न बैठकर यहां से चले गये।

मैं पहली बार आपके सामने इस बजट के उपलक्ष्य में खड़ा हुआ हूं। पहली बार मैं आज इसके ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं निवेदन करूंगा कि टोकाटोकी को सहन करने की हिम्मत मुझमें नहीं है। उसके बावजूद हम यही बताना चाह रहे हैं कि जो 163 और 25 आयी हैं, मुझे खुशी हो रही है कि विपक्ष की कुछ सीटों पर हमारे भाई लोग वहां जाकर बैठे हैं और इसका कारण यही है कि जो बजट अबकी बार हमें मिला है, जिस तरीके का बजट हमारी वसुन्धराजी ने दिया है और जिस तरह से माननीया मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट की घोषणा की है, तो शायद अगली बार वे सीटें हमारे भाइयों से भर जाएं, यह उम्मीद करके हम चल रहे हैं। यह सही भी है कि हमारे इस बजट के कारण 163 में ज्यादा मत फैलो, यह बात सही है कि अब 163 के बाद ज्यादा सीटें और मिलने वाली हैं।

मैं, आदरणीया, दौसा क्षेत्र से आया हूं और दौसा में 10 सालों से, आदरणीय खाद्य मंत्री बैठे हुए हैं, उन्हीं के डिपार्टमेंट का कब्जा हमारे दौसा क्षेत्र से था। एक भाई तो, अच्छा रहा, अपनी नीतियों के कारण अपने को छोड़कर चला गया, जबकि दूसरे आज कांग्रेस की वकालत के कारण बार-बार इस सदन

(श्री शंकर लाल शर्मा)

का समय बरबाद करते हैं। सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि दौसा के अन्दर हमारे खाद्य विभाग का क्या हाल है। आपने देखा होगा कि कल-परसों ही दो ट्रक खाद के पकड़े गये हैं। खाद्य विभाग की नीति है कि अगर कोई डीलर को पकड़ता है तो उसकी जांच होती है। जांच कौन करता है, जो उनको हटाने वाले हैं। हटाने वाले, गत समय के अन्दर हमारे एक डीलर दुबई के अन्दर थे, और दुबई के अन्दर उनको हटाया गया। हटाने के

(21.00 बजे)

बाद उनकी जांच हुई और जांच के बाद में उनको पुनः डीलरशिप आबंटित हो गई। अब यह मालूम नहीं है कि दुबई में उनकी जांच करने के लिए कौन गया था। शायद आपको मालूम नहीं हो, तो मोहन लालजी टोल्डा हैं, जो कि हमारे सिकराय के हैं, उनको दुकान दुबारा आबंटित पिछले कार्यकाल में कर दी गई। यह था हमारे पिछले कार्यकाल का हाल कि दुबई में बैठा हुआ डीलर यहां दुकान चला रहा है। यह दु:ख की भी बात है। हमारी यह ऐसी नीति है, एक ऐसी नीति है कि पंच बदलते हैं, सरपंच बदलते हैं, एम एल ए और एम पी बदलते हैं, सरकारें बदलती हैं लेकिन राजस्थान के डीलर वे के वे ही रहते हैं। येन-केन-प्रकारेण आज हटाओ और कल दुबारा वे ही डीलर वापस आकर वहां बैठ जाता है।

अगर हमें वाकई हमारी खाद्य सामग्री आम जनता तक पहुंचानी है, ईमानदारी से सामग्री उनके पास पहुंचानी है। तो इस डीलर प्रथा में कुछ बदलाव करना पड़ेगा, उनको हटाने के लिए कोई कानून लाना पड़ेगा। केवल मात्र यह नहीं कि 90 दिन तक जांच कर लो, नहीं करोगे तो उन्हीं को देना पड़ेगा। अगर एक डीलर को हटाया तो बगल वाले डीलर को उसका चार्ज दे दिया गया। मतलब, एक डीलर और पांच दुकानें। अब वह कहां वितरण करेगा? कैसे वितरण करेगा? क्या वितरण करेगा?

मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि दौसा के अन्दर बाहर के स्टूडेंट्स रहते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए केरोसीन वितरण किया जाता है। मैं आपके द्वारा यह बताना चाहूंगा कि दौसा के अन्दर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें कोई भी बच्चा आज के जमाने में केरोसीन लेकर स्टोव से खाना नहीं बना रहा है, न वह लालटेन को काम में ले रहा, लेकिन 6 हजार लीटर केरोसीन उनके नाम से आबंटित हो रहा था। जब हमने कार्यवाही चालू की कि यह केरोसीन कहां जा रहा है, तो अब जाकर 6 हजार की जगह 500 लीटर कर दिया गया है।

मेरे कहने का मतलब यह है....(व्यवधान) सभापति महोदया, मैं तो पहली बार खड़ा हुआ हूं। अभी तक तो दौसा की समस्याएं हैं। हमारे भाई अभी

(श्री शंकर लाल शर्मा)

कह रहे थे कि हम ऐसी जगह पर रह रहे हैं। मैं खाद्य सामग्री के बारे में बता रहा था कि कृपया इसके ऊपर आप ठोस कार्यवाही करके इस डीलरशिप को जब तक नहीं हटायेंगे, इस सिस्टम को जब तक नहीं बदलेंगे, तब तक हमारी सामग्री गरीब तक नहीं पहुंचेगी।

दौसा की जहां तक पानी की समस्या है, यह हालत सही है कि दौसा आज रेगिस्तान के रूप में बनता जा रहा है। दौसा में जो जांच हुई है....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, थोड़ा संक्षेप में बोलिये आप। आप अपने पाइंट्स बोलिये, लेकिन संक्षेप में, थोड़ा जल्दी-जल्दी बोलिये।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): मैं, मंत्री महोदय, आपको बता रहा हूं कि 'इसरो' के द्वारा 2002 की जांच हुई है कि दौसा क्षेत्र रेगिस्तान की तरफ बढ़ रहा है और 26 प्रतिशत रेगिस्तान के अन्दर तब्दील हो गया है। कारण एक ही है कि दौसा के अन्दर पीने के लिए पानी नहीं है, दौसा के अन्दर फ्लोराइड युक्त पानी है। हमारी योजनाएं पिछले कई वर्षों से, जैसे कि आज ईसरदा डैम से आने का है, कभी बीसलपुर डैम से आने का है लेकिन जब तक दौसा को बाहर से पानी नहीं पिला सकते, दौसा में वैसे ही हमारे कहावत है कि 'दौसा शहर चिड़ी का बासा, अन्न घणों, पर पाणी को तासा'; हमारे दौसा शहर को आपके द्वारा हम मुख्य मंत्री साहिबा से चाहेंगे कि हमारी समस्या, जो कि पानी की सबसे बड़ी विकट समस्या है, उसके ऊपर ध्यान देकर समस्या से निदान दिलवायें।

हमारे स्वास्थ्य मंत्री महोदय यहां बैठे हुए हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उन्होंने दौसा क्षेत्र का दो बार दौरा किया और आपके दौरे के कारण इतना फायदा हुआ कि दौसा का जो हास्पिटल है, उसकी साफ सफाई और उसकी व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। लेकिन आज भी दौसा कांस्टिट्यूएंसी में 18 डाक्टर कम हैं; आज हमारे यहां 15 कम्पाउण्डर और 21 ए.एन.एम. कम हैं। आज हमारे सी टी स्कैन और अन्य मशीनें नहीं हैं। वहां ट्रोमा बिल्डिंग बन गई है, इमरजेंसी बन गई, बिल्डिंग के अन्दर कोई कमी नहीं है लेकिन वह बिल्डिंग डाक्टर और मशीनरी के कारण खाली पड़ी है।

हमारे दौसा में दो हाइवे 11 और 11ए हैं, आये-दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं और एक्सीडेंट के कारण हालत यह होती है कि अस्पताल में लाया जाता है और वहां से सीधा जयपुर रेफर किया जाता है। अगर हमारे इस दौसा

(श्री शंकर लाल शर्मा)

हास्पिटल में भी इमरजेंसी और ट्रोमा वार्ड करके, सीनियर डाक्टर्स आप वहां उपलब्ध करा देंगे तो जयपुर का भार भी कम होगा और उस क्षेत्र की उन्नति भी होगी।

मैं आपके द्वारा शिक्षा क्षेत्र के बारे में कहना चाहता हूं। वैसे तो हमारे दौसा में 9,500 बच्चे पी.जी. कालेज में हैं। मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने अलग-अलग फैकल्टी के अनुसार कालेज को बांट दिया, लेकिन राजस्थान के अन्दर दौसा के अन्दर 1,850 लड़कियां हैं और जनसंख्या के हिसाब से गर्ल्स कालेज में हाइएस्ट लड़कियां हैं। हमारा दौसा क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, शायद आपको पिछले दिनों का मालूम भी होगा, यह तो शुक्र करो हमारी मुख्य मंत्री साहिबा का कि जिनके शासन के कारण, दौसा के अन्दर आम जन अपने ताण्डव नृत्य के कारण हमारे रात और दिन कोई बिजनेस नहीं कर सकता था, बहन-बेटी बाजार में नहीं आ सकती थीं, हालत यह थी कि कोई मोटर साइकिल और बोलेरो बाजार में खड़ी नहीं कर सकता था, पर आज उसी दौसा क्षेत्र में उनके कुशल प्रशासन के कारण शांति तो आ गई। लेकिन हमारी लड़कियां आज भी को-एजुकेशन में जाने से डरती हैं, उनके मां-बाप उन्हें को-एजुकेशन में नहीं भेजते। अगर हमारे उस गर्ल्स कालेज को पी.जी. कालेज में बदल देंगे तो दौसा क्षेत्र, जो कि अपने आप में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है उनकी बच्चियां भी आगे शिक्षा ग्रहण कर लेंगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप।

श्री शंकर लाल शर्मा (दौसा): माननीय सभापति महोदया, ठीक है, आपने मुझे फिर भी इतना टाइम दिया। उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं।

आखिर में, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि हमारी मुख्य मंत्री महोदया ने प्रदेश की जनता के लिए 2014 में कोई भेदभाव नहीं किया। सभी वर्गों को, गरीब को, अमीर को, व्यापारी को और हर क्षेत्र के वर्ग को जो यह बजट दिया, उसके लिए राजस्थान आगे खुशहाली के रास्ते पर बढ़कर बड़ी प्रगति करेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री भागीरथजी चौधरी।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): आदरणीय सभापति महोदया, आपने परिवर्तित बजट 2014-2015 पर मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

(श्री भागीरथ चौधरी)

सम्माननीय सभापति महोदया, मैं राजस्थान की दूरदर्शी मुख्य मंत्री महोदया का आभार और धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने पूर्ववर्ती सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन के कारण मरी हुई अर्थव्यवस्था को पुन: पटरी पर लाने एवं 'सर्वे भवन्तु सुखिन: सर्वे सन्तु निरामया' का संकल्प लेकर एक संतुलित एवं समन्वित विकास वाला परिवर्तित बजट 2014-15 राजस्थान की जनता के लिए प्रस्तुत किया। पिछली सरकार की अदूरदर्शी सोच एवं वित्तीय कुप्रबन्धन से राज्य सरकार को उबार कर माननीया मुख्य मंत्रीजी द्वारा विजन 2020 का संकल्प राजस्थान को विकसित एवं समृद्धशाली राज्य बनाने के लिए लिया गया है। यह सार्थक है उन कोटि-कोटि मतों का, कोटि-कोटि जन आकांक्षाओं का जिन्होंने आपको प्रतिनिधित्व दिया है।

सभापति महोदया, पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने हजारों-हजार करोड़ का राजस्व घाटा इन मुख्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर एक बहुत बड़ा बोझ बनाकर सुपुर्द किया है। सभापति महोदया, फिर भी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी ने आर्थिक विकास दर को 12 प्रतिशत की दर से बढ़ाने का संकल्प लिया है, यह बहुत बड़ा सराहनीय और बधाई का कार्य है।

सभापति महोदया, पूर्ववर्ती सरकार की नीतियों के कारण राज्य का विकास अवरुद्ध हुआ है। राज्य के विकास में जो बाधाएं उत्पन्न हुई हैं, उसे पुन: पटरी पर लाने के लिए हम सब का दायित्व है कि हम सब सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें। मुझे पूर्व प्रधान मंत्री अटल बिहारी वाजपेयीजी की चार पंक्तियां याद आती हैं जो हमें पिछली सरकार के कुप्रबन्धन से उत्पन्न बाधाओं से निपटने के लिए कदम मिलाकर चलने के लिए प्रेरित करती हैं...

'बाधाएं आती हैं, आयें, घिरें प्रलय की घोर घटाएं,
पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं।
निज हाथों में हंसते-हंसते आग लगाकर जलना होगा,
कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा।।'

सभापित महोदया, राजस्थान का आधारभूत ढांचा तय करता है कि राज्य का आर्थिक ढांचा कैसा हो। मुझे खुशी है कि परिवर्तित आय व्ययक 2014-2015 में इस पर विशेष ध्यान देकर, 20 हजार किलोमीटर सड़कों के योजनाबद्ध विकास के साथ, OPRC पद्धति द्वारा सड़कों के रख-रखाव की व्यवस्था एवं सड़क मेंटीनेंस के महत्वपूर्ण प्रावधान के साथ-साथ ग्राम पंचायत

(श्री भागीरथ चौधरी)

मुख्यालयों पर RCC सड़क एवं छोटे गांवों के लिए 1 हजार 294 किलोमीटर की सड़कों का प्रावधान सराहनीय है।

यह मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदया से निवेदन करना चाहूंगा कि सड़कों की गुणवत्ता पर विशेष प्रावधान किया जाये। आम जन से सड़कों की गुणवत्ता पर शिकायत के लिए कोई हेल्प लाइन नम्बर एवं तत्काल कार्यवाही के लिए मोबाइल यूनिट हो जो कि त्वरित कार्यवाही करें। क्योंकि सड़कें बनाने के बाद तो केवल जांच हो सकती है, शिकायत सही पाये जाने पर दंड दिया जा सकता है किन्तु इन सबसे जनता ने जो कष्ट झेला है, वह ऐसे नहीं होता है। कुल मिलाकर, राजस्थान में सड़कों की दयनीय स्थिति आपसे ज्यादा कोई जान नहीं सकता। मेरा निवेदन इतना ही है कि जब सड़कें बनें, उनकी गुणवत्ता अच्छी हो। इसके लिए मानिटरिंग व्यवस्था और मजबूत होनी चाहिए। इसके लिए विशेष प्रावधान हो।

मैंने प्राय: देखा है कि विशेष रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की छोटी सड़कें, जिस नोडल एजेंसी के माध्यम से सड़कें बनती हैं, उनके इंजीनियर मौके पर नहीं जाते हैं, बल्कि आफिस में लिपिकीय कार्य करते रहते हैं। असली इंजीनियर तो ठेकेदार और उसके मजदूर होते हैं।

माननीय सभापति महोदया, किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन की मांग पर 40,000 कृषि कनेक्शन इसी वित्तीय वर्ष में जारी करने की घोषणा किया जाना, निश्चित ही किसान वर्ग को भारी राहत पहुंचाना है।

सभापति महोदया, वैसे तो पूर्व माननीय सदस्यों ने सभी विभागों के बारे में सारी बातें विस्तृत रूप से बता दी हैं, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि आदरणीय यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया ने सभी क्षेत्र, चाहे शिक्षा हो, चिकित्सा व स्वास्थ्य हो, सड़क हो, कृषि हो, उद्योग हो, बिजली हो, पानी हो, पशुपालन हो, गो-पालन हो, सहकारिता हो, खाद्य सुरक्षा हो, वन एवं पर्यावरण हो, पर्यटन हो, चाहे हवाई यात्रा हो, पुरातत्व एवं संग्रहालय हो, कला संस्कृति हो, देवस्थान हो, रोजगार हो, कौशल विकास हो, महिला एवं बाल विकास हो, युवा मामले एवं खेल हो, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता हो, जनजाति क्षेत्र हो, कर्मचारी कल्याण हो, चाहे पत्रकार कल्याण हो, कर प्रशासन हो, पारिवारिक पेंशन हो, वित्तीय प्रबन्धन हो, राजकोषीय स्थिति मजबूत करके राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने में मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने एक बहुत ही इतना बजट प्रस्तुत किया है, शायद मेरे हिसाब से इस राजस्थान के 67 साल की आजादी

(श्री भागीरथ चौधरी)

के अन्दर ऐसा सुन्दर और वह भी प्रथम वर्ष में इस तरह का बजट प्रस्तुत किया है, यह बहुत बड़ा सराहनीय काम है। हर वर्ग, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे शिक्षक हो, सभी इस बजट को सराह रहे हैं और कोई वित्तीय बोझ नहीं बढ़ाते हुए, कोई किसी तरह का कर नहीं लगाते हुए, ऐसा सराहनीय बजट मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी ने प्रस्तुत किया है, जिसकी आम जन भूरि-भूरि प्रशंसा कर रहा है।

सभापति महोदया, 67 साल की आजादी के इस देश में अधिकांश समय कांग्रेस ने राज किया है। उन्होंने क्या दिया? भुखमरी, बेकारी और बेरोजगारी दी है। आज बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि जब न्यूजपेपर में इस तरह का आया कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा बेरोजगारी और सबसे ज्यादा गरीबी हिन्दुस्तान में है तो शर्म के मारे हमारा सिर झुक जाता है और इसका केवल, और केवल, कारण कांग्रेस की सरकार है, यू पी ए की सरकार है जिन्होंने इस देश को बेकारी, भुखमरी और बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं दिया।

सभापति महोदया, वसुन्धराजी ने 2003 से 2008 तक शासन किया। मुझे भी सौभाग्य मिला, उस 2003 से 2008 के शासन में विधायक रहने का मौका मिला और मैं यह कह सकता हूं कि 2003 से 2008 में वसुन्धराजी ने विकास के आयाम खड़े किये। आज भी आम जन बोल रहा है कि वसुन्धराजी, जो पूर्व में भी मुख्य मंत्री रही हैं, और आम जन, जो गरीब, गांव में झोंपड़ी में बैठा है, आज भी वह मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को याद करता है कि मुख्य मंत्रीजी ने हर क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में हो, उन्होंने वह विकास का काम किया जो आज भी आम जनता याद करती है। उसी का परिणाम है, 2008 में कोई न कोई कारण रहा होगा परन्तु विकास की बात में कोई कमी नहीं रही थी।

आज विपक्ष वाले कह रहे हैं कि 163 सीटें आई हैं। यह जरूर है, कांग्रेस तो झूठ बोलती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती है और ऐसे करके 2008 में सत्ता में आ गये और इसका परिणाम है कि 2003 से 2008 में पूरे देश में... (व्यवधान) सब भाग गये। मैं यह कह रहा हूं कि वे सदन ही छोड़कर नहीं गये हैं, मैं तो कह रहा हूं कि वे यह विचार कर रहे हैं और उनको आत्मग्लानि हो रही है। वे सोच रहे हैं, वे पार्टी छोड़ने के लिए भी विचार कर रहे हैं, मुझे तो ऐसा लग रहा है। उनको पता है कि उनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं।

(श्री भागीरथ चौधरी)

सभापति महोदया, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है, वह ऐसा ऐतिहासिक बजट है जिसके अन्दर हर वर्ग, हर समाज का ध्यान रखा गया है और आज यह हालत है कि कांग्रेस के पास कुछ बोलने के लिए बचा भी नहीं है। इसलिए वे सदन छोड़कर चले गये हैं। मैं तो यही बात कहना चाहूंगा कि आज हर क्षेत्र के अन्दर और सबसे बड़ी बात तो, मुख्य मंत्री, वसुन्धरा राजेजी को मैं बहुत-बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि गो-पालन, एक ऐसा विभाग गायों की रक्षा के लिए उन्होंने किया है। यह एक पूरे देश में ही नहीं, दुनिया में भी अनुकरणीय है। आज गाय सुरक्षित हैं तो हम सब सुरक्षित हैं। गाय हम सबकी मां है और गाय के लिए अलग से विभाग बनाकर उन्होंने चिंता की है और इसी वजह से आज यह हालत है कि आम जन इतना खुश है।

मैं, सभापति महोदया, आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहूंगा कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने चाहे यहां की मेट्रो रेल लाइन हो, पता नहीं, हम यह नहीं कह रहे हैं कि मेट्रो लाइन नहीं बननी चाहिए परन्तु इसके बजाय मैं तो यह कह रहा हूं कि इस देश के अन्दर यदि कोई विकास हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारीजी वाजपेयी प्रधान मंत्री बने, उन्होंने दो सपने संजोये थे, एक तो चतुर्भुज सड़क योजना से गांव और ढाणी, शहर को सड़कों से जोड़ें; दूसरा, उनका सपना था, इस देश की नदियां जुड़ें। मैं तो यह कहता हूं, इसकी बजाय उनको नदियां जोड़नी चाहिए थीं। अब की बार तो हम गांव और ढाणी में गये थे, कांग्रेसी कहने लग गये थे कि अब की बार तो विधान सभा से लोक सभा में चुनाव परिणाम अलग होंगे। मैंने कहा, हमारा एक ही सूत्र है, नरेन्द्र भाई मोदी और वसुन्धराजी का एक ही सपना है कि इस देश की नदियां जुड़नी चाहिए। यदि नदियां जुड़ जायेंगी, हर खेत को पानी मिल जायेगा, हर हाथ को काम मिल जायेगा, बेरोजगारी खतम हो जायेगी, नौजवानों को रोजगार मिल जायेगा, गांवों में खुशहाली आ जायेगी और यह प्रदेश समृद्धशाली हो जायेगा।

इस देश में सबसे ज्यादा पानी की कमी है तो राजस्थान में है। सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है तो राजस्थान में है। इसलिए, सभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी और यहां हमारे चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, बस एक काम कर दो, नदियों को जोड़ दो। फिर कोई जरूरी नहीं है, राजस्थान की हमारी धरती सोना उगलेगी।

श्री सभापति: अब सम-अप करें।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): सभापति महोदया, मेरे क्षेत्र की तो कुछ बात करूं। यह तो प्रदेश की बात थी।

श्री सभापति: अब समय बहुत हो चुका है और बहुत सारे सदस्यों को अभी बोलना बाकी है।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): दो मिनट में ही। सभापति महोदया, अंत में राजस्थान की संवेदनशील और यशस्वी मुख्य मंत्री महोदया से आग्रह करता हूं कि पिछली सरकार के कुप्रबन्धन से जो अव्यवस्था और विकास अवरुद्ध हुआ है, इस बजट से मैं आशान्वित हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की निम्न समस्याओं का त्वरित निदान होगा। मदनगंज-किशनगढ़ की यू आई डी एस एस एम टी के अन्तर्गत उच्चाधिकारियों के पास लम्बित 182 करोड़ रुपये की पेयजल योजना से किशनगढ़ की जनता को राहत और जीवनदान मिलेगा।

सभापति महोदया, मुझे दु:ख है कि बीसलपुर बांध बना है, वह अजमेर जिले की आम जनता के लिए, गांव और ढाणी के लिए बना है। पहले अजमेर की जनता को पीने का पानी उपलब्ध हो और उसके बाद चाहे जयपुर और चाहे कहीं जाये। आज यह हालात है कि मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में 6-6, 7-7 दिन से पानी नहीं आ रहा है और पूरे अजमेर जिले के अन्दर स्टील पाइपलाइन है पर मेरे किशनगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जो शहर में आने वाली सिर्फ सीमेंट की पाइपलाइन है और उससे भी अवैध कनेक्शन लिये जा रहे हैं। 6-6, 7-7 दिन तक पानी नहीं आ रहा है। हमारा सबसे बड़ा दु:ख तो यह है कि हमारे आज के ठीक एक साल पहले जुलाई में पूर्व मुख्य मंत्री, अशोकजी गहलोत गये थे, उस समय में घोषणा की थी कि 220 करोड़ रुपये की पेयजल योजना स्वीकृत हो गई है परन्तु दु:ख की बात है, सिर्फ वह घोषणा करके आये। सिर्फ वे शिलालेख करके आते थे, शिलान्यास करते थे। कुछ नहीं किया।

श्री सभापति: दो मिनट करते हुए अभी आपके 20 मिनट हो गये।

श्री भागीरथ चौधरी (किशनगढ़): दो मिनट में ही। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अराई क्षेत्र में उद्योग प्रसार की प्रबल सम्भावनाएं देखते हुए वहां रीको की स्थापना की जाये।

तीसरा, माननीय मुख्य मंत्री महोदया से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि अराई में सुराज संकल्प यात्रा के दौरान जब वे पधारी थी तो राजकीय

(श्री भागीरथ चौधरी)

महाविद्यालय की घोषणा की थी और आई टी आई की घोषणा की थी। मुझे विश्वास है कि सुराज संकल्प यात्रा में जो वसुंधराजी ने घोषणा की है, वह पूरी करेंगे।

अराई क्षेत्र में बढ़ते हुए औद्योगिक प्रसार और औद्योगिक क्षेत्रों के विकास को देखते हुए, यहां बिजली मंत्रीजी विराजे हुए हैं, 132 के वी जी एस एस की स्थापना की आवश्यकता है।

कुल मिलाकर जो यह बजट पेश किया गया है, वह सभी वर्गों को ध्यान में रखकर, संतुलित, विकासोन्मुखी, राज्य हित में सही मायने में, राजस्थान की जनता ने जो विश्वास अपना मत देकर व्यक्त किया है, यह बजट उनकी आकांक्षाओं पर सही प्रतीत होता है।

सभापति महोदया, आपने मुझे समय दिया, उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री हमीर सिंहजी भायल।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): आदरणीय सभापति महोदया, मैं बाड़मेर से पहली बार आया हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, आदरणीय मुझे समय ज्यादा दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सभी को पांच मिनट का है, आपको दस मिनट का दे रहे हैं।

श्री हमीरसिंह भायल (सिवाना): मेरे बड़े भाई साहब अभी बीस मिनट बोले हैं। मेहरबानी करके आप थोड़ा समय दें। (व्यवधान)

राजस्थान को देश के क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े प्रदेश का गौरव हासिल है। यहां की विकट भौगोलिक परिस्थिति, शिक्षा का अभाव आदि होने के उपरांत भी सांस्कृतिक, मानवीय एवं आध्यात्मिक दृष्टि से हम बहुत सम्पन्न हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि मैं इस प्रदेश का निवासी हूं। धन्य है यहां की जनता जिसमें सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता है। राजस्थान की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों को आत्मसात करते हुए, हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री वसुंधरा राजेजी में विश्वास जता कर, उनके नेतृत्व में विधान सभा में 163 एवं लोक सभा में 25 में से 25 सीटें देकर जो अपना अपार समर्थन एवं लाड़ दिया है, उनके हम आभारी हैं। जनता की आशाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप हमारी मुख्य मंत्रीजी ने लोक कल्याणकारी योजनाओं का समावेश करते हुए, जनता की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल कर, बड़ा ही संतुलित बजट पेश किया है। जिसके लिए माननीय मुख्य मंत्री महोदया का बहुत-बहुत साधुवाद।

(श्री हमीरसिंह भायल)

माननीय सभापति महोदया, 2003-04 में जब हमारी सरकार थी तब प्रदेश का राजस्व घाटा 3 हजार 424 करोड़ था। उसकी पूर्ति करते हुए 2007-08 में भाजपा की सरकार में घाटे को बदल कर 1 हजार 563 करोड़ रुपए सरप्लस कर दिया था। लेकिन पिछली कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में उनके अकुशल आर्थिक प्रबंध एवं नीतियों के कारण प्रदेश का राजस्व घाटा 2 हजार 500 करोड़ का आ गया। जनता ने उनकी उन्हीं नीतियों से परेशान होकर उनका सूपड़ा साफ कर दिया, उनसे राज छीन लिया और विकसित राजस्थान का सपना जनता ने संजोया। उसको मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा राजेजी के नेतृत्व में यह हमारी भाजपा की सरकार पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध है। राजस्थान को शक्तिशाली, विकसित एवं समृद्धशाली बनाना है तो आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन किया जाना नितांत आवश्यक है। जिस हालात में राज्य को पिछली सरकार ने दिवालिया बनाकर छोड़ा था, उससे उबरना एवं प्रदेश को प्रगति के मार्ग पर लाना एक चुनौती है। परन्तु जनता के प्यार और सहयोग, वसुंधराजी जैसी कुशल प्रबंधक एवं योग्यतम हमारे मंत्री, अधिकारी एवं कर्मचारियों के सहयोग से सब सम्भव हो जाएगा। हम असम्भव को सम्भव करके दिखाएंगे। नदी के प्रवाह के विपरीत नाव चलाने वाला ही तो असली एवं कुशल नाविक होता है।

माननीया मुख्य मंत्रीजी ने 15 लाख युवाओं को आगामी पांच वर्षों में रोजगार उपलब्ध करवाने का जहां बजट में संकल्प किया है, यह एक सराहनीय कदम है। देश के कर्णधार युवाओं की ओर से मुख्य मंत्रीजी का धन्यवाद।

प्रदेश में सड़कों की हालत ऐसी है कि इस बार कुछ कहना ही नहीं बन पा रहा है। हाइवे, एम डी आर, ओ डी आर, ए आर, सभी सड़कों की स्थिति एक समान ही है। क्षतिग्रस्त सड़कों में वाहनों का चलना तो अलग, पैदल चलना ही दुश्वार हो गया है। हमारी सरकार के गठन के बाद 20 हजार किलोमीटर सड़क के निर्माण एवं मरम्मत का कार्य जो सरकार ने हाथ में लिया है, इससे आम नागरिक को राहत मिलेगी। गर्व की बात है कि प्रतिदिन 15 किलोमीटर का निर्माण अब हमारे प्रदेश में होगा और प्रदेश प्रगति के मार्ग पर दौड़ेगा। किसी ने सही कहा है कि गांवों में विकास सड़कों के माध्यम से ही सम्भव है। सड़कें होंगी, आवागमन के साधन होंगे, शहर और कस्बों में मिलने वाली सारी सुविधाएं परिवहन के माध्यम से गांवों में आ जाएगी, गांवों से शहरों

(श्री हमीरसिंह भायल)

की ओर लोगों का पलायन रुकेगा। इसलिए सड़कों का निर्माण आवश्यक है।

राजस्थान हाइवे अथोरिटी का गठन कर क्षतिग्रस्त हाइवे से होने वाली परेशानियों से निजात मिलेगी। सभी ग्राम पंचायतों को सड़कों से जोड़ा जाएगा। पांच हजार किलोमीटर धार्मिक एवं पर्यटन सहित 20 हजार किलोमीटर सड़कों का निर्माण जन सहभागिता के द्वारा, 9 हजार ग्राम पंचायत मुख्यालयों को जोड़ने हेतु धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, करौली, कैलादेवी पद मार्ग, आदि का निर्माण लोक कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों के प्रतीक हैं।

रोडवेज को घाटे से उबारने के लिए राज्य सरकार 10 करोड़ प्रति माह अनुदान देगी। इससे रोडवेज की सेवाओं में सुधार आएगा जिससे आम आदमी को बेहतर सुविधा मिल पाएगी।

गत सात माह में कालीसिंध की 600 मेगावाट यूनिट, छबड़ा 250 मेगावाट यूनिट, रामगढ़ स्टीम टरबाइन 50 मेगावाट का उत्पादन वाणिज्यिक आधार पर आरम्भ कर राज्य में कुल 900 मेगावाट की वृद्धि की गई है। आगामी पांच वर्षों में 6 हजार 500 मेगावाट से अधिक नई विद्युत क्षमता स्थापित करने का कार्यक्रम; सरकार ने जो 40 हजार कृषि कनेक्शन, 220 33 केवी जी एस एस, 11 132 जी एस एस, बाड़मेर में ग्रीन ऊर्जा प्रसारण तंत्र स्थापित करना, प्राकृतिक ऊर्जा को बढ़ावा देने हेतु सौर ऊर्जा के क्षेत्र में पांच हार्स पावर के पम्पसेट पर 32 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान किया है। इससे किसानों को फायदा होगा। सोलर ऊर्जा के माध्यम से बूंद-बूंद सिंचाई की जहां योजना बनायी, वह भी सार्थक सिद्ध होगी।

जनता जल योजना को पूर्ण रूप से पंचायतों को सुपुर्द किया, जिसमें टी एफ सी व एस एफ सी योजनाओं पर वैट के अंशदान का प्रावधान कर 605 ग्राम पंचायतों को लाभान्वित किया गया। पांच लाख हैंडपम्प स्वीकृत कराने का प्रावधान, जहां विद्यमान जल प्रदाय योजना का पानी नहीं पहुंच पाया है, वहां पानी का पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। जालौर की जनता को नर्मदा का मीठा पानी पिलाने के लिए 303 करोड़ का जो प्रावधान किया गया है, जालौर जिले की जनता माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करती है।

मैं माननीया मुख्य मंत्रीजी का आभार प्रकट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र पेयजल के संकट के निवारण हेतु पोकरण फलसूण्ड, बालोतरा सिवाना में विभागीय मांग अनुसार 160 करोड़, उम्मेद सागर-देवास-

(श्री हमीरसिंह भायल)

समदड़ी-कण्ड परियोजना मांग अनुसार 257.50 करोड़ का जो बजट प्रावधान किया गया है, उसके लिए सिवाना क्षेत्र की जनता की तरफ से मैं आपको पूर्ण धन्यवाद देता हूं।

विकास योजनाओं के क्षेत्र में गुरु गोलवलकर योजना पुन: आरम्भ की गई है तथा मनरेगा में स्थायी परिसम्तियों के निर्माण का प्रशंसनीय कदम उठाया गया है।

चिकित्सा में 1,079 उप स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, 51 नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण, 18 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र भवनों का निर्माण, 7 नये मेडिकल कालेज और 700 सीटों से डाक्टरों की कमी पूरी होगी।

महिला एवं बाल विकास में 100 आंगनबाड़ी केन्द्र वहां पर शुरू हुए। शिशु पालन गृह का निर्माण, 4,850 नये आंगनबाड़ी भवनों का निर्माण, 41,923 आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत, 611 भवनों का विस्तार किया गया है। मां यशोदा अवार्ड, एस सी, एस टी, बी पी एल महिलाओं के पक्ष में विक्रय पत्रों पर चार से घटा कर तीन प्रतिशत स्टांप ड्यूटी का प्रावधान किया गया है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

हुकूम, मेरी एक सिवाना की जो मांग है, वह निवेदन कर दूं। उपजाऊ भूमि के लिहाज से सिवाना क्षेत्र का कश्मीर माना जाता था। भूभाग में पानी नीचे चले जाने व बरसात के नहीं होने से पीने का पानी भी नहीं है, खेती तो क्या करे। परन्तु अब हमें विश्वास जगा है कि नर्मदा का पानी यदि सिवाना क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है तो खेती हो सकती है। मेरी मुख्य मंत्री महोदया से गुजारिश है कि वे सिवाना तक पानी पहुंचाने के लिए कार्ययोजना बनायें। इस क्षेत्र में जीरा, सरसों, ईसबगोल अधिक होता है, लिहाजा किसानों के हित एवं राज्य में उत्पादन बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाना नितान्त आवश्यक है।

पिछली सरकार द्वारा बजट प्रावधानो में खोले गये कालेज सिवाना को पुन: खोलने की स्वीकृति प्रदान करावें और सिणधरी मुख्यालय पर कालेज हो। सिवाना मुख्यालय पर सार्वजनिक निर्माण विभाग का अधिशासी अभियंता कार्यालय खोलना; ढंढाली व कुंडल में पी एच सी, पादरू में सी एच सी खोलना, मंत्रीजी विराज रहे हैं; सिवाना से समदड़ी ग्राम पंचायत मुख्यालय गौरव पथ योजना से डबल रोड से जोड़ना; सिवाना में बरसाती पानी के संरक्षण हेतु भाखल्डा बेल्ट में छोटे-छोटे एनिकट का निर्माण एवं नदी एवं

(श्री हमीरसिंह भायल)

नालों के प्रवाह क्षेत्र में चैक डैम निर्माण हेतु बजट प्रावधान; ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हल्देश्वर की पहाडियों में वीर दुर्गादास की कर्मस्थली पर स्मारक निर्माण; हिंगलाज माता मंदिर का जीर्णोद्धार करवाना; महाभारत काल के भीमगोड़ा, आदि व राजा भोज के पौत्र वीर नारायण परमार द्वारा गढ़ सिवाना का निर्माण जो किया, उनका जीर्णोद्धार एवं प्राधिकरण के अधीन लेकर उनका विकास हो, संरक्षित हों; सिंचाई में सिंचाई विभाग का सहायक अभियंता स्तर तक का कार्यालय सृजित करना; सिवाना में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पचास बेड का चिकित्सालय; बालोतरा को जिला बनाना, यह हमारा सबका लक्ष्य है कि बालोतरा जिला बने। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, श्री हीरालालजी रैगर।

श्री हीरालाल (निवाई): माननीय सभापतिजी, आज के बजट भाषण में आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

2014 का यह बजट माननीया वसुन्धराजी ने 14 तारीख को पेश किया, यह ऐतिहासिक बजट ही नहीं बल्कि ऐतिहासिक दस्तावेज है। मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

राजस्थान प्रदेश इटली और यूनाइटेड किंगडम से भी बड़ा प्रदेश है। यहां की 52 प्रतिशत जनता कृषि पर आधारित है जब-जब भी प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो राजस्थान को नया आयाम मिला है और विकास को गति प्रदान की है। सबसे पहले माननीय स्वर्गीय भैरोंसिंहजी शेखावत राजस्थान के मुख्य मंत्री बने, उनके कार्यकाल में अन्त्योदय योजना, एस सी/एस टी और ओ बी सी को पंचायतों में आरक्षण और पंचायतों को कोई फंड नहीं मिलता था, माननीय शेखावत साहब की सोच थी कि पंचायतों को भी विकास के लिए कुछ फंडिंग की व्यवस्था की जाए, तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में प्रदेश का चहुंमुखी विकास हुआ।

2003 में आदरणीया वसुन्धराजी ने परिवर्तन यात्रा के जरिये राजस्थान का परिवर्तन कर, राजस्थान की जनता ने उनको मुख्य मंत्री बनाया। माननीया वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनीं तो पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के कारण राजस्थान की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। उस स्थिति में राजस्थान को 'बीमारू' राज्यों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय वसुन्धराजी की

(21.35 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

(श्री हीरालाल)

सरकार ने बाहर निकाला। राजस्थान ओवरड्राफ्ट से ग्रस्त था, कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए एक तारीख को बैंक से ऋण लेना पड़ता था। माननीया वसुन्धराजी ने ओवरड्राफ्ट खतम किया और समय पर कर्मचारियों को तनख्वाह मिलने लगी। उस समय में माननीया वसुन्धराजी ने पूरे राजस्थान का चहुंमुखी विकास किया।

आज का यह जो बजट है, तीन दिन से विद्वान सदस्यों ने बहस में भाग लिया, पक्ष और विपक्ष के विद्वान सदस्यों ने इसमें भाग लिया। बड़े दुख की बात है कि कांग्रेस के माननीय सदस्यों ने, जिनको राजस्थान की जनता भी देख रही है, ऐसे महत्वपूर्ण बजट में भाग नहीं लेकर एक तरह से ठीक काम नहीं किया। मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं, जो बजट माननीया वसुन्धराजी ने दिया। गरीब ग्रामीण जनता को स्वच्छ पेयजल के लिए आर ओ की व्यवस्था, मेडिकल कालेज खोलना, कृषि के नये आयाम पैदा करना, इस बजट की विशेषताएं हैं।

मैं अपने निवाई विधान सभा क्षेत्र के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं है। माननीय पी डब्ल्यू डी मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब सुराज संकल्प यात्रा में माननीय वसुन्धराजी पधारीं तो सड़कों की व्यवस्था ठीक नहीं थी, लेकिन जब हमारी सरकार बनी वसुन्धराजी मुख्य मंत्री बनीं तो उन सड़कों में सुधार हुआ, सड़कें जो टूट रही थीं उनका पैचवर्क किया गया। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के पीपलू उपखंड में आज भी सड़कों के विकास की बहुत कमी है। इसलिए मेरे पीपलू क्षेत्र में इस बजट में सड़कों की तरफ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि आज भी वह बहुत पिछड़ा हुआ है।

शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूलों में टीचर्स की जगह खाली पड़ी है, छात्रों की कमी है। मैं शिक्षा मंत्री जी को...

श्री सभापति: मैं, माननीय सदस्य, आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि जो विषय आप लोग डिमाण्ड्स पर बोल सकते हैं, आपको मालूम है, आपके पास में डिमांड्स की सूची आ गयी है, वे आप डिमांड्स पर बोल लेना। आप सीधा अपने क्षेत्र के बारे में ऐसी कोई चीज, जो डिमांड के अलावा हो, वह आप बोल दें। तो सबका क्रम से नम्बर आ जाएगा। मैं, माननीय सदस्य, यह निवेदन करना चाहूंगा कि पांच मिनट से ज्यादा नहीं दिया जाएगा, मैं दूसरा नाम पुकार लूंगा।

श्री हीरालाल (निवाई): मुझे तो, माननीय सभापतिजी, बहुत कम टाइम हुआ है। मैं पीपलू क्षेत्र में अलग से पंचायत समिति निर्माण करने की भी मांग करता हूं।

अब आपने यह कह ही दिया तो मैं दो मिनट में अपना सारा भाषण समाप्त करता हूं। मैं चिकित्सा मंत्री महोदयजी को निवेदन करूंगा कि जो डाक्टरों की जगह खाली पड़ी हैं; मेरे यहां गायनोकोलोजिस्ट की, लेडी डाक्टर की व्यवस्था की जाए; स्कूलों में टीचर्स की कमी है, वो पूरी की जाए और ऊर्जा मंत्रीजी से मेरा निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में बड़ा गांव में अलग से एक जी एस एस खोला जाए।

आपने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री ओटाराम देवासी।

श्री ओटाराम (सिरोही): आदरणीय सभापति महोदय, जिस तरह से हमारे राजस्थान की लोकप्रिय व यशस्वी मुख्य मंत्री, आदरणीया वसुंधरा राजेजी ने 14 जुलाई को 2014-15 का जो बजट पेश किया, उस बजट के अन्दर एक अलग तरह की विशेषता है। आज दिन तक जो बजट होता है तो कई तरह की चर्चाएं होती हैं, कई तरह के आब्जेक्शन आते हैं परन्तु पहला ऐसा बजट है जिसके अन्दर आज तक न तो कोई आब्जेक्शन आया, न कोई ऐसी बात सामने आई। यह सबसे बड़ी बात है। पूरे राजस्थान में सबसे बड़ा कदम है।

आज अपन सभी गाय को गाय माता कहते हैं। राजस्थान की सरकार जिस तरह से बहुत बड़ा निर्णय लेकर, गोपालन मंत्रालय अलग से बनाकर, बहुत बड़ा काम कर रही है, विशेष तौर से पर्यटन के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में, किसानों के क्षेत्र में, युवाओं के क्षेत्र में, कर्मचारियों के बारे में, पूरे राजस्थान में इस बजट से बहुत अच्छा मेसेज गया है।

मैं विशेष तौर से इसमें आदरणीय सभापति के माध्यम से सबसे पहले, सभी वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी, मेरे अपने सिरोही विधान सभा क्षेत्र में 2007-08 में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, नर्मदा की योजना बनी, उस योजना में सिरोही जिले को शामिल किया गया। परन्तु 2007-08 और 2009 के बाद जो सरकार आई, उस सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में, हमने बार-बार क्वेशचन लगाए, तो एक ही आवाज आ रही थी कि आपके यह योजना लागू नहीं है। जिस तरह से राजस्थान के अन्दर सुराज संकल्प यात्रा

(श्री ओटाराम)

चालू हुई, सिरोही के अन्दर राजस्थान की मुख्य मंत्री, आदरणीया वसुंधरा राजेजी पधारीं, तो सिरोही की जनता ने एक ही मांग की कि आपके हाथ से नर्मदा की योजना बनी थी, उस योजना को आगे बढ़ाया जाए। आदरणीय सुमेरपुर से आने वाले राठौड साहब ने बात कही, आने वाले समय में सिरोही की जनता को नर्मदा का पेयजल का पानी कैसे मिले, यह हमारी भी मंशा है।

आज पूरे सिरोही जिले में पीने के पानी की बहुत विकट समस्या है। हर गांव में एक-एक टैंकर जा रहा है। मैं तो राजस्थान की सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इतना प्रबंधन किया कि हर गांव में एक-एक टैंकर और जहां दो की जरूरत थी, वहां दो की व्यवस्था की और लोगों को पानी पिलाया जा रहा है। आने वाले समय में अगर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाए तो मेरा यह विश्वास है, आपके माध्यम से और चिकित्सा मंत्रीजी के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कल के कार्यक्रम में जब रिप्लाई हो तो कम से कम सिरोही और सुमेरपुर के लिए, मेरे सिरोही जिले के लिए नर्मदा के पानी के लिए, जिस तरह से पोस्ट क्रिएट की है पाली जिले में एस ई की, मेरे यहां ए ईएन की है, मेरा यह निवेदन है कि आने वाले समय में वहां एक्सईएन की पोस्ट क्रिएट करें ताकि आने वाले समय में उसका सर्वे चालू हो जाए। राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है कि उसमें सर्वे के लिए कल से ही बजट की घोषणा हो, यही मेरी भावना है।

इसी को ध्यान में रखते हुए, चिकित्सा मंत्रीजी विराजमान हैं, मैंने इनको निवेदन भी किया है कि मेरे यहां ट्रौमा सेंटर बना हुआ है, वह आने वाले समय में जल्दी से जल्दी चालू हो जाए, यह मेरी भावना है, ताकि आने वाले समय में लोगों को सुविधा हो।

श्री सभापति: मंत्री महोदय, इधर।

श्री ओटाराम (सिरोही): मेरी तरफ देख रहे थे, ट्रौमा सेंटर की तरफ । आने वाले समय में ट्रौमा सेंटर चालू हो जाए।

मेरे वहां एक ला कालेज है, वह दो साल से बंद पड़ा है। युवा आने वाले समय में एल एल बी के लिए आगे बढ़ सकें, ला कालेज में उनको सुविधा मिल सके, यही मेरी भावना है।

मेरे यहां एक गोडाणा बांध है, उसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए बजट के माध्यम से मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं।

मुझे समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नवनीतलाल नीनामा।

श्री नवनीत लाल (घाटोल): मान्यवर सभापति महोदय, राजस्थान का बजट माननीया मुख्य मंत्रीजी के द्वारा पेश किया गया है। इस बजट को पढ़कर मुझे वह दिन, वह समय याद आ रहा है जब हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब इस कृषि प्रधान देश में जन साधारण किस तरह से अपना निर्वहन करता था। किस तरह से अपनी झोंपड़ियां थीं, किस तरह से नदी-नाले और नालों का पानी पीकर जिंदा रहता था। इस प्रकार की सारी जानकारी लेकर यह बजट बनाया गया है।

मान्यवर, जब 4 अप्रैल, 2013 को चारभुजा जी से यात्रा शुरू हुई, यात्रा पूरे मेवाड़ का चक्कर काटने लगी, तब कांग्रेसी भाइयों को यह मन में आया कि उदयपुर संभाग का आदिवासी बी जे पी की तरफ न चला जाए। इस तरह की मन की भावना को देखते हुए कांग्रेस के भाइयों ने कम्बल, साड़ियां बांटकर आदिवासियों को लुभाने की योजना बनाई थी। लेकिन वह योजना सफल नहीं हुई और पूरा उदयपुर सम्भाग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गया। जिस तरह से यहां हमारे आदिवासियों का वातावरण बना, माननीया वसुंधराजी को आज घर-घर में बच्चे, महिलाएं, खेलने वाला खिलाड़ी, स्कूल में बैठे बालक, हर व्यक्ति के मुंह पर यह था कि वसुंधरा राजे का राज कब आएगा। यह योजना थी और राज आ गया।

मान्यवर, अभी माननीया वसुंधराजी ने सबसे बड़ा जो काम किया है, वह यह किया है कि महिलाओं के बैंक में खाते खोलकर, बैंक में खाता रखकर, आदिवासियों को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, इस प्रकार की योजना बनाई। इस योजना से पूरा उदयपुर संभाग, दक्षिणी राजस्थान वाहवाही कर रहा है।

माननीया वसुंधराजी को धन्यवाद देता हुआ, समय के अभाव में मैं ज्यादा चर्चा नहीं करके, मेरे क्षेत्र की कुछ समस्याएं हैं उन पर निवेदन करना चाहता हूं।

मान्यवर, बांसवाड़ा जिले में माही डैम नाम से जो डैम बना हुआ है, तालाब बड़ा, यह सन् 1966 में गुजरात और राजस्थान की मिली सरकार से, गठबंधन से बना हुआ डैम है। उसका सर्वे होकर डैम पूर्ण हो चुका है। वहां पर अभी माननीया वसुन्धराजी, मुख्य मंत्रीजी द्वारा 20 करोड़ रुपया स्वीकृत किया गया है लेकिन वहां पर मेन आफिस, मुख्य अभियंता का आफिस हटा दिया

(श्री नवनीत लाल)

गया है और जे.ईएन., ए.ईन. के भरोसे यह पैसा जाएगा तो उसका नेतृत्व कौन करेगा? अत: मेरा आग्रह है कि यह मुख्य अभियंता का जो पद है वह वापस बांसवाड़ा में यथा-स्थान रखा जाए। ऐसा मेरा आग्रह है।

दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र घाटोल पंचायत समिति पीपलखूंट प्रतापगढ़ क्षेत्र में पड़ता है। वह सूखा एरिया है, पीने के पानी की दिक्कत है। जहां पर एक बोरी बांध कटी नाम का, जो तालाब का निर्माण हो चुका है, लेकिन उसकी नहरें अव्यवस्थित हैं। अत: मेरा आग्रह है कि उन नहरों को व्यवस्थित करवाया जाए ताकि उससे सम्बन्धित पंचायतों को पानी बराबर सप्लाई हो सके।

मान्यवर, मेरा आग्रह है कि प्रतापगढ़ क्षेत्र में पंचायत समिति पीपलखूंट है और रोहनिया करके एक गांव है, जो इस प्रकार का गांव है कि उसके चारों तरफ माही डैम का पानी फैला हुआ है और नदियां भी चारों तरफ उसके फैली हुई हैं। वहां पर न तो विद्युत की व्यवस्था और न सड़क की व्यवस्था है। भूड़न नाम की नदी जो मध्य प्रदेश से आती है और माही डैम में मिल जाती है, तो वह नदी, उस पंचायत समिति पीपलखूंट से वह ग्राम पंचायत टूटी हुई है। अत: मेरा आग्रह है कि उस पर पुल का निर्माण करवाया जाए, उस नदी पर ताकि वहां की जनता का पंचायत समिति से आवागमन शुरू हो।

दूसरा मेरा निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र गढ़ी और विधान सभा क्षेत्र घाटोल के बीच में सांप नाम की नदी बह रही है। उस नदी पर पुल बनाना अति आवश्यक है। इसलिए उस पुल का सर्वे करके निर्माण करवाया जाए। मैंने उसका एस्टिमेट बनवा कर माननीय मंत्रीजी को प्रस्तुत कर दिया है, लेकिन फिर भी उस पर विशेष ध्यान दिया जाए। इतनी ही बात कहकर मेरी बात को विराम देता हूं।

श्री सभापति: श्री भैराराम चौधरी।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): माननीय सभापति महोदय, आज इस 14वीं विधान सभा में मुझे पहली बार बोलने का मौका मिल रहा है और शायद, जैसे ओसियां विधान सभा क्षेत्र से यह साढ़े तीन साल और चार साल के बाद में विधान सभा में आवाज, शायद आपके इस सदन में आ रही होगी।

2014-15 के परिवर्तित बजट को, मैं अभी समझ रहा हूं कि सभी लोग सुबह से आये हुए भूखे हैं, इसलिए मैं इसको सदन के पटल पर रख कर और पढ़ा हुआ माना जाए। यह, आई थिंक, सबसे बढ़िया आइडिया है। (व्यवधान)

श्री सभापति: उसके लिए तो आपको आसन की अनुमति लेनी पड़ेगी।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): नहीं, सर। माननीय सभापति महोदय ने भी, यह तो, सर, सवेरे से मैं समझ रहा हूं कि भोजन नहीं किया हुआ है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आपके पास में लिखा हुआ है?

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): मैं आपसे अनुमति ले लेता हूं।

श्री सभापति: अगर लिखित में है तो आसन आपको अनुमति देता है। लिखित में है? नहीं, तो पांच मिनट बोल लीजिए आप।

श्री भैराराम चौधरी (ओसियां): ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह ओसियां की आवाज साढ़े तीन-चार साल बाद सदन में आ रही है। हमारे इससे पहले अशोक गहलोत साहब ने, पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने हमारे राजस्थान में एक, राजस्थान के इतिहास में एक ऐसा बजट दिया था जिससे ओसियां और लूणी, तो उसमें से एक ही जैसे फिल्म चली थी, 150 तो उनके पास में बाकी रह गई थीं। इसलिए अब हमारे को, अब क्या बहुत ज्यादा उसके बारे में कहें, और वह 150 और नहीं चलीं। वह तो मांग, साहब, अशोकजी गहलोत से आगे कर लेंगे। एक ही चलायी, उसी में ही, हम तो वीर तेजाजी और महाराज सूरजमल की जय बोलते-बोलते, यह तो, साहब, मुश्किल से गाड़ी पार हुई है।

मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस बजट के अन्दर, वह चाहे आपके सड़क की बात हो, चाहे आपकी कृषि की हो, चाहे आपकी चिकित्सा की हो और वह चाहे इस पूरे प्रदेश के विकास से सम्बन्धित, इसमें एक-एक पाइंट को छुआ है। उन पाइंट्स को कैसे छुआ है? जहां तक मैं समझ रहा हूं कि यह 4 अप्रैल, 2013 से जो 'सुराज संकल्प यात्रा' का आगाज हुआ 'चार-भुजा' से, उस यात्रा से पूरे प्रदेश का भ्रमण किया गया और इस पूरे प्रदेश की ग्राउंड की स्थिति समझी है; वह चाहे सड़क की समझी, चाहे कृषि की समझी और शिक्षा के क्षेत्र में समझी। वह चाहे पशुपालन हो, चाहे कोई सा भी अन्य फील्ड हो, इतना व्यवस्थित बजट जो हमारी माननीया मुख्य मंत्रीजी ने दिया है, यह उनके अनुभव, उनके कौशल और उनकी जो टीम है और इस बजट में सम्पूर्ण क्षेत्र के, वह चाहे व्यापारिक जगत का हो, चाहे शिक्षा जगत का हो, चाहे कृषि जगत का हो, उन्होंने हर क्षेत्र के जो मुख्य आदमी और उनकी टीम से पूरे विचार-

(श्री भैराराम चौधरी)

विमर्श करके इतना बढ़िया यह पूरे प्रदेश का बजट दिया है। इसकी हम एकदम अपने हृदय तल से भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं और इसका समर्थन करते हैं।

एक बात देखने को और मिली है कि हम बहुत ही किसान क्षेत्र से आते हैं। इसमें यह जो आपके सदन में मैं एक-दो दिनों से देख रहा था, चर्चा हो रही थी, उसमें वे कह रहे थे कि इसमें किसानों के लिए कुछ नहीं किया, इसमें चिकित्सा के लिए कुछ नहीं किया, इसमें शिक्षा के लिए कुछ नहीं किया, जहां तक मैं समझ रहा हूं, उन्होंने इस बजट भाषण को बिलकुल पढ़ा ही नहीं है और बिना पढ़े ही, बिना किसी तर्क के या बिना किसी आधार के, बस, उनको विरोध ही करना है। यह तो हो सकता है कि विरोधियों की आदत में हो लेकिन इस बजट के अन्दर 100 में से 100 प्रतिशत नहीं, मैं तो कहता हूं कि 100 में से 1000 प्रतिशत हम लोग इसका समर्थन करते हैं और इस प्रदेश के विकास की गति अब जो दौड़ेगी और अगले पांच साल तक इस पूरे प्रदेश के विकास के नये आयाम स्थापित होंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ में, मैं समझ रहा हूं कि शायद आप घंटी बजाएंगे। आपसे वैसे ही डर लग रहा है क्योंकि पहली-पहली बार ही हमारे को विधान सभा में बोलने का मौका मिला है और आगे से ...(व्यवधान) आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शंकरसिंह राजपुरोहित (आहौर): माननीय सभापति महोदय, आप सुरक्षा का बहुत बड़ा काम करते हों, और आपको तो वर्षों का अनुभव है। (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 21.58 बजे शुक्रवार, दिनांक 18 जुलाई 2014 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

बी ए डी पी योजना के अन्तर्गत अधूरी सड़कों का निर्माण

51. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार बी ए डी पी योजना के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों से अधूरी पड़ी सड़कों/मिसिंग लिंक सड़कों को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर शहरों के नजदीक अथवा घनी आबादी वाले कस्बों व गांवों में गति अवरोधक बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार जैसलमेर शहर के राजकीय महाविद्यालय के आगे गति अवरोध बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार जैसलमेर से बाड़मेर के मध्य कि.मी. 129 से कि.मी. 130 के बीच अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा बी.ए.डी.पी. योजना के अन्तर्गत विगत 10 वर्षों से कोई सड़क अधूरी नहीं है परन्तु विगत 10 वर्षों में स्वीकृत सड़कों में से 58 सड़क कार्य अपूर्ण हैं। जिनके पूर्ण होने की सम्भावित तिथि सहित विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधक बनाने के सम्बन्ध में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार (मौर्थ) के प्रपत्र क्रमांक आर.डब्ल्यू./एन.एच.-11064/1/91-डीओ 1 दिनांक 28.06.1996 द्वारा मापदण्ड निर्धारित हैं, जिसके अनुसार राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति अवरोधक नहीं बनाने चाहिये परन्तु विशेष परिस्थितियों में जहां राष्ट्रीय राजमार्गों पर गति नियंत्रण करना अत्यन्त आवश्यक हो, वहां रम्बल स्ट्रिप बनाई जा सकती है। मौर्थ के प्रपत्र क्रमांक आर.डब्ल्यू./ एन.एच.-11064/1/91-डीओ 1 दिनांक 28.06.1996 की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(3) जी नहीं। मौर्थ द्वारा जारी उपरोक्त मापदण्ड के अनुसार जैसलमेर शहर के राजकीय महाविद्यालय के आगे गति अवरोधक नहीं बनाया जा सकता है। परन्तु इस स्थल पर रम्बल स्ट्रिप बनाई जा सकती है। इसके लिए निविदा प्रक्रियाधीन है एवं यह कार्य एक माह में पूर्ण किया जाना सम्भावित है।

(4) जी नहीं। जैसलमेर से बाड़मेर के मध्य जैसलमेर से बाड़मेर कि.मी. 123/410 से 144/500 तक का भाग लिग्नाइट कोयला की खान क्षेत्र के नीचे आने के कारण सड़क के वर्तमान एलाइनमेंट पर मौर्थ द्वारा कोई नये कार्य स्वीकृत नहीं किये जा रहे हैं। इस क्षेत्र में लिग्नाइट कोयले का खनन करने वाले राजस्थान सरकार के उपक्रम बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कम्पनी लिमिटेड (बी.एल.एम.सी.एल.) द्वारा प्रस्तावित भाडका से जालिपा वाया भादरेस वाला नया एलाइनमेंट सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार द्वारा दिनांक 15.07.2011 को अनुमोदित किया जा चुका है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-3 पर प्रस्तुत है। नये एलाइनमेंट पर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण में जितनी भी लागत मौर्थ निर्धारित करेगी, उसे वहन करने के सम्बन्ध में बी.एल.एम.सी.एल. ने पत्र दिनांक 02 मई, 2014 द्वारा सहमति दी है, जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 पर प्रस्तुत है। नये एलाइनमेंट हेतु राशि रुपये 159.89 करोड़ की डी.पी.आर. विभाग द्वारा मौर्थ को वांछित स्वीकृति हेतु पत्र दिनांक 07.07.2014 प्रस्तुत की जा चुकी है**,** जिसकी प्रति परिशिष्ट-**5** पर प्रस्तुत है। नये एलाइनमेंट का कार्य वांछित स्वीकृति प्राप्त होने पर किया जा सकेगा।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

सहरिया बहुल क्षेत्र में विकास योजनाओं हेतु बजटीय प्रावधान

52. श्री ललित कुमार (किशनगंज) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जनजाति क्षेत्र के विकास के लिए अलग से बजट का प्रावधान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार बारां जिले के सहरिया बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज एवं शाहबाद के विकास के लिए कोई ठोस कार्य योजना तैयार कर सहरिया जनजाति के जीवन स्तर को सुधारने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस प्रकार एवं नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ 10 (25) आयोजना/ग्रुप-5/09 दिनांक 30.9.2010 द्वारा राज्य योजना की 12.56 प्रतिशत राशि का प्रावधान जनजाति उपयोजना मद मे करने के निर्देश दिये गये हैं । आदेश की प्रति अनुलग्नक "अ" संलग्न है । इसी क्रम में आयोजना (ग्रुप-5) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ10 (10) आयोजना/ग्रुप-5/2009 दिनांक 6.2.2012 द्वारा समस्त विभागों को राज्य योजना में जनजाति प्रवाह के रूप में बजट उपशीर्ष 796 मांग संख्या 30 में राशि आरक्षित करने के दिशा निर्देश प्रदान किये गये। परिपत्र की प्रति अनुलग्नक "ब" पर संलग्न है।

(2) सरकार द्वारा बारां जिले के सहरिया बाहुल्य क्षेत्र किशनगंज एवं शाहबाद के विकास हेतु भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत सहरिया व्यक्तियों के सम्पूर्ण विकास हेतु सी सी डी योजना स्वीकृत की गई है, जिसमें मुख्यत: शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, कौशल विकास एवं संसाधन विकास करना है। योजना का विवरण परिशिष्ट "स" पर संलग्न है। राजस्थान सरकार द्वारा सहरिया समग्र विकास योजना किशनगंज एवं शाहबाद तहसील में सहरिया व्यक्तियों के सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान हेतु संचालित की जा रही है, जिसमें मुख्यत: कुपोषण निवारण, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आधारभूत संरचनाओं का निर्माण कराया जायेगा। विवरण परिशिष्ट "द" पर संलग्न है।

(प्रतियां व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

नगर में चम्बल से पेयजल की आपूर्ति

53. श्रीमती अनीता (नगर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र नगर को चम्बल पेयजल योजना से पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उक्त योजना का कार्य कब तक पूर्ण कर क्षेत्रवासियों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। सतही जल स्रोत चम्बल नदी से विधान सभा क्षेत्र नगर के कस्बा नगर एवं 232 ग्रामों को क्लस्टर वितरण प्रणाली द्वारा पेयजल उपलब्ध

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

कराने हेतु चम्बल-धौलपुर-भरतपुर वृहद् पेयजल परियोजना के प्रथम चरण के द्वितीय भाग की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 30 मई, 2013 को राशि रुपये 720.31 करोड़ की जारी की गई। कस्बा नगर एवं 232 ग्रामों को उक्त प्रगतिरत योजना से कार्यादेश अनुरूप माह मार्च, 2016 तक लाभान्वित करना प्रस्तावित है।

बड़ी सादड़ी के पशु चिकित्सालयों में रिक्त पद

54. श्री गोतम कुमार (बड़ी सादड़ी) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में वर्तमान में कितने पशु चिकित्सालय कहां-कहां पर संचालित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से किस-किस चिकित्सालय में किस-किस स्तर के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं? चिकित्सालयवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सालयों में पद रिक्त रहने के क्या कारण हैं? क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार रिक्त पदों के भरने तक पशुओं की आपात चिकित्सा हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में 5 प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय तथा 8 पशु चिकित्सालय संचालित हैं। सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में संचालित पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) कर्मियों की सेवानिवृति, नियमित नियुक्ति/पदोन्नति में विलम्ब आदि के कारण पशु चिकित्सालयों में पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जाता है।

(4) पशु चिकित्सालय, बांसी एवं केवलपुरा के अतिरिक्त प्रत्येक पशु चिकित्सालय पर तकनीकी चिकित्सा कर्मी कार्यरत हैं। पशु चिकित्सालय, बांसी

(पशुपालन मंत्री)

का अतिरिक्त कार्य पशु चिकित्सा उपकेन्द्र सांगरिया के पशुधन सहायक को तथा पशु चिकित्सालय केवलपुरा का अतिरिक्त कार्यभार पशुधन आरोग्य चल इकाई, बड़ी सादड़ी के पशुधन सहायक को दिया गया है। आपात चिकित्सा व्यवस्था तहसील स्तरीय पशुधन आरोग्य चल इकाई द्वारा सम्पादित की जा रही है।

परिशिष्ट-1

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में संचालित पशु चिकित्सालयों का विवरण

क्र.सं.	**प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय**	**क्र.सं.**	**पशु चिकित्सालय**
1.	बड़ी सादड़ी	1.	निकुम्भ
2.	डूंगला	2.	बान्सी
3.	बोहेडा	3.	भाणुजा
4.	मंगलवाड चौराहा	4.	खारदेवला
5.	देवगढ़	5.	चिकारडा
6.	-	6.	केवलपुरा
7.	-	7.	ग्यासपुर
8.	-	8.	रठाजना

परिशिष्ट-2

विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के पशु चिकित्सालयों में स्वीकृत व रिक्त पदों की सूचना

क्र.सं.	नाम चिकित्सालय	वरिष्ठ पशु चिकित्सक		पशु चिकित्सक		पशु चिकित्सा सहायक		पशुधन सहायक		पशुधन परिचर		जलधारी		सफाईकर्ता	
		स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद	स्वीकृत पद	रिक्त पद
1.	बड़ी सादड़ी	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	0	1	1
2.	भाणुजा	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
3.	बोहेडा	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1
4.	बांसी	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0
5.	खरदेवला	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
6.	केवलपुरा	0	0	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0	0
7.	निकुम	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0
8.	डूंगला	1	0	0	0	1	0	0	0	1	1		0	1	0
9.	मंगलवाड चौराहा	1	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0
10.	चिकारडा	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	1	1
11.	देवगढ़	1	1	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0	0
12.	रठाजना	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
13.	ग्यासपुर	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1
	योग	**5**	**3**	**8**	**7**	**9**	**2**	**6**	**1**	**12**	**8**	**2**	**1**	**9**	**6**

चौरासी में लम्बित घरेलू विद्युत कनेक्शन

55. **श्री सुशील कटारा** (चौरासी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी में घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित परिवारों को विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में अभी भी हजारों की संख्या में बी.पी.एल. परिवार घरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार वित्तीय वर्ष 2014-15 में उक्त परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) विधान सभा क्षेत्र चौरासी में कितने बी.पी.एल. परिवार विद्युत सुविधा से वंचित हैं? परिवारों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। घरेलू विद्युत कनेक्शन देना एक सतत् प्रक्रिया है। विधान सभा क्षेत्र चौरासी में आवेदित घरेलू विद्युत कनेक्शनों को विद्युत तंत्र उपलब्धतानुरूप नियमानुसार मांग पत्र जारी किये जा रहे हैं। मांग पत्र की राशि जमा होने के पश्चात विद्युत कनेक्शन दिये जा रहे हैं। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत 12वीं पंचवर्षीय योजना में 15,889 बी पी एल परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भावित है।

(2) जी हां। वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौरासी में 16,766 बी पी एल परिवार विद्युत सुविधा से वंचित हैं। पूर्व में स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत (10वीं योजना में) 300 से अधिक आबादी वाली ढाणी/मजरों में निवास करने वाले 8,162 बी पी एल परिवारों को नि:शुल्क घरेलू विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये थे। 12वीं योजना के अन्तर्गत 100 से 300 तक की आबादी वाली ढाणियों/मजरों में योजना के अनुरूप 15,889 बी पी एल घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जाना संभावित हैं।

(3) जी हां। 100 व 100 से अधिक आबादी वाली ढाणियों में निवास करने वाले बी पी एल परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन देने के लिए पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना स्वीकृत हो चुकी है। निविदा कार्य प्रक्रियाधीन है। 12वीं पंचवर्षीय योजना में 15,889 बी पी एल परिवारों को घरेलू विद्युत कनेक्शन दिया जाना सम्भावित है।

(ऊर्जा मंत्री)

(4) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौरासी में लगभग 16,766 बी पी एल परिवार विद्युत सुविधा से वंचित हैं।

गारंटी अवधि की सड़कों का रख-रखाव नहीं करने वाले संवेदकों के विरुद्ध कार्यवाही

56. श्री रमेश (सपोटरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या जिला करौली में विगत पांच वर्षों में संवेदकों द्वारा गारंटी अवधि में सड़कों का रख-रखाव निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया गया है? यदि हां, तो किस-किस सड़क का किस-किस संवेदक द्वारा व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) गारंटी अवधि में सड़कों का रख-रखाव नहीं रखने वाले संवेदकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई एवं किया जाना प्रस्तावित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त प्रकरणों में विगत पांच वर्षों में किस-किस फर्म/संवेदक को कब-कब ब्लैकलिस्टेड किया गया व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जिला करौली में विगत पांच वर्षों में संवेदकों द्वारा गारण्टी अवधि में सड़कों के रख-रखाव का सड़कवार विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) गारण्टी अवधि में सड़कों का अनुबन्धानुसार रख-रखाव नहीं रखने वाले संवेदकों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(3) उक्त प्रकरणों में विगत पांच वर्षों में फर्म को डिबार किये जाने का विवरण परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

प्रश्न संख्या-57

(स्थगित)

जायल को नागौर लिफ्ट परियोजना से पेयजल उपलब्ध कराने की कार्य योजना

58. डा. मंजू बाघमार (जायल) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. मंजू बाघमार)

(1) क्या नागौर लिफ्ट परियोजना से नागौर जिले को पेयजल आपूर्ति हेतु योजना स्वीकृत की गई है? उक्त परियोजना द्वारा जिले को कितने वर्षों तक एवं कितनी मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल को उक्त परियोजना का पानी कब तक उपलब्ध करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नागौर जिले के समस्त 12 शहरों/कस्बों एवं 1,480 ग्रामों को सतही जल स्रोत इंदिरा गांधी नहर से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण की माह अगस्त, 2006 में राशि रुपये 761.01 करोड़ तथा द्वितीय चरण की माह अगस्त, 2012 में राशि रुपये 2,938.00 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई। उक्त दोनों चरणों की सम्मिलित योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2045 तक की अभिकल्पित कुल पेयजल मांग 389.62 एम.एल.डी. में से शहरों/कस्बों हेतु 139.00 एम.एल.डी. तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु 250.62 एम.एल.डी. निर्धारित है।

(2) विधान सभा क्षेत्र जायल के कुल 172 ग्रामों में से तीन ग्राम प्रथम चरण में सम्मिलित हैं तथा इनमें से एक ग्राम ऊंटवालिया को लाभान्वित किया जा चुका है। क्षेत्र के शेष 169 ग्रामों को कलस्टर वितरण प्रणाली द्वारा परियोजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत पैकेज सीडीएस-4 के तहत लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है। आधारभूत संरचनाओं के कार्यों यथा जल शोधन संयंत्र, पम्पिंग स्टेशन एवं मुख्य पाइपलाइन की स्वीकृत योजनाओं की निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने एवं कार्यादेश जारी होने के पश्चात् पैकेज सीडीएस-4 की निविदा प्रक्रिया प्रारम्भ की जावेगी।

प्रदेश के जिला पशु चिकित्सालयों में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि

59. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा वर्ष 2013-14 के बजट में 15 जिलों में जिला पशु चिकित्सालयों को क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी? उनमें से

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

कितने जिलों में चिकित्सालय क्रमोन्नत कर दिये गये एवं कितने जिलों में क्रमोन्नयन शेष है? जिलों के नाम सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त जिलों में क्रमोन्नयन के उपरान्त भौतिक सुविधाओं, कार्मिकों एवं चिकित्सकों के पदस्थापन, प्रयोगशाला आदि के क्या नवीन कार्य स्वीकृत किये गये? उक्त प्रत्येक चिकित्सालय में इनकी वर्तमान स्थति क्या है?

(3) क्रमोन्नयन के कारण प्रत्येक चिकित्सालय में नवीन सुविधाओं के सृजन पर कितना व्यय किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट में 18 जिला स्तरीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की गई थी। समस्त 18 जिला स्तरीय प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालयों को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में क्रमोन्नत किया जा चुका है।

(2) क्रमोन्नत हुए बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में समस्त आवश्यक भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। वर्ष 2013-14 में इन बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में 9 में एक्सरे तथा 7 में सोनोग्राफी मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। इसके अतिरिक्त, भवन/मशीनरी, साज सामान, आदि के लिये वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना अन्तर्गत राशि प्रस्तावित की गई है।

इनके लिए समस्त आवश्यक पद स्वीकृत कर दिये गये हैं। नवीन स्वीकृत पदों को कार्मिकों की उपलब्धता अनुसार भरा जा रहा है।

क्रमोन्नत हुए बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों के प्रत्येक जिले में जिला रोग निदान इकाई पूर्व से ही कार्यरत है।

क्रमोन्नत बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में नवीन भौतिक सुविधाओं, नवीन स्वीकृत पद एवं जिले में प्रयोगशालाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) वर्ष 2013-14 में क्रमोन्नत हुए बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयों में एक्सरे एवं सोनोग्राफी मशीन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राशि रु. 74.29 लाख का व्यय किया गया। क्रमोन्नत बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालयवार किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट-अ

वित्तीय वर्ष 2013-14 के बजट घोषणा में क्रमोन्नत बहुउद्देश्यीय पशु चिकित्सालयों में उपलब्ध करवाई गई भौतिक सुविधा/पद एवं जिले में पशुरोग निदान प्रयोगशालाओं का विवरण

क्र. सं.	बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय का जिला मुख्यालय	एक्सरे मशीन की स्थापना	सोनोग्राफी मशीन की स्थापना	कुल स्वीकृत नवीन पद	वर्ष 2013-14 में किया गया व्यय (लाखों में)	पशुरोग निदान प्रयोगशाला कार्यरत है या नहीं
1.	भीलवाड़ा	0	1	13	4.10	कार्यरत
2.	दौसा	0	0	13	-	कार्यरत
3.	झुन्झुनूं	1	1	12	9.16	कार्यरत
4.	हनुमानगढ़	0	1	13	4.08	कार्यरत
5.	चूरू	0	0	13	-	कार्यरत
6.	धौलपुर	1	1	13	9.16	कार्यरत
7.	सवाई माधोपुर	0	1	13	4.09	कार्यरत
8.	करौली	0	0	13	-	कार्यरत
9.	जैसलमेर	0	0	13	-	कार्यरत
10.	बाडमेर	1	0	13	5.07	कार्यरत
11.	जालौर	1	0	13	5.07	कार्यरत
12.	सिरोही	0	0	13	-	कार्यरत
13.	बारां	1	1	13	9.16	कार्यरत
14.	बूंदी	1	0	13	5.10	कार्यरत
15.	चित्तौड़गढ़	0	0	13	-	कार्यरत
16.	डूंगरपुर	1	1	13	9.16	कार्यरत
17.	राजसमन्द	1	0	13	5.07	कार्यरत
18.	प्रतापगढ़	1	0	13	5.07	कार्यरत

जयपुर डिस्काम द्वारा किसानों से वसूली गई पेनल्टी राशि का समायोजन

60. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(1) क्या यह सही है कि जयपुर डिस्काम द्वारा आदेश जारी कर विद्युत चोरी में पेनल्टी की राशि को चार गुणा कर क्षेत्र के किसानों व उपभोक्ताओं से करोड़ों रुपये की अवैध वसूली की गई है? यदि हां, तो कब किस आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि इस तरह का आदेश सरकार द्वारा गजट नोटिफिकेशन के द्वारा ही जारी किया जा सकता है? यदि हां, तो इस प्रकरण में कौन-कौन अधिकारी दोषी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त प्रकरण में किसानों व उपभोक्ताओं से की गई नियम विरुद्ध वसूली को समायोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के पत्र क्रमांक 1711 दिनांक 11.02.2013 के तहत जारी दिशा-निर्देशों की पालना में जयपुर डिस्काम द्वारा आदेश क्रमांक 285 दिनांक 12.02.2013 (जेपीआर 5-691) जारी किया गया है जिसके तहत चोरी के प्रथम अपराध में प्रशमन राशि एवं वैधानिक दायित्व राशि नियमानुसार लिये जाने का प्रावधान निर्धारित किया गया है। आदेशों की प्रतियां प्रपत्र-'अ' एवं 'ब' पर उपलब्ध हैं।

(2) विद्युत अधिनियम-2003 की धारा 50 सपठित धारा 181 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए तथा धारा 184 के अन्तर्गत भारत सरकार के ऊर्जा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस.ओ. 790 (ई) दिनांक 08.6.2005 द्वारा जारी आदेशों की अनुपालना में राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचना दिनांक 20 जून, 2006 के तहत वैधानिक दायित्व के लिए चोरी के प्रकरणों में विद्युत की प्रमात्रा के अनन्तिम निर्धारण हेतु प्रावधान निर्धारित किये गये थे। आदेश क्रमांक जेपीआर 5-691 के तहत उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार ही वैधानिक दायित्व राशि का अन्तिम निर्धारण किया जाता है एवं राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 28.02.2004 के तहत निर्धारित दर के अनुसार ही प्रशमन राशि ली जाती है। आदेशों की प्रतियां प्रपत्र-'स' एवं 'द' पर उपलब्ध हैं।

(3) निगम द्वारा जारी आदेश क्रमांक जेपीआर 5-691 के तहत चोरी के प्रकरणों में प्रशमन एवं वैधानिक दायित्व राशि विद्युत अधिनियम 2003

(ऊर्जा मंत्री)

एवं राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा जारी अधिसूचना/नियम अनुसार ही ली जा रही है। अत: राशि समायोजित नहीं की जा सकती है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जमवारामगढ़ से गुढ़ा किशोरी मार्ग पर सड़क का निर्माण कार्य

61. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में सरकार द्वारा बजट वर्ष 2013-14 में जमवारामगढ़ (जयपुर) नकची घाटी-आंधी-झिरी-गुढा किशोरी मार्ग पर सड़क बनाने हेतु 90 करोड़ रुपये की घोषणा की गयी थी?

(2) क्या सरकार उक्त सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र चालू करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नक्ची घाटी-आंधी-झिरी-गुढा किशोरी मार्ग सड़क को बी.ओ.टी. आधार पर विकसित करने हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनायी गयी थी। परन्तु इस सड़क का बड़ा भाग वन्य जीव अभयारण्य में आने व पर्याप्त यातायात न होने के कारण यह परियोजना अव्यावहारिक (नान-वायबल) पायी गयी।

(2) उक्त सड़क का निर्माण किया जाना राज्य सरकार की प्राथमिकताओं एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

गोगुन्दा के आदिवासियों के उत्थान हेतु संचालित योजनाएं

62. श्री प्रताप लाल भील (गोगुन्दा) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा, कोटड़ा एवं झाड़ोल के आदिवासी जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं संचालित की जा रही हैं?

(2) क्या उक्त योजनाओं से आदिवासियों के जीवन स्तर में कोई

(श्री प्रताप लाल भील)

सुधार आया है? यदि हां, तो किस स्तर पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा जनजाति के लोगों के उत्थान के लिये गोगुन्दा विधान सभा क्षेत्र में माडा की योजनाओं का संचालन कर विकास किया जा रहा है। कोटड़ा एवं झाड़ोल पंचायत समितियों में अनुसूचित क्षेत्र की योजनाओं से विकास कार्य संचालित किये जा रहे हैं। संचालित योजनाओं की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) जनजाति के उत्थान हेतु संचालित योजनाओं से इनके जीवन स्तर में सुधार हुआ है। जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग तीनों पंचायत समितियों के जनजाति समुदाय के जीवन स्तर में सुधार का अध्ययन माणिक्य लाल वर्मा आदिम जाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, उदयपुर से करवाया जाएगा। इसके साथ ही साक्षरता, स्वास्थ्य आदि के उपलब्ध समंकों से जीवन स्तर में सुधार परिलक्षित होता है। उपलब्ध समंकों का विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(सूची व विवरण पुस्तकालय में रखे गये)

अलवर जिले में फ्लोराइड समस्या से ग्रस्त गांवों में शुद्ध पेयजल की योजना

63. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) अलवर जिले के कितने गांवों के पानी में फ्लोराइड की समस्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों को स्वच्छ व शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित प्रबंधन सूचना तंत्र (आई.एम.आई.एस.) के अनुसार जिला अलवर के 167 ग्रामों (दिनांक 1 अप्रैल, 2014 की स्थिति के अनुसार) के स्थानीय भू-जल में फ्लोराइड की मात्रा निर्धारित मानक 1.5 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(2) जी हां। जिले के उक्त 167 ग्रामों में से 82 ग्रामों को दूरस्थ सही पेयजल गुणवत्ता के जल स्रोत निर्मित कर लाभान्वित कर दिया गया है। विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

11 ग्रामों को स्वच्छ पेयजल से लाभान्वित करने हेतु स्वीकृत योजनाओं के कार्य प्रगति पर हैं। विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

1.5 मिलीग्राम/लीटर से अधिक फ्लोराइड की मात्रा वाले शेष 74 ग्रामों हेतु प्रस्ताव बनाये जाकर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धतानुसार स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्णय लिया जावेगा। विवरण परिशिष्ट-द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद उपखण्ड में कृषि उपज मण्डी की स्थापना

64. श्री गोतमलाल (धरियावद) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उपखण्ड धरियावद में कृषि उपज मण्डी नहीं होने से किसानों को अपनी उपज को बेचने हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है जिससे समय व धन का अपव्यय होता है?

(2) क्या सरकार उपखण्ड धरियावद में कृषि उपज मण्डी खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अधिसूचना दिनांक 21.5.2009 के द्वारा धरियावद को कृषि उपज मण्डी समिति, प्रतापगढ़ की गौणमण्डी घोषित किया गया है। किसानों द्वारा अपनी उपज विक्रय हेतु धरियावद गौणमण्डी प्रांगण में लाई जा रही है।

(2) जी नहीं। नई कृषि उपज मण्डी समिति के गठन हेतु राज्य सरकार द्वारा 40 लाख रुपये प्रति वर्ष वार्षिक आय के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। धरियावद गौणमण्डी की आय निर्धारित मापदण्ड से कम होने के कारण गौणमण्डी धरियावद को स्वतंत्र मण्डी के रूप में घोषित नहीं किया जा सकता।

अलवर शहर में हाइटेंशन विद्युत लाइनों को भूमिगत करने की कार्य योजना

65. श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री बनवारीलाल सिंघल)

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र के अधिकतम भाग में विद्युत हाइटेंशन लाइनें मकानों के ऊपर से गुजर रही हैं? यदि हां, तो क्या विगत पांच वर्षों में इसके कारण कोई जन हानि हुई है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जन हित में उक्त हाइटेंशन लाइनों को भूमिगत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र की सभी विद्युत लाइनें भारतीय विद्युत अधिनियम 1956 के तहत वर्णित प्रावधानों के अनुसार डाली गई हैं। परन्तु शहर व आसपास स्थित कृषि भूमि पर निर्मित आवासीय कालोनियों में उपरोक्त लाइनों के पास व नीचे नियमों के विपरीत निर्माण कार्य किया गया है जिसके लिये समय-समय पर विभाग द्वारा उपरोक्त निर्माण को हटाने के लिये समाचार पत्रों में अपील जारी की जाती है। उक्त विधान सभा क्षेत्र में मकानों के ऊपर से गुजर रही विद्युत लाइनों के कारण किसी भी जन हानि की सूचना नहीं है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

सांवलियाजी से भादसोड़ा चौराहे तक फोरलेन सड़क का निर्माण

66. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा गत वर्षों में सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी से भादसोड़ा चौराहे तक सांवलियाजी मन्दिर मण्डल एवं सरकार के संयुक्त सहयोग से फोरलेन सड़क निर्माण कार्य की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कार्य हेतु सांवलियाजी मन्दिर मण्डल द्वारा कोई सहयोग राशि सरकार को दी गई है? यदि हां, तो कब व कितनी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि मन्दिर मण्डल द्वारा उक्त कार्य के लिए 8 करोड 88 लाख रुपये की राशि सरकार को सौंप दी गई है? यदि हां, तो अब

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

तक उक्त फोरलेन सड़क के निर्माण कार्य को प्रारम्भ नहीं करने के क्या कारण रहे? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त मार्ग के निर्माण कार्य को शीघ्र प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2013-14 में सुप्रसिद्ध कृष्णधाम सांवलियाजी से भादसोड़ा सड़क की फोरलेन चौड़ाइकरण एवं सुदृढ़ीकरण की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा सहभागिता योजना (सांवलिया मन्दिर ट्रस्ट 50 प्रतिशत एवं राज्य सरकार 50 प्रतिशत) के तहत 1,481.40 लाख रुपये की जारी की गई। स्वीकृति की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। सांवलियाजी मन्दिर मण्डल द्वारा सहभागिता के तहत लागत का 50 प्रतिशत भाग राशि रुपये 740.70 लाख एवं सांवलियाजी मन्दिर बाइपास के कार्य का भी 50 प्रतिशत भाग राशि रुपये 147.67 लाख, कुल राशि 888.37 लाख मार्च 2013 में जमा कराई गई है। जमा राशि के चालान की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है।

(3) जी हां। उक्त फोरलेन सड़क का कार्य माह जुलाई 2013 से प्रारम्भ है जिसके अन्तर्गत 5 पुलियाओं की एक तरफा चौड़ाइकरण का कार्य किया गया। सड़क के दोनों तरफ पेड़ों की कटाई की स्वीकृति जिला कलक्टर महोदय के पत्रांक राजस्व/12-8/13/पे.काटा./1510 दिनांक 25.09.2013 के पश्चात् कि.मी. 1 से 3 तक पेड़ कटाई का कार्य किया गया तथा पेड़ों को वन विभाग को सुपुर्द किया गया। कि.मी. 4 से 6 के पेड़ों को मन्दिर मण्डल ट्रस्ट में जमा कराये जाने के निर्णयों के तहत कार्यवाही प्रगति पर है एवं कि.मी. 6 से 9 तक फोरलेन के बाइपास हेतु मन्दिर मण्डल द्वारा भूमि अधिग्रहण कर विभाग को आदिनांक तक नहीं सौंपी गई है। उक्त कारणों से कार्य की प्रगति बाधित रही है। बाइपास का कार्य मन्दिर मण्डल द्वारा भूमि अधिग्रहण सौंपने के पश्चात् सम्भव हो सकेगा। शेष कार्य मई 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(4) जी हां। उक्त कार्य प्रगति पर है तथा मई 2015 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है तथा बाइपास कार्य मन्दिर मण्डल द्वारा भूमि उपलब्ध कराने के पश्चात् सम्भव हो सकेगा।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

जनजाति क्षेत्रों में महाराष्ट्र पैटर्न लागू करने की योजना

67. श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत पांच वर्षों में कुल राज्य योजना की कितनी प्रतिशत राशि का जनजाति उप योजना के लिए व्यय किया गया? मदवार आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश की कुल जनसंख्या में से कितनी प्रतिशत जनसंख्या जन-जाति उप योजना क्षेत्र के अन्तर्गत आती है एवं उस पर प्रदेश के कुल बजट की कितनी प्रतिशत राशि व्यय की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा आदिवासियों के विकास के लिए वर्ष 1999-2000 में महाराष्ट्र पैटर्न लागू किया गया है? यदि हां, तो उन नीतियों के अनुसार पांच वर्षों में कितना बजट प्रावधान किया गया तथा वास्तविक व्यय कितना किया गया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग सम्बन्धित विभागों द्वारा पूर्ण रूप से किया गया है? यदि हां, तो भौतिक उपलब्धियां क्या रहीं? यदि पूर्ण उपयोग नहीं किया गया है तो क्यों एवं कौन से सुधारात्मक उपाय प्रस्तावित हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में कुल राज्य योजना की 11.66 प्रतिशत राशि का जनजाति उपयोजना के लिये व्यय किया गया। वर्षवार राज्य योजना मद एवं जनजाति उपयोजना मद में आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण अनुलग्नक "अ" पर संलग्न है।

(2) राज्य की कुल जनसंख्या का 13.47 प्रतिशत जनजाति जनसंख्या है। वर्ष 2014-15 हेतु कुल राज्य योजना 4698933.18 लाख रुपये (छियालिस हजार नौ सौ निवासी करोड़ एवं तैतीस लाख अठारह हजार) में से 646984.62 लाख रुपये (छह हजार चार सौ उनतर करोड चौरासी लाख बासठ हजार) जनजाति प्रवाह हेतु रखे गये है, जो कुल राज्य योजना का 13.77 प्रतिशत है। विगत पांच वर्षों में कुल राज्य योजना की 11.66 प्रतिशत राशि का जनजाति उपयोजना के लिये व्यय किया गया।

(3) जी हां। राज्य सरकार (वित्त विभाग) के यू.ओ. नोट दिनांक 31 दिसम्बर 1999 द्वारा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में महाराष्ट्र प्रणाली

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

अपनाये जाने सम्बन्धित प्रस्तावों को स्वीकार किया गया था जिसके सम्बन्ध में विस्तृत प्रक्रिया अनुलग्नक "ब" पर संलग्न है। पिछले पांच वर्षों में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में जनजाति कल्याण निधि अन्तर्गत 75484.67 लाख रु. (सात सौ चौपन करोड़ चौरासी लाख एवं सडसठ हजार रुपये) का सशोधित बजट प्रावधान किया गया तथा वास्तविक व्यय 59784.09 लाख रु. (पांच सौ सतयानवे करोड़ चौरासी लाख एवं नौ हजार रुपये) का किया गया। वर्षवार एवं मदवार प्रावधान एवं व्यय का विवरण अनुलग्नक "द" पर संलग्न है।

पुन: राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.10(25) आयोज/गुप-5/09 दिनांक 30.09.2010 द्वारा राज्य योजना की 12.56 प्रतिशत राशि का प्रावधान जनजाति उपयोजना मद में करने के निर्देश दिये गये। आदेश की प्रति अनुलग्नक "स" संलग्न है। जनजाति उपयोजना प्रवाह अन्तर्गत गत 5 वर्षो में 18,566.04 करोड रुपये के आबंटन के विरुद्ध विभिन्न विभागों द्वारा 16,288.60 करोड रुपये व्यय किये गये। वर्षवार विवरण अनुलग्नक "अ" पर संलग्न है।

(4) जी हां। सम्बन्धित विभागों द्वारा जनजाति क्षेत्र के लिए आबंटित राशि का उपयोग किया जा रहा है। राज्य योजना अन्तर्गत जनजाति उपयोजना मद हेतु राशि विभिन्न विभागों को उनके बजट मद में ही प्राप्त होती है एवं विभागीय बजट को उनके द्वारा व्यय किया जाकर उपलब्धियां हासिल की जाती हैं। जनजाति उपयोजना हेतु व्यय भी उनके द्वारा किया जाकर निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति की जा रही है। विभिन्न विभागों द्वारा जनजाति उपयोजना मद में गत पंचवर्षीय योजना (2007-08 से 2011-12) एवं बारहवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षो (2012-13 एवं 2013-14) में वर्षवार भौतिक उपलब्धियों का विवरण अनुलग्नक "य" पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्तकालय में रखे गये)

जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में रिक्त तकनीकी पदों पर भर्ती की प्रक्रिया

68. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) व **श्री राजेन्द्र सिंह यादव** (कोटपूतली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2013 में पम्प चालक, फीटर, मीटर रीडर, लाइनमैन एवं सहायक के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की गई थी? यदि हां, तो कब एवं कितने पदों के लिए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त भर्ती के लिए आवेदन-पत्र मांग लिये गये हैं? यदि हां, तो कुल कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विभाग में भर्ती करने के लिए दोबारा से आवेदन पत्र मांगने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सरकार रिक्त पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को पूर्ण कर नियुक्तियां देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। विभाग में तकनीकी संवर्ग के वर्णित 1,294 पदों पर भर्ती प्रक्रिया माह अगस्त, 2013 में प्रारम्भ की गई थी। वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जी हां। उक्त वर्णित पदों पर भर्ती के लिये विभाग में कुल 1,82,624 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। पदवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) विभाग में तकनीकी संवर्ग में श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.09.2008 के क्रम में प्रतिवर्ष नियुक्ति हेतु विज्ञप्ति नहीं निकालने के कारण तीन वर्ष आयु सीमा में अतिरिक्त छूट केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को दी गई है जो विगत वर्षों में विभाग द्वारा भर्ती नहीं किये जाने के कारण दिनांक 1.1.2014 को निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके थे। जो अभ्यर्थी दिनांक 1.1.2014 को 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं 38 वर्ष की आयु पूर्ण नहीं की है, उन्हीं अभ्यर्थियों से आवेदन मांगे गये हैं।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

(5) जी हां। प्राप्त आवेदनों के क्रम में वरीयता सूची तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त तद्‌नुसार भर्ती की चयन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

परिशिष्ट–अ

विभाग में तकनीकी संवर्ग अन्तर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
1	विद्युतकार-द्वितीय	39
2	फीटर-द्वितीय	50
3	सहायक	956
4	लाइनमैन-द्वितीय	20
5	मीटर रीडर-प्रथम	68
6	पम्प चालक-द्वितीय	161
	कुल योग	**1294**

परिशिष्ट–ब

विभाग में तकनीकी संवर्ग अन्तर्गत विभिन्न पदों पर भर्ती के लिये प्राप्त आवेदन पत्रों का श्रेणीवार विवरण

क्रम संख्या	पदनाम	प्राप्त आवेदन पत्र
1	विद्युतकार-द्वितीय	11613
2	फीटर-द्वितीय	11083
3	सहायक	127379
4	लाइनमैन-द्वितीय	2579
5	मीटर रीडर-प्रथम	11098
6	पम्प चालक-द्वितीय	18872
	कुल योग	**182624**

परिशिष्ट-स

विभाग में तकनीकी संवर्ग के कर्मचारियों के श्रेणीवार रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	पदनाम	रिक्त पद
1	2	3
1.	फारमैन प्रथम	07
2.	फारमैन द्वितीय	38
3.	पी.डी. प्रथम	221
4.	पी.डी. द्वितीय	657
5.	फीटर प्रथम	85
6.	फीटर द्वितीय	206
7.	विद्युतकार प्रथम	26
8.	विद्युतकार द्वितीय	78
9.	मीटर निरीक्षक	68
10.	मीटर रीडर	92
11.	मिस्त्री-प्रथम	04
12.	मिस्त्री-द्वितीय	27
13.	लाइनमैन-द्वितीय	41
14.	मैसन	37
15.	एम.आर.टी.	20
16.	राजस्व सुपरवाइजर	07
17.	सहायक	883
18.	बेलदार	449
19.	एस.एफ.ए.	21
20.	जे.एफ.ए.	58
21.	मैकेनिक	43
22.	कारपेन्टर/लेथ आपरेटर	10
23.	ड्रिलिंग पर्यवेक्षक	14
24.	वरिष्ठ वैधक	07
25.	बोरिंग आपरेटर	48
26.	डिलर बोरिंग	44

1	2	3
27.	सहा. डिलर बोरिंग	42
28.	वाहन चालक	194
29.	चौकीदार/कीमैन	124
30.	आर्टीजन	06
	योग	3557

प्रदेश के किसानों को फसलों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी के लिए अनुदान

69. श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि सरकार द्वारा किसानों को फसलों की सुरक्षा हेतु उनके खेत की तारबन्दी करने के लिए अनुदान देने की घोषणा की गई थी? यदि हां, तो कब? क्या सरकार घोषणानुसार किसानों को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

सुराज संकल्प घोषणा पत्र में जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु तारबन्दी हेतु अनुदान दिये जाने की घोषणा की गई थी। उक्त सुराज संकल्प घोषणा पत्र को मंत्री परिषद की आज्ञा 270/2013 द्वारा सरकार के नीतिगत दस्तावेज के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। जंगली जानवरों से फसलों की सुरक्षा हेतु प्रकरण का परीक्षण करवाया जा रहा है।

निवाई में लम्बित कृषि/घरेलू विद्युत कनेक्शन

70. श्री हीरालाल (निवाई) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विगत पांच वर्षों में निवाई विधान सभा क्षेत्र में कृषि कनेक्शन एवं घरेलू कनेक्शन हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कृषि कनेक्शन कब तक के स्वीकृत किये गये व कितने कृषि कनेक्शन लम्बित हैं? उपभोक्ता के नाम एवं पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा भेदभाव पूर्ण तरीके से वी सी आर भरने की शिकायतें प्राप्त हो रही हैं? यदि हां, तो कितने वी सी आर उद्योगों के एवं कितने वी सी आर कृषि उपयोग एवं घरेलू उपभोक्ताओं के भरे गये? नाम एवं पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में निवाई विधान सभा क्षेत्र में 3,531 कृषि कनेक्शन एवं 20,063 घरेलू कनेक्शन हेतु आवेदन प्राप्त हुए। उनमें से सामान्य श्रेणी के माह दिसम्बर, 2008 तक के लगभग सभी कृषि आवेदकों (विवादित को छोड़कर) के कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं एवं मार्च 2009 तक लम्बित कृषि आवेदकों के मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने की प्रक्रिया जारी है। शेष लम्बित कृषि आवेदकों के नाम एवं पते सहित विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

उदयपुर जिले में राजमार्गों को चौड़ा करने की योजना

71. श्री फूलसिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार उदयपुर से झाडोल बलीचा हाइवे से नया खेड़ा झाडोल रोड तथा उदयपुर से खाखा चोसदा वाली रोड वाया उमेडा को चौड़ा करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

उदयपुर से झाडोल वाया नया खेड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग को चौड़ा करने सम्बन्धी कार्यवाही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करने सम्बन्धी नोटिफिकेशन जारी किये जाने के उपरान्त की जा सकेगी।

उदयपुर से खारवा चासदा वाया उमरड़ा सड़क का चौड़ाइकरण विचाराधीन नहीं है। इसका चौड़ाइकरण यातायात गणना, राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्धारित होगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

जोधपुर जिले में जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग में रिक्त पद

58. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के स्वीकृत कार्यरत एवं रिक्त पदों की वर्तमान स्थिति क्या है और ये पद कब से रिक्त हैं? पदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त रिक्त पदों को कब तक भरने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में विभिन्न संवर्गों अन्तर्गत स्वीकृत, पदस्थापित एवं रिक्त पदों का पदवार वांछित विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) विभाग में सहायक अभियन्ता (सिविल, यांत्रिकी एवं विद्युत) के 159 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा विज्ञप्ति जारी की जा चुकी है। आयोग के स्तर पर चयन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर रिक्त पदों को भरने सम्बन्धी कार्यवाही की जा सकेगी।

कनिष्ठ अभियन्ताओं के सहायक अभियन्ता पद पर पदोन्नति होने से विभाग में हुए रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने के सम्बन्ध में प्रकरण प्रक्रियाधीन है।

विभाग में तकनीकी संवर्ग के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए प्राप्त आवेदनों के क्रम में वरीयता सूची तैयार करने की कार्यवाही पूर्ण करने के उपरान्त तद्नुसार भर्ती की चयन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ की जावेगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धौलाई ग्राम (मानसरोवर) में पेयजल आपूर्ति

59. श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' (चित्तौड़गढ़) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जयपुर जिले की मानसरोवर क्षेत्र के धौलाई गांव में विधान सभा नगर नाम से आवासीय कालोनी बसी हुई है? यदि हां,

(श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या')

तो उक्त आवासीय कालोनी में पेयजल आपूर्ति किस प्रकार से की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा नगर के निवासियों द्वारा बार-बार पेयजल की मांग करने पर सरकार द्वारा उक्त कालोनी एवं आस-पास की अन्य कालोनियों को बीसलपुर पेयजल परियोजना से जोड़ने का प्रोजेक्ट लाया गया था? यदि हां, तो कब? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या विधान सभा नगर एवं आस-पास की कालोनियों को उक्त परियोजना से जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो किस-किस कालोनी को एवं किस-किस कालोनी को जोड़ना शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा नगर के नजदीक ही पत्रकार कालोनी को बीसलपुर पाइपलाइन द्वारा जोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त पाइप लाइन विधान सभा नगर कालोनी से होकर ही पत्रकार कालोनी तक पहुंचाई गई है?

(5) क्या सरकार उक्त पाइप लाइन द्वारा विधान सभा नगर को पेयजल आपूर्ति करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जयपुर जिले के मानसरोवर क्षेत्र के धौलाई ग्राम के आस -पास विधान सभा नगर कालोनी एवं जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित/गैर अनुमोदित नव-विकसित कालोनियों हेतु विभागीय आधारभूत संरचना तंत्र तथा पेयजल वितरण तंत्र प्रणाली नहीं होने के कारण यह कालोनी विभागीय पेयजल योजना से नहीं जुडी है। इस कालोनी में कालोनी निवासियों द्वारा निजी स्तर पर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था है।

(2) जी नहीं।

(3) जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित पत्रकार कालोनी की पेयजल आपूर्ति योजना प्राधिकरण द्वारा हस्तान्तरण करने के उपरान्त, विभाग द्वारा वर्ष 2009 से इस कालोनी में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इस कालोनी में पूर्व में स्थापित तीन नलकूपों के सूख जाने से, मानसरोवर स्थित जलकल गृह (बीसलपुर परियोजना एवं स्थानीय नलकूपों के पानी) से पाइप लाइन द्वारा जोड़कर दिनांक 27 फरवरी, 2014 से इस कालोनी में पेयजल आपूर्ति प्रारम्भ की गई है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इसके अतिरिक्त विधान सभा नगर एवं इसके आस-पास नव-विकसित किसी भी कालोनी को बीसलपुर परियोजना से नहीं जोड़ा गया है।

(4) जी हां। मानसरोवर स्थित जलकल गृह से बिछाई गई उक्त पाइप लाइन मानसरोवर स्थित वी.टी. रोड के चौराहे से पत्रकार कालोनी को जाने वाली मुख्य सड़क से गुजरती है।

(5) जी नहीं। बीसलपुर पेयजल परियोजना से पूर्ण क्षमता अनुरूप जयपुर शहर तथा ग्रामीण क्षेत्रों को पेयजल आपूर्ति की जा रही है। विधान सभा नगर एवं इसके आस-पास अन्य नव-विकसित कालोनियों की पेयजल मांग इस परियोजना में सम्मिलित नहीं होने के कारण इनमें परियोजना से पेयजल आपूर्ति करना विचाराधीन नहीं है।

किसानों को आयुर्वेदिक औषधियों के विक्रय की कार्य योजना

60. श्री कैलाश चौधरी (बायतू) : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधियां जैसे शंख पुष्पी, नीम, गोखरू, आक, ऐलोवेरा आदि की प्रचुर मात्रा में पैदावार होती है?

(2) क्या यह भी सही है कि पश्चिमी राजस्थान के किसानों को इन औषधियों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है तथा जिनको जानकारी है उनको व्यवस्थित बिक्री केन्द्र नहीं होने के कारण अपनी पैदावार का उचित मूल्य प्राप्त नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सरकार किसानों को आयुर्वेदिक औषधियों की उपयोगिता के बारे में जानकारी देने तथा उपज के विक्रय हेतु कोई योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। पश्चिमी राजस्थान में आयुर्वेदिक औषधियां जैसे- शंख पुष्पी, गोखरू, नीम, आक, ऐलोवेरा (ग्वारपाठा) आदि प्राकृतिक रूप से प्रचुर मात्रा में पैदा होती हैं।

(2) जी हां। यह सही है कि किसानों को इन औषधियों के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं होती किन्तु कुछ जानकारी अवश्य होती है। उद्यान विभाग ऐलोवेरा (ग्वारपाठा) की खेती के बारे में समय-समय पर कृषकों को जानकारी

(कृषि मंत्री)

उपलब्ध करवा रहा है। इसके साथ ही राजस्थान स्टेट मेडिसिनल प्लान्ट्स बोर्ड, जयपुर द्वारा समय-समय पर प्रशिक्षण एवं आयुष मेलों के माध्यम से औषधीय पादपों की उपयोगिता, उत्पादन एवं विपणन के बारे में जानकारी एवं कृषि साहित्य (ब्रोशर, पम्पलेट, आदि) उपलब्ध करवाया जाता है। उद्यान विभाग द्वारा भी कृषकों को समय-समय पर प्रशिक्षण आयोजित कर औषधीय पौधों की जानकारी एवं साहित्य उपलब्ध कराया जाता है।

औषधीय फसलों का क्षेत्रफल एवं उत्पादन कम होने के कारण व्यवस्थित बिक्री केन्द्र स्थापित नहीं है। अत: औषधीय फसलों की खेती के अन्तर्गत सघन रूप से क्षेत्रफल एवं उत्पादन में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा प्रयास जारी हैं।

कृषि उपज मण्डी समितियों के अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति

61. श्री अमराराम (पचपदरा) : क्या कृषि विपणन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों के कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी जयपुर स्थित सरकार के किन-किन विभागों में कब-कब से प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित हैं? इनका वेतन कहां-कहां से आहरित किया जा रहा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कृषि उपज मण्डी समितियों के अधिकारियों/कर्मचारियों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापन के क्या नियम निर्धारित हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार प्रतिनियुक्ति पर गये उक्त कार्मिकों को कृषि कार्य की महत्ता के मद्देनजर रखते हुए पुन: उनके मूल विभाग में पदस्थापित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य की कृषि उपज मण्डी समितियों का कोई भी अधिकारी/कर्मचारी जयपुर स्थित राज्य सरकार के विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित नहीं है।

(कृषि विपणन मंत्री)

(2) कृषि उपज मण्डी (मण्डी समिति कर्मचारी) सेवा नियम, 1975 में प्रतिनियुक्ति पद पर पदस्थापन के कोई नियम निर्धारित नहीं हैं।

(3) बिन्दु संख्या 1 के अनुक्रम में प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रदेश में नई टोल नीति का निर्धारण

62. श्री राजेन्द्र सिंह यादव (कोटपूतली), **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़) व **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार प्रदेश में नई टोल नीति लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार प्रदेश के राजमार्गों पर टोल की दरें बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार नई टोल नीति के तहत निजी वाहनों को दर बढ़ोतरी से मुक्त रखने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या किसी कम्पनी द्वारा निर्माण कार्य किये जाने वाले हाइवे पर रोड का कार्य पूर्ण होने से पूर्व टोल वसूली प्रारम्भ की जा सकती है? यदि नहीं, तो जयपुर-दिल्ली मार्ग पर किस आधार पर प्रारम्भ किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में प्रचलित टोल नीति (एक्ट एवं टोल नियम) राजस्थान रोड डवलपमेंट एक्ट 2002 के तहत राजस्थान राज्य सड़कों पर लागू है। लेकिन खान सड़कों (Mining Roads) को डवलप करने के लिए पृथक टोल नीति राज्य सरकार में विचाराधीन है।

(2) जी नहीं। वर्तमान में प्रचलित दरें फी नोटिफिकेशन 28 मार्च, 2013 के अनुसार निर्धारित हैं जो 1 अप्रैल, 2013 से लागू हैं। उक्त दरें दो वर्ष पश्चात् 10 प्रतिशत की वृद्धि के साथ संशोधित किये जाने का प्रावधान है। तद्नुसार 01.04.2015 से दरों में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी।

(3) जी नहीं। सरकार का प्रचलित टोल नीति में निजी वाहनों को दर बढ़ोतरी का कोई विचार नहीं है। खान सड़कों (Mining Roads) के डवलपमेंट

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

हेतु विचाराधीन टोल नीति के प्रस्ताव में निजी वाहनों को टोल बढ़ोतरी से मुक्त किये जाने पर विचार करना राज्य का नीतिगत मामला है।

(4) जी हां। जयपुर-दिल्ली मार्ग का चौड़ाइकरण एवं टोल वसूली भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा की जा रही है। उनके प्रबन्धक (तक.) से प्राप्त उत्तर दिनांक 09.07.2014 के अनुसार ''जयपुर-दिल्ली मार्ग पूर्व में चार लेन का था। उस समय भी इस पर टोल वसूली की जा रही थी। चार से छह लेनीकरण करने के लिए रियायतग्राही करार में टोल वसूली का प्रावधान प्रथम दिवस से ही है।'' भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उत्तर की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

सिरोही तहसील में सड़कों के निर्माण की स्वीकृतियां

63. श्री सुखराम विश्नोई (सांचौर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2013 में सिरोही तहसील में मीरपुर से पिचवानिया महादेव, कृष्णगंज की सड़क के निर्माण की स्वीकृति जारी की थी? यदि हां, तो उक्त निविदा अब तक स्वीकृत क्यों नहीं की गई और उसके क्या कारण हैं? निविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2013 में सिरोही तहसील में बरलूट से सियाणा सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी की थी? यदि हां, तो उक्त निविदा अब तक स्वीकृत क्यों नहीं की गई और उसके क्या कारण हैं? निविदा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने वर्ष 2013 में सिरोही तहसील में आकूणा से जालोर जिले की सीमा तक सड़क निर्माण की स्वीकृति जारी की थी? यदि हां, तो उक्त निविदा अब तक स्वीकृत क्यों नहीं की गई और उसके क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने उक्त सभी कार्य निरस्त कर दिये हैं? यदि हां, तो आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा सिरोही तहसील में मीरपुर से पिचवानिया महादेव, कृष्णगंज सड़क के निर्माण की स्वीकृति विशेष

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

प्राथमिकता योजनान्तर्गत जारी की गई थी। प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.01.2014 को कार्यों के समीक्षा के दौरान कार्यादेश जारी नहीं होने वाले कार्यों को बजट प्रावधानानुसार निरस्त योग्य माना गया। समीक्षा मीटिंग के नोट की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। उक्त निर्णयानुसार निविदा निरस्त की गयी।

(2) जी हां। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा सिरोही तहसील में बरलूट से सियाणा सड़क के निर्माण की स्वीकृति विशेष प्राथमिकता योजनान्तर्गत जारी की गई थी। प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.01.2014 को कार्यों के समीक्षा के दौरान कार्यादेश जारी नहीं होने वाले कार्यों को बजट प्रावधानानुसार निरस्त योग्य माना गया। समीक्षा मीटिंग के नोट की प्रति परिशिष्ट-2 पर प्रस्तुत है। उक्त निर्णयानुसार निविदा निरस्त की गयी।

(3) जी हां। वर्ष 2013 में राज्य सरकार द्वारा सिरोही तहसील में आकूणा से जालोर जिले की सीमा तक सड़क के निर्माण की स्वीकृति विशेष प्राथमिकता योजनान्तर्गत जारी की गई थी। प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है। वित्त विभाग द्वारा दिनांक 22.01.2014 को कार्यों के समीक्षा के दौरान कार्यादेश जारी नहीं होने वाले कार्यों को बजट प्रावधानानुसार निरस्त योग्य माना गया। समीक्षा मीटिंग के नोट की प्रति परिशिष्ट-**2** पर प्रस्तुत है। उक्त निर्णयानुसार निविदा निरस्त की गयी।

(4) जी हां। समीक्षा मीटिंग कार्यवाही विवरण की प्रति परिशिष्ट-**2** पर प्रस्तुत है।

(प्रतियां पुस्तकालय में रखी गयीं)

दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाइवे पर निर्माणाधीन अण्डरपास

64. श्री जगदीश नारायण (जमवारामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिल्ली-अजमेर एक्सप्रेस हाइवे वी.के.आई. रोड नं. 5 के सामने जयपुर पर मार्ग को ऊंचा कर अण्डरपास बनाये जाने का कार्य प्रारम्भ किया गया था? यदि हां, तो कब व उक्त कार्य कब तक पूर्ण किया जाना था और इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगदीश नारायण)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कार्य में विलम्ब के कारण आम जनता को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और कई दुर्घटनाएं भी घटित होने से कई व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है? यदि हां, तो विगत पांच वर्षों में उक्त दुर्घटनाओं में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अण्डरपास के कार्य को अब कब तक पूर्ण कर आवागमन प्रारम्भ कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। दिल्ली-जयपुर-अजमेर नेशनल हाइवे का कार्य भारत सरकार के उपक्रम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भा.रा.रा.प्रा.) द्वारा किया जा रहा है। भा.रा.रा.प्रा. के प्रबन्धक (तक.) से प्राप्त उत्तर दिनांक 09.07.2014 के अनुसार 'यह कार्य सितम्बर 2011 में प्रारम्भ किया गया था एवं जुलाई 2014 तक पूर्ण किया जाना है। विलम्ब का मुख्य कारण 132 केवी की लाइन को शिफ्ट/ऊंचा करना है जो कि राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा किया जाना है।' भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उत्तर की प्रति परिशिष्ट-1 पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उपरोक्त जवाब के अनुसार 'अभी यह अण्डरपास रियायतग्राही द्वारा यातायात के लिये बन्द किया हुआ है।'

(3) भा.रा.रा.प्रा. से प्राप्त उपरोक्त जवाब के अनुसार '132 केवी की लाइन को राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड द्वारा ऊंचा करने पर अण्डरपास का कार्य पूर्ण कर लिया जावेगा एवं तदनुसार यातायात खोल दिया जावेगा।'

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

चौहटन में नर्मदा नहर की क्षतिग्रस्त वितरिका

65. श्री तरुण राय कागा (चौहटन) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर की भीमगुडा टेल वितरिका जिसकी लम्बाई 35 से 40 किलोमीटर है व जिसका अन्तिम छोर ग्राम पंचायत बावरवाला के राजस्व गांव दासोरिया, नवापुरा व बावरवाला में

(श्री तरुण राय कागा)

स्थित है, इन गांवों में वितरिका क्षतिग्रस्त है एवं उनकी मरम्मत के लिये किस फर्म को निविदा जारी की गई?

(2) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौहटन की नर्मदा नहर परियोजना के भीमगुडा टेल का अन्तिम छोर ग्राम पंचायत बावरवाला के राजस्व गांव बावरवाला में डिग्गी नम्बर 23-24 है, सप्ताह में तीन दिन पानी की सप्लाई चालू रहने से ओवरफ्लो हो जाता है व पानी खेतों में भर जाता है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है व इससे हुए नुकसान को देखते हुए सरकार द्वारा क्या मुआवजा राशि तय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर की भीमगुडा टेल माइनर की लम्बाई 18 कि.मी. है जिसके अन्तिम छोर पर ग्राम पंचायत बावरवाला है। यह टेल माइनर ग्राम दासोरिया व नवापुरा से भी गुजरती है। वर्तमान में इस माइनर की मरम्मत की आवश्यकता नहीं होने से निविदा प्रकाशन कराया जाना प्रस्तावित नहीं है।

(2) जी हां। कई बार रबी की फसल के दौरान व पीने के पानी की मांग में कमी आने से डिग्गी संख्या 23 व 24 (अन्तिम छोर) पर अस्थायी रूप से जल भराव की स्थिति बन जाती है। इस जल भराव से सिंचाई किया हुआ क्षेत्र प्रभावित नहीं होने से मुआवजा राशि दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

बीसलपुर बांध के जल ग्रहण क्षेत्र एवं सहायक नदियों पर बांध/एनिकट बनाने के निर्धारित मानदण्ड

66. डा. किरोड़ी लाल (लालसोट) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र एवं सहायक नदियों पर बांध व एनिकट बनाने के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) बीसलपुर बांध में मेवाड़ क्षेत्र की कौन-कौनसी नदियों का पानी आता है?

(3) बीसलपुर परियोजना के कारण मेवाड़ अंचल की कौन-कौनसी परियोजनाओं से बांध व एनिकट प्रभावित हुए हैं?

(डा. किरोडी लाल)

(4) क्या यह सही है कि बीसलपुर परियोजना के जलग्रहण क्षेत्र एवं सहायक नदियों के क्षेत्र के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने विशेष निर्देश प्रदान किये हैं? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) बीसलपुर बांध के जलग्रहण क्षेत्र एवं सहायक नदियों में बांध, एनिकट बनाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार के आदेश दिनांक 29.03.2012 द्वारा जारी गाइड लाइन अनुसार प्रस्ताव तैयार कर राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा जल उपलब्धता का अध्ययन कर निर्णय किया जाता है। आदेश दिनांक 29.03.2012 की प्रति परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) बीसलपुर बांध में मेवाड़ क्षेत्र की बनास, खारी, मैनाली, उनली, मानसी, गंभीरी, वागन, चन्द्रभागा, गोमती, कौठारी, बेडच, औराई नदियों का पानी आता है।

(3) बीसलपुर परियोजना के कारण मेवाड़ अंचल की प्रभावित हुई परियोजनाओं, बांधों एवं एनिकटों की सूची परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(4) जी नहीं।

(प्रति व सूची पुस्तकालय में रखी गयीं)

प्रदेश में सस्ती विद्युत सुविधा की कार्य योजना

67. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों को विद्युत सुविधा प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो प्रदेश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या को कितनी मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रदेश के निवासियों को सस्ती विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए विशेष प्रयास किये जा रहे हैं? यदि हां, तो किये जा रहे प्रयासों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। वर्तमान में प्रदेश की लगभग 84 प्रतिशत जनसंख्या को प्रतिदिन औसतन 8,753 मेगावाट विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

(2) राज्य के उपभोक्ताओं को विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित विद्युत दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है।

(ऊर्जा मंत्री)

राज्य सरकार द्वारा निम्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को अनुदान प्रदान कर सस्ती दरों पर विद्युत उपलब्ध कराई जा रही है:-

श्रेणी	विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अनुमोदित दर	राज्य सरकार द्वारा दिया जा रहा अनुदान	अनुदान के बाद प्रभावी विद्युत दरें
बीपीएल 50 यूनिट/माह	2.75 रु./यूनिट	1.90 रु./यूनिट	0.85 रु./यूनिट
लघु घरेलू 50 यूनिट/माह	3.00 रु./यूनिट	1.30 रु./यूनिट	1.70 रु./यूनिट
सामान्य कृषि (मीटर्ड)	3.93 रु./यूनिट	3.03 रु./यूनिट	0.90 रु./यूनिट
सामान्य कृषि (फ्लैट रेट)	500 रु./एच.पी./माह	415 रु./एच.पी./माह	85 रु./एच.पी./माह

प्रदेश के निवासियों को सस्ती विद्युत सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु राज्य सरकार द्वारा विद्युत उत्पादन में बढ़ोतरी, वित्तीय पुनर्संरचना योजना (एफ.आर.पी.), विद्युत छीजत में कमी, विद्युत दुरुपयोग पर अंकुश, मीटरों में ऊर्जा का सही अंकन/पठन, विद्युत राजस्व की प्रभावी वसूली, विद्युत उपकरणों का उचित रखरखाव, इत्यादि प्रयास/कार्य किये जा रहे है।

बहरोड़ में कृषकों से वी.सी.आर. से प्राप्त राशि

68. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक कितनी वी.सी.आर. भरी गईं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त वी.सी.आर. के तहत सरकार को कितनी राशि प्राप्त हुई? क्या सरकार किसानों को राहत देने हेतु वी.सी.आर. की राशि माफ करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ के अन्तर्गत दिनांक 01 अप्रैल, 2013 से दिनांक 31 मार्च, 2014 तक भरी गई वी सी आर का विवरण निम्नानुसार है:-

(ऊर्जा मंत्री)

क्र.सं.	उपखण्ड का नाम	भरी गई वी.सी.आर. की संख्या
1	बहरोड़	685
2	मांडन	345
	कुल योग	**1030**

(2) उक्त वी.सी.आरों. के तहत कुल 42.38 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई है। किसानों से अधिक भार के फलस्वरूप वसूल की गई राशि रुपये 3.83 लाख को बिलों में समायोजित करने के आदेश जारी कर दिये गये हैं। शेष वसूल की गई राशि नियमानुसार ली गई है और इसे वापस लौटाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जयपुर शहर एवं सांगानेर में बिजली के तारों को भूमिगत करने की कार्य योजना

69. श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जयपुर शहर की कालोनियों में नीचे व झूल रहे बिजली के तारों को भूमिगत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की कालोनियों में नीचे और झूल रहे बिजली के तारों को भूमिगत करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। जयपुर शहर की कालोनियों में खिंचे विद्युत तारों की समय-समय पर जांच के दौरान विद्युत तारों के नीचे व झूल रहे पाये जाने पर उन्हें ठीक करवा दिया जाता है। वर्तमान में विद्युत तारों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह कार्य अत्यधिक खर्चीला है।

(2) जी नहीं। सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की कालोनियों में खिंची हुई विद्युत लाइनों की समय-समय पर देख-रेख व मरम्मत की जाती है। विद्युत लाइन नीची व झूलती हुई पाई जाने पर उसे तुरन्त प्रभाव से ठीक किया जाता है। वर्तमान में उक्त विद्युत लाइनों को भूमिगत करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है क्योंकि यह कार्य अत्यधिक खर्चीला है।

बाड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण का कार्य

70. श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में विद्युतीकरण का कार्य कराया गया है? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में व कितने ग्राम अभी तक विद्युतीकरण से वंचित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत ग्राम सेवरपाली में अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक प्रारम्भ करवा दिया जायेगा?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़ी में 220 गांव हैं। इनमें से राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 210 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 10 गांवों का विद्युतीकरण शेष है। विद्युतीकृत/अविद्युतीकृत गांवों का विवरण प्रपत्र-'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। उक्त ग्राम राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित हैं। उक्त ग्राम में विद्युत तंत्र स्थापित करने का आवश्यक कार्य किया जाना प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

सीकर जिले में घरेलू विद्युत कनेक्शन

71. श्री रतन लाल जलधारी (सीकर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सीकर जिले में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक घरेलू विद्युत कनेक्शन के आवेदन लिये गये हैं? यदि हां, तो उपखण्डवार प्राप्त आवेदनों का संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदकों को विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखे।

(3) क्या सरकार लघु एवं सीमान्त काश्तकारों को सिंगलफेज पावर पम्प विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रतन लाल जलधारी)

(4) क्या सरकार समूह के अतिरिक्त एकल ढाणियों को भी घरेलू विद्युत कनेक्शन देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक, व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। सीकर जिले में वर्ष 2008 से दिसम्बर, 2013 तक घरेलू विद्युत कनेक्शन हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या 1,73,051 है। उपखण्डवार संख्या विवरण प्रपत्र-अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। जमा मांग पत्र आवेदकों को समस्त औपचारिकताएं पूर्ण करने पर विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। वर्तमान में उपरोक्त आवेदित पत्रावलियों में से 1,29,264 आवेदकों को कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। शेष रहे आवेदकों को नियमानुसार एवं संसाधनों की उपलब्धता अनुसार विद्युत कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। सिंगलफेज पावर पम्प को विद्युत उपलब्ध कराना तकनीकी एवं व्यावहारिक रूप से साध्य नहीं है। कृषि कार्य के लिए 3 फेज बिजली का ही प्रावधान विद्युत विनियामक आयोग द्वारा किया गया है।

(4) वर्तमान में एकल ढाणी/गैर आबादी क्षेत्र में आवेदक द्वारा "स्व-वित्त-पोषित योजना" के तहत विद्युत कनेक्शन का सम्पूर्ण खर्चा वहन करने पर कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त एकल ढाणी के पास पहले से स्थापित सिंगल फेज ट्रासफार्मर से 500 मीटर की परिधि में अधिकतम 5 घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। आदेश की प्रति प्रपत्र-ब पर उपलब्ध है।

(विवरण व प्रति पुस्तकालय में रखे गये)

जैसलमेर जिले में संचालित पशु औषधालय को स्वीकृत अनुदान

72. श्री छोटू सिंह (जैसलमेर) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के पशु औषधालय कहां-कहां संचालित हैं? स्थानवार, श्रेणीवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार जैसलमेर जिले में वेटेरिनरी कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(श्री छोटू सिंह)

(3) क्या सरकार स्थायी गौशालाओं का अनुदान तीन माह से बढ़ाकर नौ माह तक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र जैसलमेर में वर्तमान में संचालित श्रेणी वार पशु चिकित्सा संस्थाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं।

(3) अभाव ग्रस्त क्षेत्र में अभाव अवधि के दौरान पंजीकृत गौशाओं को केन्द्रीय सहायता कोष से निर्धारित मापदण्ड अनुसार सहायता दी जा रही है। राज्य सरकार द्वारा सुराज संकल्प में गौसंवर्धन एवं संरक्षण हेतु की गयी घोषणा के प्रति सरकार गम्भीर है। नीतिगत निर्णय विचाराधीन है। निर्णयोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

परिशिष्ट-अ

जिला जैसलमेर में संचालित पशु चिकित्सा संस्थाएं

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	संस्था के स्थान का नाम	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत का नाम	नगरपालिका/ नगर निगम आदि	तहसील	पंचायत समिति
1.	जि.च.प.चि. इकाई	जैसलमेर	जैसलमेर	-	जैसलमेर	जैसलमेर	-
2.	मु.मो.वेटे.यू.	जैसलमेर	जैसलमेर	-	जैसलमेर	जैसलमेर	-
3.	बहु. पशु चिकि.	जैसलमेर	जैसलमेर	-	जैसलमेर	जैसलमेर	-
4.	मु.मो.वेटे.यू.	फतेहगढ़	जैसलमेर	फतेहगढ़	-	फतेहगढ़	सम
5.	प्र.श्रे. पशु चिकि.	फतेहगढ़	जैसलमेर	फतेहगढ़	-	फतेहगढ़	सम
6.	प्र.श्रे. पशु चिकि.	सम	जैसलमेर	सम	-	जैसलमेर	सम
7.	प्र.श्रे. पशु चिकि.	मोहनगढ़	जैसलमेर	मोहनगढ़	-	जैसलमेर	जैसलमेर
8.	प्र.श्रे. पशु चिकि.	चांदन	जैसलमेर	चांदन	-	जैसलमेर	जैसलमेर
9.	प्र.श्रे. पशु चिकि.	रामगढ़	जैसलमेर	रामगढ़	-	जैसलमेर	सम
10.	प्र.श्रे. पशु चिकि.	देवीकोट	जैसलमेर	देवीकोट	-	फतेहगढ़	सम
11.	पशु चिकि.	बडोडा गांव	जैसलमेर	बडोडा गांव	-	जैसलमेर	जैसलमेर
12.	पशु चिकि.	देवा	जैसलमेर	देवा	-	जैसलमेर	जैसलमेर

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	संस्था के स्थान का नाम	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत का नाम	नगरपालिका/ नगर निगम आदि	तहसील	पंचायत समिति
13.	पशु चिकि.	सुल्ताना	जैसलमेर	सुल्ताना	-	जैसलमेर	जैसलमेर
14.	पशु चिकि.	खींया	जैसलमेर	खींया	-	जैसलमेर	जैसलमेर
15.	पशु चिकि.	खुहडी	जैसलमेर	खुहडी	-	जैसलमेर	सम
16.	पशु चिकि.	म्याजलार	जैसलमेर	म्याजलार	-	जैसलमेर	सम
17.	पशु चिकि.	जोगा	जैसलमेर	राघवा	-	जैसलमेर	सम
18.	पशु चिकि.	डांगरी	जैसलमेर	डांगरी	-	फतेहगढ़	सम
19.	पशु चिकि.	झिझनियाली	जैसलमेर	झिझनियाली	-	फतेहगढ़	सम
20.	पशु चिकि.	लखा	जैसलमेर	लखा	-	फतेहगढ़	सम
21.	पशु चिकि.	सतो	जैसलमेर	सतो	-	फतेहगढ़	सम
22.	पशु चिकि.	बासनपीर जूनी	जैसलमेर	बासनपीर	-	जैसलमेर	जैसलमेर
23.	पशु चिकि.	पिथला	जैसलमेर	पिथला	-	जैसलमेर	जैसलमेर
24.	पशु चिकि.	सोढाकोर	जैसलमेर	सोढाकोर	-	जैसलमेर	जैसलमेर
25.	पशु चिकि.	बीदा	जैसलमेर	बीदा	-	जैसलमेर	सम
26.	पशु औष.	मूलाना	जैसलमेर	मूलाना	-	फतेहगढ़	सम
27.	उपकेन्द्र	हमीरा	जैसलमेर	हमीरा	-	जैसलमेर	जैसलमेर

क्र. सं.	संस्था का प्रकार	संस्था के स्थान का नाम	विधान सभा क्षेत्र	ग्राम पंचायत का नाम	नगरपालिका/ नगर निगम आदि	तहसील	पंचायत समिति
28.	उपकेन्द्र	दव	जैसलमेर	दव	-	जैसलमेर	सम
29.	उपकेन्द्र	पूनमनगर	जैसलमेर	पूनमनगर	-	जैसलमेर	सम
30.	उपकेन्द्र	लूणार	जैसलमेर	लूणार	-	जैसलमेर	सम
31.	उपकेन्द्र	पोछीना	जैसलमेर	पोछीना	-	जैसलमेर	सम
32.	उपकेन्द्र	भादासर	जैसलमेर	मोकला	-	जैसलमेर	जैसलमेर
33.	उपकेन्द्र	अमरसागर	जैसलमेर	अमरसागर	-	जैसलमेर	जैसलमेर
34.	उपकेन्द्र	नेहडाई	जैसलमेर	नेहडाई	-	जैसलमेर	जैसलमेर
35.	उपकेन्द्र	भागुका गांव	जैसलमेर	बसनजीर की जूनी	-	जैसलमेर	जैसलमेर
36.	उपकेन्द्र	नरसिंहों की ढाणी	जैसलमेर	नरसिंहों की ढाणी	-	फतेहगढ़	सम
37.	उपकेन्द्र	डेढा	जैसलमेर	डेढा	-	जैसलमेर	सम

किशनगढ़ बास की गो-पालक बीमा योजना

73. श्री रामहेत सिंह यादव (किशनगढ़ बास) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गो-पालक बीमा योजना के तहत कितने गो-पालकों का बीमा किया गया? नाम व पते सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त योजना के तहत पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में कितने छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) गत दो वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में गोपालक बीमा योजना के तहत 22 गोपालकों का बीमा किया गया। नाम व पते सहित सूची परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। गोपालक बीमा योजना अन्तर्गत जिन गोपालकों द्वारा बीमा कराया जाता है, उनके कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत छात्रों (अधिकतम दो) को जनश्री योजना (भारतीय जीवन बीमा निगम) अन्तर्गत राशि रु. 100 प्रति माह एक वर्ष तक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है। गत पांच वर्षों में विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ बास में इस योजनान्तर्गत 1,009 छात्रों को छात्रवृत्ति का भुगतान किया गया। सूची परिशिष्ट-ब पर उपलब्ध है।

(3) गोपालक बीमा योजनान्तर्गत बीमित गोपालकों के छात्रों द्वारा आवेदन करने पर सभी पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई है।

(सूचियां पुस्कालय में रखी गयीं)

जोधपुर जिले की पंजीकृत गौशालाओं को देय अनुदान

74. श्री बाबू सिंह (शेरगढ़) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वित्तीय वर्ष 2012-13 व 2013-14 के दौरान सरकार द्वारा प्रदेश

(श्री बाबू सिंह)

की कितनी पंजीकृत गौ-शालाओं को अनुदान दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार आगामी वर्ष में जिला जोधपुर की पंजीकृत गौ-शालाओं को अनुदान देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार सभी पंजीकृत गौ-शालाओं को अभावग्रस्त नहीं होने पर भी निरन्तर अनुदान राशि जारी रखने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 2012-13 में आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा 17 पंजीकृत गौशालाओं को अनुदान दिया गया। वर्ष 2013-14 में 485 पंजीकृत गौशालाओं को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग द्वारा तथा 801 पंजीकृत गौशालाओं को पशुपालन विभाग द्वारा अनुदान दिया गया।

(2) वित्तीय वर्ष 2014-15 में अभाव ग्रस्त क्षेत्र में अभाव अवधि के दौरान पंजीकृत गौशालाओं को केन्द्रीय सहायता कोष से अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें जोधपुर जिले की 13 तहसीलों की 122 गौशालाओं को अनुदान दिये जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

(3) राज्य सरकार द्वारा सुराज संकल्प में गौसंवर्धन एवं संरक्षण हेतु की गयी घोषणा के प्रति सरकार गम्भीर है। नीतिगत निर्णय विचाराधीन है। निर्णयोपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा।

जोधपुर स्थित वरमूल डेयरी में अनियमितता

75. श्री कैलाश भंसाली (जोधपुर) : क्या डेयरी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर स्थित वरमूल डेयरी की वर्तमान आर्थिक स्थिति का तथ्यात्मक प्रतिवेदन सदन की मेज पर रखते हुए गत पांच वर्षो की विभागीय आन्तरिक और सी.ए. आडिट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में जोधपुर स्थित डेयरी में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और लापरवाही के कितने प्रकरण प्रकाश में आये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जोधपुर स्थित वरमूल डेयरी की वर्तमान आर्थिक स्थिति का विवरण निम्नानुसार है

वरमूल डेयरी वर्ष 2013-14 तक 61,31,677 रुपये के संचित लाभ में है, जिसमें से वर्ष 2013-14 के लेखे अन-अंकेक्षित हैं। विवरण प्रदर्श-क पर संलग्न है।

वर्तमान वर्ष में अप्रैल से जून, 2014 तक की अवधि में वरमूल डेयरी रुपये 10.28 लाख के संचित लाभ में है। विवरण प्रदर्श ख पर संलग्न है।

गत पांच वर्षों की विभागीय आन्तरिक और सी ए आडिट का विवरण निम्नानुसार है :-

गत पांच वर्षों की विभागीय आन्तरिक रिपोर्ट का विवरण प्रदर्श-ग पर संलग्न है।

गत पांच वर्षों की सी ए आडिट की प्रतियां प्रदर्श-घ पर संलग्न हैं।

(2) जोधपुर स्थित डेयरी में गत पांच वर्षों में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और लापरवाही के तीन प्रकरण सामने आये हैं। तथ्यात्मक विवरण प्रदर्श-च पर संलग्न है।

(विवरण व प्रतियां पुस्कालय में रखे गये)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों की सफाई व्यवस्था

76. श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) : क्या इन्दिरा गांधी नहर मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों की सफाई के लिए मशीनें खरीदी गई हैं? यदि हां, तो कितनी मशीनें एवं कब खरीदी गईं?

(2) गत पांच वर्षों में उक्त मशीनों की खरीद के पश्चात् किस-किस वर्ष में कितनी दूरी में नहरों की सफाई की गई?

(3) उक्त अवधि में मशीनों के रख-रखाव एवं पी.ओ.एल. पर किस-किस वर्ष में कितनी-कितनी राशि व्यय की गयी?

उत्तर

(1) जी हां। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में नहरों की सफाई व अन्य कार्यों हेतु 58 मशीनें वर्ष 1990, 1997, 1998, 1999 व 2007 में खरीदी गई थीं, जिनका विवरण तालिका-अ पर संलग्न है।

(इन्दिरा गांधी नहर मंत्री)

(2) गत पांच वर्षों में मशीनों द्वारा की गई नहरों की सफाई का विवरण तालिका-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त अवधि में मशीनों के रखरखाव एवं पी ओ एल पर वित्तीय वर्ष वार किये गये व्यय का विवरण तालिका-स पर संलग्न है।

(विवरण पुस्कालय में रखा गया)

जनजाति क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विस्तार अधिनियम, 1999 के नियम-उपनियम

77. श्री प्रहलाद गुंजल (कोटा उत्तर) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(1) क्या सरकार द्वारा प्रदेश के जनजाति क्षेत्रों के लिए पंचायती राज विस्तार अधिनियम, 1999 के तहत नियम, उप-नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या पंचायती राज विस्तार अधिनियम के अन्तर्गत राज्य स्तरीय आदिवासी परिषद् का गठन किया गया है? यदि हां, तो इसकी आन्तरिक कार्य प्रणाली की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार ने इस परिषद् की अनुशंसा पर कोई कार्यवाही अब तक की है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) अधिनियम, 1999 के तहत ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, जयपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-4(6) पीसा रूल्स/लीगल/पी.आर./10/1938 दिनांक 1.11.2011 द्वारा राजस्थान पंचायती राज (उपबन्धों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के सम्बन्ध में उपान्तरण) नियम, 2011 लागू हुए हैं। अधिसूचना की प्रति संलग्न है।

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग में भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद, प्रशासनिक सुधार (अनुभाग-3) विभाग, जयपुर की आज्ञा क्रमांक प 6(32)प्रसु/अनु-3/91 दिनांक 06/06/14 से पुनर्गठित की गयी है।

(जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री)

राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद की कार्यप्रणाली हेतु राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद नियम, 1980 है। (प्रति संलग्न है)

(3) आदेश दिनांक 06/06/14 से पुनर्गठित परिषद की अभी तक कोई भी बैठक आयोजित नहीं हुई है।

पूर्व में आदेश दिनांक 27/08/10 से गठित परिषद की कुल 5 बैठकें क्रमशः दिनांक 22/10/10, 21/07/11, 09/02/12, 07/09/12 एवं 12/04/13 आयोजित हुई हैं। उक्त बैठकों की अनुशंसानाएं एवं पालनाओं की अद्यतन स्थिति संलग्न है।

(प्रतियां पुस्कालय में रखी गयीं)

बामनवास एवं टोडाभीम में माडा विकास बोर्ड का गठन

78. श्री कुंजीलाल (बामनवास) : क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में माडा विकास बोर्ड गठन के क्या नियम हैं? नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बामनवास व टोडाभीम की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए माडा विकास बोर्ड का गठन करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में माडा विकास बोर्ड का गठन नहीं किया गया है। अतः गठन किए जाने के कोई नियम नहीं हैं।

(2) जी नहीं। प्रदेश में जनजाति समुदाय के समग्र विकास हेतु अपेक्षित सुझाव देने हेतु भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के प्रावधानों के तहत राजस्थान जनजाति परामर्शदात्री परिषद का गठन किया हुआ है।

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-50 का विवरण)

प्रपत्र–अ

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(अजमेर जिला वृत्त)

अजमेर शहर वृत्त के अन्तर्गत अजमेर शहर में बीपीएल श्रेणी में उपभोक्ताओं को जारी विद्युत कनेक्शन का उपखण्डवार विवरण

क्र. सं.	उपखण्ड का नाम	बीपीएल श्रेणी में उपभोक्ताओं को जारी विद्युत कनेक्शनों की संख्या
1	स.अ. (नउख-द्वितीय) अविनिनिलि अजमेर	261
2	स.अ. (नउख-तृतीय) अविनिनिलि अजमेर	893
3	स.अ. (नउख-पंचम) अविविनिलि अजमेर	288
4	स.अ. (पवस) अविविनिलि शास्त्रीनगर	365
5	स.अ. (नउख-प्रथम) अविविनिलि अजमेर	1158
6	स.अ. (नउख-चतुर्थ) अविविनिलि अजमेर	288
7	स.अ. (पवस) अविविनिलि मेयो	144
8	स.अ. (पवस) अविविनिलि मदार	170
	योग	**3567**

अधीक्षण अभियन्ता
(अजमेर शहर वृत्त)